दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

मार्च, 2019

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

नोट :

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **9**

- संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिये) संशोधन आदेश, 2019 9
- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 9
- राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंज़ूरी 11
- PRANAM आयोग 11
- अनुच्छेद 35A और 370 12
- हानिकारक और अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 संशोधन 13
- मलेरिया से निपटने में कारगर दवा 14
- नई जलविद्युत नीति 14
- द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ 15

आर्थिक घटनाक्रम **16**

- प्रधानमंत्री 'जी-वन' योजना 16
- उषा थोराट टास्क फोर्स 17
- राष्ट्रीय लघु बचत कोष 18
- मर्चेंट डिस्काउंट रेट 18
- DIPAM 19
- खुला बाज़ार परिचालन 20
- नेशनल हाउसिंग बैंक 20
- अगले पाँच वर्षों में धीमी गति से पवन ऊर्जा क्षमता का विस्तार: क्रिसिल 21
- कीरू पनबिजली परियोजना 22
- भारत का रणनीतिक/सामरिक पेट्रोलियम भंडार 23

नोट :

- विद्युत व्यापार को बढ़ावा देने के लिये मानदंडों में संशोधन 23
- लघु वित्त बैंक 24
- विदेशी विनिमय व्यवस्था के तहत बैंकिंग प्रणाली में 5 अरब डॉलर डालेगा रिज़र्व बैंक 25
- फॉल आर्मीवर्म 25
- वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट- 2019 26
- सरकार ने चालू वित्त वर्ष का विनिवेश लक्ष्य हासिल किया 27
- नवीन लेखा प्रणाली मानक (IndAS) 28
- गिल्ट फंड 28
- फिनटेक कॉनक्लेव 2019 29
- व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (TReDS) 30
- इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2019 31
- ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई-मार्केटप्लेस 32

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **34**

- अरुण-3 जल विद्युत परियोजना 34
- वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक- 2019 34
- वेनेज़ुएला की मदद करेगा रेड क्रॉस 36
- युवा विज्ञानी कार्यक्रम 37
- स्पार्क पहल के तहत IIT-मंडी के प्रस्तावों का चयन 37

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी **37**

- एटमोस्फेरिक वॉटर जनरेटर 39
- अरोरा सुपरकंप्यूटर 39
- नैदानिक परीक्षण नियमों का नया मसौदा 40
- तमिलनाडु स्वच्छ ऊर्जा में शीर्ष स्थान की ओर 41
- बायो-डाइजेस्टर प्रौद्योगिकी 42

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी **44**

- गैंडों (Rhinos) का संरक्षण 44

नोट :

- बांदीपुर टाइगर रिज़र्व में लगी आग 45
- इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 46
- वन सर्वेक्षण 47
- कृत्रिम वर्षा 48
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण मंच में प्लास्टिक पर चर्चा 48
- भारत में मिली मेंढक की एक नई प्रजाति 49
- जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स पर मानवीय प्रभाव 50
- वैश्विक पर्यावरण आउटलुक 50
- बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क 51
- वेस्ट नील वायरस 52
- भारत के लिये एक जलवायु भेद्यता सूचकांक 52
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा- 4 53
- सेप्टिक टैंकों के मानदंड पूरे होंगे 53
- वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट 54
- द्वीपों के लिये नए नियम : IPZ 2019 55
- वायनाड में 4 इकोटूरिज़्म (पर्यावरण पर्यटन) केंद्र बंद 56
- जलवायु की वैश्विक स्थिति: WMO 58

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **60**

- नई पनबिजली नीति 60
- चक्रवात ईदाई 61
- बंगाल डेल्टा में प्रवास 61
- सोलर सुनामी कर सकता है सनस्पॉट साइकिल को सक्रिय 63
- सुपर वोर्म एक्वीनोक्स मून 64
- अल-नीनो के लिये पूर्वानुमान 65

सामाजिक मुद्दे **66**

- पोषण पखवाड़ा 66
- DEPwD को मिला सातवाँ गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 67

नोट :

- भारत, अवैध दवा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र 68
- कार्य आधारित लैंगिक अंतराल 69
- डोंगरिया कोंध 70
- अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस- 2019 71
- बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 71
- समान कार्य असमान वेतन 73

कला एवं संस्कृति **74**

- हड़प्पा सभ्यता 74
- आदिवासी कलाकारों के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 74
- इंडियन म्यूज़ियम ऑफ अर्थ 75

आंतरिक सुरक्षा **76**

- समुद्री सुरक्षा पर समझौता 76
- हनोई शिखर सम्मेलन 2019 77
- 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी 77
- निटविर सेक्टर (Knitwear Sector) विकसित करने की योजना 77

चर्चा में **77**

- समावेशी इंटरनेट सूचकांक- 2019 78
- निर्माण प्रौद्योगिकी भारत -2019 78
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, 2019 79
- स्पेस-एक्स क्रू ड्रैगन 79
- गिनीज़ में शामिल 'कुंभ मेला- 2019' 80
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 80
- वन नेशन वन कार्ड 80
- BOLD-QIT परियोजना 81
- आईपीओ (Initial Public Offering-IPO) 81

नोट :

- त्रिसूर कोले वेटलैंड 81
- अल नागाह 2019 82
- NRETP हेतु ऋण अनुबंध 82
- चीन का कृत्रिम सूर्य 82
- लंदन पेशेंट 83
- नोस्ट्रो एकाउंट्स (Nostro Accounts) 83
- 9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन 83
- जन-औषधि दिवस 83
- गूगल 'बोलो' एप 84
- स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार- 2019 84
- विश्व वन्यजीव दिवस 84
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 85
- इरोड हल्दी को मिला GI टैग 85
- भारत और रूस ने किया परमाणु पनडुब्बी सौदा 85
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्त्व संस्थान 86
- महिलाओं को बेहतर आजीविका प्रदान करने का प्रयास 86
- परिवहन एवं विपणन सहायता योजना 86
- ई- धरती एप 87
- अमचंग वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों की मौत 87
- वैश्विक ट्रेडमार्क प्रणाली 87
- पिंक टैक्स 87
- क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग 88
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ 88
- भारत ऊर्जा प्रारूपण फोरम 88
- नवाचार और उद्यमिता उत्सव-2019 89
- AFINDEX-19 89
- योनो कैश 89

नोट :

- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 89
- VC 11184 90
- भारत के पहले लोकपाल 90
- 'खांदेरी' नौसेना में शामिल होने के लिये तैयार 91
- CAPEX 91
- क्षुद्र ग्रह 'रायुगु' 91
- UNNATEE 91
- BEE स्टार रेटिंग प्रोग्राम 92
- आपदा जोखिम पर कार्यशाला 92
- एबेल पुरस्कार- 2019 92
- अभ्यास 'मित्र शक्ति- 2019' 92
- क्षुद्रग्रह बेन्नू पर जल के प्रमाण 93
- विश्व जल दिवस- 2019 93
- नवरोज़ 94
- साइक्लोन ट्रेवर और वेरोनिका (Cyclone Trevor & Veronica) 94
- गोलन हाइट्स 94
- अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एयरो एक्सपो-2019 94
- वर्चुअल सिम कार्ड 95
- CBSE शिक्षा वाणी 95
- विश्व क्षय रोग दिवस 95
- भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास (AUSINDEX) 96
- GRAPES-3, म्यूओन टेलीस्कोप फैसिलिटी 96
- भारतीय सेना का पर्वतारोहण अभियान 96
- मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया-प्रशांत समूह 97
- एम्प्लॉयी स्टॉक परचेज़ स्कीम 97
- 3 वैज्ञानिकों को ट्यूरिंग पुरस्कार 97
- रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव 98
- नमक की सबसे लंबी गुफा 98

नोट :

- मांकडिंग 98
- आईएनएस 'मगर' 99
- ओडिसी नृत्य 99
- फकीम वन्यजीव अभयारण्य 99
- नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर 100
- कॉफी की पाँच किस्मों को जीआई टैग 100

विविध **101**

- CISF 124
- NCRB का 34वाँ स्थापना दिवस 125
- इडुक्की का मरयूर गुड़ 125
- ओरांग राष्ट्रीय उद्यान 125
- पिनाका रॉकेट सिस्टम 126
- सिरसी सुपारी को जीआई टैग 126
- नवाचार केंद्र 127
- गिरनार वन्यजीव अभयारण्य 127
- वुड स्नेक 127
- डेलाइट सेविंग टाइम 127
- World Wide Web 128
- सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 128

दृष्टि The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिये) संशोधन आदेश, 2019

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान आदेश (जम्मू और कश्मीर में लागू) संशोधन आदेश, 2019 [Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Amendment Order, 2019] के माध्यम से संविधान आदेश, 1954 (जम्मू और कश्मीर में लागू) [Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Order, 1954] में संशोधन के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंज़ूरी दे दी है।

- राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) संशोधन आदेश, 2019 जारी किये जाने के बाद संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम,2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के संशोधित तथा प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

जम्मू-कश्मीर के युवाओं को मिलेगा लाभ

अधिसूचित होने पर यह आदेश सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये पदोनत्ति के लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त 'आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये' 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा।

- उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये 10% आरक्षण जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों में पेश किया गया। यह सरकारी नौकरियों में मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

पृष्ठभूमि

- संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा 4 में उप-धारा (4A) को जोड़कर लागू किया गया। धारा (4A) में सेवा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों जिसमें गुर्जर और बकरवाल भी शामिल हैं, को पदोन्नति का लाभ (Benefit of promotion) देने का प्रावधान है।
- 24 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, 1995 का 77वाँ संविधान संशोधन अब जम्मू-कश्मीर राज्य के लिये लागू कर दिया गया है।
- एक अध्यादेश द्वारा जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 (Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004) में संशोधन कर नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया है।
- इससे पहले, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा से केवल 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले युवाओं के लिये 3% आरक्षण का प्रावधान था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाली आबादी द्वारा लंबे समय से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की जाती रही रही है, क्योंकि उन्हें जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से होने वाली गोलीबारी का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 (National Mineral Policy 2019) को मंज़ूरी दे दी है।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य अधिक प्रभावी, सार्थक और कार्यान्वयन योग्य नीतियाँ तैयार करना है जो स्थायी खनन प्रथाओं के साथ ही पारदर्शिता, बेहतर विनियमन एवं प्रवर्तन, संतुलित सामाजिक तथा आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती हैं।

नोट :

लाभ

- नई राष्ट्रीय खनिज नीति अधिक प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करेगी।
- यह परियोजना प्रभावित व्यक्तियों विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मुद्दों का समाधान करने के साथ ही भविष्य में सतत् खनन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी।

खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में शामिल प्रावधान :

- RP/PL धारकों के लिये पहले इनकार करने के अधिकार (Right of First Refusal) को लागू करना।
- निजी क्षेत्रों को अन्वेषण के लिये प्रोत्साहित करना।
- राजस्व शेयर आधार पर समग्र RP (Reconnaissance Permit) सह PL (Prospecting License) सह ML (Mining Lease) के लिये नए क्षेत्रों में नीलामी।
- खनन संस्थाओं के विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहन।
- निजी क्षेत्र के खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये खनन पट्टों का हस्तांतरण और समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण।
- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में निजी क्षेत्रों में खनन के वित्तपोषण को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्रों द्वारा अन्य देशों में खनिज संपत्ति के अधिग्रहण के लिये खनन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया है।
- इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि खनिज के लिये दीर्घकालिक आयात नीति से निजी क्षेत्र को व्यापार हेतु बेहतर योजना तैयार और व्यापार में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी।
- नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिये गए आरक्षित क्षेत्रों जिनका उपयोग नहीं किया गया है, को युक्तिसंगत बनाने और इन क्षेत्रों को नीलामी हेतु रखे जाने का भी उल्लेख किया गया है, जिससे निजी क्षेत्र को भागीदारी के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
- इस नीति में निजी क्षेत्र की सहायता करने के लिये वैश्विक मानदंड के साथ कर, प्रभार और राजस्व के बीच सामंजस्य बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 के तहत शुरू किये जाने वाले बदलावों में 'मेक इन इंडिया' पहल और लैंगिक संवेदनशीलता (Gender sensitivity) पर ध्यान देना शामिल है।
- खनिजों में विनियमन के लिये ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सक्षम प्रणाली, जागरूकता और सूचना अभियान शामिल किये गए हैं।
- NMP 2019 का उद्देश्य प्रोत्साहन के माध्यम से निजी निवेश को आकर्षित करना है जबकि खनिज संसाधनों के डेटाबेस बनाए रखने के लिये प्रयास किये जाएंगे।
- नई नीति, खनिजों की निकासी और परिवहन के लिये तटीय जलमार्गों एवं अंतर्देशीय शिपिंग के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। साथ ही खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिये समर्पित खनिज गलियारों को प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव करती है।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के समान विकास के लिये
- ज़िला खनिज निधि का उपयोग किया जाएगा।
- 2019 नीति पीढ़ीगत समानता (Inter-Generational Equity) की अवधारणा को भी प्रस्तुत करती है जो न केवल वर्तमान पीढ़ी की भलाई के लिये काम करती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों हेतु (खनन क्षेत्र में सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये) तंत्र को संस्थागत बनाने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी निकाय का गठन करने का भी प्रस्ताव करती है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, मौजूदा राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 (NMP 2008) का स्थान लेती है जिसे वर्ष 2008 में घोषित किया गया था।
- NMP 2008 की समीक्षा करने की प्रेरणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामान्य कारण बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक निर्देश के बाद आई।

नोट :

- शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, खान मंत्रालय ने NMP 2008 की समीक्षा करने के लिये खान मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. के. राजेश्वर राव की अध्यक्षता में 14 अगस्त, 2017 को एक समिति गठित की थी।
- समिति की बैठकों और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद, समिति ने रिपोर्ट तैयार कर खान मंत्रालय को प्रस्तुत की। खान मंत्रालय ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर पूर्व विधायी परामर्श नीति (Pre-legislative Consultation Policy-PLCP) प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित किया। PLCP प्रक्रिया में प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को अंतिम रूप दिया गया।

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति (National Policy on Software Products-NPSP) को मंज़ूरी दे दी।

उद्देश्य- सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 2025 तक 35 लाख रोज़गार सृजन करने के साथ-साथ लगभग 40% तक इस उद्योग की वृद्धि दर को पहुँचने में मदद करना। साथ ही अगले सात वर्षों में नीति के तहत विभिन्न योजनाओं में ₹1500 करोड़ के परिव्यय के साथ 2025 तक 70 से 80 बिलियन डॉलर के व्यापार को सुनिश्चित करना।

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- उभरती हुई प्रौद्योगिकी जैसे- इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, बिग डाटा, रोबोटिक्स को बढ़ावा देना भी इसी नीति के उद्देश्य बताए गए हैं।
- उपरोक्त संदर्भ में ₹1500 करोड़ के एक फंड (सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास कोष/Software Products Development Fund) निर्माण को भी मंज़ूरी दी गई है। इसमें सरकारी अंशदान ₹1000 करोड़ का होगा जिससे सॉफ्टवेयर उत्पाद से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके। ये कोष वित्तीय रूप से एक पेशेवर वित्तीय संस्थान द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- यह नीति वैश्विक बाज़ार में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों की हिस्सेदारी को दस गुना तक बढ़ाने पर भी ध्यान देगी। सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्ट अप (जिसमें 1000 स्टार्ट अप टियर II और III से जुड़े हैं) के वित्तीय पोषण पर भी ध्यान दिया गया है।
- 10 लाख आईटी पेशेवरों के कौशल विकास के साथ-साथ 10,000 नेतृत्व दायक पेशेवरों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है।
- इस नीति में सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिये नवाचार प्रोत्साहन एवं बौद्धिक संपदा से जुड़े साफ्टवेयर उत्पादों पर भी ध्यान दिया गया है।
- राष्ट्रीय साफ्टवेयर उत्पाद मिशन (National Software Product Mission) की भी शुरुआत करने की योजना है जिसमें सरकार के साथ शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति की घोषणा राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति की घोषणा के अगले ही दिन की गई है।

कुछ रोचक तथ्य

वर्तमान समय में आईटी-आईटीईएस उद्योग का कुल राजस्व 168 बिलियन डॉलर है। इसमें साफ्टवेयर उत्पाद उद्योग से मात्र 7.1 बिलियन डॉलर का ही राजस्व प्राप्त होता है, जबकि 2.3 बिलियन डॉलर का निर्यात होता है।

PRANAM आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में असम की सरकार ने पैरेंट्स रेपॉन्सबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटबिलिटी एंड मॉनिटरिंग (Parents Resposibility And Norms for Accountibility and Monitoring - PRANAM) आयोग का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- PRANAM आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों के बूढ़े माता-पिता और उन पर निर्भर दिव्यांग भाई-बहनों से जुड़ी समस्याओं पर लाए गए 'PRANAM' विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिये गठित पैनल है।
- यह देश में अपनी तरह का एकमात्र विधेयक है जिसमें राज्य के सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता की उनके बुरे वक़्त में सुरक्षा का प्रयास किया गया है।
- यह विधेयक राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये अपने माता-पिता और उन पर निर्भर दिव्यांग भाई-बहनों की देख-भाल को अनिवार्य बनाता है।
- आयोग को अगर यह सूचना मिलती है कि कर्मचारी अपने माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल नही कर रहें हैं या उनकी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहें हैं तो बिल के अनुसार, उनके वेतन का 10–15 प्रतिशत हिस्सा उनके माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहनों को हस्तानांतरित कर दिया जाएगा।
- इस विधेयक से राज्य के लगभग 4 लाख कर्मचारियों के 8 लाख माता-पिता लाभान्वित होंगे।
- भविष्य में विधेयक में राज्य में कार्यरत निजी क्षेत्र एवं केंद्र के कर्मचारी भी शामिल किये जाएंगे।

अनुच्छेद 35A और 370

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) संशोधन आदेश, 2019 [Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Amendment Order, 2019] को मंज़ूरी दे दी है।

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) संशोधन आदेश, 2019 जारी किये जाने के बाद संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के संशोधित तथा प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद 370

- 17 अक्तूबर, 1949 को संविधान में शामिल, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान से जम्मू-कश्मीर को छूट देता है (केवल अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर) और राज्य को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देता है।
- यह तब तक के लिये एक अंतरिम व्यवस्था मानी गई थी जब तक कि सभी हितधारकों को शामिल करके कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान हासिल नहीं कर लिया जाता।
- यह राज्य को स्वायत्तता प्रदान करता है और इसे अपने स्थायी निवासियों को कुछ विशेषाधिकार देने की अनुमति देता है।
- राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान पर लागू नहीं होते हैं।
- राज्य का नाम और सीमाओं को इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है।
- राज्य का अपना अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक अलग दंड संहिता (रणबीर दंड संहिता) है।
- राज्य विधानसभा की अवधि छह साल है, जबकि अन्य राज्यों में यह अवधि पाँच साल है।
- भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में जम्मू-कश्मीर के संबंध में कानून पारित कर सकती है। संघ द्वारा बनाया गया कोई अन्य कानून केवल राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू-कश्मीर में तभी लागू होगा जब राज्य विधानसभा की सहमति हो।
- राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि इस अनुच्छेद को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राज्य विधानसभा इसकी सिफारिश नहीं कर देती है।

अनुच्छेद 35A

- अनुच्छेद 35A, जो कि अनुच्छेद 370 का विस्तार है, राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है और उन स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है तथा राज्य में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं देता है।

नोट :

- इस अनुच्छेद का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकीय संरचना की रक्षा करना था।
- अनुच्छेद 35A की संवैधानिकता पर इस आधार पर बहस की जाती है कि इसे संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था। हालाँकि, इसी तरह के प्रावधानों का इस्तेमाल अन्य राज्यों के विशेष अधिकारों को बढ़ाने के लिये भी किया जाता रहा है।

अनुच्छेद 35A और 370 को रद्द करने से संबंधित मुद्दे

- वर्तमान में इन अनुच्छेदों से मिले अधिकारों को कश्मीरियों द्वारा धारित एकमात्र महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता के रूप में माना जाता है। अत: इससे छेड़छाड़ से व्यापक प्रतिक्रिया की संभावना है।
- यदि अनुच्छेद 35A को संवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया जाता है तो जम्मू-कश्मीर 1954 के पूर्व की स्थिति में वापस आ जाएगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार की राज्य के भीतर रक्षा, विदेश मामलों और संचार से संबंधित शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी।
- यह भी तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को दी गई कई प्रकार की स्वायत्तता वैसे भी कम हो गई है और संघ के अधिकांश कानून जम्मू-कश्मीर राज्य पर भी लागू होते हैं।

आगे की राह

- अनुच्छेद 370 को एकतरफा निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह ज़रूरी है कि जम्मू-कश्मीर और केंद्र इस मामलें में सर्वसम्मति से आगे आएँ। यह कार्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देकर और आत्मविश्वास के बल पर ही संभव हो सकता है।
- कश्मीर के युवाओं तथा निवासियों को इस तथ्य से आश्वस्त होना चाहिये कि कश्मीर देश की आर्थिक प्रगति का हिस्सा है और भारत का अभिन्न अंग है।
- राज्य सरकार को आम सहमति से लोकतंत्र का मार्ग भी अपनाना चाहिये। यह महत्त्वपूर्ण है कि इसमें निर्णय लेने के विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला शामिल हो और उन्हें ध्यान में रखा जाए।

हानिकारक और अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 संशोधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के ज़रिये हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियम, 2016 में संशोधन किया है। गौरतलब है कि इस संशोधन का उद्देश्य देश के अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान को मज़बूती प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु

- निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया गया है-
  - नियमों के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ-साथ सतत् विकास के सिद्धांतों को कायम रखना।
  - पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए, 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' और 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देना।
- **संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ:**
  - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और निर्यातौन्मुख इकाइयों (EOU) द्वारा ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध।
  - रेशम अपशिष्ट के निर्यातकों को अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेने से छूट दी गई है।
  - इसके साथ ही सतत् विकास के सिद्धांतों को बरकरार रखा गया है और यह भी ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण पर न्यूनतम असर हो।
  - भारत में निर्मित इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निर्यात के एक वर्ष के अंदर किसी खराबी की स्थिति में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बगैर वापस लाया जा सकता है।
  - जिन उद्योगों को जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अब हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियम, 2016 के नियमों के तहत भी किसी प्राधिकरण की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि ऐसे उद्योगों द्वारा उत्पन्न हानिकारक और अन्य अपशिष्ट अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं, अपशिष्ट संग्राहकों या निपटान करने वालों को सौंप दिये जाते हों।

नोट :

मलेरिया से निपटने में कारगर दवा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बुर्किना फासो (Burkina Faso) में मच्छर मारने की एक दवा 'आइवरमेक्टिन' (Ivermectin) का परीक्षण किया गया।

प्रमुख बिंदु

- परीक्षण में यह बात सामने आई है कि आइवरमेक्टिन दवा लेने के पश्चात् लोगों का रक्त मच्छरों के लिये घातक हो जाता है जिससे पुन: दूसरों को काटने और संक्रमित करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।
- मलेरिया से एक साल में 200 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित होते हैं और 2017 में इससे 4,35,000 लोगों की मौत हो गई। इनमें से ज़्यादातर अफ्रीका के थे।
- गौरतलब है कि इस दवा का उपयोग पहले से ही परजीवियों से होने वाले संक्रमण को रोकने में होता रहा है। किंतु मलेरिया के मामले में इसका परीक्षण पहली बार किया गया है।
- यह दवा मलेरिया नियंत्रण की अन्य विधियों के साथ प्रयुक्त करने से अधिक प्रभावी होगी।
- इस दवा के परीक्षण के लिये बुर्किना फासो के आठ गाँवों के 590 बच्चों सहित 2,700 लोगों को शामिल किया गया।
- उस गाँव में जहाँ यह दवा इस्तेमाल नहीं की गई थी वहाँ औसतन 2.5 बच्चे मलेरिया से प्रभावित थे, लेकिन जिन गाँवों में यह दवा दी गई वहाँ औसतन 2 बच्चे इससे ग्रसित थे।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि मलेरिया के खिलाफ लड़ाई आंशिक रूप से रुकी हुई है क्योंकि मच्छर उन कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं जो कि आमतौर पर इस्तेमाल किये जाते हैं।
- मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करने के लिये अन्य विधियों का परीक्षण किया जा रहा है जिसमें टीका और आनुवंशिक संशोधन भी शामिल हैं।

हालाँकि यह परीक्षण छोटे स्तर पर किया गया था किंतु इसके परिणाम आशाजनक रहे हैं।

नई जलविद्युत नीति

चर्चा में क्यों ?

नई जलविद्युत नीति के तहत सरकार ने बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को 'अक्षय ऊर्जा की स्थिति' (Renewable Energy Status) प्रदान करने की मंज़ूरी दी है। इससे पहले 25 मेगावाट (MW) क्षमता से कम की केवल छोटी परियोजनाओं को ही अक्षय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को ऊर्जा के एक अलग स्रोत के रूप में माना जाता था।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आँकड़ों के अनुसार, भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की स्थापित क्षमता फरवरी 2019 तक 75,055.92 मेगावाट की थी।
- इसमें कुल ऊर्जा मिश्रण का लगभग 21.4% हिस्सा शामिल था, बाकी हिस्सा थर्मल, परमाणु और बड़े हाइड्रो स्रोतों से प्राप्त हुआ।
- हालाँकि नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को शामिल करने से ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) में काफी बदलाव आएगा।
- अक्षय ऊर्जा क्षमता अब कुल ऊर्जा मिश्रण की 1,20,455.14 मेगावाट या 34.4% होगी।
- यह नीति अक्षय ऊर्जा मिश्रण को भी काफी बदल देगी। फरवरी 2019 से पहले, पवन ऊर्जा ने सभी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 50% योगदान दिया, यह अब केवल 29.3% रह जाएगी।
- इसी तरह सौर ऊर्जा का हिस्सा 34.68% से घटकर 21.61% हो जाएगा।
- हालाँकि, हाइड्रो सेक्टर में इसकी हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 41% से अधिक होने की संभावना है।

नोट :

प्रभाव

- पनबिजली ऊर्जा ग्रिड स्थिरता प्रदान करती है, जबकि पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कारण ग्रिड स्थिरता और एक बेहतर ऊर्जा मिश्रण प्रदान करने हेतु माना जाता है।
- ऊष्मा में तेज़ वृद्धि और पनबिजली में पूर्ण ठहराव के कारण पिछले कुछ वर्षों से थर्मल-हाइड्रो मिश्रण में भारी असंतुलन है।
- इस पुनर्वर्गीकरण से तात्कालिक रूप से 2022 तक भारत को 175 GW के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- नीति से एक और लाभ यह भी होगा कि सतलज जल विकास निगम (SJVN) जैसे राज्य द्वारा संचालित पनबिजली कंपनियों के शेयर की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- इससे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को सस्ता ऋण प्राप्त करने और स्वच्छ ऊर्जा के लिये वितरण कंपनियों से मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- राज्य वितरण कंपनियों को अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों की तरह एक निश्चित प्रतिशत जलविद्युत खरीदने के लिये बाध्य किया जाएगा। इससे हाइड्रोपावर के लिये एक बाज़ार तैयार होगा और यह क्षेत्र प्रतिस्पर्द्धी बनेगा।
- इन परियोजनाओं को न केवल बुनियादी ढाँचे के लिये बजटीय समर्थन प्राप्त होगा बल्कि 'ग्रीन फाइनेंस' तक भी पहुँच बनाई जा सकेगी।

द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में 2.74 मिलियन नए टीबी मरीज़ों की पुष्टि हुई है जो वर्ष 2016 के 2.79 मिलियन की तुलना में 0.5 मिलियन कम है। जबकि वैश्विक स्तर पर 10 मिलियन नए टीबी मरीज़ों की पुष्टि हुई है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में वर्ष 2017 में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 204 टीबी मरीज़ों की पुष्टि हुई है।
- भारत ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी के पूर्णतया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि सतत् विकास लक्ष्य वर्ष 2030 से 5 वर्ष पूर्व प्राप्त किया जाना है।
- द लैंसेट वैश्विक स्वास्थ्य आर्टिकल के अनुसार, भारत सहित तीन सर्वाधिक प्रभावित देशों में वर्ष 2015 के आँकड़ों के आधार पर टीबी मरीज़ों की संख्या में 2035 तक 57 % कमी तथा इससे होने वाली मृत्यु में 72 % की कमी की संभावना है।

भारत के संदर्भ में

- देश में औषधि-संवेदनशील व औषधि-प्रतिरोधी टीबी रोग के निदान और उपचार में सुधार की आवश्यकता है।
- टीबी रोग से ग्रस्त 8 मिलियन मरीज़ों को अगले 30 वर्ष में बचाया जा सकेगा, यदि टीबी से संबंधित जाँच में अनुदान और उपचार पूर्ण करने में आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। टीबी के कारण मौतों से होने वाली आर्थिक हानि 32 बिलियन डॉलर है, जबकि मात्र 290 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता से इन मौतों को बचाया जा सकता है।
- लैंसेट कमीशन की संस्तुति के अनुसार, भारत को टीबी से संबंधित सेवाओं में सुधार तथा निजी क्षेत्र की संबद्धता से दवा की आपूर्ति के साथ ही द्वितीय श्रेणी की दवाओं हेतु सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2018 में 2.15 मिलियन टीबी के मामले दर्ज किये जा चुके हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 % अधिक हैं।
- पिछले वर्ष निजी क्षेत्र में 0.54 मिलियन मामले दर्ज किये गए जो की वर्ष 2017 की तुलना में 35% अधिक हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ

- टीबी सेवाओं का प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकरण किया जाना जिससे उपचार में विलंब को रोका जा सके।
- कुल टीबी मरीज़ों के 10 % की या तो उपचार से पूर्व ही मृत्यु को हो जाती है या उनका उपचार सही मेडिकल उपचार से पूर्व स्व उपचार के कारण विलंब से होता है। यहाँ तक कि प्राथमिक उपचार में भी 4.1 महीने तक का विलंब हो जाता है।

आगे की राह

- संक्रमण चक्र के प्रभाव को कम करने के लिये टीबी मरीज़ों की पहचान हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

प्रधानमंत्री 'जी-वन' योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री 'जी-वन योजना' (Jaiv Indhan-Vatavaran Anukool Fasal Awashesh Nivaran Yojana: JI-VAN) के लिये वित्तीय मदद को मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना (जी-वन योजना) के तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय मदद प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जो लिग्नोसेल्यूलॉज़िक बायोमास (Lignocellulosic Biomass) और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक (Feedstock) का इस्तेमाल करती हैं।

लिग्नोसेल्यूलॉज़िक बायोमास (LC biomass) – यह बायोमास सेल्यूलोज़ (Cellulose), हेमिसेल्यूलोज़ (Hemicelluloses) और लिग्निन (Lignin) से बना होता है।

- 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिये इस योजना में कुल 1969.50 करोड़ रुपए की मंज़ूरी प्रदान की गई है।
- स्वीकृत कुल 1969.50 करोड़ रुपए में से 1800 करोड़ रुपए 12 वाणिज्यिक परियोजनाओं की मदद, 150 करोड़ रुपए 10 प्रदर्शित परियोजनाओं और बाकी बचे 9.50 करोड़ रुपए उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (Centre for High Technology-CHT) को प्रशासनिक शुल्क के रूप में दिये जाएंगे।

विवरण

- इस योजना के तहत12 परियोजनाओं को वाणिज्यिक स्तर पर और 10 दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल परियोजनाओं के प्रदर्शन स्तर पर दो चरणों में वित्तीय मदद दी जाएगी।
- पहला चरण (2018-19 से 2022-23) – इस चरण के दौरान 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं तथा 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी।
- दूसरा चरण (2020-21 से 2023-24)- दूसरे चरण में बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को वित्तीय मदद दी जाएगी।
- इस परियोजना के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित एवं मदद करने का काम किया गया है। इसके लिये वाणिज्यिक परियोजनाएँ स्थापित करने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol-EBP) कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मदद पहुँचाने के अलावा निम्नलिखित लाभ भी प्राप्त होंगे -
- जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करने की भारत सरकार की परिकल्पना को साकार करना।
- जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल का विकल्प प्रस्तुत कर उत्सर्जन के ग्रीन हाउस गैस (GHG) मानक की प्राप्ति।
- बायोमास और फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का समाधान करना और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
- दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना और बायोमास आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण एवं शहरी लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करना।
- बायोमास कचरे और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के संग्रहण की समुचित व्यवस्था कर स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना।
- दूसरी पीढ़ी के बायोमास को इथेनॉल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने की विधि का स्वदेशीकरण करना।
- योजना के लाभार्थियों द्वारा बनाए गए इथेनॉल की अनिवार्य रूप से तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति करना, ताकि वे EBP कार्यक्रम के तहत इनमें निर्धारित प्रतिशत में मिश्रण कर सकें।

नोट :

उद्देश्य

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल का मिश्रण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इथेनॉल की कीमत ज़्यादा रखने और इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद 2017-18 के दौरान 150 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद ही प्राप्त की जा सकी जो कि देशभर में पेट्रोल में इथेनॉल के मात्र 4.22 प्रतिशत मिश्रण के लिये पर्याप्त है।
- इसी वजह से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बायोमास और अन्य कचरों से दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्राप्त करने की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं। इससे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत जीवाश्म पेट्रोल की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
- प्रधानमंत्री जी-वन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल क्षमता विकसित करने और इस क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम 2003 में लागू किया था। इसके ज़रिये पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना है।
- वर्तमान में EBP 21 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कंपनियों के लिये पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाना अनिवार्य बनाया गया है।
- मौजूदा नीति के तहत पेट्रोकेमिकल के अलावा मोलासिस और नॉन फीड स्टाक उत्पादों जैसे सेल्यूलोज़ और लिग्नोसेल्यूलोज़ जैसे पदार्थों से इथेनॉल प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

उषा थोराट टास्क फोर्स

चर्चा में क्यों

आर.बी.आई. ने उषा थोराट (पूर्व डिप्टी गवर्नर) की अध्यक्षता में एक समिति (आठ सदस्यीय समिति) का गठन किया है। इसका कार्य अपतटीय रुपए बाज़ार में भारतीय मुद्रा की स्थिरता हेतु आवश्यक नीतियाँ बनाने हेतु सुझाव देना है। यह समिति अपनी रिपोर्ट जून 2019 तक जमा करेगी।

(अन्य सदस्य-अजीत रानाडे, सुरेन्द्र रोशा, साजिद चिनॉय आर्थिक मामले विभाग से नामित एक सदस्य जे.पी. मार्गन के सदस्य)

अन्य कार्य

- यह समिति के ऑफशोर रूपी मार्केट/अपतटीय रुपए बाज़ार (Off Shore Rupee Market) के विकास के कारकों पर भी ध्यान देगी। साथ ही यह समिति घरेलू बाज़ार में विनिमय दरों तथा बाज़ार तरलता पर अपतटीय बाज़ारों से पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन करेगी।
- यह समिति अपतटीय रुपए व्यापार से उत्पन्न अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देगी और उनके समाधान का सुझाव देगी। साथ ही अप्रवासी भारतीयों से घरेलू बाज़ार संदर्भों में प्रोत्साहन प्राप्ति में वृद्धि हेतु भी सुझाव देगी। यह समिति भारतीय मुद्रा के अप्रवासी भारतीयों के बीच चलन/उपयोग बढ़ाने के प्रयासों पर भी विचार करेगी।

ऑफशोर रूपी मार्केट/अपतटीय रुपए बाज़ार

- भारतीय राष्ट्रीय सीमा के बाहर 'रुपया' एक मुद्रा है जिसमें अन्य प्रकार के व्यापार और लेन-देन भी होते हैं। घरेलू मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भी यह बाज़ार जुड़ा है। अपतटीय रुपए बाज़ार का सबसे अच्छा उदाहरण मसाला बांड भी है जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से पैसे लेने हेतु किया जाता है लेकिन यह कार्य भारतीय मूल्य वर्ग में ही होगा।

विनिमय दर

- विदेशी धरती पर एक देशी मुद्रा की कीमत वहाँ की मुद्रा के किसी मात्रा के बराबर होगी। यह तय करने वाली दर को मुद्रा विनिमय दर या विनिमय दर कहा जाता है।

नोट :

राष्ट्रीय लघु बचत कोष

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय लघु बचत निधि (National Small Savings Fund-NSSF) से बजट में उल्लिखित धनराशि से अधिक उधार ले सकती है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यान देने वाली बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) पर सरकार की निर्भरता बढ़ी है।
  - हालाँकि वित्तीय वर्ष-2020 हेतु 21% का लक्ष्य वित्तीय वर्ष-2019 के 22.4% से थोड़ा कम है किंतु यह वित्तीय वर्ष-2015 की तुलना में 3% अधिक है।
- ऐसे राज्य जो पहले इस कोष के प्रमुख कर्ज़दार थे, अब 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बाज़ार के कर्ज़ (राज्य विकास ऋण) पर अधिक भरोसा कर रहे हैं।
  - अप्रैल 2016 के बाद सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों (अरुणाचल प्रदेश, केरल, दिल्ली (UT) और मध्य प्रदेश को छोड़कर) द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत से कर्ज़ न लेने की वज़ह से केंद्र और सार्वजनिक उपक्रमों हेतु उपलब्ध कर्ज़ का हिस्सा बढ़ा है।
- हालाँकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बाज़ार से लिये जाने वाले कर्ज़ की लागत NSSF के कर्ज़ की तुलना में ज़्यादा होती है।

राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF)

- भारत में राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) की स्थापना 1999 में की गई थी।
- राष्ट्रीय लघु बचत कोष (निगरानी और निवेश) नियम, 2001 के तहत वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) इस कोष को प्रशासित करता है।
- राष्ट्रीय लघु बचत कोष का उद्देश्य भारत के संचित निधि से छोटी बचत लेन-देन को हटाना और पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है।
- राष्ट्रीय लघु बचत कोष सार्वजनिक खाते के रूप में संचालित होता है, इसलिये इसका लेन-देन सीधे केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित नहीं करता है।
- लघु बचत को तीन प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-
  - डाकघर जमा
  - बचत पत्र
  - सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई (IIT Mumbai) द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि अनधिकृत शुल्क एवं उच्च Merchant Discount Rate- MDR डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया में बड़े बाधक हैं।

अध्ययन के बारे में

- अध्ययन में कहा गया है कि 2018 में व्यापारियों पर क्रेडिट कार्ड MDR का करीब 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बोझ पड़ा है।
- यह डेबिट कार्ड एमडीआर के मद में आई कुल 3,500 करोड़ रुपए की लागत के मुकाबले काफी अधिक है।
- जबकि मूल्य के लिहाज से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से 2018 में लगभग 5.7 लाख करोड़ रुपए का समान लेन-देन हुआ है।

नोट :

क्या है MDR ?

- MDR वह शुल्क है, जो कार्ड से भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी बैंक को चुकाते हैं।
- मास्टरकार्ड, वीज़ा जैसा पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ़ सेल/कार्ड स्वाइप मशीन ज़ारी करने वाले बैंकों को MDR में मुआवज़ा/छूट प्राप्त होता है।
- इसे बैंक और व्यापारी के बीच एक पूर्व निर्धारित अनुपात में साझा किया जाता है एवं लेन-देन के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने डेबिट कार्ड, BHIM UPI या आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से दिसंबर 2020 तक किये जाने वाले 2,000 रुपए तक के लेन-देन पर MDR शुल्क वहन करने का निर्णय लिया।

MDR का डिजिटल भुगतान पर प्रभाव

- बैंक ज़्यादा-से-ज़्यादा पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS)/कार्ड स्वाइप मशीन जारी करना चाहते हैं किंतु छोटे व्यापारियों के लिये पॉइंट ऑफ़ सेल/कार्ड स्वाइप मशीन रखना ज़्यादा खर्चीला है क्योंकि उन्हें बैंकों को MDR के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है, जबकि नकद लेन-देन में ऐसी किसी राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

साधारण कार्ड उपयोगकर्त्ताओं को इन तकनीकी विषयों की कम जानकारी होती है, अत: बैंकों की यह ज़िम्मेदारी है कि वह कार्ड और भीम-यू.पी.आइ. (BHIM-UPI) उपयोगकर्त्ताओं को इन अतिरिक्त शुल्कों से बचाए।

DIPAM

चर्चा में क्यों ?

वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों (Central Public Sector Enterprises- CPSEs) की गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण में तेज़ी लाने के लिये निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के तहत एक विशेष सेल स्थापित करने की योजना बनाई है ।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत नीति आयोग द्वारा CPSEs की गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी।
- इस सूची पर परामर्शदाता समूह के साथ चर्चा के बाद परिसंपत्तियों को अलग-अलग कर बेचा जा सकता है।
- इस समूह में प्रशासनिक मंत्रालयों, आर्थिक मामलों के विभाग, निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के अधिकारी शामिल हैं।
- वित्त मंत्री की अध्यक्षता में विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र द्वारा नीति आयोग की रिपोर्ट ली जाएगी, जिसके बाद CPSEs और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय मौद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
- गौरतलब है कि नीति आयोग पहले से ही लगभग 35 CPSEs की पहचान कर चुका है जो खुले बाज़ार में एकमुश्त बिक्री के लिये जा सकते हैं।
- संपत्ति मौद्रीकरण सेल ही उन लोगों की अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामलों को भी देखेगा जो पाकिस्तान या चीन चले गए और अब भारत के नागरिक नहीं हैं।
- यह केंद्र सरकार की CPSEs की गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों, मुख्य रूप से भूमि और भवन, के मौद्रीकरण के लिये प्रक्रिया और तंत्र अपनाने की समग्र योजनाओं का एक हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

- गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संपत्तियाँ हैं जो या तो आवश्यक नहीं हैं या कंपनी के व्यावसायिक कार्यों में उपयोग नहीं की जाती हैं।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक विनिवेश और शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन के तहत अचल संपत्तियों के मौद्रीकरण के लिये संस्थागत ढांचा तैयार करने की मंजूरी दी है।
- साथ ही CPSEs की परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण की योजना वित्त मंत्रालय की रही है जिसके तहत नीति आयोग इन कपनियों की प्रत्येक गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों की सूची तैयार करेगा।

नोट :

क्या है DIPAM ?

- विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग था।
- 14 अप्रैल, 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) कर दिया गया।

DIPAM के अंतर्गत निम्नलिखित मामले आते हैं:

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश से संबंधित सभी मामले।
- बिक्री या निजी प्लेसमेंट या पूर्ववर्ती केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले।

खुला बाज़ार परिचालन

चर्चा में क्यों ?

कुछ समय पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने खुला बाज़ार परिचालन (Open Market Operations-OMO) के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पूंजी डालने का निर्णय लिया था। हाल ही में OMO के ज़रिये पूंजी डालने के बावजूद तरलता परिदृश्य में कमी होने की बात सामने आई है।

प्रमुख बिंदु

- खुला बाज़ार परिचालन (OMO) धन की कुल मात्रा को विनियमित या नियंत्रित करने के लिये मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिये नियोजित की गई है।
- RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के लिये खुले बाज़ार का संचालन किया जाता है।
- केंद्रीय बैंक, आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत तरलता में कमी लाने के लिये सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है और इस प्रणाली को नियंत्रित रखने के लिये सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है।
- अक्सर ये परिचालन दिन-प्रतिदिन के आधार पर किये जाते हैं, जो बैंकों को उधार देने में मदद के साथ-साथ मुद्रास्फीति को संतुलित करते हैं।
- RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में रुपए के मूल्य को समायोजित करने के लिये अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों जैसे रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात के साथ OMO का उपयोग किया जाता है।

क्या है मामला ?

- CARE रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाज़ार परिचालन (Open Market Operations-OMO) के माध्यम से बाज़ार में डाली गई मुद्रा (12,500 करोड़ रुपए) तथा वेतन और पेंशन के उच्च सरकारी खर्चों के बावजूद 34,266 करोड़ रुपए की कमी आई है।
- 15 फरवरी को समाप्त पखवाड़े के दौरान गैर-खाद्य ऋण या व्यक्तियों और कंपनियों के लिये ऋण 14.3 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ा, जो पिछले एक पखवाड़े में 14.4 प्रतिशत (पिछले वर्षों की तुलना में) धीमा था। इसने जमा वृद्धि को पार कर 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
- बैंक विशेषज्ञों के अनुसार, उच्च ऋण वृद्धि के बीच कम जमा वृद्धि बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी में योगदान करने वाला एक कारक रहा है।

नेशनल हाउसिंग बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) के लिये पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio-CAR) को मार्च 2022 तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिये वर्तमान अनुपात 12% है जिसे अगले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जायेगा।
- वित्तीय संस्थाएँ होने के नाते हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को किसी भी अन्य वित्तीय क्षेत्र में विफलताओं से उत्पन्न जोखिमों, तरलता और सॉल्वेंसी से संबंधित जोखिमों तथा अन्य धन संबंधी जोखिम से अवगत कराया जाता है। इसीलिये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के नियामक ढाँचे की समीक्षा की गई।
- HFCs ने इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि मुद्रा की तरलता समय की ज़रूरत है। नियामकों को मज़बूत बैलेंस शीट के साथ HFC के लिये पूंजी की आसान पहुँच बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि तरलता की कमी आवास बाज़ार के समग्र विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में काम कर रही है।
- पूंजी की उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, खासकर यदि हमें 2022 तक आवास के संदर्भ में सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- विनियामक परिवर्तन द्वारा बड़े हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जिनकी पूंजी 15% से अधिक है, जैसे कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC), रेपको होम फाइनेंस (RHF), इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस (IHF) और दीवान हाउसिंग फाइनेंस (DHF) को कुछ खास प्रभावित किये जाने की संभावना नहीं है ।
- प्रणालीगत स्तर पर किया गया यह परिवर्तन लाभ के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिये एक अच्छा प्रयास है। साथ ही HFC को दिशा-निर्देशों को पूरा करने के लिये तीन साल का रोडमैप भी प्रदान करता है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio-CAR)

- नेशनल हाउसिंग बैंक ने तरलता जोखिम के खिलाफ एहतियाती उपाय के रूप में हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों (HFC) की पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 15% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
- CAR, बैंक की उपलब्ध पूंजी का एक माप है जिसे बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात को पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (capital-to-risk Weighted Assets Ratio-CRAR) के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग जमाकर्त्ताओं की सुरक्षा और विश्व में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।

अगले पाँच वर्षों में धीमी गति से पवन ऊर्जा क्षमता का विस्तार: क्रिसिल

चर्चा में क्यों ?

हाल में जारी क्रिसिल की एक रिपोर्ट ने आने वाले पाँच वर्षों में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में क्षमता विस्तार की धीमी दर का अनुमान लगाया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2019 से 2023 तक पवन ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि दर धीमी होने की संभावना है, ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि दर में कमी केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ (सीटीयू) ग्रिड कनेक्टेड कैपेसिटी के आवंटन से प्रेरित है।
- ऐसा पाया गया है कि एक प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया में बदलाव से उद्योग की वृद्धि दर धीमी हो गई है। मूल उपकरण निर्माताओं (Original Equipment Manufacturers-OEMs) के लिये बोली की प्रतिक्रिया और लाभप्रदता दोनों में गिरावट आई है।
- ऊर्जा क्षमता को मुख्य रूप से सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया (SECI) और PTC इंडिया जैसे अपेक्षाकृत मज़बूत समकक्षों में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया जाएगा, जो राज्य के जोखिम को कम करेंगे।
- दूसरी ओर, राज्यों की नीलामी प्रक्रिया धीमी हो गई है क्योंकि कई राज्यों ने अपने गैर-सौर नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) को पूरा करने में मदद हेतु उनके द्वारा नीलाम की गई योजनाओं के तहत पवन ऊर्जा की खरीद के लिये PTC और SECI के साथ बिजली आपूर्ति समझौतों (PSAs) पर हस्ताक्षर किये हैं।

नोट :

क्रिसिल (CRISIL)

- क्रिसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान, जोखिम तथा नीति संबंधी सलाहकार सेवाएँ प्रदान करती है।
- इसकी अधिकांश हिस्सेदारी 'स्टैंडर्ड एंड पूअर्स' के पास है, जो मैकग्रा हिल फाइनेंशियल का एक विभाग है।

कीरू पनबिजली परियोजना

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने जम्मू-कश्मीर में मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (M/s Chenab Valley Power Projects Private Limited-M/s CVPPPL) को कीरू पनबिजली परियोजना (624 मेगावाट) के निर्माण के लिये निवेश करने की मंज़ूरी दे दी है।

योजना परिव्यय

- यह परियोजना 4287.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (जुलाई, 2018 के मूल्य स्तर पर) से कार्यान्वित की जाएगी। इसमें 426.16 करोड़ रुपए के विदेशी घटक (Foreign Component-FC) एवं निर्माण के दौरान ब्याज (Interest During Construction-IDC) के साथ-साथ कीरू पनबिजली परियोजना (Kiru Hydro Electric Project) के निर्माण के लिये मैसर्स CVPPPL में NHPC द्वारा लगाई जाने वाली 630.28 करोड़ रुपए की इक्विटी भी शामिल है। इसमें पकल डल परियोजना (Pakal Dul HE Project) के कार्यान्वयन के लिये मंज़ूरी देते वक्त कैबिनेट द्वारा पहले से ही निर्माण पूर्व गतिविधियों के लिये स्वीकृत 70 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (M/s CVPPPL)

- मैसर्स CVPPPL दरअसल NHPC, जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (Jammu & Kashmir State Power Development Corporation-JKSPDC) और PTC की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिनकी इक्विटी शेयरभागिता क्रमश: 49%,49% एवं 2% है।

परियोजना के बारे में

- यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवार ज़िले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इसमें सबसे गहरे नींव स्तर के ऊपर 135 मीटर ऊँचे कंक्रीट ग्रैविटी डैम (Concrete Gravity Dam), 4 सर्कुलर, 5.5 मीटर के आंतरिक व्यास एवं 316 से लेकर 322 मीटर तक की लंबाई वाले प्रेशर शाफ्ट, एक भूमिगत बिजलीघर (Underground Power House) और 7 मीटर व्यास व 165 से लेकर 190 मीटर तक की लंबाई तथा घोड़े की नाल के आकार वाली 4 टेल रेस सुरंगों (Tail Race Tunnel) का निर्माण करना शामिल है।
- इस परियोजना से उत्तरी ग्रिड को आवश्यक बिजली सुलभ होगी और इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज़ के क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। यह परियोजना साढ़े चार वर्षों में पूरी की जाएगी।
- कीरू पनबिजली परियोजना की परिकल्पना एक 'रन ऑफ रिवर (Run of River-RoR) योजना' - यानी 'जल भंडारण के बगैर योजना' के रूप में की गई है। इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की गई है जिससे 624 मेगावाट (4x156 मेगावाट) की स्थापित क्षमता वाली यह परियोजना सिंधु जल संधि 1960 (Indus Water Treaty 1960) की ज़रूरतों को पूरा करती है।

पृष्ठभूमि

- इस परियोजना की आधारशिला 3 फरवरी, 2019 को रखी गई थी।
- जम्मू-कश्मीर की सरकार ने टोल टैक्स एवं राज्य वस्तु एवं सेवा कर (State Goods and Service Tax-SGST) के भुगतान से पहले ही छूट देने और इसमें निरंतर कमी करते हुए मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ इसके वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से लेकर अगले 10 वर्षों की अवधि तक जल उपयोग प्रभार की अदायगी से भी छूट दी है।

नोट :

भारत का रणनीतिक/सामरिक पेट्रोलियम भंडार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने देश में रणनीतिक तेल भंडारण सुविधा के क्षेत्र में सउदी अरब को भारत में निवेश के लिये आमंत्रित किया।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार ने देश में आपातकालीन कच्चे तेल का भंडार बनाने के लिये सऊदी अरब से निवेश की मांग की है जो तेल की कीमतों में अस्थिरता के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करेगा और तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता के सामने आने वाले व्यवधानों को दूर करेगा।
- दोनों देशों के मंत्रियों ने भारतीय तेल एवं गैस क्षेत्र में विभिन्न सऊदी निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की जिसमें महाराष्ट्र में पहले संयुक्त उद्यम वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदम भी चर्चा भी शामिल हैं।
- यह परियोजना जिसकी लागत लगभग 44 अरब डॉलर यानी करीब 3.08 लाख करोड़ रुपए है, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगी।
- महाराष्ट्र के रत्नागिरि ज़िले में स्थापित की जाने वाली इस परियोजना के लिये वहाँ की सरकार अब तक ज़मीन का प्रबंध नहीं कर पाई है।
- हाल में दोनों देशों के पेट्रोलियम मंत्रियों ने तेल शोधन एवं पेट्रोरसायन परिसर के बारे में चर्चा की। साथ ही सऊदी अरब नेशनल ऑयल कंपनी के निवेश से भारत के पश्चिमी तट पर प्रस्तावित तेल रिफाइनरी परियोजनाओं में तेज़ी लाने पर भी चर्चा की गई।

उद्देश्य

- भारत देश में खपत किये जाने वाले प्रत्येक पाँच बैरल तेल में से चार बैरल तेल का आयात करता है जो सामान्यत: खाड़ी देशों एवं अफ्रीका से आयात किया जाता है।
- आयातक देशों में वर्षभर होने वाले राजनीतिक जोखिम से बचने के लिये भारत अपने देश में रणनीतिक भंडार का विस्तार कर रहा है।
- भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के होने से वैश्विक जगत के राजनीतिक संकटों का भारतीय अर्थव्यस्था पर नकारात्मक प्रभाव कम होगा।

भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार

- सामरिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट जैसे प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपदाओं के दौरान आपूर्ति में व्यवधान से निपटने के लिये कच्चे तेल के विशाल भंडार होते हैं।
- भारत के रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार वर्तमान में विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), मंगलुरु (कर्नाटक) और पाडुर (केरल) में स्थित हैं।
- हाल ही में सरकार ने चंदीखोल (ओडिशा) और पादुर (कर्नाटक) में दो अतिरिक्त सुविधाएँ स्थापित करने की घोषणा की थी।
- पहली बार तेल के संकट के बाद रणनीतिक भंडार की इस अवधारणा को 1973 में अमेरिका में लाया गया था।
- पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी गुफाओं में भंडारण की अवधारणा को पारंपरिक रूप से एक ऊर्जा सुरक्षा उपाय के रूप में लाया गया है जो भविष्य में हमले या आक्रमण के कारण तेल की आपूर्ति में कमी आने पर सहायक हो सकती हैं।
- यह भूमिगत भंडारण, पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की अब तक की सबसे अच्छी आर्थिक विधि है, क्योंकि भूमिगत सुविधा भूमि के बड़े स्तर की आवश्यकता को नियंत्रित करती है, कम वाष्पीकरण सुनिश्चित करती है, क्योंकि गुफाओं का निर्माण समुद्र तल से बहुत नीचे किया जाता है, इसलिये कच्चे तेल का निर्वहन जहाज़ो से करना आसान होता है।

विद्युत व्यापार को बढ़ावा देने के लिये मानदंडों में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission-CERC) ने पड़ोसी देशों को भारत के बाज़ारों से अधिक बिजली खरीदने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये नियमों में संशोधन किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विद्युत मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में बिजली के सीमा पार व्यापार के लिये नए दिशा-निर्देश जारी करने के बाद नियमों को संशोधित किया है।
- CERC ने कुछ प्रतिबंधात्मक नियमों को हटा दिया था और बाज़ारों में बिजली व्यापार को अधिक आकर्षक बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था।
- विदेशी संस्थानों को केवल भारतीय पावर ट्रेडिंग संस्थाओं के माध्यम से पावर एक्सचेंज में भाग लेने की आवश्यकता होगी।
- वित्त वर्ष 2017-18 में नेपाल, बांग्लादेश और म्याँमार को 7.2 बिलियन यूनिट्स (BU) की आपूर्ति की गई और वित्त वर्ष 2018-19 के पहले दस महीनों में इन देशों को 6.4 बिलियन यूनिट का निर्यात किया गया है।
- बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक, बिजली एक्सचेंजों पर सीमापार व्यापार आगे बढ़ने से वार्षिक रूप से बिजली की 5-6 बिलियन अतिरिक्त यूनिट का विद्युत बाज़ार का लाभ मिल सकता है।
- बांग्लादेश भारतीय विद्युत का सबसे बड़ा खरीदार है।
- उक्त तीनों पड़ोसी देशों के अलावा भारत मदुरै से श्रीलंका में न्यू हैबराना तक संपर्क स्थापित करने की संभावनाएँ तलाश रहा है।
- नवंबर 2014 में भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के अन्य देशों के साथ स्वैच्छिक आधार पर संबंधित सदस्य देशों के कानूनों, नियमों और विनियमों के अधीन सीमा पार से विद्युत व्यापार को सक्षम बनाने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- बाद में अगस्त 2018 में भारत ने बंगाल की खाड़ी के सदस्य देशों के बीच बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (BIMSTEC) हेतु ग्रिड इंटर-कनेक्शन की स्थापना के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- बिम्सटेक के सदस्य देशों में भारत, बांग्लादेश, म्याँमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और थाईलैंड शामिल हैं।

लघु वित्त बैंक

चर्चा में क्यों ?

- इनवेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट एजेंसी (Investment Information and Credit Agency- ICRA) ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अगर वित्तीय वर्ष 2023 तक 4000-6000 करोड़ की बाह्य पूंजी उपलब्ध हो तो लघु वित्त बैंकों (Small Financial Banks- SFBs) में 20-30% वार्षिक दर से वृद्धि की संभावना है।

प्रमुख बिंदु

- लघु वित्त बैंकों ने विविधीकरण के माध्यम से व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के अलावा, प्रबंधन, जमा और अपने इक्विटी पर बेहतर रिटर्न के तहत परिसंपत्तियों में वृद्धि दर्ज़ की है।
- दिसंबर 2018 तक इन बैंकों ने प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में 33% की वार्षिक वृद्धि (लगभग 64,325 करोड़ रुपए) की है।
- ये बैंक अपने उत्पादों में विविधता लाने में भी सक्षम हुए हैं, जिसके कारण परिसंपत्ति वर्ग में माइक्रोफाइनेंस की हिस्सेदारी, जो मार्च 2017 में 60% थी, दिसंबर 2018 में 44% तक गिर गई।
- मार्च 2018 के 9% से दिसंबर 2018 तक 5.8% घटकर सकल एनपीए के साथ इन बैंकों के परिसंपत्ति गुणवत्ता संकेतकों (Asset Quality Indicators) में सुधार हुआ है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि शाखाओं की स्थापना, सिस्टम अपग्रेड और नियुक्तियों ने इन बैंकों के लिये परिचालन व्यय अनुपात (Operating Expense Ratio) को उच्च रखा है। लेकिन अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान सुधार के कुछ संकेत दिखाई दिये।
- ज्ञातव्य है कि ICRA 1991 में अग्रणी वित्तीय/निवेश संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्थापित भारतीय स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।

क्या होती हैं SFBs?

- इन बैंकों की स्थापना छोटी व्यावसायिक इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं जैसे अर्थव्यवस्था के कुछ अदम्य क्षेत्रों को वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करने के लिये की गई है।

नोट :

- वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोर समिति द्वारा इनकी स्थापना की सिफ़ारिश की गई थी।
- यह वाणिज्यिक बैंकों (Commercial Banks) का एक छोटा और सीमित संस्करण है जो कि जमा ले सकते हैं और ऋण दे सकते हैं।
- एस.एफ.बी. की स्थापना के लिये न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिये।
- यह अन्य उत्पाद जैसे कि बीमा, म्युचुअल फंड आदि बेच सकते हैं और एक पूर्ण वाणिज्यिक बैंक का आकार ले सकते हैं।

विदेशी विनिमय व्यवस्था के तहत बैंकिंग प्रणाली में 5 अरब डॉलर डालेगा रिज़र्व बैंक

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तीन साल की अवधि तक विदेशी विनिमय व्यवस्था (Foreign Exchange Swap) के तहत पाँच अरब डॉलर की नकदी डालने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह स्वैप या अदला-बदली व्यवस्था रिज़र्व बैंक की ओर से विदेशी मुद्रा विनिमय की खरीद-बिक्री के रूप में होगी।
- तरलता प्रबंधन (Liquidity Management) के लिये यह तरीका पहली बार उपयोग किया जा रहा है।
- इसके तहत बैंक की ओर से रिजर्व बैंक को डॉलर बेचे जाएंगे और साथ ही वह स्वैप की अवधि समाप्त होने के बाद इतनी ही राशि के डॉलर की खरीद की सहमति देगा।
- नकदी के सतत् प्रवाह के मद्देनज़र दीर्घावधि विदेशी विनिमय व्यवस्था के तहत यह राशि बैंकिंग प्रणाली में डाली जाएगी।
- नकदी के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये रिज़र्व बैंक इसी वित्त वर्ष में यह राशि डालेगा।
- विदेशी करेंसी की अदला-बदली के माध्यम से यह प्रक्रिया 26 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च 2022 तक चलेगी।
- इसके माध्यम से जुटाए गए डॉलर स्वैप की अवधि तक रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में प्रदर्शित होंगे और रिज़र्व बैंक की आगामी देनदारियों में भी परिलक्षित होंगे।
- माना जा रहा है की इस कदम से मुक्त बाजार संचालन (Open Market Operations) पर निर्भरता कम होगी, जिसका कुल ऋण की राशि में एक बड़ा हिस्सा है। मुक्त बाजार संचालन अधिक होने से दरों पर प्रभाव पड़ता है।
- इसके लिये बाज़ार सहभागियों (Market Participants) को उस प्रीमियम के साथ बोली लगानी होगी, जो वे रिज़र्व बैंक को स्वैप की अवधि के दौरान देने के लिये तैयार हैं।
- रिज़र्व बैंक के अनुसार, नीलामी कटऑफ प्रीमियम के आधार पर बहु-मूल्य (Multiple Price) आधारित होगी।
- इस कदम से रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो 1 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान 401.7 बिलियन डॉलर था।

विदेशी विनिमय से होने वाले प्रमुख लाभ

करेंसी स्वैप के माध्यम से विदेशी मुद्रा भंडार को मज़बूती मिलती है और रिज़र्व बैंक द्वारा त्वरित तथा सही समय पर सहायता देना संभव हो जाता है।

विदेशी मुद्रा कोष को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने से आयात, ऋण किस्त का भुगतान करने में आसानी रहती है और घरेलू मुद्रा को मज़बूती मिलने के साथ विनिमय दर में अस्थिरता से भी बचाव होता है।

इस तरह की सुविधा से रुपए की विनिमय दर तथा पूंजी बाजारों में भी स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है।

फॉल आर्मीवर्म

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फॉल आर्मीवर्म (Fall Armworm) की समस्या से निपटने के लिये बैंकाक में एक बैठक आयोजित करने जा रहा है। फॉल आर्मीवर्म से पीड़ित देशों के प्रतिनिधि इस बैठक मंद भाग लेंगे और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- फॉल आर्मीवर्म या स्पोडोप्टेरा फ्रूजाईपेर्डा (Spodoptera Frugiperda), अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक कीट है। यह कीट एशियाई देशों में फसलों को काफी नुकसान पहुँचा रहा है।
- अमेरिकी मूल का यह कीट दुनिया के अन्य हिस्सों में भी धीरे-धीरे फैलने लगा है।
- फॉल आर्मीवर्म पहली बार 2016 की शुरुआत में मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया गया था और कुछ ही दिनों में लगभग पूरे उप-सहारा अफ्रीका में तेज़ी से फैल गया।
- दक्षिण अफ्रीका के बाद यह कीट भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्याँमार, थाईलैंड और चीन के यूनान क्षेत्र तक भी पहुँच चुका है।

फॉल आर्मीवर्म या स्पोडोप्टेरा फ्रूजाईपेर्डा

- इस कीड़े की पहली पसंद मक्का है लेकिन यह चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सब्जियाँ और कॉटन समेत 80 से अधिक पौधों की प्रजातियों को खा सकता है।
- वर्ष 2017 में दक्षिण अफ्रीका में इस कीट के फैलने के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ था। यह कीट सबसे पहले पौधे की पत्तियों पर हमला करता है, इसके हमले के बाद पत्तियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे उन्हें कैंची से काटा गया हो। यह कीट एक बार में 900-1000 अंडे दे सकता है।
- भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मई 2018 में इस विनाशकारी कीट की मौजूदगी कर्नाटक में दर्ज की गई थी और तब से अब तक यह पश्चिम बंगाल तथा गुजरात तक पहुँच चुका है। उचित जलवायु परिस्थितियों के कारण यह न केवल पूरे भारत में बल्कि एशिया के अन्य पड़ोसी देशों में भी फैल सकता है। कर्नाटक राज्य भारत में सबसे बड़े मक्का उत्पादकों में से एक है और मक्का देश में व्यापक रूप से उत्पादन किया जाने वाला तीसरा अनाज है।

फॉल आर्मीवर्म पर नियंत्रण

- इस कीट को नियंत्रित करने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में जीएम फसलों और कीटनाशकों का उपयोग शामिल है, हालाँकि, कुछ आर्मीवर्म ने इन रणनीतियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है और वे फसलों को नष्ट कर रहे हैं।
- आर्मीवर्म को नियंत्रित करने के लिये वैज्ञानिक प्राकृतिक तरीकों की तलाश में लगे हुए हैं। इन प्राकृतिक तरीकों में हड्डों (Wasps) का पालन तथा जीवाणु-युद्ध (Germ Warfare) भी शामिल हैं।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO)

- संयुक्त राष्ट्र संघ तंत्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी।
- खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है।

वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट- 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सतत् विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solution Network- SDSN) ने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट-2019 ज़ारी की है।

प्रमुख बिंदु

- SDSN ने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट-2019 में 156 देशों को शामिल किया है।
- सबसे खुशहाल देशों में फ़िनलैंड लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: डेनमार्क एवं नॉर्वे हैं।
- इस वर्ष भारत का स्थान 140वाँ है जो पिछले वर्ष से 7 स्थान नीचे है।
- पड़ोसी देशों में चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्याँमार को क्रमश: 93, 67, 154, 100, 95, 125, 130 और 131वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

नोट :

रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष सतत् विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solution Network- SDSN) द्वारा प्रकाशित की जाती है।
- वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2012 से शुरू हुआ था। इस वर्ष इसका सातवाँ संस्करण प्रकाशित किया गया है।
- खुशहाली को आँकने के लिये सूचकांक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भ्रष्टाचार और उदारता की अवधारणा को आधार बनाया जाता है।

SDSN

- संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वाधान में संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solution Network- SDSN) 2012 से काम कर रहा है।
- SDSN सतत् विकास हेतु व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाता है, जिसमें सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और पेरिस जलवायु समझौते का कार्यान्वयन भी शामिल है।
- SDSN संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करता है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष का विनिवेश लक्ष्य हासिल किया

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष का विनिवेश लक्ष्य पार कर लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि चालू वित्त वर्ष (2018-19) में अब तक विनिवेश से 85,000 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं जो निर्धारित लक्ष्य से 5,000 करोड़ रुपए अधिक हैं।

प्रमुख बिंदु

- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) में सरकार की 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी को 14,500 करोड़ रुपए में खरीदा है।
- सरकार को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (CPSE-ETF) की पाँचवी किस्त से करीब 9,500 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर एक दिन में सरकार को इससे 24,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
- विनिवेश का सबसे बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा शुरू की गई ETF के कई चरणों से आया जिसके परिणामस्वरूप अकेले इस मोड के माध्यम से कुल 45,730 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ।
- वर्षों से निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति विभाग ने अपने दो प्रमुख उपक्रमों ETF-CPSE ETF और भारत 22-ETF पर निर्भर रहा है। इस वित्त वर्ष के दौरान दो बार भारत-22 की पेशकश की गई जिससे सरकार को 18,729.85 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
- ETF के सब्सक्राइबर को ऐसी इकाइयाँ दी जाती हैं जो ट्रेडिंग के लिये स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती हैं।
- 14,500 करोड़ रुपए का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से आया जो REC में सरकार के 52.63 प्रतिशत स्टाक के कारण हासिल हुआ।
- समझा जाता है कि PFC ने आंतरिक संसाधनों और बाज़ार उधार के माध्यम से इस सौदे को वित्तपोषित किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिये इसी रणनीति का उपयोग किया था क्योंकि ओएनजीसी ने एचपीसीएल में सरकार की पूरी हिस्सेदारी लगभग 37,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी।
- PFC-REC सौदे के अलावा कुछ छोटे स्तर के अधिग्रहण भी हुए। इनमें NBCC द्वारा HSCC लिमिटेड की खरीद तथा WAPCOS द्वारा NPCC लिमिटेड का अधिग्रहण शामिल है।
- इस साल आए कुछ अन्य IPO में इरकॉन, राइट्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और मिश्र धातु निगम लिमिटेड शामिल हैं। कोल इंडिया में 3 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री की पेशकश की गई जिसका मूल्य 5,218 करोड़ रुपए था।

नोट :

नवीन लेखा प्रणाली मानक (IndAS)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रिज़र्व बैंक ने नवीन लेखा प्रणाली मानक (IndAs) के क्रियान्वयन को दूसरी बार स्थगित किया है। इसका अनुपालन 1 अप्रैल, 2019 से प्रस्तावित था।

मुख्य बिंदु

- इसे बैंकों द्वारा प्रयोग किये जाने के लिये बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संसोधन की आवश्यकता होगी। यह संसोधन अभी तक न हो पाने के कारण IndAS के अनुपालन को स्थगित करना पड़ा। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक द्वारा दिशा-निर्देशों का जारी न किया जाना भी इसके स्थगन का कारण है।
- यह ऋण-हानि प्रावधान (Loan-Loss Provision) के कारण बैंकों के अनुपालन भार में वृद्धि कर सकता है। जो संभावित साख हानि मॉडल (Credit Loss Model) पर आधारित है।
- IndAS के अनुपालन के लिये बैंकों को अपने सॉफ्टवेयर प्रणाली को परिवर्तित कर इसके अनुरूप करना होगा।
- रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ व वित्तीय संस्थान वर्तमान वित्तीय वर्ष से IndAS का अनुपालन कर रहे हैं, जबकि भारतीय कंपनियाँ वर्ष 2016 से इस लेखा प्रणाली का प्रयोग कर रही हैं।
- यह बैंकों के वित्तीय बोझ में वृद्धि करेगा।

IndAS क्या है ?

- IndAS एक लेखा प्रणाली है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक के अनुरूप है।
- वर्ष 2016 में रिज़र्व बैंक ने इसके अनुपालन हेतु बैंकों के लिये मार्गदर्शन नोट जारी किया था।

गिल्ट फंड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गिल्ट फंड्स ने अन्य सभी डेब्ट फंड श्रेणियों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 8.3 प्रतिशत का वार्षिक रिटर्न दिया है। टॉप गिल्ट फंडों ने रिटर्न में 11 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रदर्शित की है।

- इसी अवधि के दौरान अन्य डेब्ट फंड्स, जो कॉर्पोरेट बॉण्ड में निवेश करते हैं, ने 4.9 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया।
- हालाँकि वर्ष 2017 तथा वर्ष 2018 की पहली छमाही में गिल्ट फंड्स का प्रदर्शन कुछ ख़ास नही रहा।

गिल्ट फंड्स क्या हैं ?

- गिल्ट फंड वे म्यूचुअल फंड योजनाएँ होती हैं जो मुख्य रूप से सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) में निवेश करती हैं।
- इन सरकारी प्रतिभूतियों में केंद्र सरकार की दिनाँकित प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ और ट्रेजरी/राजस्व बिल शामिल होते हैं।
- गिल्ट फंड्स में निवेश करने के बाद निवेशकों को किसी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इन प्रतिभूतियों की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। ये फंड्स दीर्घावधिक सरकारी प्रतिभूति पत्रों में निवेश करते हैं।

गिल्ट म्यूचुअल फंड के प्रकार

सामन्यत: गिल्ट म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं-

- लघु अवधि के म्यूचुअल फंड
- दीर्घ अवधि के म्यूचुअल फंड

नोट :

लघु अवधि के म्यूचुअल फंड

- लघु अवधि की योजनाओं के तहत अल्पकालिक सरकारी बॉण्ड में निवेश किया जाता है, जो बहुत कम अवधि की होती हैं।
- सामान्यत: ये म्यूचुअल फंड अगले 15-18 महीनों में परिपक्व हो जाते हैं।
- चूँकि ये फंड राज्य या केंद्र सरकार द्वारा समर्थित हैं, इसलिये इनमे कोई क्रेडिट जोखिम नहीं होता और इनकी कम अवधि में परिपक्वता के कारण ब्याज दरों में बदलाव का कम जोखिम होता है।

दीर्घ अवधि के म्यूचुअल फंड

- दीर्घ अवधि के गिल्ट फंड्स, दीर्घकालिक सरकारी बॉण्ड में निवेश करते हैं
- इनकी परिपक्वता अवधि 5 साल से 30 साल तक होती है।
- गिल्ट फंडों में सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक ब्याज दर में बदलाव की संभावना होती है।
- कुछ मामलों में दीर्घकालीन गिल्ट फंड अल्पकालिक गिल्ट फंड्स की तुलना में ब्याज दरों में बदलाव के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया देते हैं।

फिनटेक कॉनक्लेव 2019

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग 25 मार्च, 2019 को एकदिवसीय फिनटेक कॉनक्लेव का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (Dr. Ambedkar International Center) में किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य फिनटेक क्षेत्र में भारत की बढ़ती ऊँचाइयों को आकार देना, भविष्य की रणनीति एवं नीतिगत प्रयासों हेतु योजना बनाना तथा व्यापक वित्तीय समावेश के लिये उचित कदमों पर विचार करना है।
- इस कॉनक्लेव में एचडीएफसी बैंक, इंडसइन्ड, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई कार्ड, टाटा कैपिटल सहित प्रमुख वित्तीय संस्थान एवं बैंक बाज़ार, फोन पे, कैपिटल फ्लोट, ज़ेरोधा, पेटीएम, मोबिक्विक, पे यू सहित फिनटेक एवं अग्रणी वैंचर कैपिटल निवेशक, राज्य सरकारें, एमएसएमई इत्यादि शामिल होंगे।
- डिजिटल इंडिया एवं वित्तीय समावेशन के लिये स्वैच्छिक आधार तथा विकास पर केंद्रित भारत सरकार के प्रयासों की वज़ह से ही वित्तीय प्रौद्योगिकी (Financial Technology-FinTech) के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच दिलचस्पी पैदा हुई है।

पृष्ठभूमि

- भारत वैश्विक रूप से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले फिनटेक बाज़ारों में से एक है और इस उद्योग के अनुसंधानों से अनुमान लगाया गया है कि 2029 तक भारत का फिनटेक बाज़ार एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है।
- भारतीय फिनटेक प्रणाली विश्व में तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है जिसमें 2014 के बाद लगभग छह बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है।
- भारतीय फिनटेक उद्योग उन्नत जोखिम प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अत्याधुनिक बौद्धिक संपदा का निर्माण कर रहा है जो भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाने के साथ-साथ भारत में पेपरलेस अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा।

फिनटेक क्या है ?

- फिनटेक (FinTech) Financial Technology का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है।
- दूसरे शब्दों में यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का कार्यान्वयन है।
- पहले के समय में बैंक से पैसा निकालने के लिये रजिस्टर मेन्टेन करना होता था जिसमें काफी समय भी लगता था। लेकिन अब बैंकिंग सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने से कोर बैंकिंग सिस्टम प्रचलन में आ गया है और पैसे का लेन-देन आसान हो गया है, इसे भी हम फिनटेक कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर UPI या भीम एप जो कि वित्तीय तकनीक का एक हिस्सा हैं, पैसा भेजने की समस्या को तुरंत हल कर देते हैं।

नोट :

- अगर एक के बाद एक, बैंक अपनी मोबाइल वॉलेट सर्विस लॉन्च कर रहे हैं तो यह इन्हीं फिनटेक कंपनियों की वजह से है। यही कारण है कि अब बैंक इन फिनटेक कंपनियों को अपने साथ ला रहे हैं।
- ये फिनटेक स्टार्ट-अप बैंकों के लिये पेमेंट, कैश ट्रांसफर जैसी सर्विसेज़ में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। साथ ही ये देश के दूरदराज़ के इलाकों तक बैंकिंग सर्विसेज़ उपलब्ध करा रहे हैं।
- फिनटेक प्रदाता अब बचत, उधार, बीमा और अन्य वित्तीय उत्पादों तथा सलाहकारी सेवाओं की पेशकश शुरू कर रहे हैं।
- देश में आज पेटीएम, मोबीक्विकऔर फ्रीचार्ज जैसी कंपनियाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और बैंकों के साथ समन्वय से छोटी कंपनियों को भी अपने नए आइडिया पर काम करने का मौका मिल रहा है।
- केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वक्त देश में फिनटेक सेक्टर का कारोबार 33 अरब डॉलर का है जो 2020 तक 73 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है।
- सरकार की कोशिश भी देश की इकोनॉमी को कैशलेस बनाने की है, ऐसे में फिनटेक कंपनियों की भूमिका आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी।

व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (TReDS)

संदर्भ

व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (Trade Receivable Discounting System-TReDS) MSME को कॉर्पोरेट से मिलने वाले प्राप्यों के भुगतान के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा शुरू की गई एक पहल है।

- इसका गठन RBI द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and Settlement Systems Act 2007) के तहत स्थापित नियामक ढाँचे के तहत किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- TReDS प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य MSMEs की महत्त्वपूर्ण ज़रूरतों जैसे-तत्काल प्राप्यों का नकदीकरण और ऋण जोखिम को समाप्त करने वाले दोहरे मुद्दों का समाधान करना है।
- TReDS प्लेटफॉर्म, एक नीलामी तंत्र द्वारा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित बड़े कॉर्पोरेटों के समक्ष MSMEs के विक्रेताओं के बीजक/विनिमय बिलों के बट्टाकरण (Discounting) में सहायता प्रदान करता है। इससे प्रतिस्पर्द्धात्मक बाज़ार दरों पर व्यापार प्राप्यों की त्वरित वसूली सुनिश्चित होती है।
- TReDS भारत में विक्रेताओं के लिये फैक्टरिंग विदाउट रीकोर्स (Factoring Without Recourse) शुरू करने का एक प्रयास है, इससे MSMEs को प्राप्यों की त्वरित वसूली के साथ-साथ योग्य मूल्य का पता लगाने में सहायता होगी।

TReDS प्लेटफॉर्म में हिस्सा लेने हेतु पात्र निकाय :

- TReDS, MSMEs के बीजक/बिलों को अपलोड, स्वीकार, बट्टाकरण, व्यापार और निपटान करने हेतु विभिन्न प्रतिभागियों को एक जगह पर लाने हेतु एम मंच/प्लेटफॉर्मर प्रदान करता है।

* (MSMED अधिनियम, 2006 के अनुरूप पारिभाषित MSMEs आपूर्तिकर्त्ता)

TReDS संव्यवहार कौन शुरू कर सकता है:

- MSMEs विक्रेताओं के व्यापार प्राप्यों के वित्तपोषण के लिये विक्रेता और खरीदार दोनों TReDS लेन-देन शुरू कर सकते हैं।
- जब MSMEs विक्रेता बीजक (Invoice) अपलोड करता है और ब्याज़ लागत का वहन करता है, तो इसे 'फैक्टरिंग' कहा जाता है अर्थात् (एकल विक्रेता-एकाधिक खरीदार)। 'रिवर्स फैक्टरिंग' (एकल खरीदार-एकाधिक विक्रेता) के मामले में खरीदार द्वारा लेन-देन शुरू किया जाता है और ब्याज़ लागत को भी खरीदार द्वारा वहन किया जाता है।

TReDS के मुख्य लाभ

सभी सहभागियों के लिये

- स्वचालित पारदर्शी प्लेटफॉर्म

नोट :

- पेपरलेस और परेशानीमुक्त
- लागत में कमी

विक्रेता को लाभ

- प्रतिस्पर्द्धी मूल्य की खोज
- विक्रेता पर किसी प्रकार के दायित्व का न होना (Without Recourse)।
- MSMEs को सबसे बेहतर बोली चुनने का अधिकार।
- भुगतान हेतु खरीदार के साथ किसी तरह की अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जाती।
- एकल वित्तपोषक पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती।
- उत्पादकता में वृद्धि और दक्षतापूर्ण चलनिधि प्रबंधन।
- वित्तपोषण के विकल्पों में वृद्धि।

ख़रीदारों को लाभ

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास, अधिनियम 2006 (MSMED अधिनियम, 2006) के प्रावधानों का अनुपालन।
- MSME, विक्रेताओं के साथ बेहतर शर्तों के लिये मोल-तोल कर सकते हैं।
- खरीदारों के लिये निविष्टि (इनपुट) की कम लागत।
- कम प्रशासनिक लागत।
- प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य की खोज।
- कुशल नकदी प्रवाह प्रबंधन।
- यह सुनिश्चित करना कि उनके विक्रेताओं को नकदी/कार्यशील पूंजी की कमी नहीं है।

इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैश्विक फिनटेक निरीक्षण मंच, मेडिसी (Medici) और ज़ोन स्टार्टअप्स (Zone Startups) द्वारा जारी की गई 'इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2019' के अनुसार, देश में 338 ऑनलाइन ऋण प्रदाता स्टार्टअप है। जो घरेलु उपभोक्ताओं के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को भी लक्षित कर रहे है।

मुख्य बिंदु

- 'इंडिया फिनटेक रिपोर्ट' (India Fintech Report) के अनुसार, डिजिटल ऋण प्रदाता कंपनियों (फिनटेक कंपनियों) का वर्तमान योगदान 23% है जिसके वर्ष 2023 तक 48% होने का अनुमान है।
- पारंपरिक ऋण प्रदाता (बैंक व अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) कुल आवेदित ऋणों का 25% से 40% तक ही ऋण उपलब्ध करवा पाते हैं, वहीं फिनटेक कंपनियाँ ऋण मूल्यांकन के लिये अधिक डाटा जैसे लेन-देन व्यवहारों, एप आधारित डेटा, अवस्थिति सूचना, सामाजिक डेटा आदि तक पहुँच के कारण इस सीमा का 10% से 15% तक विस्तार करने के उद्देश्य के साथ बाज़ार के लिये बड़ा अवसर उपलब्ध करवा सकती हैं।
- फिनटेक ऋण सेवाएँ शहरी उपभोक्ताओं को प्रमाणपत्रों के सत्यापन की दीर्घ प्रक्रिया से मुक्त करने के साथ ही ग्रामीण ऋण आवेदकों को भी वैकल्पिक ऋण तंत्र तक पहुँच प्रदान करेगी जो उन्हें साहूकारों के जाल में फँसने से बचाएगा।
- फिनटेक ऋण सेवा उन 300 मिलियन घरेलू उपभोक्ताओं तक ऋण बाज़ार की पहुँच उपलब्ध करवाएगी जिनकी बैंक तक पहुँच नहीं है। इसलिये विभिन्न उपयोगों के लिये मूल्यांकन हेतु पहचान प्रमाणीकरण, क्रेडिट स्कोर, नौकरी पात्रता व अन्य सामाजिक डेटा का संग्रह निकट भविष्य में अधिक ध्यान आकर्षित करेगा।
- फिनटेक ऋण सेवाओं की उच्च ब्याज दर और गैर-निष्पादित संपत्तियों के आँकड़ों का अभाव इस ऑनलाइन ऋण तंत्र की प्रमुख चुनौती है।

नोट :

अन्य संबंधित बिंदु

- पूर्व में रिज़र्व बैंक ऑनलाइन पीयर-टू-पीयर ऋण प्लेटफॉर्म को एन.बी.एफ.सी. की मान्यता प्रदान कर चुका है। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मध्यवर्ती संस्था के रूप में ऋण सुविधा सेवाओं को उपलब्ध करवाता है जिसमें ऋण प्रदाता व प्राप्तकर्त्ता दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं।

ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई-मार्केटप्लेस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कॉफी बोर्ड ने नई दिल्ली में ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई-मार्केटप्लेस का आरंभ किया है। गौरतलब है कि ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई-मार्केटप्लेस, कॉफी की खेती करने वाले किसानों के लिये सहायक सिद्ध हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

- किसान इस प्रायोगिक परियोजना से बाज़ारों के साथ पारदर्शी ढंग से जुड़ सकेंगे जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उचित मूल्य की प्राप्ति होगी।
- ब्लॉकचेन की सहायता से कॉफी उत्पादकों और खरीदारों के बीच की दूरी कम होगी और किसानों को अपनी आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
- भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कॉफी छाया में उगाई जाती है, उसे हाथ से तोड़ा जाता है और धूप में सुखाया जाता है। यहाँ उगाई जाने वाली कॉफी दुनिया की बेहतरीन कॉफी में शुमार है।
- विश्व बाज़ार में भारतीय कॉफी की बहुत ज़्यादा मांग है और यह प्रीमियम कॉफी के रूप में बेची जाती है इसके बावजूद कॉफी उगाने वाले किसानों की आमदनी बहुत कम है।

उद्देश्य

- ब्लॉकचेन आधारित मार्किटप्लेस एप का उद्देश्य भारतीय कॉफी के व्यापार में पारदर्शिता लाना है।
- इस पहल से भारतीय कॉफी की ब्रांड इमेज़ तैयार करने में मदद मिलेगी और खरीदारों तक सीधी पहुँच कायम होने से कॉफी उत्पादकों की बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।

भारतीय कॉफी बोर्ड

- भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा VII के द्वारा 'कॉफी बोर्ड' का गठन किया।
- अध्यक्ष इस बोर्ड का मुख्य कार्यपालक होता है तथा इसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष के अलावा शेष 32 सदस्य कॉफी उत्पादन से संबंधित उद्योग, कॉफी व्यापार हितैषी, श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं के हितैषी, कॉफी उगाने वाले प्रमुख राज्यों के सरकार के प्रतिनिधि तथा सांसद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं।

बोर्ड के प्रमुख कार्य

- उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता का प्रोन्नयन।
- भारतीय कॉफी के लिये उचित लाभ प्राप्त करने हेतु निर्यात संवर्द्धन।
- स्वदेशी बाज़ार के विकास का समर्थन।

भारतीय कॉफी

- भारत में 3.66 लाख कॉफी किसानों द्वारा 4.54 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर कॉफी की खेती की जाती है।
- इसकी खेती मुख्यत: कर्नाटक (54 प्रतिशत), केरल (19 प्रतिशत) और तमिलनाडु (8 प्रतिशत) में होती है।
- कॉफी की खेती आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी होती है।

नोट :

- देश में उत्पादित कॉफी के 65% से 70% भाग का निर्यात किया जाता है, जबकि शेष कॉफी का उपभोग देश में ही किया जाता है।
- भारत में उगाई जाने वाली कॉफी मुख्यत: दो प्रकार की है- अरेबिका एवं रोबस्टा।

अरेबिका तथा रोबस्टा कॉफी में प्रमुख अंतर

- अरेबिका मृदु कॉफी है, इसकी फलियाँ अधिक खुशबूदार होने के कारण रोबस्टा फलियों की तुलना में इसका बाज़ार मूल्य अधिक होता है।
- रोबस्टा की तुलना में अरेबिका को उच्च उन्नतांशों में उगाया जाता है। अरेबिका के लिये 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडा और सम तापमान उपयुक्त होता है, जबकि रोबस्टा के लिये 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म और उन्नत तापमान उपयुक्त होता है।
- अरेबिका को अधिक देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है तथा यह बड़े जोतों के लिये उपयुक्त है, जबकि रोबस्टा सभी प्रकार के खेतों के लिये उपयुक्त है।
- अरेबिका का संग्रहण नवंबर से जनवरी के बीच होता है, जबकि रोबस्टा के लिये यह अवधि दिसंबर से फरवरी तक होती है।
- अरेबिका सफेद तना छेदक, पत्ती किट्ट आदि जैसे कीटाणुओं एवं रोगों के प्रति संवेदी है और इसे रोबस्टा की तुलना में अधिक छाया की आवश्यकता होती है।

क्या है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी ?

- ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो एक सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन-देन का एक विकेंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करती है।
- लेन-देन के इस साझा रिकॉर्ड को नेटवर्क पर स्थित कोई भी व्यक्ति देख सकता है।
- वास्तव में ब्लॉकचेन डेटा ब्लॉकों की एक श्रृंखला होती है तथा प्रत्येक ब्लॉक में लेन-देन का एक समूह समाविष्ट होता है।
- ये ब्लॉक एक-दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जुड़े होते हैं तथा इन्हें कूट-लेखन के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम एवं सबसे बड़ा उदाहरण बिटकॉइन नेटवर्क है।
- यह तकनीक सुरक्षित है। इसे हैक करना मुश्किल होता है।
- साइबर अपराध और हैकिंग को रोकने के लिये यह तकनीक सुरक्षित मानी जाती है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अरुण-3 जल विद्युत परियोजना

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने अरुण-3 जल विद्युत परियोजना (नेपाल भाग) के ट्रांसमिशन घटक के लिये जून 2017 के मूल्य स्तर पर 1236.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निवेश को अपनी स्वीकृति दे दी है।

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति की बैठक के दौरान फरवरी 2017 में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति की बैठक में अरुण-3 जलविद्युत परियोजना (900 मेगावॉट) के उत्पादन घटक के लिये मई, 2015 के मूल्य स्तर पर 5723.72 करोड़ रुपए लागत की परियोजना के लिये निवेश प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई थी।
- वर्तमान स्वीकृति 400 किलोवाट D/C डिडिंग (नेपाल में)- बथनाहा (अंतर्राष्ट्रीय सीमा) वाया धलकेबर (नेपाल में) ट्रांसमिशन लाइन के लिये है। यह ट्रांसमिशन लाइन 217 किलोवाट की है और नेपाल में अरुण-3 जल विद्युत परियोजना (Hydro Electric Project-HEP) से विद्युत् निकालने के लिये है। यह नेपाल के भू-भाग के अंदर है।

लाभ

- परियोजना के ट्रांसमिशन घटक के निर्माण से लगभग 400 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
- यह परियोजना नेपाल के साथ आर्थिक संपर्क को मज़बूत बनाने के लिये भारत को अधिशेष विद्युत प्रदान करेगी।
- इस परियोजना से विद्युत् नेपाल के धलकेबर से भारत के मुज़फ्फरपुर में भेजी जाएगी।

पृष्ठभूमि

- अरुण-3 जल विद्युत परियोजना (Hydro Electric Project-HEP) पूर्वी नेपाल के सनखुवासभा ज़िले में अरुण नदी पर है।
- इस परियोजना के अंतर्गत 70 मीटर ऊँचा गुरुत्व बांध (concrete gravity dam) और भूमिगत पावर हाउस के साथ 11.74 किलोमीटर की हेड रेस सुरंग (Head Race Tunnel-HRT) नदी के बाएँ किनारे पर बनाई जाएगी तथा 4 इकाइयों में से प्रत्येक इकाइ 225 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेंगी।
- SJVN लिमिटेड ने यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय स्पर्द्धी बोली के माध्यम से प्राप्त की है। नेपाल सरकार और SJVN लिमिटेड ने परियोजना के लिये मार्च 2008 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।
- यह समझौता ज्ञापन 30 वर्ष की अवधि के लिये बिल्ड ओन ऑपरेट तथा ट्रांसफर (Build Own Operate and Transfer-BOOT) के आधार पर किया गया था। 30 वर्ष की अवधि में 5 वर्ष की निर्माण अवधि भी शामिल है।
- परियोजना विकास समझौते (Project Development Agreement) पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किये गए। इस समझौते में 25 वर्षों की संपूर्ण रियायत अवधि के लिये नेपाल को नि:शुल्क 21.9 प्रतिशत विद्युत प्रदान करने का प्रावधान है।

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक- 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक- 2019 जारी किया गया। इसमें दुनिया के 115 देशों की ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन स्तर पर सर्वेक्षण किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में इस साल भारत को 76वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले साल यह 78वें स्थान पर था।

नोट :

- दक्षिण एशियाई देशों में श्रीलंका ही एक ऐसा देश है जो भारत से आगे है इसे 60वाँ स्थान मिला है।
- अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग इस प्रकार है :

देश	वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक- 2019
चीन	82
बांग्लादेश	90
नेपाल	93
पाकिस्तान	97

- स्वीडन अपनी पिछले साल की रैंकिंग को बरकरार रखते हुए इस साल भी प्रथम स्थान पर है, जबकि हैती को सबसे आख़िरी पायदान प्राप्त हुआ है।
- ब्रिक्स देशों में भी भारत को दूसरे सबसे बेहतर देश का स्थान प्राप्त हुआ है जबकि ब्राज़ील 46वें रैंक के साथ पहले स्थान पर है।
- उभरते और विकासशील देशों की श्रेणी में मलेशिया 31वीं रैंक हासिल कर पहले पायदान पर है।

ऊर्जा सूचकांक

- इसे विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) द्वारा जारी किया जाता है।
- इसके अंतर्गत दुनिया के देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और सतत पर्यावरण को बनाए रखने का उल्लेख किया जाता है।
- इसमें विभिन्न देशों के प्रदूषण स्तर का आकलन भी होता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पाँच सालों से ऊर्जा संरक्षण मामले में कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ है।
- ऊर्जा संक्रमण के लिये तैयारी के घटक में शामिल 6 संकेतक निम्नलिखित हैं :
  1. पूंजी और निवेश
  2. विनियमन और राजनीतिक प्रतिबद्धता
  3. संस्थान और शासन
  4. संस्थान और अभिनव व्यावसायिक वातावरण
  5. मानव पूंजी और उपभोक्ता भागीदारी
  6. ऊर्जा प्रणाली संरचना

भारत के संदर्भ में

- भारत को उच्च प्रदूषण स्तर वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि CO_2 के उत्सर्जन में दूसरे देशों के सापेक्ष भारत अग्रणी है।
- भारत कोयला के उपभोग में भी वृद्धि कर रहा है।
- भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के लिये नीतियाँ बनाने में शीर्ष तीन देशों में शामिल किया गया है।
- विद्युतीकरण की दिशा में सबसे तीव्र दर से विकास करने वाले देशों में भी भारत शामिल है।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum)

- विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिये एक मंच के रूप में काम करना है।
- यह स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
- इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम. श्वाब ने की थी।
- इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर प्रदान की जानी है और ये स्तर संस्था के काम में उनकी सहभागिता पर निर्भर करते हैं।
- इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है।

नोट :

वेनेज़ुएला की मदद करेगा रेड क्रॉस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रेड क्रॉस ने संकट से जूझ रहे वेनेज़ुएला में राहत सामग्री वितरित करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि वेनेज़ुएला में राजनीतिक दखलंदाज़ी के खतरे के बावजूद रेड क्रॉस निष्पक्षता से राहत सामग्री का वितरण करने जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के प्रमुख ने सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि रेड क्रॉस निष्पक्षता और स्वतंत्रता के अपने सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करेगा।
- रेड क्रॉस द्वारा दी जाने वाली सहायता के पहले चरण में 650,000 लोगों को मदद मिलेगी।
- संयुक्त राष्ट्र की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, वेनेज़ुएला की लगभग 24% आबादी (सात मिलियन लोग) को मानवीय सहायता की सख्त आवश्यकता है।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि जीवन स्तर में गिरावट की वज़ह से कुपोषण और जानलेवा बीमारियाँ बढ़ रही हैं।
- वेनुज़ुएला की सरकार ने आर्थिक संकट के लिये अमेरिका और विपक्षी नेता गुइदो को दोषी ठहराया था।

वेनेज़ुएला संकट क्या है ?

- दक्षिण अमेरिकी देश वेनेज़ुएला इस समय अभूतपूर्व राजनीतिक संकट के दौर से गुज़र रहा है और यह वहाँ लंबे समय से जारी आर्थिक संकट की देन है।
- पिछले दिनों वेनेज़ुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे जिसके पश्चात् प्रमुख विपक्षी नेता जुआन गाइदो ने स्वयं को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया।
- वेनेज़ुएला के इस संकट ने विश्व को भी दो हिस्सों में बाँट दिया और धीरे-धीरे यह संकट वैश्विक रूप लेने की ओर अग्रसर हो चला।
- अमेरिका और यूरोपीय देश वेनेज़ुएला के विपक्षी नेता के समर्थन में हैं तो रूस और चीन जैसे देश खुलकर मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पक्ष में हैं।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़

- रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानवीय ज़िन्दगी व स्वास्थ्य का बचाव करना है।
- इसकी स्थापना युद्ध भूमि पर जख्मी और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिये वर्ष 1863 में हेनरी ड्यूनेन्ट ने जिनेवा में की थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसे तीन बार (वर्ष 1917,1944 और 1963) नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है।
- रेड क्रॉस मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है।
- रेड क्रॉस ने मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वयं प्रेरित सेवा, एकता एवं सार्वभौमिकता के सिद्धांतों को आत्मसात किया है।
- भारतीय रेड क्रॉस का सोसायटी अधिनियम 1920 में पारित किया गया है जो शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, रोगों को रोकने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने पर बल देता है।

नोट :

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

युवा विज्ञानी कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization-ISRO) ने इस वर्ष से स्कूली बच्चों हेतु 'युवा विज्ञानी कार्यक्रम' (Young Scientist Programme) नामक एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- इसरो द्वारा शुरू किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष के उभरते क्षेत्र में रुचि जगाने के इरादे से युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मूलभूत ज्ञान प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लगभग दो सप्ताह तक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा।
- इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिये हर साल प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से 3 छात्रों का चयन किया जाना प्रस्तावित है। इसमें ऐसे राज्य शामिल होंगे जो CBSE, ICSE और राज्य के पाठ्यक्रम को कवर करते हैं।
- 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण तथा वर्तमान में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र इस कार्यक्रम के लिये पात्र होंगे। इस कार्यक्रम हेतु चयनित छात्रों को इसरो के अतिथिगृह/हॉस्टल में ठहराया जाएगा।
- पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्र द्वारा की जाने वाली यात्रा हेतु रेलगाड़ी के द्वितीय श्रेणी का किराया, पाठ्य सामग्री, रहने एवं खाने इत्यादि में आने वाले खर्च का वहन भी इसरो द्वारा ही किया जाएगा।
- चयनित छात्र को इसरो के रिपोर्टिंग केंद्र तक लाने एवं ले जाने हेतु एक अभिभावक/माता-पिता को भी रेलगाड़ी में द्वितीय श्रेणी के किराये की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- ध्यातव्य है कि इसरो ने त्रिपुरा में एक इनक्यूबेशन केंद्र विकसित किया है और भविष्य में ऐसे ही चार अन्य केंद्र त्रिची, नागपुर, राउरकेला और इंदौर में विकसित किये जाने की योजना है।

चयन प्रक्रिया

- इसरो ने भारत में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों से संपर्क किया है ताकि वे अपने संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से तीन छात्रों के चयन की व्यवस्था कर सकें और इसरो को सूची के बारे में बता सकें।
- यह चयन शैक्षणिक प्रदर्शन और पाठ्येतर गतिविधियों पर आधारित है, जो स्पष्ट रूप से चयन मानदंड में वर्णित है और जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पहले से ही परिचालित कर दिया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित छात्रों को चयन मानदंडों में विशेष भारांक दिया गया है। मार्च 2019 के अंत तक प्रत्येक राज्य से चयनित उम्मीदवारों की सूची अपेक्षित है।

स्पार्क पहल के तहत IIT-मंडी के प्रस्तावों का चयन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्द्धन योजना' (Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration-SPARC) पहल के तहत IIT-मंडी के 7 अनुसंधान प्रस्तावों का चयन किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ये अनुसंधान परियोजनाएँ निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करती हैं-
  - ऊर्जा और सतत् जल उपलब्धता,
  - उन्नत सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार,
  - संक्रामक रोग और नैदानिक अनुसंधान,
  - मानविकी और सामाजिक विज्ञान,
  - नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग,
  - उन्नत कार्यक्षमता और मेटा मैटेरियल
  - बेसिक साइंसेज़
- परियोजना के भागीदार देशों हेतु नोडल संस्थानों (भारत से ही) को चिह्नित किया गया है।
  - IIT मंडी जर्मनी के लिये नोडल संस्थान होगा।

क्या होंगे लाभ ?

- स्पार्क (SPARC) द्वारा दिया जाने वाला अनुदान अमेरिका, फ्राँस, जर्मनी, ब्रिटेन और ताइवान (रिपब्लिक ऑफ चाइना) जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ IIT-मंडी को जोड़ने में मदद करने के साथ-साथ संयुक्त अनुसंधान करने हेतु दुनिया भर के शोधकर्ताओं की मदद भी करेगा।
- IIT-मंडी इन क्षेत्रों में छात्रों को अल्पावधि पाठ्यक्रम भी प्रदान कर सकेगा।

स्पार्क (SPARC)

- 'स्पार्क' का लक्ष्य भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को बेहतर बनाना है।
- इस योजना के तहत 600 संयुक्त शोध प्रस्ताव दो वर्षों के लिये दिये जाएंगे, ताकि कक्षा संकाय में सर्वोत्तम माने जाने वाले भारतीय अनुसंधान समूहों और विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रख्यात अनुसंधान समूहों के बीच उन क्षेत्रों में शोध संबंधी सुदृढ़ सहयोग संभव हो सके।
- देश के लिये उभरती इसकी प्रासंगिकता और अहमियत के आधार पर 'स्पार्क' के तहत सहयोग हेतु पाँच महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (मौलिक शोध, प्रभाव से जुड़े उभरते क्षेत्र, सामंजस्य, अमल-उन्मुख अनुसंधान और नवाचार प्रेरित) के साथ-साथ प्रत्येक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत उप-विषय से संबंधित क्षेत्रों की भी पहचान की गई है।
- समाज की प्रगति के लिये सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अनिवार्य है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किये गए अनुसंधान का इस्तेमाल उन समस्याओं के समाधान के लिये किया जाएगा, जिनका सामना समाज को करना पड़ रहा है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने अगस्त 2018 में 418 करोड़ रुपए की कुल लागत से 31 मार्च, 2020 तक कार्यान्वयन के लिये 'अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के संवर्द्धन हेतु योजना (स्पार्क)' को मंज़ूरी दी थी।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर 'स्पार्क' के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय समन्वयकारी संस्थान है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

- परियोजना के दौरान विकसित होने वाले IPR का निर्धारण भाग लेने वाले संस्थानों के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।
- भारतीय संस्थानों को पेटेंट/रॉयल्टी के द्वारा लाभ प्राप्त होगा।
- सभी विवादों का समाधान भारतीय क्षेत्राधिकार में होगा। किसी भी विशेष भटकाव का समाधान MHRD द्वारा स्पार्क सेल के माध्यम से किया जाएगा और अनुमोदन का अधिकार शीर्ष समिति के पास होगा।

नोट :

एटमोस्फेरिक वॉटर जनरेटर

चर्चा में क्यों ?

नवरत्न कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Ltd-BEL) ने एक नए उत्पाद, एटमोस्फेरिक वॉटर जनरेटर (Atmospheric Water Generator-AWG) का एयरो इंडिया 2019 कार्यक्रम में अनावरण किया है।

प्रमुख बिंदु

- एटमोस्फेरिक वॉटर जनरेटर दुनिया में पेयजल की बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने हेतु एक नया समाधान उपलब्ध कराएगा।
- वायुमंडल में मौज़ूद नमी से जल निकालने के लिये एटमोस्फेरिक वॉटर जनरेटर का उपयोग किया जा सकता है।

AWG की कार्य प्रणाली

- वॉटर जनरेटर वायुमंडल में मौज़ूद नमी से जल निकालने और इसे शुद्ध करने के लिये नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है।
- यह वायुंडल की नमी को संघनित करते हुए शुद्ध, सुरक्षित और स्वच्छ पीने योग्य पानी बनाने के लिये उष्मा विनिमय का प्रयोग करता है।
- इसमें एक मिनरलाइज़ेशन यूनिट भी लगी है जो पानी को पीने योग्य बनाने के लिये उसमें खनिज मिलाती है।
- एटमोस्फेरिक वॉटर जनरेटर को गतिशील वाहनों में भी लगाया जा सकता है।
- एटमोस्फेरिक वॉटर जनरेटर (AWG) 30 लीटर/दिन, 100 लीटर/दिन, 500 लीटर/दिन और 1,000 लीटर/दिन तक जल उपलब्ध करा सकता है।

AWG का निर्माण

- एटमोस्फेरिक वॉटर जनरेटर (AWG) का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा CSIR-IICT और MAITHRI (हैदराबाद स्थित एक स्टार्ट-अप कंपनी) के सहयोग से किया जा रहा है।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टार्ट-अप इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में स्टार्ट-अप कंपनियों को सहायता प्रदान कर रही है।

अरोरा सुपरकंप्यूटर

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर बनाने का निर्णय लिया है जिसे अरोरा सुपरकंप्यूटर (Aurora Supercomputer) कहा जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- अरोरा सुपर कंप्यूटर (Aurora Supercomputer) को शिकागो के बाहर लेमोंट, इलिनॉय (Lemont, Illinois) स्थित आर्गन नेशनल लेबोरेटरी (Argonne National Laboratory) में स्थापित किया जाना है।
- यह पहला ऐसा कंप्यूटर होगा जो एक्ज़ास्केल अर्थात् प्रति सेकंड एक बिलियन बिलियन गणनाएँ करने में सक्षम होगा।
- इसकी स्पीड अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर से सात गुनी, जबकि 2008 में बनाए गए पेटास्केल से 1,000 गुना अधिक होगी।
- यह नया सुपर कंप्यूटर शोधकर्त्ताओं को दवा, जलवायु परिवर्तन, दहन इंजनों की आंतरिक कार्यप्रणाली और सौर पैनल जैसे विषयों के बारे में अधिक सटीक समझ विकसित करने में सक्षम बनाएगा।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिये बनाया गया इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन्स (IBM) कॉर्पोरेशन सिस्टम जिसे समिट (OLCF-4) कहा जाता है, दुनिया का सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर है। इसकी गति 143.5 पेटाफ्लॉप्स है।

भारत में सुपरकंप्यूटर

- भारत के पहले सुपरकंप्यूटर PARAM 8000 को 1991 में लॉन्च किया गया था।

नोट :

- वर्तमान में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर लगाया गया है जिसे प्रत्यूष कहा जाता है। इसकी गति 4.0 पेटाफ्लॉप्स है।
- नेशनल सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्टिंग में मिहिर नामक सुपरकंप्यूटर लगाया गया है, जिसकी गति 2.8 पेटाफ्लॉप्स है।
- कंप्यूटिंग स्पीड का मात्रक या इकाई
- टेराफ्लॉप्स (Teraflops): कंप्यूटिंग स्पीड की इकाई जिसमें एक मिलियन मिलियन (10 ^ 12) फ्लोटिंग-पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड (FLOPS) होते हैं।
- पेटाफ्लॉप्स (Petaflops): कंप्यूटिंग स्पीड की इकाई जिसमें एक हज़ार मिलियन मिलियन (10 ^ 15) फ्लोटिंग-पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड (FLOPS) होते हैं।
- एक्ज़ाफ्लॉप्स (Exaflops): कंप्यूटिंग स्पीड की इकाई जिसमें एक बिलियन बिलियन (10 ^ 18) फ्लोटिंग-पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड (FLOPS) होते हैं।

नैदानिक परीक्षण नियमों का नया मसौदा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नैदानिक परीक्षण नियमों का एक नया मसौदा जारी किया गया जिसमें नई दवाओं को त्वरित स्वीकृति प्रदान करने और देश में नैदानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये कदम उठाते हुए सरकार ने दवा कंपनियों को भारत में नई दवाओं के परीक्षण में छूट देने का फैसला किया है लेकिन यह छूट केवल ऐसे मामलों में दी जाएगी जिसमें दवाओं को भारत के शीर्ष औषधि नियामक केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation-CDSCO) द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा CDSCO द्वारा निर्दिष्ट देशों में उनका विपणन किया जाता है।

- यह छूट उन दवाओं के परीक्षण के लिये भी मिलेगी, जिनके विपणन के लिये अनुमोदन मिल चुका है लेकिन भारत में उन पर परीक्षण चल रहा है।

क्या कहते हैं नए नियम ?

- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नैदानिक परीक्षण नियमों के अनुसार, भारत में किये जाने वाले किसी नैदानिक परीक्षण के दौरान घायल होने वाले मरीज़ों को 'जब तक आवश्यक हो' या जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि चोट का संबंध परीक्षण से नहीं है, तब तक के लिये चिकित्सकीय देख-रेख प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- नए नियमों के अनुसार, जिन रोगियों ने किसी नई दवा की जाँच के लिये किये जाने वाले नैदानिक परीक्षण में भाग लिया है, परीक्षण समाप्त होने के बाद उन्हें प्रायोजक द्वारा वह दवा नि:शुल्क लेकिन कुछ संशोधनों के साथ प्राप्त हो सकती है।
- यदि किसी मरीज़ को एक अनुसंधान भागीदार के रूप में नामांकित किया जाता है, तो शोधकर्त्ता का यह कर्त्तव्य है कि वह उस प्रतिभागी की देखभाल करे।
- एक प्रतिभागी जो किसी नैदानिक परीक्षण में अधिकतम जोखिम उठा रहा है, उसे पर्याप्त उपचार प्राप्त करने, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने और पर्याप्त मुआवज़ा प्राप्त करने का अधिकार है (चोटों या मृत्यु के मामले में)।
- उल्लेखनीय है कि भारत के नैदानिक परीक्षण नियमों के पिछले मसौदे में प्रायोजक को रोगी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में क्षतिपूर्ति का 60 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

विशेषताएँ

- इंडियन सोसाइटी ऑफ़ क्लिनिकल रिसर्च (Indian Society of Clinical Research-ISCR) के अनुसार, नए नियम बहुत संतुलित हैं। यह उन रोगियों के अधिकारों, सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखेगा जो नैदानिक परीक्षणों में भाग लेते हैं इसके अलावा यह नैतिक और गुणवत्तापूर्ण नैदानिक परीक्षणों के संचालन में वृद्धि करेगा जिससे रोगियों के लिये आवश्यक नई दवाओं के विकास में मदद मिलेगी।

नोट :

- ऐसे नियम पहली बार परिभाषित किये गए हैं जो रोगियों के लिये आवश्यक दवाओं की जाँच के बाद पहुँच प्रदान करने की शर्तें निर्धारित करते हैं।
- वैश्विक नैदानिक परीक्षणों के लिये अनुमोदन की समय-सीमा 90 कार्य दिवस है। नए नियम वैश्विक दवा विकास में भारत की भागीदारी का समर्थन करेंगे क्योंकि यह समय-सीमा भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में बढ़त प्रदान करती है और नैदानिक परीक्षण के संबंध में भारत के ये नियम विकसित देशों के नियमों के अनुरूप हैं।
- कुछ कार्यकर्त्ताओं द्वारा नि:शुल्क परीक्षण के बाद दवा तक नि:शुल्क पहुँच या पोस्ट-ट्रायल एक्सेस को एक अच्छा कदम माना गया है, क्योंकि अक्सर ये दवाएँ सस्ती नहीं होती हैं। कार्यकर्त्ताओं ने नए नियमों में अन्य प्रावधानों को शामिल किये जाने के साथ ही कुछ चिंताओं को भी व्यक्त किया है जिसमें मुआवज़ा मानदंड और परीक्षण संबंधी कुछ छूट शामिल हैं।
- नए नियमों पर सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मृत्यु और स्थायी विकलांगता के मामलों में क्षतिपूर्ति या किसी परीक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागी की अन्य प्रकार की चोटों का निर्धारण भारत की सर्वोच्च दवा नियामक संस्था, भारतीय औषधि महानियंत्रक (Drug Controller General of India-DCGI) द्वारा किया जाएगा। लेकिन रोगियों के लिये कार्य करने वाले कुछ कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि परीक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागी हेतु किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति तय करने के लिये एक समिति होनी चाहिये जो पारदर्शी तरीके से कार्य करे।

समस्याएँ

रोगियों के लिये कार्य करने वाले कुछ कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि ऐसी छूट से समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- समस्या यह है कि भारत विशाल नस्लीय विविधता वाला देश है और इस प्रकार के परीक्षण अधिकांशत: पश्चिमी देशों में किये जाते हैं। उदाहरण के लिये यदि किसी दवा की खोज अमेरिका जैसे देश में की जाती है तो इस दवा का परीक्षण एक श्वेत आबादी पर किया जाता है, इसलिये भारत की विविधता को देखते हुए नस्लीय रूप से विविध आबादी के लिये परीक्षण की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह दवा हमारी विविध आबादी के अनुरूप होगी।
- यदि सरकार उस स्थिति के लिये सचेत नहीं है जिसमें वह इस प्रकार की छूट देती है तो ऐसे मामलों में दी जाने वाली छूट खतरनाक हो सकती है। इस प्रकार यह छूट केवल आवश्यक दवाओं के लिये होनी चाहिये जैसे कि पहले दी जाती थी।
- नए नियमों के अनुसार, जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि चोट नैदानिक परीक्षण के कारण नहीं है, तब तक चिकित्सा प्रबंधन प्रदान करने संबंधी नियम में हेर-फेर किया जा सकता है। क्योंकि जिस दवा का परीक्षण/अध्ययन किया जा रहा है वह अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है, ऐसे में यह यह सिद्ध करना मुश्किल हो सकता है कि चोट किसी परीक्षण के दौरान लगी है या नहीं।

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)

- केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation-CDSCO) भारतीय दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के लिये एक राष्ट्रीय विनियामक निकाय है।
- औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिये यह केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।
- CDSCO में भारतीय औषधि महानियंत्रक (Drug Controller General of India-DCGI) औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों का विनियमन करता है।

CDSCO के कार्य

- औषधि के आयात पर विनियामक नियंत्रण, नई औषधियों एवं नैदानिक परीक्षणों का अनुमोदन औषधि परामर्शीय समिति एवं औषधि तकनीकी सलाहकारी बोर्ड की बैठकें, केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के तौर पर कुछ विशिष्ट लाइसेंसों की अनुमति देना आदि।

तमिलनाडु स्वच्छ ऊर्जा में शीर्ष स्थान की ओर

चर्चा में क्यों ?

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु कुल स्थापित क्षमता के साथ शीर्ष स्थान हासिल करने की ओर अग्रसर है क्योंकि राज्य में आने वाले वर्ष में पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्षमता वृद्धि की अपार संभावनाएँ हैं।

नोट :

कर्नाटक की क्षमता

- जनवरी 2019 तक कर्नाटक 13,042 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष राज्य है, जबकि तमिलनाडु की कुल स्थापित क्षमता 12,125 मेगावाट है।
- तमिलनाडु पवन क्षमता में अग्रणी राज्य है, जबकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है।
- सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती स्थापित क्षमता और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार के कारण कर्नाटक लगभग चार साल पहले पाँचवे स्थान से शीर्ष स्थान पर पहुँच गया है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अनुसार, सितंबर 2015 में तमिलनाडु 8,466 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा में अग्रणी राज्य था, जबकि कर्नाटक की क्षमता 4,606 मेगावाट थी।
- कर्नाटक की 13,042 मेगावाट की कुल नवीकरणीय क्षमता में से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 5,323 मेगावाट (जिसमें धरातलीय क्षमता में 5,175 मेगावाट तथा रूफटॉप श्रेणी में 154 मेगावाट) शामिल हैI इसके बाद 4,683 मेगावाट क्षमता के साथ पवन ऊर्जा का स्थान आता है तथा शेष छोटे हाइड्रो, को-जेन पावर (Co-gen Power) तथा बायो-पावर हैं।

तमिलनाडु की क्षमता

- तमिलनाडु में पवन ऊर्जा 8,764 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ प्रमुख बनी हुई है, जबकि सौर श्रेणी में राज्य की कुल स्थापित क्षमता 2,233 मेगावाट (धरातलीय स्तर पर 2,098 मेगावाट तथा रूफटॉप स्तर पर 135 मेगावाट) है।
- जैव-शक्ति (Bio-power) तथा को-जेन (Co-gen) क्षमता का कुल योगदान क्रमश: 1,004 मेगावाट तथा 941 मेगावाट है तथा छोटे हाइड्रो की कुल क्षमता 123 मेगावाट है।
- अक्षय ऊर्जा परामर्श फर्म ब्रिज ने उम्मीद जताई है कि 2019 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कुल क्षमता 15,860 मेगावाट हो जाएगी।
- तमिलनाडु में 1,872 मेगावाट नई सौर क्षमता के बढ़ने की उम्मीद है, जबकि कर्नाटक में 1,555 मेगावाट की वृद्धि की संभावना है।

पवन ऊर्जा क्षेत्र

- 2019 में पवन ऊर्जा क्षेत्र में समग्र रूप से क्षमता वृद्धि 2,300 मेगावाट होने की उम्मीद है तथा तमिलनाडु और गुजरात में नई क्षमता स्थापित होने की उम्मीद है।
- अनुकूल परिस्थिति के कारण तमिलनाडु कर्नाटक की तुलना में काफी अधिक वृद्धि कर सकता है और समस्त राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल कर सकता है।

बायो-डाइजेस्टर प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) द्वारा बायो-डाइजेस्टर प्रौद्योगिकी (Bio-Digester Technology) विकसित की गई है। इस तकनीकी से आने वाले वर्षों में स्वच्छता क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन की संभावना है।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक (National Institute of Technology Karnataka- NITK) के परिसर में दक्षिण कन्नड़ निर्मिथि केंद्र (Dakshina Kannada Nirmithi Kendra) में बायो डाइजेस्टर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया।
- एमएम इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड (MM Industrial Controls Pvt Ltd.) के प्रबंध निदेशक ने इस बायो-डाइजेस्टर प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी दी।
- इनके अनुसार, इस तकनीकी में बायो-डाइजेस्टर टैंक के साथ संलग्न एक जैव-शौचालय होता है जो मानव मल को बायोगैस और पुन: उपयोग किये जा सकने वाले जल में परिवर्तित करता है।

नोट :

स्वदेशी तकनीक

- वर्तमान में DRDO द्वारा विकसित तकनीक का उपयोग भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
- इसमें एनएरोबिक माइक्रोबियल इनोकुलम (Anaerobic Microbial Inoculum) तकनीकी का उपयोग किया गया है ताकि जीवों को बायोगैस और पानी में परिवर्तित किया जा सके। इसका उपयोग कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों के लिये भी किया जा सकता है।
- इस प्रौद्योगिकी का उपयोग पारंपरिक शौचालयों में भी किया जा सकता है।
- इस प्रौद्योगिकी को स्थापित करने में पारंपरिक शौचालयों के टैंको की तुलना में कम स्थान की जरूरत होती है।
- बायो-डाइजेस्टर टैंक के रखरखाव और स्थापना की लागत भी कम होती हैं।
- टंकियों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है और माइनस (-) 20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के तापमान में संचालित किया जा सकता है।
- इस तकनीक का इस्तेमाल स्वतंत्र घरों, अपार्टमेंट ब्लॉक, स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों एवं छात्रावासों में किया जा सकता है।

मुफ्त रखरखाव

- अधिकांश शहरी क्षेत्रों में सेप्टिक टैंक और खुले कुएँ आसपास के क्षेत्र में स्थित होते हैं जो साफ पानी को प्रदूषित करते हैं।
- ऐसी समस्या को ख़त्म करने में बायो-डाइजेस्टर टैंक काफी उपयोगी हैं। बायो-डाइजेस्टर टैंक जीवनभर के लिये रखरखाव-मुक्त होते हैं, क्योंकि एनएरोबिक माइक्रोबियल इनोकुलम को टैंक में केवल एक ही बार डाला जाता है।
- यह माइक्रोब (Microb) स्व-बहुगुणन प्रक्रिया करता रहता है और मल का निस्तारण होता रहता है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research & Development Organization-DRDO)

- डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (Defence Science Organisation- DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (Technical Development Establishment- TDEs) और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (Directorate of Technical Development & Production- DTDP) के संयोजन के बाद किया गया।
- DRDO रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है।
- यह रक्षा प्रणालियों के डिज़ाइन एवं विकास के साथ-साथ तीनों क्षेत्रों के रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणाली एवं उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।
- डीआरडीओ सैन्य प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग प्रणालियाँ, मिसाइलें, नौसेना प्रणालियाँ, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन और जीवन विज्ञान शामिल है।

एनएरोबिक माइक्रोबियल इनोकुलम Anaerobic Microbial Inoculum- AMI

- AMI बैक्टीरियल संघ (Bacterial Consortium) है जो मल पदार्थ को गैस एवं जल में परिवर्तित करता है।
- ये अवायवीय वातावरण में काम करते हैं और बाहरी वातावरण के संपर्क में बहुत संवेदनशील होते हैं।
- ये बैक्टीरियल कंसोर्टियम बहुत शक्तिशाली होते हैं जो सामान्यत: 5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच काम कर सकते हैं। एनएरोबिक डाइज़ेशन (Biomethanation) एक बहुत पुरानी तकनीक है और ज़्यादातर बायोगैस उत्पादन के लिये प्रचलित है।

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

गैंडों (Rhinos) का संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नई दिल्ली में उन देशों की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया जहाँ एशियाई गैंडे (राइनो) पाए जाते हैं। इस बैठक में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिये भारत, नेपाल और भूटान के बीच सीमा-पार सहयोग को रेखांकित किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस बैठक में गंभीर रूप से लुप्तप्राय सुमात्रा प्रजाति के प्राकृतिक और संरक्षित प्रजनन में तेज़ी लाने के लिये आपसी सहयोग एवं प्रौद्योगिकियों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।
- बैठक के तहत एक देश के भीतर या गैंडे पाए जाने वाले देशों के बीच इनके अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर भी जोर दिया गया।

एक सींग वाला गैंडा

- इंडोनेशिया, मलेशिया एवं अन्य एशियाई देशों में भी गैंडों का निवास है।
- वर्तमान वैश्विक आबादी के अनुसार एक सींग वाले भारतीय गैंडों की संख्या 3,584 है। भारत में असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2,938 गैंडे हैं, जबकि नेपाल में 646।
- हालाँकि भूटान में गैंडे नहीं हैं लेकिन असम से सटे मानस नेशनल पार्क और पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिज़र्व से कभी-कभार कुछ गैंडे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर जाते है।
- चीन से लेकर बांग्लादेश तक जवन और सुमात्रन गैंडे विलुप्त होने वाले हैं।
- सुमात्रन राइनो, सभी राइनो प्रजातियों में सबसे छोटा और दो सींगों वाला एकमात्र एशियाई गैंडा है, जो मलेशिया के जंगलों से विलुप्त हो गया है।
- IUCN के प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के एशियाई राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप के अध्यक्ष के अनुसार, वर्तमान में मलेशिया के सबा द्वीप में केवल एक तथा इंडोनेशिया में कुछ ही राइनो पाये जाते हैं।
- IUCN प्रत्येक चार वर्ष में पृथ्वी पर उपस्थित उन सभी प्रजातियों की सूची प्रकाशित करता है जो संकट में हैं। इस सूची को 'IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़' (IUCN-Red List of Threatened Species) कहा जाता है।
- रेड लिस्ट दुनियाभर के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाती है, इसलिये दुनिया में जैवविविधता पर इसे सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय सूची माना जाता है।
- IUCN द्वारा जारी की जाने वाली इसी रेड लिस्ट के अंतर्गत भारत में उड़ने वाली गिलहरी, एशियाई सिंह, काले हिरण, गेंडे, गंगा डॉल्फिन, बर्फीले तेंदुए सहित अनेक जीवों को संकटग्रस्त करार दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- 1905 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पहली बार एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिये अधिसूचित किया गया था जब इनकी संख्या 10 से भी कम हो गई थी।
- 1908 में इसका गठन विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिये संरक्षित वन के रूप में कर दिया गया।
- 1970 के दशक में गैंडों की संख्या कुछ सौ थी जो वर्तमान में 3,584 है।
- काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल में किया गया था।

नोट :

IUCN क्या है

- IUCN पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है।
- IUCN की स्थापना 5 अक्तूबर, 1948 को फ्राँस में हुई थी। इसकी पहली बैठक में दुनिया के 18 देशों के सरकारी प्रतिनिधियों, 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाले 107 राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था।
- इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड शहर में अवस्थित है।
- इसका मूल लक्ष्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है, जहाँ मूल्यों और प्रकृति का संरक्षण हो सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये IUCN प्रकृति की अखंडता और विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिये वैश्विक समाज को प्रोत्साहित करता है।
- साथ ही, यह प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग और पारिस्थितिकीय संरचना को बेहतर बनाने की दिशा में भी सक्रिय है। रेड लिस्ट इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1963 में की गई थी। इसके अतिरिक्त, जैव विविधता, सतत ऊर्जा, हरित अर्थव्यवस्था आदि भी इसके महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हैं।

बांदीपुर टाइगर रिज़र्व में लगी आग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिज़र्व में आग लगने की घटना सामने आई।

- इस घटना से पारिस्थितिक तंत्र को दीर्घकालिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। यह टाइगर रिज़र्व नीलगिरि बायोस्फीयर का एक हिस्सा है। 2014 की जनगणना के अनुसार यहाँ बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा (575 से अधिक) है।
- देश की वन नीति अपने संरक्षित परिदृश्यों चाहे वह बांदीपुर हो या ऊपरी पश्चिमी घाट के वर्षावन, के लिये शून्य वन अग्नि दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, जंगलों में लगने वाली आग (वनाग्नि) को पूरी तरह रोकने से (Blanket Approach of Zero Fire) उन शुष्क, पर्णपाती जंगलों को नुकसान पहुँच सकता है, जहाँ आग के सह-अस्तित्व में वृक्ष विकसित होते हैं।

बांदीपुर टाइगर रिज़र्व में आग लगने का कारण

- वर्ष 2018 में मानसून विशेष रूप से मज़बूत था, लेकिन साल के अंत में उत्तर-पूर्व में मानसून विफल रहा। मानसून के कारण जंगलों का सघन विकास हुआ, जबकि सितंबर से प्रचंड गर्मी ने वनस्पतियों को भंगुर और सूखा बना दिया।
- हालाँकि अधिकांश जंगलों की आग की तरह बांदीपुर की आग की घटना को भी मानव निर्मित माना जा रहा है।

जंगल की आग के सकारात्मक प्रभाव

- भारतीय वैज्ञानिकों का एक 6 सदस्यीय समूह जो फायर-प्रोन फॉरेस्ट सिस्टम (Fire-Prone Forest Systems) का अध्ययन कर रहा है, ने आग से लड़ने वाली आग के महत्त्व को बताते हुए जंगल की आग के और स्पष्ट दृश्य की तत्काल आवश्यकता जाहिर की है।
- जंगल में लगने वाली आग के प्रमुख कारण ऐतिहासिक, पारिस्थितिक, वैज्ञानिक या अन्य हो सकते हैं।
- भारत में जंगलों में आग लगने की घटनाएँ कम-से-कम 60,000 साल पहले से ही होती रही हैं। कई बार प्राकृतिक रूप से या फिर मानवजनित रूप से हज़ारों वर्षों से वन जलते रहे हैं।
- जंगल की आग में कुछ पेड़-पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं, तथा कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जो जलकर नष्ट नहीं होते साथ ही कुछ सुप्त बीज आग में जलकर पुनर्जीवित हो जाते हैं।
- एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि मौसमी सूखे के दौरान, वनों में आग लगने की समस्या के रूप में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के शुष्क पर्णपाती वनों को चित्रित किया गया है।

सुप्त बीजों का पुनर्जीवन

- वास्तव में कई स्थानिक पेड़-पौधे आग के साथ विकसित होते हैं, इस प्रकार आग कई प्रजातियों के निष्क्रिय बीजों को पुनर्जीवित करने में मदद करती है।

नोट :

- एक अध्ययन से पता चला है कि मुदुमलाई में नए उगे हुए पेड़ ज़मीन में लगने वाली आग से बच जाते हैं और जब तक वे एक निश्चित ऊँचाई तक नहीं पहुँच जाते, तब तक इन पेड़ों में उच्च दर से वृद्धि होती रहती है।

आक्रामक प्रजातियों पर अंकुश

- कुछ वैज्ञानिक जंगल की आग को पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिये पूरी तरह से हानिकारक मानते हैं लेकिन अधिकतर साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि जंगलों में लगने वाली आग से अधिकांशत: आक्रामक प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं।
- उदाहरण के लिये एक अध्ययन में पाया गया कि कर्नाटक के बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिज़र्व में आदिवासी समुदायों द्वारा प्रचलित 'कूड़े में लगाई जाने वाली आग' की परंपरा का बहिष्कार करने पर लैंटाना प्रजाति की वनस्पति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने वहाँ के स्थानिक पौधों के स्थान का अतिक्रमण कर लिया।
- एक अध्ययन से पुष्टि हुई है कि एक परजीवी झाड़ी (हेयरी मिस्टलेट-Hairy Mistletoe) परिपक्व पेड़ों को प्रभावित करती है। आग के नही लगने के कारण उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप जंगली आँवले के पेड़ों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।
- लेकिन वैज्ञानिकों ने बड़े पैमाने पर जंगलों में लगने वाली आग जैसे कि कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में लगी आग पर चिंता व्यक्त की है। क्योंकि उच्च तीव्रता वाली आग का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष

- वन प्रबंधन में आग वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। दिसंबर महीने के आसपास वनों में बड़े पैमाने पर ईंधन भार (जंगलों में फैला सूखा कूड़ा और बायोमास) वाले क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं के बाद भी इसे रोका जा सकता है।
- जंगल के किसी एक क्षेत्र को यदि आग से लगातार संरक्षित किया जाता है, तो चार साल में घास, लकड़ी और टहनियों के उच्च संचय के कारण इस क्षेत्र में स्वत: आग लग सकती है। लेकिन आग को एक उपकरण के रूप में बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

आगे की राह

- वैज्ञानिकों ने नीति निर्माताओं और वन विभागों से अनुरोध किया है कि वे कानून में बदलाव करके वनों के लिये अधिक वैज्ञानिक और विचारशील प्रबंधन की अनुमति प्रदान करें।
- साथ ही गैर-सरकारी संगठनों एवं कार्यकर्त्ताओं को जंगल की आग के बारे में जटिलताओं और बारीकियों पर ध्यान देते हुए सहयोग करने की बात कही है।

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (India Cooling Action Plan-ICAP) जारी किया।

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP)

- कूलिंग की ज़रूरत हर क्षेत्र में है तथा यह आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- इसकी ज़रूरत आवासीय और व्यापारिक इमारतों के साथ कोल्ड चेन रेफ्रिज़रेशन, परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होती है।

उद्देश्य

- ICAP का उद्देश्य पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक लाभों को हासिल करने के लिये कार्यों में तालमेल का प्रयास करना है।
- समाज को पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए सभी के लिये स्थायी शीतलन और उष्मीय सहूलियत प्रदान करना।

नोट :

प्रमुख लाभ

- अगले 20 वर्षों तक सभी क्षेत्रों में शीतलता से संबंधित आवश्यकताओं से जुड़ी मांग तथा ऊर्जा आवश्यकता का आकलन।
- शीतलता के लिये उपलब्ध तकनीकों की पहचान के साथ ही वैकल्पिक तकनीकों, अप्रत्यक्ष उपायों और अलग प्रकार की तकनीकों की पहचान करना।
- सभी क्षेत्रों में गर्मी से राहत दिलाने तथा सतत् शीतलता प्रदान करने वाले उपायों को अपनाने के बारे सलाह देना।
- तकनीशियनों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- घरेलू वैकल्पिक तकनीकों के विकास हेतु 'शोध एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र' को विकसित करना।
- इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

लक्ष्य

- वर्ष 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में शीतलक मांग (Cooling Demand) को 20% से 25% तक कम करना।
- वर्ष 2037-38 तक रेफ्रीजरेंट डिमांड (Refrigerant Demand) को 25% से 30% तक कम करना।
- वर्ष 2037-38 तक शीतलन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता को 25% से 40% तक कम करना।
- वर्ष 2022-23 तक कौशल भारत मिशन के तालमेल से सर्विसिंग सेक्टर के 100,000 तकनीशियनों को प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना।

वन सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा गठित एक समिति ने वन आच्छादित क्षेत्र का आकलन करने के लिये वन सर्वेक्षण के अंतर्गत वनों में और वन क्षेत्र से बाहर उगने वाले पेड़ों (निजी/सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण या ग्रीनलैंड) के अलग-अलग सर्वेक्षण की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार प्रत्येक दो वर्षों में वन सर्वेक्षण करवाती है जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वनों से आच्छादित हिस्से का आकलन किया जाता है।
- इसके अंतर्गत जंगल में और जंगलों से बाहर उगने वाले पेड़ों को शामिल किया जाता है।
- आलोचक काफी समय से इस बात की आलोचना करते रहे हैं कि दोनों क्षेत्रों के पेड़ों को एक ही श्रेणी में शामिल करना पारिस्थितिक रूप से बेहतर नहीं है, लेकिन सरकारी समिति द्वारा इस तरह की सिफारिश करने का यह पहला उदाहरण है।
- इंडिया स्टेट ऑफ़ फॉरेस्ट रिपोर्ट (SFR), 2017, जो फरवरी 2018 में जारी की गई, के अनुसार, भारत में 2015 और 2017 के बीच वन क्षेत्र में 0.94% की वृद्धि दर्ज की गई।
- दस्तावेज़ में कहा गया है कि भारत में लगभग 7,08,273 वर्ग किमी. वन आच्छादित क्षेत्र है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.53% (32,87,569 वर्ग किमी.) है।
- 1988 से सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य भारत में वन आच्छादित क्षेत्र को देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% करना रहा है।
- SFR के विभिन्न संस्करणों में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत 21 के आस-पास रहा है, अत: सरकार अपने मूल्यांकन में वनों के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों, जैसे निजी/सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण या ग्रीनलैंड को भी शामिल करती है।

नोट :

कृत्रिम वर्षा

चर्चा में क्यों ?

कर्नाटक के लगभग 176 ताल्लुका क्षेत्रों में सूखा पड़ने के पश्चात् इस वर्ष हाल ही में कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने मानसून 2019 और 2020 के लिये राज्य में कृत्रिम वर्षा करवाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की है।

प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार कृत्रिम वर्षा के लिये पूर्व में चलाई गई 'वर्षाधारी' परियोजना को अपनाएगी।
- क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है।
- क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) के लिये सिल्वर आयोडाइड (Silver Iodide) या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (ड्राई आइस) को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है।
- विमान में सिल्वर आयोडाइड के दो बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं, जिनमें सिल्वर आयोडाइड का घोल उच्च दाब (हाई प्रेशर) के साथ भरा होता है।
- जहाँ बारिश करानी होती है वहाँ पर हवा की विपरीत दिशा में इसका छिड़काव किया जाता है।
- कहाँ और किस बादल पर इसे छिड़कने से बारिश की संभावना ज़्यादा होगी, इसका फैसला मौसम वैज्ञानिक करते हैं। इसके लिये मौसम के आँकड़ों का सहारा लिया जाता है।
- कृत्रिम वर्षा की इस प्रक्रिया में बादल के छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की भारी बूँदें बनने लगती हैं और वे बरसने लगती हैं।
- क्लाउड सीडिंग का उपयोग वर्षा में वृद्धि करने, ओलावृष्टि के नुकसान को कम करने, कोहरा हटाने तथा तात्कालिक रूप से वायु प्रदूषण कम करने के लिये भी किया जाता है।

वर्षाधारी परियोजना

- 22 अगस्त, 2017 को कर्नाटक सरकार ने बंगलूरू में कृत्रिम वर्षा के लिये वर्षाधारी परियोजना को आरंभ किया था।
- 2018 में राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस परियोजना से बारिश में 27.9% की वृद्धि हुई है और लिंगमनाकी जलाशय में 2.5 tmcft (Thousand Mllion Cubic Feet) का अतिरिक्त प्रवाह रहा है।
- एक स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा इसे सफल परियोजना घोषित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण मंच में प्लास्टिक पर चर्चा

चर्चा में क्यों ?

पृथ्वी के पर्यावरणीय संकट पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण मंच की पाँच दिवसीय वार्षिक बैठक का आयोजन नैरोबी में किया जा रहा है जिसमें दुनिया भर के देशों से हज़ारों प्रतिनिधि, व्यापारी, नेता और प्रचारक भाग ले रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में दुनिया भर के देशों ने प्लास्टिक कचरे, दीर्घकालिक प्रदूषण के स्रोत और महासागर की खाद्य श्रृंखला को हानि पहुँचाने के खिलाफ प्रदूषण को रोकने के लिये अपनी प्रतिबद्धता तय की।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अलग-अलग देशों को अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्लास्टिक के उत्पादन को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करना है, जिसमें 2015 के पेरिस समझौते से प्रेरित एक लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की स्वैच्छिक कटौती करना है।
- इस बैठक में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एवं सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत बड़े पैमाने पर प्लास्टिक और रासायनिक कचरे से पारिस्थितिक तंत्र को होने वाले खतरे की चेतावनी के रूप में शामिल किया जा सकता है।

नोट :

- वर्तमान में दुनिया भर में प्रतिवर्ष 300 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है तथा महासागरों में कम-से-कम पाँच ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं।
- माइक्रोप्लास्टिक्स सबसे गहरी समुद्री खाइयों से लेकर पृथ्वी की सबसे ऊँची चोटियों तक पाया जाते हैं, साथ ही प्लास्टिक की खपत साल-दर-साल बढ़ रही है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

- रिपोर्ट के अनुसार, प्लास्टिक टिकाऊ, लचीला और हल्का होता है, इसका निपटान करने के बजाय यथासंभव लंबे समय के लिये इसे सर्वश्रेष्ठ बनाकर सकारात्मक रूप में उपयोग करना चाहिये।
- इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिकूल रिपोर्ट आई है, जिसमें स्पष्ट रूप से मानव जाति द्वारा लापरवाही से किये जाने वाले उपयोग के कारण मानव जाति को ही नुकसान पहुँचाने को संदर्भित किया गया है।
- हालाँकि जलवायु, पर्यावरण, अपशिष्ट ये सभी चीजें परस्पर एक-दुसरे से जुड़ी हुई हैं।
- एक अध्ययन के अनुसार, 1995 के बाद से कृषि, वनों की कटाई और प्रदूषण के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान की लागत $ 20 ट्रिलियन से कहीं ज़्यादा पाई गई।

भारत में मिली मेंढक की एक नई प्रजाति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 2 सेमी लंबे तथा विभिन्न रंगों वाले मेंढक की खोज को एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- जून 2010 में पहली बार इस मेंढक को केरल के वायनाड में पत्तियों के नीचे पाया गया था।
- यह एक नई प्रजाति है इसके कई दिलचस्प आकार और रंग पैटर्न पाए गए हैं जो अन्य पश्चिमी घाट के मेंढकों में नहीं देखा जाता।
- हाल ही में देश और विदेश के वैज्ञानिकों की एक टीम ने जीवों के शारीरिक संरचना, कंकाल और आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन किया।
- उन्होंने दुनिया भर के संग्रहालय में संग्रहित समान प्रजातियों के मेंढकों के नमूनों की आपस में तुलना की।
- इस अध्ययन के अनुसार केरल के वायनाड में पाए जाने वाले मेढकों का आकार अन्य समान आकार के मेंढकों से पूरी तरह से अलग पाया गया।
- हालाँकि, आनुवंशिक अध्ययनों से एक बात सामने आई है कि वायनाड में पाए जाने वाले मेंढकों के सबसे करीबी परिवार पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले Nycibatrachinae (नायसीबत्ट्राचिने) समूह तथा श्रीलंका में पाए जाने वाले Lankanectinae (लंकानेक्टिने) समूह के मेंढक हैं।

एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना (Astrobatrachus kurichiyana)

- वैज्ञानिकों की टीम ने इस नई प्रजाति के मेंढक को एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना नाम दिया है क्योंकि विविध रंगों एवं आकार वाला यह छोटा मेंढक एस्ट्रोबाट्राचस वंश का है तथा इसे वहाँ पाए जाने वाले कुरिचियाना जनजातियों द्वारा कुरिचियाना नाम दिया गया था।
- आनुवंशिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह प्रजाति कम-से-कम 60 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई हैं।
- यह मेंढक एक नई प्रजाति के साथ ही नए परिवार से भी संबंधित है।

कुरिचिया जनजाति

- इस जनजाति को मलाई ब्राह्मण (Malai Brahmins) या पहाड़ी ब्राह्मण (Hill Brahmins) भी कहा जाता है।
- वे वायनाड जिले में दूसरे सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हैं। ये वायनाड की पहाड़ी जनजातियों के जाति पदानुक्रम में शीर्ष पर हैं।
- इस समुदाय को कुरिचिया नाम इनकी तीरंदाजी में विशेषज्ञता के लिये कोट्टायम राजा द्वारा दिया गया था यह नाम 'कुरी वीचवन' वाक्यांश से लिया गया है जिसका अर्थ है 'वह जिसने लक्ष्य पाया'।
- यह भी कहा जाता है कि `कुरिचिया' नाम कुरी या चंदन के पेस्ट से लिया गया है जिसे वे अपने माथे और छाती पर रिवाज के तौर पर लगाते हैं।

नोट :

- ये भूमि स्वामी समुदाय हैं और एक मातृसत्तात्मक पारिवारिक प्रणाली का पालन करते हैं।
- उन्होंने स्लैम और बर्न (शिफ्टिंग) की खेती को पुनम खेती (Punam Cultivation) के नाम से जाना।

जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स पर मानवीय प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

जैविक विज्ञान को समर्पित पत्रिका PLOS Biology (पी.एल.ओ.एस. बायोलॉजी) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली लगभग 84% प्रतिशत प्रजातियों पर मानवीय प्रभाव परिलक्षित होते हैं।

प्रमुख बिंदु

- क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के जेम्स एलन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स पर मानवीय प्रभावों का अध्ययन किया है।
- यह अध्ययन 5,457 संकटापन्न प्रजातियों पर आधारित है जिनमें 1,277 स्तनधारी, 2,120 पक्षी और 2,060 उभयचर शामिल हैं।
- टीम ने आठ मानव गतिविधियों के प्रभावों का मानचित्रण किया। इन आठ गतिविधियों में शिकार और कृषि के लिये प्राकृतिक आवासों का रूपांतरण किया जाना भी शामिल है।
- 1237 प्रजातियाँ अपने 90 प्रतिशत से अधिक आवासों में और 395 प्रजातियाँ अपनी संपूर्ण सीमा में मानवीय गतिविधियों से प्रभावित हैं।
- जहाँ 72% प्रजातियाँ इन 'हॉटस्पॉट' से गुज़रने वाली सड़क मार्गों के कारण प्रभावित होती हैं वहीँ सबसे अधिक 3834 प्रजातियाँ प्राकृतिक आवासों के कृषि भूमि में रूपांतरण के कारण प्रभावित हैं।
- औसत 125 प्रभावित प्रजातियों के साथ मलेशिया अत्यधिक प्रभावित प्रजातियों वाले देशों में पहले स्थान पर है।
- भारत में औसत 35 प्रजातियाँ प्रभावित हैं और यह 16वें स्थान पर है।
- दक्षिण-पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय वन, जिनमें भारत के पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व हिमालय शामिल हैं, प्रभावित प्रजातियों के 'हॉटस्पॉट' हैं।
- जहाँ दक्षिण-पश्चिमी घाट में प्रभावित होने वाली प्रजातियों की औसत संख्या 60 है, वहीँ हिमालयी उपोष्णकटिबंधीय विस्तृत वन में औसत 53 प्रजातियाँ प्रभावित हैं।

निष्कर्ष

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, अत: यहाँ विकास की योजना इस तरह से बनाने की आवश्यकता है कि वन्यजीव और जैव-विविधता से समृद्ध क्षेत्रों के संरक्षण को प्राथमिकता मिले।

वैश्विक पर्यावरण आउटलुक

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nation Environment Programme-UNEP) ने हाल ही में वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट (Global Environment Outlook- GEO) का छठा संस्करण जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में होने वाली एक-चौथाई अकाल मौतों और बीमारियों का एक बड़ा कारण मानव जनित प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति है। 2015 में लगभग 9 मिलियन मौतें इसी के कारण हुईं।
- रिपोर्ट के अनुसार घातक गैसीय उत्सर्जन, पीने के पानी को प्रदूषित करने वाले रसायन और पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के कारण विश्व में महामारी की स्थिति बनती जा रही है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी।
- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण समुद्र में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ और अतिवृष्टि का खतरा बना हुआ है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण अन्य प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा है।

नोट :

- स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न होने से प्रतिवर्ष 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु रोगजनक बीमारियों से होती है।
- समुद्र में पहुँचने वाले रसायनों से कई पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं वायु प्रदूषण से सालाना 6-7 मिलियन मौतें होती हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य अपशिष्ट, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 9% है, को नष्ट किया जा सकता है। वर्तमान में उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों का एक तिहाई भाग दुनिया फेंक देती है और केवल अमीर देशों में यह 56% है।

बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय (Ministry of Environment and Forests-MOEF) के इको-सेंसिटिव ज़ोन (Eco-Sensitive Zone-ESZ) की विशेषज्ञ समिति की 33वीं बैठक आयोजित हुई।

- इसमें बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के कुछ क्षेत्रों को इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- हाल में पर्यावरण और वन मंत्रालय की ESZ की विशेषज्ञ समिति की बैठक में 5 नवंबर, 2018 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के आधार पर बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के आस-पास के लगभग 168.84 वर्ग किमी. क्षेत्र को ESZ क्षेत्र घोषित किया गया।
- 2016 में जारी पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से 268.9 वर्ग किमी. का ESZ क्षेत्र चिह्नित किया गया था।
- नए ESZ संरक्षित क्षेत्र की परिधि 100 मीटर (बंगलुरु की ओर) से 1 किलोमीटर (रामनगरम ज़िले) तक होगी।
- ESZ कमेटी के अनुमान के अनुसार, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में 150 से 200 के बीच हाथी देखे गए।

इको-सेंसिटिव ज़ोन

- इको-सेंसिटिव ज़ोन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र हैं।
- इको-सेंसिटिव ज़ोन में होने वाली गतिविधियाँ 1986 के पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम) के तहत विनियमित होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है।
- सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, इको-सेंसिटिव ज़ोन का विस्तार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किमी. तक के दायरे में हो सकता है। लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किमी. से भी अधिक क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन में शामिल किया जा सकता है।
- इको-सेंसिटिव ज़ोन के लिये घोषित दिशा-निर्देशों के तहत निषिद्ध उद्योगों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास के क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है।
- ये दिशा-निर्देश वाणिज्यिक खनन, जलाने योग्य लकड़ी के वाणिज्यिक उपयोग और प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाओं जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं।
- कुछ गतिविधियों जैसे कि पेड़ गिराना, भूजल दोहन, होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग आदि को इन क्षेत्रों में नियंत्रित किया जाता है।
- इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास की गतिविधियों को नियंत्रित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क

- कर्नाटक के बंगलूरू में स्थित बन्नेरघट्टा उद्यान की स्थापना 1972 में की गई थी और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिज़र्व बना दिया गया जिसे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है।
- 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहीं स्थापित किया गया।

नोट :

- यहाँ जंगली बिल्लियों, भारतीय तेंदुओं, बाघ, चीतों एवं हाथियों को नैसर्गिक रूप से देखा जा सकता है।
- यह एक चिड़ियाघर, पालतू जानवरों का कार्नर, पशु बचाव केंद्र, तितली पार्क, मछलीघर, सांपघर, मगरमच्छ फॉर्म और सफारी पार्क के साथ ही एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है।
- कर्नाटक का चिड़ियाघर प्राधिकरण, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलूरू और अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एन्वायरमेन्ट (ATREE), बंगलूरू इसकी सहयोगी एजेंसियाँ हैं।

वेस्ट नील वायरस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल के मालापुरम में एक सात वर्षीय बच्चे में वेस्ट नील वायरस (West Nile Virus- WNV) के लक्षण देखे गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- WNV एक मच्छर जनित बीमारी है। यह बीमारी मुख्यत: संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
- इसकी खोज पहली बार 1927 में युगांडा के पश्चिमी नील उप-क्षेत्र में की गई थी।
- WNV का पहला गंभीर प्रकोप 1990 के दशक के मध्य में अल्जीरिया और रोमानिया में हुआ था।
- यह वायरस संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1999 में सामने आया। उस वर्ष न्यूयॉर्क में 62 मनुष्य, 25 घोड़े और अनगिनत पक्षी इस वायरस से ग्रसित पाए गए थे।
- तब से कम-से-कम 48 राज्यों में WNV से प्रभावित लोगों की 40,000 से अधिक रिपोर्ट्स प्राप्त की गई हैं और यह अमेरिका में मच्छरों से मनुष्यों में फैलने वाला आम वायरस है।

WNV के लक्षण

- WNV से संक्रमित लगभग 80% लोगों में WNV का या तो कोई लक्षण नहीं दिखता है या हल्का बुखार हो सकता है।
- इसमें सिरदर्द, तेज़ बुखार, थकान, शरीर में दर्द, उल्टी, कभी-कभी त्वचा पर चकत्ते और लसीका ग्रंथियों (Lymph Glands) में सूजन आ सकती है।
- यह वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है। हालाँकि, 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और कुछ प्रत्यारोपण के रोगियों के WNV से संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार पड़ने का अधिक खतरा होता है।
- वेस्ट नील वायरस मनुष्यों में एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कारण बन सकता है।
- वर्तमान में WNV के लिये कोई टीका (Vaccine) उपलब्ध नहीं है।

भारत के लिये एक जलवायु भेद्यता सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST) ने देश के विभिन्न राज्यों के सामने आने वाले जलवायु जोखिमों का आकलन करने के लिये एक अध्ययन शुरू करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आगामी अध्ययन से जिलेवार आँकड़ों के साथ पोर्टल तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत 12 हिमालयी राज्यों द्वारा सामना किये जा रहे ग्लोबल वार्मिंग जोखिमों का मूल्यांकन किया जाएगा।
- इसके तहत असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्यों को विशेष रूप से संदर्भित किया जाएगा जो पिछले साल यू.एन. जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में चर्चा में आए थे।
- इस पोर्टल के अंतर्गत देश के किसी भी राज्य के पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी भी तरह के जोखिम को देखा जा सकेगा।

नोट :

सामान्य कार्यप्रणाली

- पिछले साल मंडी और गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), और बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी जिलों के राज्य प्राधिकारियों के साथ समन्यव कर जलवायु परिवर्तन की जटिलताओं से निपटने के लिये सामान्य कार्यप्रणाली विकसित करने का प्रयास किया।
- इसके अंतर्गत शोधकर्त्ताओं ने ज़िला स्तर के आँकड़ों के आधार पर इनमें से प्रत्येक राज्य का 'भेद्यता सूचकांक' तैयार किया। जिसमें भेद्यता (Vulnerability) को मुख्य रूप से भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर निहित जोखिमों के रूप में संदर्भित किया गया।
- वैज्ञानिकों ने राज्यों के साथ कार्यशालाएँ आयोजित कर आठ प्रमुख मापदंडों को अपनाया, जिसके आधार पर भेद्यता स्कोर बनाया जा सकता है।
- पैमाने पर 0-1 अंक तक अधिसूचित किया गया है जिसमें 1 भेद्यता के उच्चतम संभावित स्तर को दर्शाता है, असम को 0.72 के स्कोर के साथ शीर्ष पर एवं 0.71 अंक के साथ मिज़ोरम दूसरे स्थान पर है। सिक्किम, 0.42 के सूचकांक स्कोर के साथ अपेक्षाकृत कम असुरक्षित है।
- विभिन्न कारकों ने राज्य के भेद्यता सूचकांक में योगदान दिया। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख कारक निम्न महिला साक्षरता और बीपीएल से ऊपर की आबादी का उच्च प्रतिशत है, जबकि नगालैंड में प्रमुख मुद्दे हैं वन कवर, खड़ी ढलान और उच्च उपज परिवर्तनशीलता का नुकसान।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा- 4

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-4) का चौथा सत्र केन्या के नैरोबी में संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु

- UNEA-4 का विषय 'पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत् उपभोग तथा उत्पादन हेतु अभिनव समाधान' (Innovative Solutions for Environmental Challenges and Sustainable Consumption and Production) था।
- सभा के दौरान राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विकास के नए मॉडल की ओर कदम बढ़ाने होंगे।
- सभी राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से 2030 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक उत्पादों जैसे- कप, कटलरी और बैग आदि में कटौती करने पर भी सहमति व्यक्त की।
- इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nation Environment Programme-UNEP) ने वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट का छठा संस्करण भी जारी किया है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (United Nations Environment Assembly-UNEA)

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का प्रशासनिक निकाय है।
- पर्यावरण के संदर्भ में निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है।
- यह दुनिया के सामने आने वाली महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करती है।
- यह पर्यावरणीय सभा वैश्विक पर्यावरण नीतियों हेतु प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून विकसित करने के लिये हर दो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।
- सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन जून 2012 में किया गया। ध्यातव्य है कि सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को RIO+20 या RIO 2012 भी कहा जाता है।

सेप्टिक टैंकों के मानदंड पूरे होंगे

संदर्भ

केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार, सेप्टिक टैंक और एकल गड्ढा (single pits) सुरक्षित स्वच्छता प्रौद्योगिकियाँ हैं जो सतत् विकास लक्ष्यों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं।

नोट :

सर्वेक्षण का परिणाम

- राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARSS) 2018-19 के आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि केवल 26% ग्रामीण जुड़वाँ-लीच गड्ढों (tween-leach pits) और ग्रामीण शौचालयों का उपयोग करते हैं। ग्रामीण शौचालयों के अवशेष (जो दो अंतर्संबंधित गड्ढों का उपयोग नहीं करते हैं) एक नई भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।
- ट्विन पिट का उपयोग न करना स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये हानिकारक हो सकता है और नई पीढ़ी को मैनुअल स्कैवेंजिंग की ओर धकेल सकता है।
- सेप्टिक टैंक सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं जिसमें 28% शौचालय एक सेप्टिक टैंक से जुड़े होते हैं जो सोख गड्ढे (soak pit) के साथ होते हैं तथा 6% टैंक बिना सोख गड्ढे के होते हैं।

केंद्रीय मंत्रालय की प्रतिक्रिया

- मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि सेप्टिक टैंक और एकल गड्ढे सुरक्षित स्वच्छता प्रौद्योगिकियाँ हैं जो सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं।
- ट्विन-लीच पिट शौचालय सबसे किफायती और सुरक्षित स्वच्छता प्रौद्योगिकियों में से एक हैं और इसे व्यापक रूप से अपनाया गया है।
- मंत्रालय ने स्वीकार किया कि देश के सामाजिक स्वरूप तथा जातिगत पूर्वाग्रहों को देखते हुए इस तरह के टैंकों को खाली करने और साफ करने के लिये मैनपावर एक बड़ी चुनौती है।
- मंत्रालय इस तरह की समस्या के तकनीकी और उद्यमशील समाधान तैयार करने पर काम कर रहा है।

राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARSS) 2018-19

- यह सर्वेक्षण विश्व बैंक सहायता परियोजना के तहत एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिये किया गया था।
- ट्विन-पिट और सिंगल-पिट सिस्टम ट्विन पिट फ्लश वॉटर सील टॉयलेट यानी दो गड्ढों और पानी उड़ेलकर मल निस्तारण वाली जल अवरोध प्रणाली पर आधारित शौचालय होता है।
- इन्हें दो गड्ढों वाला इसलिये कहा जाता है क्योंकि इनमें जलमल को इकट्ठा करने के लिये दो गड्ढों की व्यवस्था की जाती है।
- इन दो गड्ढों को बारी-बारी से इस्तेमाल किया जाता है। दोनों गड्ढों को एक ओर जंक्शन चैंबर से जोड़ा जाता है।
- गड्ढे की दीवारों में हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते के आकार में ईंटों से चिनाई की जाती है। गड्ढे के तले पर पलस्तर नहीं किया जाता और तला मिट्टी का बना होता है।
- शौचालय का इस्तेमाल करने वालों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गड्ढे का आकार घटता-बढ़ता है। हर गड्ढे की क्षमता आमतौर पर तीन साल रखी जाती है।
- करीब तीन साल में जब पहला गड्ढा भर जाता है तो जंक्शन चैंबर से उसे बंद कर दिया जाता है और दूसरे गड्ढे को चालू कर दिया जाता है।
- मानव मल का जलीय अंश हनीकॉम्ब ढाँचे से होकर ज़मीन में अवशोषित कर लिया जाता है। दो साल तक बंद रहने के बाद पहले गड्ढे में जमा पदार्थ पूरी तरह सड़कर ठोस, गंधहीन और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त खाद में परिवर्तित हो जाता है।
- इसे खोदकर बाहर निकाल लिया जाता है और कृषि तथा बागवानी में इसका उपयोग किया जाता है।
- जब दूसरा गड्ढा भी भर जाता है तो उसे भी जंक्शन चैंबर से बंद कर दिया जाता है और पहले गड्ढे को चालू कर दिया जाता है। इस तरह दोनों गड्ढों का बारी-बारी से उपयोग किया जाता है।

वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट (Global Energy & CO_2 Status Report) के अनुसार, भारत ने 2018 में 2,299 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, जो पिछले साल की तुलना में 4.8 प्रतिशत अधिक है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस साल भारत की उत्सर्जन वृद्धि दुनिया में दो सबसे बड़े उत्सर्जक देशों- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की तुलना में अधिक थी। इसका मुख्य कारण कोयले की खपत में वृद्धि बताया गया है।
- ऊर्जा मांग में वृद्धि वाले देशों का लगभग 70% योगदान चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का रहा।
- भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग 40% पाया गया जबकि, कार्बन डाइऑक्साइड के कुल वैश्विक उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 7% थी।
- संयुक्त राज्य अमेरिका 14% के योगदान के साथ विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार देश रहा।

भारत के प्रयास

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिये अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार, भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का वादा किया है।
- कार्बन उत्सर्जन कम करने के संदर्भ में ही भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा उपभोग का 40% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है साथ ही 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना सुनिश्चित किया है।
- हालाँकि IEA की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की ऊर्जा तीव्रता में सुधार पिछले साल की तुलना में इस साल 3% कम हुआ है, क्योंकि इसके नवीकरणीय ऊर्जा अधिष्ठापन में पिछले साल से 10.6% की वृद्धि हुई।

वैश्विक संदर्भ में ऊर्जा की आवश्यकता

- 2010 के बाद 2018 में वैश्विक ऊर्जा की खपत में औसत वृद्धि दर लगभग दोगुनी बढ़ गई, जो कि एक मज़बूत वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया के कुछ हिस्सों में उच्च ताप और शीतलन की ज़रूरतों से प्रेरित है।
- विगत वर्षों में सभी गैसों की मांग में वृद्धि हुई। प्राकृतिक गैसों के साथ ही सौर और पवन ऊर्जा ने दोहरे अंक में वृद्धि दर्ज की है।
- ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि के बावजूद ऊर्जा दक्षता के सुधार में कमी देखी गई।
- उच्च ऊर्जा खपत के परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पिछले साल एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए लगभग 1.7% बढ़ा है।
- दुनिया भर में तेल और गैस की मांग में सबसे अधिक वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई गई।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA)

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) एक स्वायत्त संगठन है, जो अपने 30 सदस्य देशों, 8 सहयोगी देशों और अन्य दूसरों के लिये विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करती है।
- इसकी स्थापना (1974 में) 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी जब ओपेक कार्टेल ने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ दुनिया को चौंका दिया था। IEA के मुख्य क्षेत्र हैं-
  - ऊर्जा सुरक्षा
  - आर्थिक विकास
  - पर्यावरण जागरूकता
  - दुनिया भर से इंगेजमेंट
- भारत 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी सदस्य बना।
- इसका मुख्यालय फ्राँस के पेरिस में है।

द्वीपों के लिये नए नियम : IPZ 2019

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार के लिये द्वीप संरक्षण क्षेत्र (Island Protection Zone-IPZ), 2019 को अधिसूचित किया है जो बाराटांग, हैवलॉक और कार निकोबार जैसे छोटे द्वीपों में उच्च टाइड लाइन (High Tide Line-HTL) से 20 मीटर की दूरी तथा 50 मीटर की दूरी पर बड़े इको-पर्यटन परियोजनाओं को अनुमति देने के साथ कई नियमों में छूट प्रदान करता है जिस पर पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं ने चिंता जाहिर की।

नोट :

उद्देश्य

- IPZ में परिवर्तन द्वीपों में समग्र विकास के लिये नीति आयोग के प्रस्ताव के साथ संरेखित किया गया है।
- सरकार की योजना नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और समुद्री संसाधनों का स्थायी दोहन करना है।
- इस प्रस्ताव के पहले चरण में पारिस्थितिक रूप से नाजुक द्वीपों में इको-पर्यटन परियोजनाओं के लिये बांध और अन्य बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है।

IPZ, 2019

- 2011 के IPZ अधिसूचना की तुलना में द्वीपों के विकास मानदंडों में 8 मार्च को प्रकाशित IPZ अधिसूचना छूट प्रदान करती है।
- 2011 की अधिसूचना के अंतर्गत सभी द्वीपों के लिये HTL से 200 मीटर की दूरी पर नो-डेवेलपमेंट ज़ोन (NDZ) निर्धारित किया गया था।
- यह मुख्य भूमि और बैकवाटर द्वीपों के समतुल्य अन्य द्वीपों के लिये तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone-CRZ) मानदंडों के साथ अंडमान और निकोबार के लिये मानदंड निर्धारित करता है जहाँ एक NDZ की दूरी HTL से केवल 20 मीटर होती है।
- केंद्रीय कैबिनेट ने दिसंबर 2018 में CRZ अधिसूचना को मंज़ूरी दी थी जो तटों (coast) पर बुनियादी ढाँचे के विकास और निर्माण की सुविधा के लिये कई प्रावधानों को शिथिल करता है जिसमें तटीय शहरी क्षेत्रों में फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को आसान करना तथा पहले के 200 मीटर की तुलना में HTL से 50 मीटर की दूरी पर घनी आबादी वाले तटीय ग्रामीण क्षेत्रों में NDZ को कम करना शामिल है।
- इसमें केवल पाइप लाइनों, ट्रांसमिशन लाइनों, इको सेंसिटिव ज़ोन में बिछाई जाने वाली ट्रांस-हार्बर लिंक की अनुमति थी।

IPZ 2019 अधिसूचना

- IPZ 2019 की अधिसूचना जो 10 मार्च को आम चुनावों के लिये लागू आदर्श आचार संहिता से एक दिन पहले जारी की गई थी, कई अन्य छूटों के लिये मार्ग प्रशस्त करती है।
- यह द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र IA (द्वीपों के सबसे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें कछुओं के निवास स्थान, दलदली स्थान, प्रवाल भित्तियाँ आदि शामिल हैं) में मैंग्रोव वॉक, ट्री हट्स और नेचर ट्रेल्स जैसे इको-टूरिज्म गतिविधियों के लिये अनुमति देता है।
- अधिसूचना में इको सेंसिटिव ज़ोन में रक्षा प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपयोगिता या रणनीतिक उद्देश्यों से संबंधित असाधारण मामलों में भूमि का पुनर्ग्रहण कर सड़कों के निर्माण की अनुमति दी गई है।
- नई अधिसूचना कम ज्वार रेखा (Low Tide Line) और HTL के बीच अंतर-ज्वारीय क्षेत्र (Inter-Tidal Zone) में कई नई गतिविधियों की भी अनुमति देती है जिसमें शामिल हैं- बंदरगाह, जेटी (Jetties), घाट, क्वाइल, समुद्री लिंक आदि के लिये भूमि की मरम्मत और फोरेशोर (Foreshore) सुविधाओं के लिये बांध का निर्माण।

IPZ 2019 से संबंधित चिंताएँ

- 2011 की अधिसूचना के अंतर्गत अंतर-ज्वारीय क्षेत्र में कुछ गतिविधियों जैसे- मछुआरों के लिये झोपड़ियों का निर्माण और परंपरागत रूप से वहाँ रहने वाले लोगों के लिये आवश्यक अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की अनुमति दी गई थी।
- लेकिन इसमें किया गया संशोधन खतरनाक है। इस नई अधिसूचना से इस क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा जैसे-समुद्री जैव विविधता सहित कोरल और कछुओं के निवास स्थान।

वायनाड में 4 इकोटूरिज़्म (पर्यावरण पर्यटन) केंद्र बंद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, वायनाड ज़िले में दक्षिण वायनाड वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले चार प्रमुख इकोटूरिज़्म (पर्यावरण पर्यटन) केंद्रों में पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अदालत ने 21 मार्च को एक पर्यावरण संगठन 'वायनाड प्रकृति संरक्षा समिति' द्वारा दायर याचिका पर वन प्रभाग में सभी ईकोटूरिज़्म गतिविधियों पर अंतरिम रोक जारी की।
- अदालत के निर्देशानुसार बंद किये गए प्रमुख इकोटूरिज़्म पर्यटन केंद्र निम्नलिखित है:
  1. मेप्पदी वन श्रेणी के अंतर्गत सोचीपारा जलप्रपात
  2. चेथलायथ वन रेंज के अंतर्गत कबानी पर कुरुवा द्वीप
  3. मेप्पदी वन रेंज के अंतर्गत चेम्बरा शिखर
  4. कालपेट्टा वन रेंज के तहत पदिन्हारेथरा (Padinharethara) में मीनमुट्टी जलप्रपात
- सोचीपारा जलप्रपात और कुरुवा द्वीपों में पर्यटकों के प्रवेश को हाल ही में बंद किया गया, जबकि चेम्बरा शिखर और मीनमुट्टी जलप्रपात को जनवरी 2019 के मध्य से ही जंगल की आग के जोखिम के कारण बंद किया गया था।

केरल में पर्यटन

- केरल प्रांत पर्यटन के लिये बहुत लोकप्रिय स्थान है, इसीलिये इसे 'God's Own Country' अर्थात् 'ईश्वर का अपना घर' नाम से पुकारा जाता है।
- यहाँ अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रमुख हैं - पर्वतीय तराई क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र, वन क्षेत्र, तीर्थाटन केंद्र आदि। इन स्थानों पर देश-विदेश से असंख्य पर्यटक भ्रमणार्थ आते हैं।
- पर्वतीय क्षेत्र, समुद्री तट, वन्य पशु केंद्र, कोल्लम, झीलें, जलप्रपात, पर्वत शिखर आदि पर्यटकों के लिये विशेष आकर्षण के केंद्र हैं।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) का पर्यटन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- राज्य की अर्थव्यवस्था में भी पर्यटन क्षेत्र का प्रमुख योगदान है।

पर्यटन क्षेत्र में विकास

- पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिये केरल राज्य सरकार का पर्यटन विभाग अत्यधिक सक्रिय है।
- विभाग द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिये प्रचार-प्रसार, बुनियादी सुविधाओं का विकास आदि कार्य किये जाते हैं।
- राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिये आवश्यक प्राकृतिक संतुलन तथा सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए 'दायित्वपूर्ण पर्यटन विकास' की नीति अपनाई गई है।

उपलब्धियाँ

- पर्यटन क्षेत्र में केरल की उपलब्धियाँ काफी प्रशंसनीय रही हैं।
- इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के कारण राज्य को अनेक राष्ट्रीय - अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।
- पिछले दस वर्षों में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन तथा अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्ति और पर्यटन विकास में केरल का स्थान सर्वोपरि रहा।

इकोटूरिज़्म

- पर्यावरण पर्यटन का अर्थ है वातावरण की दृष्टि से धारणीय पर्यटन जिसमें प्रमुख रूप से उन प्राकृतिक क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो पर्यावरणीय और सांस्कृतिक समझ-बूझ, मूल्यांकन और संरक्षण को बढ़ावा देते हैं।
- पर्यावरण पर्यटन का आशय यह है कि पर्यटन का प्रबंधन तथा प्रकृति का संरक्षण इस तरीके से किया जाए ताकि पर्यटन व पारिस्थितिकी के साथ-साथ रोज़गार की भी पूर्ति होती रहे।

नोट :

जलवायु की वैश्विक स्थिति: WMO

चर्चा में क्यों ?

हाल में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation- WMO) द्वारा जलवायु और सतत् विकास पर एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान वैश्विक जलवायु के संदर्भ में बयान जारी किया गया।

- इसके अनुसार, साल 2018 में समुद्र के जल स्तर में तीव्र गति से वृद्धि होना दर्शाया गया है। समुद्र में अम्लीयता बरकरार रहने के परिणाम स्वरूप यह समुद्री जैव-विविधता के लिए खतरा बना रहा।

प्रमुख बिंदु

- पिछले चार वर्षों में समुद्र के स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ अम्लीकरण अधिक पाया गया। स्थल एवं समुद्र के तापमान में वृद्धि मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन का परिणाम है।
- पहली बार 1994 में प्रकाशित विवरण में CO_2 का स्तर 357 पीपीएम था, जबकि 2017 में यह 405.5 पीपीएम तक पहुँच गया और निरंतर बढ़ता जा रहा है।
- WMO के अनुसार, 2018 और 2019 के दौरान ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता और अधिक बढ़ने की उम्मीद है।
- नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (National Oceanic and Atmospheric Administration) से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ओशिनिया और दक्षिण अमेरिका में वर्ष 2018 को 10 वर्षों में सबसे गर्म वर्ष का दर्जा दिया गया।
- वैश्विक स्तर पर कई प्रमुख जलवायु संकेतक जैसे- समुद्र के स्तर में वृद्धि और ग्लेशियर के नुकसान ने खतरनाक जलवायु परिवर्तन प्रभाव की एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित की है।
- 2018 में समुद्र की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म पाया गया, जिसमें प्रशांत क्षेत्र भी शामिल था।

प्रभाव

- समुद्र में अम्लीकरण बढ़ने के कारण समुद्री जैव विविधता पर गंभीर ख़तरा उत्पन्न हो जाता है।
- समुद्र में BOD (Biochemical Oxygen Demand) बढ़ रही है साथ ही कम ऑक्सीजन सांद्रता वाले क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है।
- 2018 में वैश्विक औसत समुद्री स्तर 2017 की तुलना में लगभग 3.7 मिमी. की वृद्धि पाई गई।
- वैश्विक रूप से समुद्रन स्तर की वृद्धि का मुख्य कारण बर्फ की चादरों का तेज़ी से पिघलना है।
- यद्यपि 2018 की शुरुआत में कमज़ोर ला-नीना की स्थिति देखी गई थी, वर्षा पर इसका प्रभाव अपेक्षित अनुमानों के विपरीत था। उदाहरण के लिये कैलिफोर्निया में ला-नीना के दौरान एक अप्रत्याशित घटना हुई जिससे कई जगहों पर बाढ़ आ गई।

भारत के संदर्भ में

- WMO ने 2018 में दुनिया भर के मौसम की विषम घटनाओं को भी रेखांकित किया जिसमें अगस्त 2018 में आई केरल की गंभीर बाढ़ भी शामिल है, इसके कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ था।
- साथ-ही-साथ 2018 में भारत में शीत लहर का भी जिक्र किया गया है कि कैसे देश में सर्दी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई।
- भारतीय मानसून ने पश्चिमी घाटों और हिमालय के पूर्वी भागों में सामान्य से कम वर्षा की लेकिन पश्चिमी हिमालय में वर्षा सामान्य से अधिक पाई गई।
- जून से सितंबर 2018 तक अखिल भारतीय स्तर पर वर्षा दीर्घकालिक औसत से लगभग 9% कम थी।

2018: चौथा सबसे गर्म वर्ष

- संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब तक के दर्ज रिकार्ड में वर्ष 2018 चौथा सबसे गर्म साल था।

नोट :

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization-WMO) के अनुसार, 2018 में औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1°C (1.8 ° F) ऊपर था।
- 2016 सबसे गर्म वर्ष बना हुआ है जिसकी वजह अल-नीनो थी।
- WMO का कहना है कि इतिहास के 20 सबसे गर्म साल पिछले 22 वर्षों के भीतर रहे हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 23 मार्च, 1950 को मौसम विज्ञान संगठन अभिसमय के अनुमोदन द्वारा स्थापित किया गया है।
- यह पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और व्यवहार, महासागरों के साथ इसके संबंध, मौसम और परिणामस्वरूप उपलब्ध जल संसाधनों के वितरण के बारे में जानकारी देने के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) की आधिकारिक संस्था है।
- 191 सदस्यों वाले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा (Geneva) में है।
- उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

नई पनबिजली नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई पनबिजली नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है, जिसमें बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के अंतर्गत नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा क्रय बाध्यता (Renewable Purchase Obligation-RPO) की घोषणा भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- नई नीति के अनुसार, बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को भी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के रूप में नामित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक केवल 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली छोटी परियोजनाओं को ही अक्षय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।
- इन उपायों की अधिसूचना के बाद शुरू की गई बड़ी पनबिजली योजनाओं में गैर-सोलर अक्षय ऊर्जा क्रय बाध्यता के तहत पनबिजली योजनाएँ शामिल होंगी (लघु पनबिजली परियोजनाएँ पहले से ही इनमें शामिल हैं)।
- पनबिजली क्षेत्र में अतिरिक्त परियोजना क्षमता के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के वार्षिक लक्ष्यों के बारे में अधिसूचित किया जाएगा।
- बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के संचालन के लिये शुल्क नीति और शुल्क नियमन में आवश्यक संसोधन किये जाएंगे।
- परियोजना काल को 40 वर्ष तक बढ़ाने के बाद शुल्ककी बैक लोडिंग द्वारा शुल्क निर्धारित करने के लिये डेवलपरों को लचीलापन प्रदान करने, ऋण भुगतान की अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाने और 2 प्रतिशत शुल्क बढ़ाने सहित शुल्क को युक्तिसंगत बनाना।
- मामले के आधार पर पनबिजली परियोजनाओं में फ्लड मोडरेशन घटक वित्तपोषण के आधार पर बजटीय सहायता प्रदान करना।
- सड़कों और पुलों जैसी आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के मामले में आर्थिक लागत पूरी करने के लिये बजटीय सहायता देना। मामले के आधार पर यह वास्तविक लागत प्रति मेगावाट 1.5 करोड़ रूपए की दर से अधितकम 200 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं और प्रति मेगावाट 1.0 करोड़ रूपए की दर से 200 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं के लिये हो सकती है।

प्रमुख प्रभाव

- अधिकांश पनबिजली परियोजनाएँ हिमालय की ऊँचाई वाले और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं, इससे विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोज़गार मिलने से इस क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।
- इससे परिवहन, पर्यटन और अन्य छोटे कारोबारी क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोज़गार/उद्यमिता के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
- इसका एक अन्य लाभ यह होगा कि सौर और पवन जैसे ऊर्जा स्रोतों से वर्ष 2022 तक लगभग 160 गीगावॉट क्षमता का एक स्थायी ग्रिड उपलब्ध हो जाएगा।

पृष्ठभूमि

- भारत में लगभग 1,45,320 मेगावाट पनबिजली क्षमता की संभावना है, लेकिन अब तक लगभग 45,400 मेगावाट का ही इस्तेमाल हो रहा है।
- पिछले 10 वर्षों में पनबिजली क्षमता में केवल लगभग 10,000 मेगावाट की वृद्धि की गई है। फिलहाल पनबिजली क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण चरण से गुज़र रहा है और कुल क्षमता में पनबिजली की हिस्सेदारी वर्ष 1960 के 50.36 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में लगभग 13 प्रतिशत रह गई है।

नोट :

चक्रवात ईदाई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मोज़ांबिक में आए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ईदाई में सबसे ज़्यादा प्रभावित बीरा नामक शहर रहा।

प्रमुख बिंदु

- इस चक्रवात से सोफाला प्रांत में सबसे अधिक नुकसान हुआ है।
- अधिकांश क्षति बीरा शहर में हुई जो देश का चौथा सबसे बड़ा शहर है, साथ ही एक बंदरगाह हब और सोफाला प्रांत की राजधानी है।

ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी Global Facility for Disaster Reduction and Recovery-GFDRR

- GFDRR, विकासशील देशों को प्राकृतिक खतरों और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी भेद्यता को बेहतर ढंग से समझने और कम करने में मदद हेतु एक वैश्विक साझेदारी है।
- इसकी स्थापना सितंबर 2006 में की गई थी।
- यह विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित अनुदान प्रक्रिया है, जो दुनिया भर में आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं का समर्थन करती है।
- 400 से अधिक स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम करते हुए GFDRR ज्ञान, वित्तपोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

उद्देश्य

- देश की विकास रणनीति के तहत मुख्यत: आपदाओं में कमी लाना और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) तथा आपदा न्यूनीकरण (ISDR) प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के तहत विभिन्न हितधारकों के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना।
- यह आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को विकास की रणनीतिय और निवेश कार्यक्रमों में एकीकृत कर आपदाओं से जल्दी और प्रभावी ढंग से उबरने में देशों की मदद करने हेतु जीएफडीआरआर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में योगदान देता है।

चक्रवात

- चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज़ आँधी को कहा जाता है।
- दोनों गोलार्द्धों के चक्रवाती तूफानों में अंतर यह है कि उत्तरी गोलार्द्ध में ये चक्रवात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में (Counter-Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा (Clockwise) में चलते हैं।
- उत्तरी गोलार्द्ध में इसे हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है।

बंगाल डेल्टा में प्रवास

हाल ही में 'डेल्टाज, वल्नरेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज: माइग्रेशन एंड अडेप्टेशन' (Deltas, Vulnerability and Climate Change: Migration and Adaptation (DECMA) नामक शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन प्रकाशित हुआ।

- अध्ययन में पाया गया कि आर्थिक कारण भारत के बंगाल डेल्टा में होने वाले प्रवासन का प्रमुख कारक हैं और अधिकांश प्रवासी 20-30 वर्ष की आयु वर्ग के हैं।
- वर्ष 2014 और 2018 के बीच तीन डेल्टाओं गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा (भारत और बांग्लादेश) वोल्टा (घाना) और महानदी (भारत) पर केंद्रित इस अध्ययन में डेल्टाओं में जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और प्रवासन के पहलूओं पर प्रकाश डाला गया है।

नोट :

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

डेल्टाओं में प्रवासन के कारण

- अध्ययन जिसमें दक्षिण और उत्तर 24 परगना ज़िले को कवर किया गया है, के अनुसार 64% लोग आर्थिक कारणों से प्रवासन करते हैं जिसमें अस्थिर कृषि, आर्थिक अवसरों की कमी और कर्ज़ जैसे कारण शामिल हैं।
- इस क्षेत्र से होने वाले प्रवासन में 28% प्रवासन सामाजिक कारणों से होता है जबकि लगभग 7% प्रवासन के लिये चक्रवात और बाढ़ जैसे पर्यावरणीय कारक ज़िम्मेदार हैं।

प्रवासन में लैंगिक असमानता

- अध्ययन में पाया गया कि भारतीय बंगाल डेल्टा से बाहर प्रवासन में लैंगिक असमानता का स्तर व्यापक है, जिसमें प्रवासन करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का लगभग पाँच गुना है।
- अध्ययन में दर्शाया गया है कि पलायन करने वाले लोगों में 83% पुरुष हैं और केवल 17% महिलाएँ शामिल हैं।
- एक ओर जहाँ अधिकांश पुरुष आर्थिक कारणों से पलायन करते हैं वहीं महिलाएँ सामाजिक कारकों से प्रेरित होकर ऐसा करती हैं।

प्रवासन के बाद गंतव्य स्थल

- प्रवास के बाद गंतव्य स्थान के संदर्भ में, अध्ययन में पाया गया है कि भारतीय बंगाल डेल्टा से प्रवास करने वाले 51% लोग राज्य के अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से कोलकाता शहर तथा 10% लोग महाराष्ट्र, 9% तमिलनाडु, 7% केरल और 6% गुजरात की ओर प्रवास करते हैं।

डेल्टा में प्रवासन का प्रकार

- प्रवास का 57% मौसमी है, जिसमें लोग वर्ष में एक या दो बार प्रवास करते हैं।
- 19% प्रवासन सर्कुलर है, जिसमें पलायन करने वाले लोग साल में तीन बार प्रवास करते हैं, भले ही इसके कारण कुछ भी हों।
- 24% प्रवासन स्थायी है, जिसमें लोग उस स्थान पर कम-से-कम छह महीने तक रहने का इरादा रखते हैं, जहाँ वे प्रवास कर रहे हैं।

प्रवासन क्या है ?

प्रवासन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की आवाजाही है। यह एक छोटी या लंबी दूरी के लिये, अल्पकालिक या स्थायी, स्वैच्छिक या मज़बूर, अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है।

प्रवासन के कारक

- **प्रतिकर्ष कारक (Push Factor)**

बेरोज़गारी, रहन-सहन की निम्न दशाएँ, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएँ, महामारियाँ तथा सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं।

- **अपकर्ष कारक (Pull Factor)**

काम के बेहतर अवसर और रहन-सहन की अच्छी दशाएँ, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं।

प्रवासन के कारण

आर्थिक कारक

- **प्रतिकर्ष कारक**

1. बेरोज़गारी या रोज़गार के अवसरों की कमी
2. ग्रामीण गरीबी
3. अस्थायी आजीविका

नोट :

- **अपकर्ष कारक**
  1. रोज़गार के अवसर
  2. धन सृजन के लिये बेहतर आय और संभावनाएँ
  3. एक नए उद्योग के लिये औद्योगिक नवाचार और तकनीकी जानकारी
  4. विशिष्ट शिक्षा की खोज

सामाजिक-राजनीतिक कारक

- **प्रतिकर्ष कारक**
  1. राजनैतिक अस्थिरता
  2. सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ (जातीय, धार्मिक, नस्लीय या सांस्कृतिक उत्पीड़न)
  3. संघर्ष या संघर्ष का खतरा
  4. अपर्याप्त या सीमित शहरी सेवाएँ और बुनियादी ढाँचा (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संसाधन, परिवहन और पानी सहित)
- **अपकर्ष कारक**
  1. परिवार का पुनर्मिलन
  2. स्वावलंबन और स्वतंत्रता
  3. एकीकरण और सामाजिक सामंजस्य
  4. खाद्य सुरक्षा
  5. सस्ती और सुलभ शहरी सेवाएँ (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संसाधन और परिवहन सहित)

पारिस्थितिकीय कारक

- **प्रतिकर्ष कारक**
  1. जलवायु परिवर्तन (चरम मौसम की घटनाओं सहित)
  2. फसल की विफलता और भोजन की कमी
- **अपकर्ष कारक**
  1. प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों की प्रचुरता (जैसे पानी, तेल)
  2. अनुकूल जलवायु

सोलर सुनामी कर सकता है सनस्पॉट साइकिल को सक्रिय

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिकों ने पाया है कि सूर्य के 11 साल के चक्र को सक्रिय करने के लिये सौर सुनामी ज़िम्मेदार है। यह माना जाता है कि 'सोलर डायनमो' सनस्पॉट की उत्पत्ति से संबद्ध है।

सोलर डायनमो

- सोलर डायनमो एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जेनरेटर है जो सूर्य में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।

सन स्पॉट

- सन स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सूर्य की सतह पर काले दिखाई देते हैं। वे गहरे (dark) इसलिये दिखाई देते हैं क्योंकि वे सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं।
- सन स्पॉट का तापमान अभी भी लगभग 6,500 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है।
- सन स्पॉट अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। यह इसलिये है क्योंकि वे उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से मज़बूत होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र इतने मज़बूत होते हैं कि सूर्य के भीतर की कुछ ऊष्मा को सतह तक पहुँचने से रोकते हैं।
- सूर्य की सतह तक उठने वाले चुंबकीय प्रवाह की मात्रा सौर चक्र में समय के साथ बदलती रहती है। यह चक्र औसतन 11 साल तक चलता है। इस चक्र को कभी-कभी सन स्पॉट चक्र भी कहा जाता है।

नोट :

सौर सुनामी

- सौर सुनामी चुंबकीय क्षेत्र की तरंगें हैं और सूर्य से लगभग 400 किमी. प्रति सेकंड की गति से गर्म, आयनीकृत गैस के रूप में गति करती हैं।
- एक कोरोनल मास इजेक्शन (Cronal Mass Ejection-CME) नामक पदार्थ के अंतरिक्ष में उत्पन्न होने के बाद सुनामी उत्पन्न होती है।
- सोलर सुनामी की खोज 1997 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी (Europen Space Agency) के SOHO (सोलर एंड हेलिओस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी) द्वारा की गई थी।

कोरोनल मास इजेक्शन

- कोरोनल मास इजेक्शन (CME) प्लाज्मा और सौर कोरोना से चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक महत्त्वपूर्ण रिलीज़ होता है। इसमें अक्सर सौर चमक (Solar Flare) होती है।
- पृथ्वी में पहुँचने पर सौर फ़्लेयर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रतिक्रिया कर भव्य प्रकाश दिखाई देने का कारण बनता है जिसे ऑरोरा (Aurora) कहा जाता है।
- सोलर फ्लेयर्स रेडियो प्रसारण को भी बाधित कर सकते हैं और उपग्रहों को कक्षा में नुकसान पहुँचा सकते हैं।

सोलर सुनामी सन स्पॉट की ओर कैसे बढ़ती है ?

- चरम तापमान और दाब की स्थिति जो सूर्य की सतह से लगभग 20,000 किमी. नीचे रहती है, के कारण एक प्लाज्मा का निर्माण होता है जिसमें अत्यधिक आयनीकृत अवस्था में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं।
- प्लाज्मा सूर्य के अंदर विशाल चुंबकीय क्षेत्रों में सीमित होता है। इन्हें अपने स्थान पर बने रहने के लिये यह आवश्यक है कि अतिरिक्त अक्षांश से बैंड पर धकेलने वाला अतिरिक्त द्रव्यमान (प्लाज्मा द्रव्यमान) मौजूद हो।
- इस प्रकार एक चुंबकीय बांध बनता है जो प्लाज्मा के एक बड़े द्रव्यमान का भंडारण करता है। एक सौर चक्र के अंत में यह चुंबकीय बांध टूट सकता है तथा ध्रुवों की ओर सुनामी की तरह भारी मात्रा में प्लाज्मा उत्पन्न होता है।
- ये सुनामी जैसी लहरें लगभग 1,000 किमी. प्रति घंटे की उच्च गति से चलती हैं, जो अतिरिक्त प्लाज्मा को मध्य अक्षांशों तक ले जाती हैं।
- वहाँ वे चुंबकीय प्रवाह के विस्फोट को जन्म देती हैं। इन्हें चमकीले पैच के रूप में देखा जाता है जो सन स्पॉट के अगले चक्र की शुरुआत का संकेतक होता है।

सुपर वोर्म एक्वीनोक्स मून

चर्चा में क्यों ?

इस वर्ष का अंतिम सुपर मून वसंत विषुव के साथ ही घटित हुआ है। इस घटना को सामान्यत: 'सुपर वोर्म एक्वीनोक्स मून' (Super Worm Equinox Moon) के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष मार्च की पूर्णिमा को तीसरे सुपरमून की परिघटना घटित हुई। यह 21 जनवरी को सुपर ब्लड वुल्फ मून (Super Blood Wolf Moon) और 19 फरवरी को सुपर स्नो मून (Super Snow Moon) के बाद घटित हुआ है।
- मार्च की पूर्णिमा को विश्व के कुछ भागों में कृमि चंद्रमा (Worm Moon) के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ठंडी जलवायु वाले प्रदेश में इसके पश्चात् जमीन गर्म होने लगती है और केंचुए दिखने लगते हैं।

सुपर मून क्या है ?

- जब चंद्रमा पृथ्वी के अपने निकटतम बिंदु पर होता है, तो इसे 'उपभू' (Perigee) कहा जाता है और जब एक पूर्ण चंद्रमा एक उपभू के साथ होता है तब इसे 'सुपर मून' कहा जाता है।
- विषुव वह परिघटना है, जब दिन और रात की अवधि समान हो जाती है और सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं।
- यह घटना एक वर्ष में दो बार होती है- प्रथम सितंबर में 'शरद विषुव' और दूसरी मार्च में 'वसंत विषुव' के रूप में।

नोट :

अन्य बिंदु

अर्थस्काई के अनुसार इससे पूर्व सुपर वोर्म मून की घटना वर्ष 2000 में हुई थी। अगली सुपर वार्म मून घटना र्ष 2030 में होगी।

अल-नीनो के लिये पूर्वानुमान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी मौसम एजेंसियों द्वारा जारी किये गए पूर्वानुमान के अनुसार, गर्मियों में अल-नीनो की अधिक संभावना जताई गई है। यदि यह अनुमान सही होता है तो भारत में बारिश का मौसम प्रभावित हो सकता है।

- उल्लेखनीय है कि विभिन्न मौसम एजेंसियों द्वारा फरवरी में प्रशांत महासागर में एक कमज़ोर अल नीनो के स्थापित होने की घोषणा की गई थी लेकिन, अब अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मौसम एजेंसियों द्वारा यह भविष्यवाणी की गई है कि अल-नीनो की स्थिति अगले कुछ महीनों तक बनी रहेगी।

अल-नीनो (El-Nino)

- प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल-नीनो कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय देश पेरू एवं इक्वाडोर के समुद्री मछुआरों द्वारा प्रतिवर्ष क्रिसमस के आस-पास प्रशांत महासागरीय धारा के तापमान में होने वाली वृद्धि को अल-नीनो कहा जाता था।
- वर्तमान में इस शब्द का इस्तेमाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही तापमान में कुछ अंतराल पर असामान्य रूप से होने वाली वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप होने वाले विश्वव्यापी प्रभाव के लिये किया जाता है।
- ला-नीना (La-Nina) भी मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है। यह घटना सामान्यत: अल-नीनो के बाद होती है। उल्लेखनीय है कि अल-नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ला-नीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है।

अल-नीनो से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र

- सामान्यत: प्रशांत महासागर का सबसे गर्म हिस्सा भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वहाँ उपस्थित हवाएँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये हवाएँ गर्म जल को पश्चिम की ओर अर्थात् इंडोनेशिया की ओर धकेलती हैं।
- वैसे तो अल-नीनो की घटना भूमध्य रेखा के आस-पास प्रशांत क्षेत्र में घटित होती है लेकिन हमारी पृथ्वी के सभी जलवायु-चक्रों पर इसका असर पड़ता है।
- लगभग 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के आस-पास इंडोनेशियाई क्षेत्र से लेकर 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मेक्सिको की खाड़ी और दक्षिण अमेरिकी पेरू तट तक का समूचा उष्ण क्षेत्रीय प्रशांत महासागर अल-नीनो के प्रभाव क्षेत्र में आता है।

अल-नीनो का प्रभाव

- अल-नीनो के प्रभाव से प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है, इससे हवाओं के रास्ते और रफ्तार में परिवर्तन आ जाता है जिसके चलते मौसम चक्र बुरी तरह से प्रभावित होता है।
- मौसम में बदलाव के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कई जगहों पर बाढ़ आती है। इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है।
- जिस वर्ष अल-नीनो की सक्रियता बढ़ती है, उस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून पर उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। इससे पृथ्वी के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति भी सामने आती है।
- भारत भर में अल-नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि ला-नीना के कारण अत्यधिक बारिश होती है।

नोट :

सामाजिक मुद्दे

पोषण पखवाड़ा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में 8 से 22 मार्च, 2019 तक 'पोषण पखवाड़ा' मनाए जाने की घोषणा की है। जिसकी शुरुआत 8 मार्च, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- 8 मार्च, 2019 को पोषण अभियान की पहली वर्षगाँठ के मद्देनजर देश भर में इस पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। और इसे जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा।
- इसका आयोजन सितंबर 2018 में आयोजित किये गए पोषण माह की तर्ज़ पर किया जा रहा है।
- इसकी गतिविधियों के समन्वय के लिये महिला और बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय का कार्य करेगा, इसी तरह राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के महिला और बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया जाएगा।

प्रमुख गतिविधियाँ

- महिला और बाल विकास मंत्री ने इस पखवाड़े के दौरान आयोजित किये जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि इससे देश भर में पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये अभियान चलाया जाएगा और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा।
- इन गतिविधियों में पोषण मेला (Poshan Mela), सभी स्तरों पर पोषाहार रैली, प्रभात फेरी (Prabhat Pheree), स्कूलों में पोषाहार विषय पर सत्र का आयोजन, स्वयं सहायता समूहों की बैठकें, एनीमिया शिविर, बाल विकास निगरानी, आशा/आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नवजात शिशुओं के घर जाकर पोषण के लिये जागरूक करना, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषाहार दिवस शामिल है।
- इस पखवाड़े के दौरान मास मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से गतिविधियाँ भी चलाई जाएंगी। लोगों की अधिकतम पहुँच के लिये मीडिया सहयोगियों तथा स्वस्थ भारत प्रेरकों के दलों के माध्यम से एक सोशल मीडिया अभियान हैशटैग #पोषण_पखवाड़ा चलाया जाएगा।
- पोषण पखवाड़े के दौरान शहरी क्षेत्र में पोषाहार पर जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

पृष्ठभूमि

- 8 मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुनू से एक असाधारण पहल राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission-NNM) का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया था।
- भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिये 9046.17 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी।

रणनीति एवं लक्ष्य

- NNM एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन का काम करेना।
- इसका लक्ष्य ठिगनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) तथा जन्म के वक्त बच्चों में कम वज़न की समस्या में प्रतिवर्ष क्रमश: 2%, 2%, 3% तथा 2% की कमी लाना था।

नोट :

DEPwD को मिला सातवाँ गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारता विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities-DEPwD) द्वारा गुजरात के भरूच जिले में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme-DDRS) पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सचिव, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा देश भर से लगभग 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- सम्मेलन का मुख्या उद्देश्य योजना के साझेदारों (Stakeholders) अर्थात् कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (Programme Implementing Agencies-PIAs), ज़िला स्तर के अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना था।
- इससे पहले DEPwD ने 22 दिसंबर, 2018 को सिकंदराबाद में, 17 जनवरी, 2019 को मुंबई में तथा 18 फरवरी 2019 को कोलकाता में देश के दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को कवर करते हुए तीन क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किये।
- हाल में DEPwD ने गुजरात के भरूच ज़िले में आठ घंटों के भीतर 260 दिव्यांगजनों में मॉडर्न आर्टिफिशियल लिम्ब्स (Legs) एक साथ प्रतिस्थापित कर '7वाँ गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। DEPwD द्वारा किया दिव्यांगजनों के लिये किया गया यह कार्य अत्यंत सराहनीय है।
- DEPwD ने पहले भी अन्य श्रेणियों में छह विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं।

DEPwD की उपलब्धियाँ

DEPwD के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (Indian Sign Language Research and Training Centre-ISLRTC) ने हाल ही में एक निर्देशिका तैयार की है जिसमें श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिये 6000 शब्द उपलब्ध हैं साथ ही 1700 से अधिक दृष्टिबाधित बच्चों का इलाज कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी (Cochlear Implant Surgery) द्वारा किया गया है, इनमें से लगभग सभी अब सामान्य जीवन जी रहे हैं।

कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी Cochlear Implant Surgery

इसमें एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कान के पास कर्णावर्त तंत्रिका को उत्तेजित करने के लिये लगाया जाता है। यह उपकरण ध्वनि को संप्रेषित करके आंतरिक भाग तक पहुँचाता है।

- DEPwD ने दिव्यांगजनों को उनके सुगम आवागमन के लिये इंजन चालित ट्राइसाइकिल (Motorized Tricycles) प्रदान की है इस कार्य में परिवहन विभाग उनकी मदद कर रहा है।

पृष्ठभूमि

- अब तक 28 राज्यों ने लगभग 13 लाख दिव्यांगजनों को यूनिवर्सल आईडी कार्ड प्रदान किया है, बहुत जल्द यह आईडी कार्ड देश के सभी दिव्यांगजनों को दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। जो कि नई पहलों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
- यद्यपि DDRS योजना 1999 से ही अस्तित्व में थी, फिर भी 1 अप्रैल, 2018 में इसके प्रावधानों में एक बड़ा सुधार किया गया।
- इसके पुनरुद्धार एवं अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये इस योजना को संशोधित किया गया है।
- योजना में किये गए सुधारों में 2.5 गुना मानदेय, अन्य लागत मानदंडों में वृद्धि, आवेदन की प्रक्रिया को सुव्यस्थित करना तथा कुछ मॉडल परियोजनाओं को तर्क संगत बनाना आदि शामिल है।

नोट :

मॉडल परियोजनाओं

प्री-स्कूल, प्रारंभिक हस्तक्षेप एवं प्रशिक्षण (Pre-Schools, Early Intervention and Training)

- बच्चों के लिये विशेष स्कूलों के साथ (Special Schools for Children with) -
  - बौद्धिक विकलांग (Intellectual Disabilities)
  - सुनने और बोलने की विकलांगता (Hearing and Speech Disabilities)
  - दृश्य विकलांगता (Visual Disabilities)
- बच्चों के लिये सेरेब्रल पल्सिड प्रोजेक्ट (Project for Cerebral Palsied children)
- कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास (Rehabilitation of Leprosy Cured Persons)
- मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के इलाज और नियंत्रण के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक पुनर्वास के लिये हॉफ वे होम (Half Way Home for psycho-Social Rehabilitation of treated and controlled Mentally ill persons)
- घर आधारित पुनर्वास (Home Based Rehabilitation)
- समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम (Community Based Rehabilitation Programme-CBR)
- लो विजन सेंटर (Low Vision Centres and)
- मानव संसाधन विकास (Human Resource Development)

भारत, अवैध दवा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पूरे दक्षिणी एशिया में इंटरनेट के माध्यम से विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर डार्कनेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर दवाओं की खरीद की वैश्विक प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ रही है।

- अवैध दवाओं का यह कारोबार अन्य देशों की अपेक्षा भारत में ज़्यादा तेज़ी से फैला है।

प्रमुख बिंदु

- भारत अवैध दवा व्यापार के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसमें पुरानी कैनबिस (Cannabis) से लेकर ट्रामाडोल (Tramadol) जैसी नई दवाओं और मेथमफेटामाइन (Methamphetamine) जैसी अवैध दवाइयाँ शामिल हैं।
- एक अध्ययन के अनुसार, कुछ ऐसे ऑनलाइन विक्रेताओं की पहचान की गई है जो दक्षिण एशिया में डार्कनेट के माध्यम से दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। साथ ही 50 ऑनलाइन क्रिप्टो-मार्केट प्लेटफॉर्म पर भारत के 1,000 से अधिक दवा कारोबारियों की भी पहचान की गई है।
- UNODC देशों के इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में भारत में अधिकारियों ने दो अवैध इंटरनेट फार्मेसियों को बंद कर दिया और कई लोगों को इस प्रक्रिया में गिरफ्तार भी किया गया था।

अवैध मार्ग

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत अवैध रूप से उत्पादित अफीम, विशेष रूप से हेरोइन के लिये भी एक पारगमन देश है। जिसके माध्यम से अवैध दवाओं का कारोबार किया जाता है।
- तस्करों द्वारा दक्षिण एशिया के रास्ते तस्करी के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला मार्ग जिसे 'दक्षिणी मार्ग' के नाम से भी जाना जाता है का एक वैकल्पिक हिस्सा भारत में है, जिसका प्रयोग पाकिस्तान या इस्लामी गणतंत्र ईरान जैसे खाड़ी देशों के माध्यम से पूर्वी अफ्रीका और गंतव्य देशों तक तस्करी के लिये किया जाता है।
- पिछले साल अगस्त में राजस्व खुफिया निदेशालय और भारतीय सेना के एक संयुक्त अभियान में नियंत्रण रेखा (Line of Control) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की गई थी।

नोट :

चिंताजनक आँकड़े

- रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में मॉर्फिन युक्त अफीम के कच्चे माल के वैश्विक उत्पादन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस और तुर्की की संयुक्त रूप से 83 प्रतिशत भागीदारी थी।
- भारत ने मॉर्फिन सहित सभी रूपों में 66 टन अफीम का उत्पादन किया।
- INCB के अनुमानों के अनुसार, चिंताजनक बात यह है कि उपलब्ध मॉर्फिन के केवल 10 प्रतिशत हिस्से का ही उपयोग दर्द प्रबंधन के लिये किया गया था और लगभग 88 प्रतिशत तक कोडीन (Codeine) में परिवर्तित कर दिया गया जिसका उपयोग खांसी की दवा बनाने के लिये किया जाता है।
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (AIIMS) के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के अनुसार, भारत अफीम का उत्पादन करने वाले शीर्ष देशों में से एक है जो रोगियों के दर्द प्रबंधन के लिये इन पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर सकता है।

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC)

- UNODP संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक कार्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम (UNDCP) और संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग (Crime Prevention and Criminal Justice Division) के संयोजन द्वारा की गई थी।
- उस समय इसकी स्थापना दवा नियंत्रण और अपराध निवारण कार्यालय (Office for Drug Control and Crime Prevention) के रूप में की गई थी। वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) किया गया।
- इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।
- वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट (World Drug Report) इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट है।

कार्य आधारित लैंगिक अंतराल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत और चीन में महिलाओं की रोजगार दर में पुरुषों की तुलना में अधिक तेज़ी से गिरावट आई है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation- ILO) ने हाल ही में एक रिपोर्ट, 'अ क्वांटम लीप फॉर जेंडर इक्वलिटी: फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ़ वर्क फॉर आल (A Quantum leap for gender equality: For a better future of work for all)' जारी किया।
- यह रिपोर्ट ILO की पहल "वूमन एट वर्क सेंटेनरी (Women at Work Centenary)" के पाँच साल के अवलोकन पर आधारित है।

इस रिपोर्ट के अनुसार

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं, भारत और चीन, में बेहतर शिक्षा, जागरूकता के बावजूद महिलाओं की रोज़गार दर पुरुषों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से गिरती हुई दिखती है।
- जनसांख्यिकी के अलावा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का औद्योगिक अर्थव्यवस्था में तेज़ी से रूपांतरण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की दृष्टि से आधारभूत सुविधाओं का अभाव इसका एक मुख्य कारण है।
- प्रबंधन में शीर्ष पदों पर महिलाओं के नेतृत्व में कमोबेश वही स्थिति है जो 30 वर्ष पूर्व थी।
- विश्व स्तर पर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक शिक्षित होने के बाद भी प्रबंधन के शीर्ष पर एक-तिहाई से भी कम महिलाएँ हैं।

नोट :

- पाँच अलग-अलग देशों में लिंक्डइन की सहायता से 22% वैश्विक नियोजित जनसंख्या के वास्तविक समय में प्राप्त आँकड़ों के अध्ययन के पश्चात् यह सामने आया है कि रोजगार दर में गिरावट और महिलाओं को कम वेतन मिलने का मुख्य कारण शिक्षा नहीं है।
- साथ ही वर्तमान में डिजिटल कौशल युक्त महिलाओं की विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में उच्चतम भुगतान वाली नौकरियों में सबसे अधिक मांग हैं।
- हालाँकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शीर्ष पर पहुँचने वाली महिलाएँ अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम-से-कम 1 वर्ष पहले पहुँचती हैं।
- भारत में रोजगार में लिंग अंतराल की एक गंभीर तस्वीर को चित्रित करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान में केवल 86,362 महिला लिंक्डइन सदस्य भारत में निदेशक स्तर के पदों पर पहुँची हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 407,316 है इसके अलावा, भारत में लिंक्डइन के केवल 23% सदस्य डिजिटल कौशल से युक्त थे।
- 2018 में भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के रोज़गार दर में 26 प्रतिशत की कमी थी। इसके अलावा 2005 और 2015 के बीच छह साल से कम उम्र के बच्चों और बिना छोटे बच्चों वाली वयस्क महिलाओं के रोजगार अनुपात में अंतर 38% तक बढ़ गया। इसे 'मातृत्व रोज़गार जुर्माना' नाम से उल्लिखित किया गया है।
- कई कारक रोज़गार की समानता में बाधक हैं, और सबसे बड़ी भूमिका इन क्षेत्रों में महिलाओं के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का न होना है।

निष्कर्ष

पिछले 20 वर्षों में महिलाओं ने अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों में जितना समय बिताया है वह शायद ही आगे कम हो और पुरुषों के लिये दिन में कार्य की अवधि में सिर्फ आठ मिनट की वृद्धि हुई है। परिवर्तन की इस गति पर समानता हासिल करने में 200 साल से अधिक समय लगेगा।

डोंगरिया कोंध

संदर्भ

ओडिशा के नियमगिरि की पहाड़ियों में रहने वाले डोंगरिया कोंध आदिवासी पहाड़ों में बॉक्साइट के खनन के कारण लगातार विस्थापित हो रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- अनेक योजनाओं, संवैधानिक और वैधानिक उपायों के बावजूद डोंगरिया समुदाय अब भी पिछड़े हैं और मुख्यधारा से अलग-थलग हैं।
- इसका मुख्या कारण है शिक्षा एवं संचार साधनों की पहुँच इन दुर्गम क्षेत्रों तक न होना।
- साथ ही इनके प्राकृतिक संसाधनों पर भी पूर्णतया इनका अधिकार नहीं है जिस कारण ये लगातार जंगलों से विस्थापित हो रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- 2000 के दशक के प्रारंभ तक डोंगरिया कोंध आदिवासी नियमगिरि रेंज के ढलानों पर रायगढ़ ज़िले के बिस्सम कटक, मुनिगुड़ा तथा कल्याणसिंहपुर ब्लॉक और कालाहांडी ज़िले के लांजीगढ़ ब्लॉक में जैसे दुर्गम रूप क्षेत्रों में शांति से रहते थे।
- 2004 में 'वेदांत' कंपनी ने नियामगिरि की तलहटी पर बसे एक गाँव लांजीगढ़ में एल्युमीनियम रिफाइनरी की स्थापना की।
- बॉक्साइट, एल्युमीनियम के लिये कच्चा माल है और ओडिशा में 700 मिलियन टन ज्ञात बॉक्साइट भंडार में से 88 मिलियन टन नियामगिरि में पाए जाने का अनुमान है।
- इस क्षेत्र में खनन अधिकार को प्राप्त करने की हड़बड़ी में पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया गया था और डोंगरिया समुदाय की सहमति नहीं ली गई थी।
- 18 अप्रैल, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि खनन मंज़ूरी तभी दी जा सकती है जब डोंगरिया ग्राम सभा इस परियोजना से सहमत हो।
- सरकार द्वारा चयनित सभी 12 गाँवों ने परियोजना के खिलाफ मतदान किया।

नोट :

आगे की राह

- सरकार को चाहिये कि पेसा एक्ट, 1996 (PESA Act, 1996) को नियमत: लागू करवाए।
- जनजातियों को उनके अधिकारों की जानकारी, उनके लिये चलाई जा रही योजनाओं की उन तक पहुँच सुनिश्चित करे।
- खनन कंपनियों को लाइसेंस देते वक़्त स्थानीय समुदायों के हित और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को सर्वोपरि रखे।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996
- पेसा एक्ट, 1996 में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से उचित स्तर पर परामर्श किया जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा, जिससे स्थानीय जनजातियों के हितों को हानि न पहुँचे।

अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस- 2019

चर्चा में क्यों ?

21 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम 'मिटीगेटिंग एंड काउंटरिंग राइज़िंग नेशनलिस्ट पोपुलिज़्म एंड इक्सट्रीम सुपरमेसिस्ट आईडियोलॉजी' (Mitigating and countering rising nationalist populism and extreme supremacist ideologies) है।

प्रासंगिकता

- दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जातिवादी व अतिवादी विचारधाराओं पर आधारित राष्ट्रवाद का प्रसार हो रहा है।
- इसके कारण नस्लवाद, विदेशियों के प्रति घृणा (ज़ेनोफोबिया) और असहिष्णुता तेज़ी से बढ़ रही है।
- साथ ही विभिन्न देशों में प्रवासियों, शरणार्थियों, अश्वेतों खासकर अफ्रीकी मूल के लोगों के प्रति हिंसात्मक घटनाएँ भी बढ़ रही हैं।
- ऐसे परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाने का महत्त्व बढ़ जाता है।

पृष्ठभूमि

21 मार्च, 1960 को पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में लोगों द्वारा नस्लभेदी कानून के खिलाफ किये जा रहे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान आग लगा दी और 69 लोगों को मार डाला।

1966 में इस दिन को याद करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया।

1979 में इस दिन महासभा ने जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के प्रति कार्रवाई के लिये कुछ कार्यक्रम अपनाए।

इसी अवसर पर महासभा ने निर्णय लिया कि 21 मार्च से विश्व में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाएगा।

नस्लीय भेदभाव

किसी व्यक्ति या समुदाय से उसके जाति, रंग, नस्ल इत्यादि के आधार पर घृणा करना या उसे समान्य मानवीय अधिकारों से वंचित करना नस्लीय भेदभाव कहलाता है।

बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index- MPI) के नए संस्करण के अनुसार, 2005-06 और 2015-16 के बीच में भारत की गरीबी की दर 55 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत रह गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (Oxford Poverty and Human Development Initiative- OPHI) द्वारा विकसित किया गया है।
- 2005-06 से 2015-16 के दौरान भारत के सबसे गरीब वर्गों जैसे- मुसलमानों और अनुसूचित जनजातियों ने गरीबी को कम करने में सबसे अधिक योगदान दिया है।
- इन दस वर्षों के दौरान भारत में कुल 271 मिलियन (27.10 करोड़) लोग गरीबी सूचकांक से बाहर आए।
- यह सूचकांक अभावों के 10 आयामों पर तैयार की गई सूची पर आधारित है। जिसमें प्रमुख रूप में स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और जीवन स्तर हेतु अभावों को लिया गया है।
- MPI बहुआयामी गरीबी को मापता है इसके तहत ऐसे लोग आते हैं जो कई प्रकार के अभावों का सामना कर रहे हैं, उदाहरण के लिये वे लोग जो अल्पपोषित हैं और जिनके पास सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त स्वच्छता और स्वच्छ ईंधन नहीं है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बहुआयामी गरीबी सबसे तेज़ी से कम हुई है।
- 2005-06 में भारत में 292 मिलियन गरीब बच्चे थे, जबकि 2015-16 में इनकी संख्या 136 मिलियन पाई गई अर्थात नवीनतम आँकड़े में पहले की अपेक्षा 47 प्रतिशत की कमी पाई गई है।
- वैश्विक MPI में कुल 105 देश शामिल हैं, जो दुनिया की आबादी का 77 प्रतिशत या 5.7 बिलियन हैं। इस अनुपात में 23 प्रतिशत लोगों (1.3 बिलियन) की पहचान बहुसंख्यक गरीब के रूप में की जाती है।

भारत की स्थिति

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 640 जिलों में मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला सबसे गरीब है, जहाँ MPI के अनुसार 76.5 प्रतिशत लोग गरीब हैं।
- राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, और नगालैंड के साथ झारखंड में MPI में काफी सुधार पाया गया है।
- 2015-16 के आँकड़ों के अनुसार, बिहार अब भी सबसे गरीब राज्य है जहाँ आधे से अधिक आबादी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही है।
- 2015-16 में चार सबसे गरीब राज्य - बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश थे जहाँ MPI के अनुसार अभी भी 196 मिलियन लोग गरीब हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 में ग्रामीण वंचितों, निचली जातियों और जनजातियों जैसे पारंपरिक वंचित उप-समूह, मुस्लिम वर्ग और छोटे बच्चे सबसे गरीब थे हालाँकि, इन परिदृश्यों में तेज़ी से सुधार हुआ है।

  गौरतलब है कि यह ट्रेंड 1998-99 से 2005-06 के बीच देखा गया है।
- 1998-99 से 2005-06 के दौरान इन समूहों की प्रगति सबसे धीमी रही और वे पीछे रह गए। यही कारण है कि 2015-16 में भी MPI के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में से आधे गरीब हैं, जबकि उच्च जाति में केवल 15 प्रतिशत हैं।
- हर छठे ईसाई की तुलना में हर तीसरा मुस्लिम बहुसंख्यक गरीब है। 10 साल से कम उम्र के पाँच में से दो बच्चे गरीब (41 प्रतिशत) हैं, लेकिन 18 से 60 वर्ष (24 प्रतिशत) के एक-चौथाई से भी कम लोग गरीब हैं।
- हालाँकि इस दशक की अवधि के दौरान जीडीपी की औसत वृद्धि दर लगभग 7.6 प्रतिशत थी।

बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI)

- भारत का MPI 0.121 है
- वर्ष 2015-16 में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की 27.5% आबादी बहु-आयामी गरीबी की गिरफ्त में थी।
- 20–33 प्रतिशत के अभाव स्कोर के साथ 19.1% भारतीय आबादी को कई प्रकार की अभावों से ग्रस्त होने का जोखिम था।
- 8.6% लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं।
- भारत में 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसमें 21.2% लोग एक दिन में 1.90 डॉलर से भी कम कमाते हैं।

नोट :

समान कार्य असमान वेतन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऑक्सफेम इंडिया (Oxfam India) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में समान कार्य के लिये महिलाओं को उनके समकक्ष पुरुषों से 34% कम वेतन प्राप्त होता है।

प्रमुख बिंदु

- ऑक्सफेम इंडिया ने 'माइंड द गैप: स्टेट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया' (Mind The Gap-State of Employment in India) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं का अवैतनिक कार्यों (घरेलू कार्य) में अत्यधिक प्रतिनिधित्व है।
- महिलाओं को समान कार्य के लिये पुरुषों से लगभग एक-तिहाई (34%) कम भुगतान किया जाता है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office) (2011-12) के अनुमानों के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नियमित रूप से वेतन पाने वाली महिलाओं को उनके समकक्ष पुरुषों से औसतन क्रमश: 123 और 105 रुपए का कम भुगतान किया जाता है।
- इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अनियमित रूप से कार्य करने वाली महिलाओं को अपने पुरुष समकक्ष की तुलना में क्रमश: 72 और 47 रुपए कम प्राप्त होते हैं।
- यदि अवैतनिक कार्यों जैसे- देखभाल और घरेलू गतिविधियों को NSSO के कार्य की परिभाषा में शामिल किया जाए तो महिला श्रम बल भागीदारी दर जो 2011-12 में 20.5 प्रतिशत थी बढ़कर 81.7 प्रतिशत हो जाती।
- धर्म के आधार पर महिला श्रम बल भागीदारी दर में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। हालाँकि जाति के आधार पर कुछ अंतर स्पष्ट रूप से दिखता हैं।
- मुस्लिम महिलाएँ अधिकतर घरेलू वस्तुओं के निर्माण में, अनुसूचित जाति की महिलाएँ निर्माण एवं साफ-सफाई कार्यों में तथा गैर-अनुसूचित जाति की महिलाएँ अधिकतर शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
- महिला रोज़गार का आधा हिस्सा 10 उद्योगों में सीमित है। प्रत्येक 7 में से 1 महिला केवल शैक्षणिक क्षेत्र में कार्यरत है।
- लगभग 49.5 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ उसी क्षेत्र में काम करती है जहाँ उनके पति काम करते हैं।
- दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है लेकिन फिर भी ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों से नीचे हैं।

आगे की राह

- रिपोर्ट में इस अंतर को कम करने के लिये कुछ सुझाव भी दिये गए हैं। जैसे-
- अधिक रोज़गार सृजन के लिये श्रम प्रधान क्षेत्रों का और अधिक विकास करने की ज़रूरत है।
- नौकरियों में वृद्धि समावेशी तरीके से होनी चाहिये साथ ही नई नौकरियों में बेहतर कार्य स्थितियों के साथ रोज़गार सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।
- सुरक्षा के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व अवकाश एवं अन्य अधिकार भी शामिल हों।

नोट :

कला एवं संस्कृति

हड़प्पा सभ्यता

चर्चा में क्यों ?

केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और छात्रों के एक समूह द्वारा कच्छ (गुजरात) में किये गए पुरातात्विक उत्खनन ने हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती चरण के दौरान प्रचलित अंत्येष्टि रिवाजों पर प्रकाश डाला है।

प्रमुख बिंदु

- कच्छ के खटिया गाँव में इस 47 सदस्यीय दल ने एक-डेढ़ महीने के लिये डेरा डाला और कब्रिस्तान जैसी जगह, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग शव को दफनाते थे, से कंकालों के नमूनों का अध्ययन किया।
- उन्होंने अलग-अलग दिखने वाली 300 कब्रों में से 26 की खुदाई की। इन सभी आयताकार कब्रों को भिन्न-भिन्न पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया था तथा कंकालों को एक विशिष्ट तरीके से रखा गया था।
- शवों के सिर पूर्व दिशा की ओर थे और पश्चिम दिशा में पैरों के बगल में, पुरातत्वविदों को मिट्टी के बर्तन और अन्य कलाकृतियाँ मिली, जिसमें शंख-चूड़ी, पत्थर और टेराकोटा से बने मोती, कई लिथिक उपकरण और पीसने वाले पत्थर शामिल थे।
- शव के बगल में सामान संभवत: मृत्यु के पश्चात् जीवन की अवधारणा को प्रस्तुत करता है।
- खुदाई की गई 26 कब्रों में से सबसे बड़ी 6.9 मीटर लंबी और सबसे छोटी 1.2 मीटर लंबी थी।
- उनमें से अधिकांश में मानव के कंकाल के अवशेष विघटित पाए गए। मनुष्यों के साथ जानवरों के कंकालों की उपस्थिति भी कुछ कब्रों में दर्ज की गई थी।
- रोचक बात यह है कि शोधकर्ताओं ने दफनाने के तरीके को असमान पाया। प्राथमिक दफन और माध्यमिक दफन (जब प्राथमिक दफन के अवशेषों को किसी अन्य कब्र में ले जायाजाए) के उदाहरण पाए गए।
- उत्खनन टीम एक पूर्ण मानव कंकाल को प्राप्त करने में कामयाब रही, जिसे महाराजा स्याजिराव विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य कांति परमार की सहायता से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी एक बॉक्स में रखा गया था।
- बरामद कंकाल और कलाकृतियों को केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में प्रदर्शन के लिये रखा जाएगा।
- अन्य कंकालों को विभिन्न प्रयोगशालाओं में आयु, लिंग, परिस्थितियों को समझने के लिये तथा डीएनए की मुख्य विशेषताओं के परीक्षण लिये भेजा जाएगा।

आदिवासी कलाकारों के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तेलंगाना के दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स/चित्रों को पहली बार वैश्विक ई-कॉमर्स बाज़ार अमेज़न द्वारा वैश्विक मंच पर लाया गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया।

प्रमुख बिंदु

- आदिवासी कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स में इनके क्षेत्रों की सहजता एवं सरलता को दर्शाते हुए विभिन्न आदिवासी समुदायों के लोकाचार को दर्शाया गया है।
- हालाँकि, कुछ समय पहले तक इन कलाकारों ने अपने पारंपरिक चित्रों को दिखाने की लोगों की मांग को स्वीकार नहीं किया था लेकिन तेलंगाना आदिवासी कल्याण विभाग (Tribal Welfare Department) द्वारा उनकी कला के संभावित संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कुछ चित्रों को मान्यता दी गई।

नोट :

- आदिवासी कलाकारों की सभी पेंटिंग्स में सरलता, अद्वितीय पैटर्न और प्रकृति से प्रेरित संदर्भ प्रदर्शित हैं।
- कुछ महीने पहले अमेज़न ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पहली बार बिक्री के लिये रखे गए पेंटिंग्स में से 17 पेंटिंग्स की बिक्री की गई जो गोंड, कोया और नाइकपोड समुदायों के कलाकारों द्वारा बनाई गई थी।
- हैदराबाद में आदिवासी कल्याण विभाग (Tribal Welfare Department in Hyderabad) के आवासीय परिसर में काम करने वाले कलाकारों ने अन्य 35 पेंटिंग्स पूरी कर ली हैं। इन्हें जल्द ही अमेज़न द्वारा ऑनलाइन बिक्री के लिये रखा जाएगा।
- चित्रों को एक व्यापक मंच प्रदान करने का विचार उस समय आया जब आदिवासी कल्याण विभाग और जनजातीय संग्रहालय (Tribal Museum) के अध्यक्ष ने जनजातीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हुए उनकी पारंपरिक चित्रकला प्रथाओं की अपील को मान्यता प्रदान की।

पेंटिंग्स की विशेषताएँ

- गोंड पेंटिंग्स (Gond Paintings) में चमकीले रंगों और जटिल रेखाओं का उपयोग किया जाता है।
- गोंड कला में ज्यादातर पक्षियों जैसे कि मोर और जानवरों जैसे- बैल, घोड़े, हिरण, हाथी और बाघ से निकलने वाले पेड़ को दर्शाया गया है।
- कोया कलाकार (Koya Artists) अपने पवित्र हरिवेनी पोस्ट्स (Hariveni' posts), पवित्र झंडों (Sacred Flags) और तुम्बा (Big Bottle Gourds) आदि पर चित्रांकन करते हैं।
- नाइकपोड आदिवासियों (Naikpod tribals) के चित्रों में उनके राजाओं के चेहरे के मुखौटे और पांडवों जैसे-भीम तथा ग्रामीण मंदिर के पारंपरिक देवताओं के प्रतिबिंब हैं।

इंडियन म्यूज़ियम ऑफ अर्थ

चर्चा में क्यों ?

अपनी प्रागैतिहासिक विरासत को बेहतर ढंग से संरक्षित करने के लिये भारत सरकार इंडियन म्यूजियम ऑफ अर्थ (The Indian Museum of Earth- TIME), 'पृथ्वी संग्रहालय' (Earth Museum) के निर्माण की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में भूगर्भीय और पुरापाषाणकालीन नमूनों का विशाल संग्रह मौजूद है। इस संग्रह की सहायता से पृथ्वी और इसके इतिहास के संबंध में बेशकीमती वैज्ञानिक जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।
- ध्यातव्य है कि ये दुर्लभ नमूने पूरे देश में अलग-अलग प्रयोगशालाओं में बिखरे हुए हैं जिन्हें एक स्थान पर एकत्रित करने के लिये केंद्र सरकार उक्त संग्रहालय के निर्माण की योजना बना रही है।
- इस संग्रहालय को अमेरिकी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (American Museum of Natural History) या स्मिथसोनियन संग्रहालय (Smithsonian Museum) के आधार पर बनाया जाएगा।
- इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा।
- किसी एक स्थान पर स्थिर सामान्य संग्रहालयों से भिन्न यह प्रस्तावित संग्रहालय डायनामिक होगा, ताकि जीवाश्म से संबंधित अनुसंधानों तथा छात्रों हेतु विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।
- इस संग्रहालय में एक ऐसे रिपॉजिटरी की भी व्यवस्था होगी जहाँ संग्रहकर्त्ता तथा शोधकर्त्ता अपने संग्रह (नमूने) सुरक्षित रख सकेंगे ताकि भावी पीढ़ी के शोधकर्त्ता उन नमूनों का अध्ययन कर सकें।

आवश्यकता क्यों ?

- भारत में एक भी ऐसा संग्रहालय नहीं है, जहाँ नए नमूनों की तुलना पहले से खोजे गए नमूनों से की जा सके।
- पुरातत्त्वीय, नृजातीय, भूगर्भीय तथा प्राणि-विज्ञान एवं पृथ्वी के विकास क्रम के संबंध में समझ विकसित करने की दृष्टि से ऐसे संग्रहालयों की आवश्यकता है।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

समुद्री सुरक्षा पर समझौता

चर्चा में ?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO और उसके समकक्ष फ्राँसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने भारत में एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिये समझौते पर मुहर लगाई।

प्रमुख बिंदु

- दोनों राष्ट्र पृथ्वी की निम्न कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का समूह स्थापित करेंगे जो वैश्विक स्तर (विशेष रूप से हिंद महासागर का वह क्षेत्र जहाँ फ्राँस का रीयूनियन द्वीप स्थित है) पर जहाज़ों के आवागमन की निगरानी करेंगे।
- इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले दोनों देश अपने वर्तमान अंतरिक्ष प्रणालियों से प्राप्त आँकड़ों को आपस में साझा करेंगे और उनका विश्लेषण करने के लिये नए एल्गोरिदम (Algorithms) विकसित करेंगे।
- ISRO और CNES दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के अध्यक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए बताया कि CNES-ISRO समझौते का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में जहाजों का पता लगाने, पहचान करने और उनकी निगरानी के लिये एक संचालन प्रणाली की स्थापना इसी वर्ष मई में स्थापित करना है।
- कार्यक्रम के अगले चरण के लिये दोनों देश संयुक्त रूप से बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये कार्यरत हैं। CNES अपने औद्योगिक भागीदारों और ISRO के साथ बेहतर तकनीकी समाधान खोजने के लिये काम कर रहा है।
- दोनों एजेंसियों ने दो जलवायु और महासागर मौसम निगरानी उपग्रहों - 2011 में स्थापित मेघा-ट्रोपिक्स (Megha-Tropiques-2011) और 2013 में स्थापित सरल-अल्टिका (SARAL-AltiKa-2013) को एक मॉडल के तौर पर माना है।
- CNES के अनुसार, इस बेड़े को 2020 में ओशनसैट-3-आर्गोस मिशन (Oceansat-3-Argos mission) के साथ लॉन्च किया जाएगा।

नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ (CNES)

- CNES फ्राँस सरकार की आधिकारिक अंतरिक्ष एजेंसी है।
- इसका मुख्यालय सेंट्रल पेरिस में स्थित है और यह फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च की देखरेख में कार्य करता है।
- इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।

भारतीय संदर्भ में समुद्र तथा समुद्री मार्गों का महत्त्व

- भारत का विशाल प्रायद्वीप और इसके चारों ओर फैली हुई द्वीपीय श्रृंखला की सामरिक अवस्थिति के कारण यह क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90%(मात्रा में) तथा 70% (मूल्य के आधार पर) समुद्री मार्ग से संचालित होता है। अत: भारत की सुरक्षा रणनीति में समुद्री सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण अवयव है।

भारतीय समुद्री सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ-

- संगठित अपराध- समुद्री रास्तों से की जाने वाली हथियारों, नशीले पदार्थों और मानवों की तस्करी संगठित अपराध के रूप में एक बड़ी समुद्री सुरक्षा चुनौती है।
- समुद्री लूट- अरब सागर के क्षेत्र में सोमालियाई लुटेरों से भारतीय व्यापारिक जहाज़ों को सदैव खतरा बना रहता है।
- समुद्री मार्ग से आतंकवाद का दंश भी भारत झेल चुका है। 26/11 का मुंबई हमला, भारतीय समुद्री सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न पहले ही खड़े कर चुका है।
- सुनामी तथा चक्रवातों जैसी प्राकृतिक आपदाएँ और तेल रिसाव जैसी मानव जनित आपदाएँ भी समुद्री सुरक्षा के लिये चुनौती है।

नोट :

चर्चा में

हनोई शिखर सम्मेलन 2019

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका (US) और उत्तर कोरिया ने वियतनाम के हनोई में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया।

- जून 2018 में सिंगापुर शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच यह दूसरा शिखर सम्मेलन था।
- अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच यह वार्ता बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई और किसी भी घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किये गए।
- वार्ता विफल होने का कारण यह था कि उत्तर कोरिया ने खुद को केवल आंशिक रूप से परमाणु मुक्त करने के बदले में आर्थिक प्रतिबंधों से पूरी तरह से राहत की मांग की थी। लेकिन, अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया खुद को पूरी तरह परमाणु हथियारों से मुक्त कर दे।
- 2018 में सिंगापुर शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी

केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने 1 मार्च, 2019 को वर्ष 2016-17 के लिये एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिये 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्रदान की।

- इस्पात मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ट्रॉफी, इस्पात मंत्री की ट्रॉफी और प्रशस्ति प्रमाण पत्र देने की योजना बनाई है।
- प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिये एकीकृत इस्पात संयंत्रों को पुरस्कार देने की योजना वर्ष 1992-93 में शुरू की गई थी। अत: वर्ष 2016-17 इस आकलन का 25वाँ वर्ष था।
- पुरस्कारों की श्रेणियाँ
- 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि के साथ प्रधानमंत्री ट्रॉफी एक ऐसे संयंत्र को दी जाती है जिसका प्रदर्शन सभी प्रतिभागी संयंत्रों में सर्वोत्तम होता है।
- 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि के साथ इस्पात मंत्री की ट्रॉफी द्वितीय सर्वोत्तम समग्र प्रदर्शन करने वाले संयंत्र को दी जाती है।
- पुरस्कारों की अन्य श्रेणियों में 'अधिकतम सुधार के लिये प्रशस्ति प्रमाण पत्र' (Certificate of Appreciation for Maximum Improvement) और 'थीम आधारित पुरस्कार' (Theme Based Awards) शामिल हैं।

संयंत्रों के प्रदर्शन का आकलन

- इन संयंत्रों के प्रदर्शन का आकलन जजों के एक पैनल द्वारा किया जाता है। जाने-माने तकनीकीविदों, प्रबंधन विशेषज्ञों, व्यापार यूनियन लीडरों, अर्थशास्त्रियों और लोहे एवं इस्पात के उपभोक्ताओं में से इस पैनल के सदस्यों का चयन किया जाता है।

निटविर सेक्टर (Knitwear Sector) विकसित करने की योजना

हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पावरटेक्स इंडिया (PowerTex India) के तहत बुनाई तथा बुने हुए कपड़ों के क्षेत्र के विकास के लिये एक व्यापक योजना की शुरुआत की है।

- मंत्रालय ने पावरटेक्स इंडिया स्कीम एवं निटवियर स्कीम के संयुक्त स्टैंडिंग फाइनेंस कंपोनेंट (Standing Finance Component-SFC) को 487.07 करोड़ रुपए व्यय की मंज़ूरी प्रदान की है। 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिये 47.72 करोड़ रुपए बुने हुए कपड़ों के लिये निर्धारित किये गये हैं।

नोट :

- योजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:
  - बुनाई और बुने हुए कपड़े के क्षेत्र में उद्योगों और संघों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) मॉडल पर नए सेवा केंद्रों का निर्माण।
  - बुनाई और बुने हुए कपड़े के क्षेत्र में मौजूदा पावर लूम सर्विस सेंटर (power loom service Centers) और वस्त्र 0अनुसंधान संघों (Textile Research Associations) और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स (Export Promotion Councils-EPCs) एसोसिएशन द्वारा संचालित आधुनिकीकरण और उन्नयन।
  - बुनाई और बुने हुए कपड़ा इकाइयों के लिये सुविधा, सूचना प्रौद्योगिकी, जागरूकता, अध्ययन, सर्वेक्षण, बाज़ार विकास और प्रचार।

पावरटेक्स इंडिया

- कपड़ा मंत्रालय ने पावरटेक्स इंडिया की शुरुआत 2017 में की थी।
- यह देश के पावरलूम क्षेत्र के विकास पर केंद्रित तीन साल की समावेशी योजना है।
- यह योजना पावर लूम टेक्सटाइल्स में ब्रांडिंग, सब्सिडी, नए बाजार, नए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर पावरलूम श्रमिकों के लिये कल्याणकारी योजनाओं को समाहित करती है।

समावेशी इंटरनेट सूचकांक- 2019

हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit- EIU) द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक- 2019 (Inclusive Internet Index- 2019) प्रकाशित किया गया।

- यह इंडेक्स यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिये कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है।
- इसका उद्देश्य शोधकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं को वो सूचनाएँ प्रदान करना है, जिनकी सहायता से विभिन्न वर्गों तक इंटरनेट का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- यह इंटरनेट से संबंधित निम्नलिखित चार आधारों पर विभिन्न देशों का आँकलन करता है:
  1. सुलभता (Accessibility)
  2. कम खर्च में उपलब्धता (Affordability)
  3. प्रासंगिकता (Relevance)
  4. तत्परता (Readiness)
- 100 देशों में स्वीडन प्रथम स्थान पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका है।
- भारत को 47वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। पड़ोसी देशों में चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और क्रमश: 42 77, 74, 72, 71, 58वें स्थान पर हैं।

निर्माण प्रौद्योगिकी भारत -2019

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया- 2019 सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संदर्भ में उपयोग हेतु सिद्ध, नवीन और वैश्विक रूप से स्थापित प्रौद्योगिकियों की पहचान करना है।
- इस सम्मेलन का आयोजन ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (Global Housing Technology Challenge) के एक घटक के रूप में किया जा रहा है।

ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज

- ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर से टिकाऊ, हरित, लचीली, सिद्ध तथा क्षमतावान नवीन तकनीकों की पहचान करना, मूल्यांकन करना और उन्हें भारतीय निर्माण क्षेत्र में मुख्यधारा में लाना है।

नोट :

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, 2019

हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) द्वारा आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, 2019 (National e-Governance Award, 2019) प्रदान किया गया।

- ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष ई-गवर्नेंस के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वर्ष इसका विषय 'डिजिटल इंडिया: सक्सेस टू एक्सीलेंस' है।
- यह पुरस्कार सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली, सरकार से सरकार (Government to Government), सरकार से नागरिक (Government to Citizen), सरकार से व्यवसाय (Government to Business) की सर्वोत्तम पहलों को मान्यता प्रदान करता है।
- यह स्टार्टअप, शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों की पहलों के साथ-साथ उभरती हुई तकनीकों को अपनाने की पहल को भी मान्यता प्रदान करता है।
- यह पुरस्कार छह निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जाता है:
  - श्रेणी I- डिजिटल सुधार के लिये सरकारी प्रक्रिया के पुनर्निर्धारण में विशिष्टता।
  - श्रेणी II- नागरिक आधारित सेवा प्रदान करने में विशिष्टता।
  - श्रेणी III- ई- गवर्नेंस में ज़िला स्तर पर पहल करने में विशिष्टता।
  - श्रेणी IV- शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं पर विशिष्ट अनुसंधान।
  - श्रेणी V- स्टार्टअप के माध्यम से ई-गवर्नेंस समाधान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में नवाचार।
  - श्रेणी VI- उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में विशिष्टता।
- इस वर्ष 6 श्रेणियों में 14 पुरस्कार दिये गए। श्रेणी-1 के अंतर्गत एक विशेष ज्यूरी पुरस्कार, आई.आर.सी.टी.सी. (IRCTC) रेल कनेक्ट मोबाइल एप (Rail Connect Mobile App) को प्रदान किया गया।

स्पेस-एक्स क्रू ड्रैगन

हाल ही में अमेरिकी स्पेस-एक्स क्रू ड्रैगन (SpaceX Crew Dragon), अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल प्रदर्शन मिशन के एक हिस्से के रूप में अमेरिका से लॉन्च किये जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के साथ सफलतापूर्वक जुड़ (Docking) गया है।

- गौरतलब है कि अंतरिक्ष यातायात की शुरुआत के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से यात्री कैप्सूल का यह जुड़ाव (Docking) कुछ ऐसा है जिसे भविष्य में नियमित रूप से करना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ता हुआ क्रू ड्रैगन

- स्पेस-एक्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिये उड़ान भरने वाले लोगों हेतु कमर्शियल अंतरिक्ष यान बनाने, लॉन्च करने और अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक जोड़ने वाली पहली कंपनी बन गई है।
- यदि सब कुछ योजना के अनुसार हो जाता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को जुलाई की शुरुआत में ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा।

क्या है स्पेस-एक्स ?

- स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन (स्पेस-एक्स) अमेरिका की प्राइवेट एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है। इसका मुख्यालय हैथॉर्न, कैलिफोर्निया में स्थित है।
- पेपाल और टेस्ला मोटर्स के संस्थापक अरबपति वैज्ञानिक इलॉन मस्क ने 2002 में इसकी शुरुआत की थी।
- 2006 में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लॉजिस्टिक्स पहुँचाने के लिये स्पेस-एक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया था।
- स्पेस-एक्स ने फाल्कन लॉन्च वाहन और ड्रैगन अंतरिक्ष यान विकसित किया है, जो वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में पेलोड वितरित करता है।

नोट :

गिनीज़ में शामिल 'कुंभ मेला- 2019'

हाल ही में 'प्रयागराज कुंभ मेला- 2019' को गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।

गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तीन सदस्यों वाली एक टीम ने 28 फरवरी से 3 मार्च तक प्रयागराज का दौरा किया और निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में कुंभ मेला-2019 को गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया:

1. सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना
2. पेंट माई सिटी (Paint My City) योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ी पेंटिंग और
3. सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र।

- इस उद्देश्य के लिये तीन दिनों तक गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीम के सदस्यों के सामने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया था।
- राजमार्ग पर 28 फरवरी को टीम के अवलोकन के लिये लगभग 503 शटल बसों को सेवा में तैनात किया गया था।
- 1 मार्च को बड़ी संख्या में लोगों ने चित्रकला अभ्यास में भाग लिया और प्रयागराज कुंभ में लगे 10 हज़ार सफाई कार्यकर्त्ताओं ने एक साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया।
- इस वर्ष कुंभ मेला 15 जनवरी को प्रारंभ हुआ था और 4 मार्च को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ इसका सफल समापन हुआ।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (National Thermal Power Corporation Limited-NTPC) केवल उन्हीं विद्युत परियोजनाओं का अधिग्रहण करेगी, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal-NCLT) में दिवालिया होने की कार्यवाही से गुज़र रही हैं। गौरतलब है कि ऐसे अधिग्रहण उचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से किये जाएंगे।

- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 के तहत किया गया था।
- NCLT कंपनियों के दिवालिया होने से संबंधित कानून पर जस्टिस एराडी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 01 जून, 2016 से प्रभाव में है।
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देती है।
- NCLT में कुल ग्यारह बेंच हैं जिसमें नई दिल्ली में दो (एक प्रमुख) तथा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलूरू, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में एक-एक है।

वन नेशन वन कार्ड

हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (National Common Mobility Card-NCMC), वन नेशन वन कार्ड (One Nation One Card) लॉन्च किया है।

- इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (National Urban Transport Policy-NUTP) के हिस्से के रूप में की गई थी।
- गौरतलब है कि यह कार्ड देश भर में लोगों को मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स समेत कई तरह के परिवहन शुल्कों का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।
- विभिन्न परिवहन सेवाओं में इस्तेमाल किये जा सकने वाले 'एक राष्ट्र एक कार्ड' से धारक पैसा भी निकाल सकेंगे।
- प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए इस कार्ड को लॉन्च किया है।
- ध्यातव्य है कि 'वन नेशन वन कार्ड' तकनीकी रूप से रुपे कार्ड पर निर्भर है और इससे यात्रा के दौरान किराये से संबंधित सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।
- स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले परिवहन भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र, स्वीकार (एक स्वचालित किराया-संग्रह प्रणाली) के साथ-साथ एक गेट तथा कार्ड-रीडर प्रणाली, स्वागत भी लॉन्च की गई है।

नोट :

BOLD-QIT परियोजना

गृह मंत्री द्वारा 4 मार्च, 2019 को असम के धुबरी ज़िले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System- CIBMS) के तहत 'BOLD-QIT' परियोजना [Border Electronically Dominated QRT (Quick Response Team) Interception Technique Project] का उद्घाटन किया गया।

- ज्ञातव्य है कि भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किमी. लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जिसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force- BSF) की है।
- असम के धुबरी ज़िले में सीमा क्षेत्र का 61 किमी. का हिस्सा, जहाँ ब्रहमपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, अनगिनत नदी चैनलों से मिलकर बनता है। अत: यहाँ सीमा की रखवाली एक दुष्कर कार्य बन जाता है।
- इस समस्या से निपटने के लिये जनवरी 2018 में BSF की सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा ने BOLD-QIT परियोजना आरंभ की थी।
- BOLD-QIT, CIBMS के तहत एक तकनीक आधारित परियोजना है जो ब्रहमपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में बिना बाड़ लगाए विभिन्न प्रकार के सेंसर की सहायता से सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- इसकी मदद से ब्रहमपुत्र नदी के समस्त क्षेत्र को माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, डिजिटल मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन, दिन और रात निगरानी कैमरों तथा घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली द्वारा उत्पन्न डेटा नेटवर्क के साथ कवर किया गया है।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन से BSF को न केवल सभी प्रकार के सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायता प्राप्त होगी बल्कि उन्हें 24 घंटे मानव निगरानी से भी राहत मिलेगी।

आईपीओ (Initial Public Offering-IPO)

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने MSTC (मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड), इस्पात मंत्रालय के तहत एक मिनी-रत्न को आईपीओ (Initial Public Offering-IPO) के लिये मंज़ूरी दे दी है।

- इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली मिनी-रत्न कंपनी तीन मुख्य क्षेत्रों ई-कॉमर्स, ट्रेडिंग और रीसाइक्लिंग में व्यवसाय करती है।

आईपीओ

- आईपीओ (IPO) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी स्वामित्व वाली कोई कंपनी (MSTC के मामले में सरकार के स्वामित्व में) आम जनता को अपने शेयरों की बिक्री कर सकती है।
- यह नई या पुरानी कंपनी हो सकती है जो किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का फैसला करती है और इसलिये सार्वजनिक हो जाती है।
- कंपनियाँ आईपीओ (IPO) के द्वारा सार्वजनिक रूप से नए शेयर जारी करके पूंजी जुटा सकती हैं या मौजूदा शेयरधारक अपने शेयर जनता को बेच सकते हैं।
- आईपीओ (IPO) के बाद कंपनी के शेयरों का खुले बाज़ार में कारोबार होता है।

त्रिसूर कोले वेटलैंड

हाल ही में वैज्ञानिकों ने त्रिसूर कोले वेटलैंड (Thrissur Kole Wetland) में विदेशी मछलियों की प्रजातियों की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई है क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मूल प्रजातियों की तुलना में उनकी संख्या बढ़ जाएगी।

- कोले वेटलैंड केरल के त्रिसूर ज़िले में स्थित है।
- पक्षियों की संख्या के मामले में त्रिसूर कोले वेटलैंड ओडिशा के चिल्का झील और गुजरात के अमीपुर टैंक (Amipur Tank) के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है।
- कोले भूमि अनूठे वेम्बनाड-कोले वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र (Vembanad-Kole wetland ecosystem) का हिस्सा है जिसे 2002 में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था।

नोट :

अल नागाह 2019

भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यासों की श्रृंखला में तीसरा 'अल नागाह अभ्यास' (Exercise Al Nagah) 12 से 25 मार्च, 2019 तक ओमान की जबल अल अखदर (Jabel Al Akhdar) पहाड़ियों में आयोजित किया जाएगा।

- इस सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएँ अर्द्ध-शहरी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में पारस्परिकता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ युद्ध कौशल, हथियारों के संचालन और गोलाबारी में विशेषज्ञता तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करेंगी।
- 2006 में भारत-ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग की बैठकों के बाद से भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा संबंध निरंतर विकसित हो रहे हैं।
- अभ्यास अल नागाह III से पहले दो संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया जा चुका है। पहला आयोजन ओमान में जनवरी 2015 तथा दूसरा भारत में मार्च 2017 में किया गया था।
- भारतीय सेना के दस्ते का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की 10वीं बटालियन के 4 अधिकारी, 9 जूनियर कमीशंड अधिकारी और 47 अन्य कर्मी करेंगे।
- रॉयल आर्मी ऑफ ओमान (RAO) की जबल रेजीमेंट की ओर से भी इतने ही सैन्यकर्मी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे।
- यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाने तथा मैत्री को मज़बूती प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

NRETP हेतु ऋण अनुबंध

हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (National Rural Economic Transformation Project-NRETP) के लिये 250 मिलियन डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।

- गौरतलब है कि विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली इस ऋण सहायता (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD Credit) के ज़रिये 'राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (NRETP)' को कार्यान्वित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (NRETP) के तहत वित्तीय समावेशन के वैकल्पिक माध्यमों का मार्गदर्शन करने, ग्रामीण उत्पादों के आसपास मूल्य श्रृंखला सृजित करने से संबंधित पहलों को बढ़ावा देने के लिये नवोन्मेषी परियोजनाएँ आरंभ की जाएंगी।
- विश्व बैंक के इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) से मिलने वाले 250 मिलियन डॉलर के ऋण हेतु 5 वर्ष की छूट अवधि, जबकि 20 वर्षों की अंतिम परिपक्वता अवधि होगी।
- इस परियोजना का प्रमुख ध्यान मूल्य-श्रृंखलाओं में महिलाओं के स्वामित्व तथा नेतृत्व वाले कृषि और गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना होगा।

चीन का कृत्रिम सूर्य

चीन इस वर्ष के अंत तक इलेक्ट्रॉनों और आयनों से बने कृत्रिम सूर्य प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है।

कृत्रिम सूर्य

- सूर्य में होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से दोहराने के लिये HL-2M टोकामक डिवाइस (Tokamak Device) का उपयोग किया जा रहा है।
- कृत्रिम सूर्य का प्लाज़्मा मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों और आयनों से बनाया गया है। टोकामक उपकरणों के मुख्य प्लाज़्मा में इलेक्ट्रॉन का तापमान 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा आयन का तापमान 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हासिल किया जा चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आयन ही टोकामक डिवाइस में ऊर्जा उत्पन्न करता है।

चुनौतियाँ

- परमाणु संलयन प्राप्त करने हेतु आयन का तापमान 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक करना होगा जो कि एक चुनौती है।
- अन्य दो चुनौतियाँ इस प्रकार हैं-
  - संलयन को लंबी अवधि तक सीमित स्थान के भीतर रखना
  - पर्याप्त उच्च-घनत्व प्रोफाइल प्रदान करना

नोट :

लंदन पेशेंट

हाल ही में HIV से पीड़ित एक व्यक्ति का लंदन में इलाज किया गया है, जिसे लंदन पेशेंट कहा जा रहा है।

- गौरतलब है कि यह मरीज़ अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Transplant) के बाद HIV वायरस से मुक्त होने वाला दूसरा व्यक्ति बन गया है।
- मरीज़ को CCR5-डेल्टा 32 तकनीक की मदद से ठीक किया गया है। CCR5-डेल्टा 32 तकनीक होमोज़ीगोस दाता कोशिकाओं से युक्त स्टेम सेल प्रत्यारोपण पर आधारित है।

बर्लिन पेशेंट

- टिमोथी रे ब्राउन (Timothy Ray Brown) को HIV से छुटकारा पाने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है।
- टिमोथी का इलाज बर्लिन में किया गया था और उसकी पहचान छुपाने हेतु 'द बर्लिन पेशेंट' कहा गया था।

नोस्ट्रो एकाउंट्स (Nostro Accounts)

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोस्ट्रो एकाउंट्स (Nostro Accounts) के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं करने के लिये इलाहाबाद बैंक पर जुर्माना लगाया है।
- नोस्ट्रो, 'Ours' के लिये लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है, जिसका उपयोग अक्सर विदेशी मुद्रा और व्यापार लेन-देन की सुविधा के लिये किया जाता है।
- नोस्ट्रो एकाउंट (Nostro Account) घरेलू बैंक का किसी विदेशी बैंक में उसी देश की मुद्रा में दर्शाया जाने वाला बैंक खाता है।

9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन

प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (Prime Minister's Science, Technology & Innovation Advisory Council- PM-STIAC) ने भारत के सतत् विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख वैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये 9 राष्ट्रीय विज्ञान मिशनों की पहचान की है।

- प्रत्येक मिशन का नेतृत्व एक प्रमुख मंत्रालय करेगा और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संस्थागत भागीदारों, युवा वैज्ञानिकों एवं उद्योगों को शामिल करेगा।
- सभी 9 मिशन इस प्रकार हैं-
  - मिशन 1: प्राकृतिक भाषा अनुवाद
  - मिशन 2: क्वांटम फ्रंटियर
  - मिशन 3: आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI)
  - मिशन 4: राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन
  - मिशन 5: इलेक्ट्रिक वाहन (EV)
  - मिशन 6: मानव स्वास्थ्य हेतु जैव स्वास्थ्य
  - मिशन 7: वेस्ट टू वेल्थ (Waste to Wealth)
  - मिशन 8: डीप ओशन एक्सप्लोरेशन
  - मिशन 9: नए भारत के नवाचारों का तेज़ी से विकास (Accelerating Growth of New India's Innovations-AGNIi)

जन-औषधि दिवस

7 मार्च, 2019 को पूरे भारत में 'जन-औषधि दिवस' मनाया गया।

- यह जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत फार्मास्युटिकल विभाग की एक पहल है।

नोट :

- ज्ञातव्य है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सस्ता बनाने हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना (PMBJP)) लाई गई थी।
- इस परियोजना के तहत सभी ब्लॉकों में 2020 तक कम-से-कम एक PMBJP केंद्र बनाने का लक्ष्य है।
- फिलहाल देश के 652 ज़िलों में 5050 से अधिक जन-औषधि स्टोर सक्रिय हैं। जन-औषधि स्टोर में ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 50-90% तक कम कीमत में जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध होती हैं।
- जन-औषधि दवाओं से प्रतिदिन लगभग 10-15 लाख लोग लाभान्वित होते हैं और जेनेरिक दवाओं की बाज़ार में हिस्सेदारी पिछले 3 वर्षों में तीन गुना बढ़कर 2 प्रतिशत से 7 प्रतिशत हो गई है।

गूगल 'बोलो' एप

गूगल ने एक नया एप 'बोलो' लॉन्च किया है।

- यह एप प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा सीखने में मदद करेगा।
- यह एप आवाज पहचानने की तकनीक तथा टेक्स्ट-टू-स्पीच तकनीक पर आधारित है।
- इसमें एक एनिमेटेड कैरेक्टर 'दीया' है जो बच्चों को कहानियाँ पढ़ने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- यह कैरेक्टर किसी शब्द का उच्चारण करने में दिक्कत आने पर बच्चों की मदद भी करती है। साथ ही टास्क खत्म होने पर उनका मनोबल भी बढ़ाती है।

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार- 2019

हाल ही में राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार- 2019 प्रदान किया।

- जहाँ इंदौर (मध्य प्रदेश) लगातार तीसरी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है वहीं अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) और मैसूर (कर्नाटक) क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) क्षेत्र को 'सबसे साफ छोटा शहर' का पुरस्कार दिया गया।
- उत्तराखंड के 'गौचर' को 'सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन' घोषित किया गया है।
- इसके अलावा भोपाल को भी लगातार तीसरी बार सबसे साफ राजधानी चुना गया है।
- गौरतलब है कि ये पुरस्कार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

विश्व वन्यजीव दिवस

3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day) मनाया गया।

- इस वर्ष इसकी थीम 'लाइफ बिलो वाटर : फॉर पीपल एंड प्लैनेट' (Life below Water: for People and Planet) है।
- यह थीम सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) के लक्ष्य संख्या 14 (सतत् विकास के लिये महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना) के उद्देश्यों की पूर्ति करता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2013 को वन्यजीवों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये इस दिवस को मनाने की पहल की थी।
- गौरतलब है कि महासागरों में 200,000 से अधिक ज्ञात प्रजातियाँ हैं।
- वैश्विक स्तर पर समुद्री और तटीय संसाधनों एवं उद्योगों का बाज़ार लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 5% है।
- तीन अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिये समुद्री और तटीय जैव विविधता पर निर्भर हैं।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 (International Women's Day 2019)

- प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है इस बार 109वाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है।
- इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय है - 'लैंगिक समानता को प्राप्त करने के प्रयासों के मद्देनजर, महिलाओं और लड़कियों के लिए इनके द्वारा नवाचार, समान सोच, बदलाव के लिये नवाचार, सोच में बदलाव'।
- 1909 में पहली बार महिलाओं के अधिकारों को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।
- राष्ट्रपति ने इस दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों के लिये शुभकामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया और महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका उद्देश्य 'ए क्वांटम लीप फॉर जेंडर इक्वलिटी : फॉर ए बेटर फ्यूचर ऑफ वर्क फॉर ऑल' है।

इरोड हल्दी को मिला GI टैग (GI Tag for Erode Turmeric)

- हाल ही में सरकार ने इरोड क्षेत्र में उगाई जाने वाली हल्दी के लिये भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया जिससे इस क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को प्रसिद्ध 'इरोड मंजल' हल्दी पर एकमात्र अधिकार प्रदान किया गया।
- वर्ष 2013 में सबसे पहले GI टैग के लिये आवेदन इरोड के व्यापारियों के एसोसिएशन द्वारा किया गया था। कुछ दिन बाद ही एक जाँच के बाद आवेदन स्वीकार को स्वीकार कर लिया गया इसे अगस्त 2018 में सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया गया।
- कुछ दिन पहले महाराष्ट्र स्थित सांगली की हल्दी को ज्यॉग्राफिकल इंडेक्स (जीआई) रैकिंग प्रदान की गई थी।

इरोड

- तमिलनाडु के कोयंबटूर ज़िले में स्थित इरोड और इसके आसपास के क्षेत्र हल्दी की खेती के लिये प्रसिद्ध हैं जिनमें कोडुमुडी, सिवागिरी, हवानी, गोबीचेट्टिपलायम, अन्थियूर, चेनमपट्टी, सत्यमंगलम और थलावाडी प्रमुख रूप से शामिल हैं।
- इन क्षेत्रों में चिन्ना नादान किस्म की हल्दी का उत्पादन बड़े पैमाने पर एक महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक मसाला फसल के रूप में किया जाता है।
- इसकी खेती से हज़ारों छोटे और सीमांत किसान जुड़े हुए हैं।
- इस हल्दी के उत्पादन के लिये गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है और जिसके लिये यह ज़िला अनुकूल है क्योंकि यहाँ का तापमान 20 से 37.9 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हल्दी के लिये दोमट या जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- ऐसा माना जाता है कि 2000 ईसा पूर्व के संगम युग के दौरान तमिल किसानों द्वारा अपने घरों के सामने हल्दी के पौधे उगाए जाते थे।
- इस बात के प्रमाण हैं कि हल्दी का उत्पादन चेरा, चोल और पांडियन के समय भी किया जाता था।
- हल्दी का धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं में अधिक महत्त्व है क्योंकि इसे एक शुभ और पवित्र जड़ी-बूटी माना जाता है।
- खाद्य पदार्थों में सुगंध एवं रंग के लिये इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही दवा और सौंदर्य प्रसाधनों आदि में भी हल्दी उपयोगी है।

भारत और रूस ने किया परमाणु पनडुब्बी सौदा

हाल ही में भारत ने रूस के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिये एक तीसरी परमाणु-संचालितपनडुब्बी चक्र III को पट्टे पर लेने हेतु 3 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- चक्र III पनडुब्बी को 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल किये जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।
- 1988 में भारतीय नौसेना ने तीन साल के लिये एक परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइल पनडुब्बी को पट्टे पर लिया था जिसे आईएनएस चक्र नाम दिया गया था।

नोट :

- 2012 में एक दूसरी पनडुब्बी जिसका नाम चक्र II था को 10 साल के लिये लीज पर लिया गया था, जो वर्तमान में पूर्वी नौसेना कमान के पास है। भारत और रूस इस पनडुब्बी के पट्टे को वर्ष 2027 तक बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं।
- चक्र III नामक नई पनडुब्बी के लिये पट्टे की अवधि अभी तक तय नहीं है। हालाँकि इस पनडुब्बी द्वारा कम-से-कम एक दशक तक भारतीय नौसेना को सेवा दिए जाने की उम्मीद है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्त्व संस्थान

9 मार्च, 2019 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्त्व संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान के परिसर में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया।

- 28 अक्तूबर, 2016 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती के अवसर पर संस्थान भवन की आधारशिला केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा रखी गई थी।
- पुरातत्त्व संस्थान (Archaeological Institute) संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) का अकादमिक विंग है।
- संस्थान में छात्रों को सहायक, उत्साहवर्द्धक और चुनौतीपूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे पुरातत्त्व के क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर पाते हैं। संस्थान पुरातत्त्व के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है।
- इस संस्थान का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों को पुरातत्त्व के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है।

महिलाओं को बेहतर आजीविका प्रदान करने का प्रयास

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) ने महिलाओं की आजीविका में सुधार लाने और कौशल विकास के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक समझौता/करार किया है।

- इस करार का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय महिला कोष (National Women Fund) और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (National Skill Development Council) के माध्यम से किया जाएगा।
- इस पहल के माध्यम से महिलाओं में ऐसे कौशल का विकास करने में मदद प्राप्त होगी, जो उन्हें तुरंत रोज़गार पाने/पैसा कमाने में मदद करेगा, जिससे आगे चलकर उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
- कौशल विकास मंत्रालय महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिये महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने के लिये समर्पित है इससे महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव के साथ ही देश के विकास में भी मदद मिलेगी।
- दोनों मंत्रालय महिलाओं को तत्काल लाभ पहुँचाने के लिये उपयुक्त मॉड्यूल तैयार करने हेतु मिलकर काम करेंगे।

परिवहन एवं विपणन सहायता योजना

हाल ही में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिये परिवहन एवं विपणन सहायता योजना (Transportation and Marketing Assistence - TMA) की शुरुआत की।

- इस योजना के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है जिसके तहत कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- TMA के तहत सरकार कृषि उत्पादों की ढुलाई के खर्च का कुछ हिस्सा वहन करेगी एवं कृषि उपज के विपणन में सहायता करेगी।
- यह योजना समुद्र और वायु दोनों माध्यमों द्वारा परिवहन पर लागू होगी।

नोट :

ई- धरती एप

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने e-Dharti एप लॉन्च किया

- इस एप में भू-संपत्ति से जुड़े सभी तीन कार्यों- रूपांतरण, प्रतिस्थापन और उत्परिवर्तन (Conversion, Substitution and Mutation) को ऑनलाइन कर दिया गया है।
- इसके बाद लोग भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और उन्हें पुन: सबमिशन के लिये L&DO के कार्यालय में जाने की ज़रुरत नहीं है।
- भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) में भुगतान प्रणाली को भी डिजिटल कर दिया गया है।

अमचंग वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों की मौत

पिछले दिनों अमचंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से लगी नरेंगी छावनी (गुवाहाटी) से हाथियों को दूर रखने के लिये सेना ने ज़मीन पर लोहे की मज़बूत कीलें लगाई थीं जिन्हें अब हटाना शुरू कर दिया गया है।

- ध्यातव्य है कि कीलों की वज़ह से हाथियों को गंभीर चोटों का सामना करना पड़ रहा था, जो आगे चलकर सेप्टिसीमिया (Septicemia) में तब्दील हो जा रही थीं।
- सेप्टिसीमिया रक्त प्रवाह का गंभीर संक्रमण है जिसे रक्त विषाक्तता के रूप में भी जाना जाता है।

अमचंग वन्यजीव अभयारण्य

- अमचंग वन्यजीव अभयारण्य असम के गुवाहाटी में स्थित है, जो लगभग 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- इस वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों और स्तनधारियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- असम सरकार ने जून 2004 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया था।
- शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव की वज़ह से इस अभयारण्य के प्राकृतिक संसाधनों पर खतरा मंडरा रहा है।

वैश्विक ट्रेडमार्क प्रणाली

हाल ही में मंत्रिमंडल ने नीस, वियना तथा लोकार्नो समझौतों से भारत के जुड़ने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी।

- नीस समझौता (Nice Agreements) ट्रेडमार्क पंजीकरण के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से संबंधित है।
- वियना समझौता (Vienna Agreements) ट्रेडमार्कों के प्रतीकात्मक तत्त्वों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से संबंधित है।
- लोकार्नो समझौता (Locarno Agreements) औद्योगिक डिज़ाइनों के लिये अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से संबंधित है।
- इन समझौतों से जुड़ने के बाद बौद्धिक संपदा (IP) के संरक्षण के संबंध में भारत के प्रति विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ जाएगा।

पिंक टैक्स

- पिंक टैक्स (Pink Tax) महिलाओं द्वारा चुकाई जाने वाली एक इनविज़िबल कॉस्ट (अदृश्य लागत) है। यह राशि उन्हें उन उत्पादों के लिये चुकानी पड़ती है जो विशेष तौर पर उनके लिये डिज़ाइन किये जाते हैं।
- न्यूयॉर्क में किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि महिलाओं के लिये बने उत्पादों की लागत पुरुषों के लिये बनाए गए समान उत्पादों की तुलना में 7% अधिक होती है।
- व्यक्तिगत देखभाल संबंधी उत्पादों (Personal Care Products) के मामले में यह अंतर 13% तक बढ़ जाता है।
- यह अंतर सिर्फ न्यूयॉर्क या विकसित देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारत में भी महिलाएँ विशेष रूप से उनके लिये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर पिंक टैक्स का भुगतान करती हैं।
- उदाहरण के तौर पर अधिकांश सैलून पुरुषों की तुलना में महिलाओं के बाल काटने पर अधिक शुल्क लेते हैं। यह रेज़र और डियोडरेंट जैसे व्यक्तिगत देखभाल संबंधी उत्पादों के लिये भी सही है।

नोट :

- एक प्रसिद्ध ब्रांड के डिस्पोज़ेबल रेज़र की कीमत पुरुषों के लिये लगभग 20 रुपए के आसपास है और उसी कंपनी की महिलाओं के लिये सबसे सस्ती डिस्पोज़ेबल रेज़र की कीमत 55 रुपए के करीब है। जबकि 'महिला संस्करण' पैकेजिंग के अलावा सामान्य से शायद ही अलग हो।

क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग

- हाल ही में मर्सर (Mercer) ने क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग (Quality of Living Ranking- 2019) जारी किया है।
- ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को रहने योग्य शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा दूसरे स्थान पर स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख शहर है।
- तीसरे स्थान पर कनाडा का वैंकूवर, जर्मनी का म्यूनिख और न्यूज़ीलैंड का ऑकलैंड हैं।
- 231 शहरों की सूची में भारत के हैदराबाद और पुणे को 143वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- बंगलूरू-149, मुंबई-154 और कोलकाता 160वें स्थान पर है।
- यह इंडेक्स शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, लोक सेवाओं और परिवहन, उपभोक्ता सामानों की उपलब्धता, आर्थिक वातावरण, सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण इत्यादि जैसे संकेतकों पर आधारित होता है।
- ज्ञातव्य है कि मर्सर (Mercer) मानव संसाधन के बारे में परामर्श देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति ने क्रेडिट रेटिंग की गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के तरीकों पर चर्चा की।

- भारत में सेबी (Security Exchange Board of India-SEBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़) विनियम, 1999 के तहत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को परिचालित करता है।
- वर्त्तमान में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ CRISIL, ICRA, CARE, INFOMERICS, BRICKWORK, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और ACUITE रैंकिंग एंड रिसर्च लिमिटेड सेबी के अंतर्गत पंजीकृत हैं।
- गौरतलब है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- सेबी के मुख्य कार्य हैं-
  1. प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
  2. प्रतिभूति बाज़ार (Securities Market) के विकास का उन्नयन तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का प्रावधान करना।

भारत ऊर्जा प्रारूपण फोरम

- हाल ही में नीति आयोग और संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने भारत ऊर्जा प्रारूपण फोरम (IEMF) की पहली कार्यशाला आयोजित की।
- पैसिफिक नॉर्थ-वेस्ट नेशनल लैबोरेटरी (PNNL) के सहयोग से इस दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- यह फोरम भारत के ऊर्जा भविष्य के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान, परिदृश्य परिचर्चा व योजना निर्माण के लिये एक मंच उपलब्ध कराता है।
- कार्यशाला में आठ विशेषज्ञ-सत्र आयोजित किये गए। इन सत्रों में भारत-केंद्रित ऊर्जा प्रारूपण पर चर्चा हुई।
- पैनल विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में ग्रामीण-शहरी विभेद को कम करने पर विशेष ज़ोर दिया।
- फोरम का लक्ष्य भारत सरकार तथा नीति निर्माताओं व विशेषज्ञों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को बेहतर बनाना तथा भारतीय संस्थानों के क्षमता निर्माण और शोध के लिये भविष्य के क्षेत्र की पहचान करना है।

नोट :

नवाचार और उद्यमिता उत्सव-2019

नवाचार और उद्यमिता उत्सव-2019 (FINE) राष्ट्रपति कार्यालय की एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर के नवाचारों को मान्यता देना, उन्हें सम्मानित तथा पुरस्कृत करना और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।

- यह रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशीलता का महोत्सव है जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी।
- नवाचार और उद्यमिता उत्सव (FINE) को पहले नवाचार उत्सव (Festival of Innovation-FOIN) के रूप में जाना जाता था।
- 2018 तक यह उत्सव राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता था। किंतु इस वर्ष इसे गुजरात के गांधीनगर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- इसका आयोजन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया है।
- आयोजन के दौरान 10वें द्विवार्षिक नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन पुरस्कार का भी वितरण किया गया।
- नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF)
- भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से वर्ष 2000 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) की स्थापना की गई थी।
- नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने देश में ज़मीनी स्तर पर तकनीकी नवाचारों और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को मज़बूत करने में योगदान दिया है।
- NIF ने देश भर से विचारों, नवाचारों और पारंपरिक ज्ञान का एक विशाल डेटाबेस तैयार किया है।

AFINDEX-19

भारत और 16 अफ्रीकी देशों के बीच 10 दिवसीय अफ्रीका-भारत संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास (Africa-India Joint Field Training Exercise-AFINDEX) पुणे में आयोजित किया जाएगा।

- गौरतलब है कि यह अभ्यास पुणे के औंध मिलिट्री स्टेशन (Aundh Military Station) और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग (College of Military Engineering) में 18 से 27 मार्च, 2019 तक चलेगा।
- यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और एक दर्जन से अधिक अफ्रीकी देशों के बीच किया जाएगा। इसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों को बढ़ाना और संयुक्त शांति अभियानों को गति देना है।
- AFINDEX-19 अफ्रीकी महाद्वीप के सदस्य राष्ट्रों के साथ बढ़ते राजनीतिक और सैन्य संबंधों की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और इससे इन देशों के साथ पहले से ही मज़बूत रणनीतिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

योनो कैश

भारतीय स्टेट बैंक ने देश भर में 16,500 से अधिक एसबीआई एटीएम से कैशलेस निकासी के लिये 'योनो कैश' (YONO Cash) एप लॉन्च किया।

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक अब बिना कार्ड का इस्तेमाल किये एटीएम से कैश निकाल सकेंगे।
- देश में बिना कार्ड के रुपए निकालने की सुविधा देने वाला SBI पहला बैंक है।
- डेबिट कार्ड द्वारा कैश निकालने में होने वाले फ्रॉड को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
- 'योनो कैश' एप उपयोगकर्त्ताओं को डेबिट कार्ड के बिना नकदी निकालने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य YONO कैश एप के माध्यम से अगले दो वर्षों में पूरे लेनदेन तंत्र को एक मंच के तहत एकीकृत करना है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) के रूप में मनाया जाता हैं।

- यह उपभोक्ता अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।

नोट :

- इस दिन को मनाने का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान, उनके हितों की रक्षा करना और साथ ही सामाजिक अन्याय, जो उन अधिकारों को कमज़ोर करता है, के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करना है।
- इसकी घोषणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ़ केनेडी द्वारा की गई थी, जिसमें उपभोक्ताओं के चार मूलभूत अधिकार बताए गए हैं-
  - सुरक्षा का अधिकार
  - सूचना पाने का अधिकार
  - चुनने का अधिकार
  - सुने जाने का अधिकार
- इस वर्ष इसकी थीम 'Trusted Smart Products' (ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स) है।

VC 11184

देश की प्रमुख जहाज़ निर्माता कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) के प्रथम मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ के समुद्री परीक्षणों को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। हर प्रकार की स्थिति में जहाज़ को सफल साबित करने के लिये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड समुद्री परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है।

- इस जहाज़ के निर्माण की शुरुआत 30 जून, 2014 को की गई थी। इसका निर्माण राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एक तकनीकी खुफिया एजेंसी जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की देखरेख में काम करती है) के लिये किया गया है।
- इस परियोजना की लागत लगभग 750 करोड़ रुपए है।
- भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद इसका नामकरण किया जाएगा। फिलहाल, इसे केवल VC 11184 नाम दिया गया है।
- यह अपनी तरह का पहला महासागर निगरानी जहाज़ होगा।
- इस जहाज़ के सफल परीक्षण के साथ ही भारत ऐसे देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास इस तरह का परिष्कृत महासागर निगरानी जहाज़ है।
- 300 चालक दल वाले इस जहाज़ में उच्च तकनीकी यंत्र और संचार उपकरण लगे हुए हैं, यह दो डीज़ल इंजनों द्वारा संचालित होता है तथा हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिये इसमें पर्याप्त स्थान है।

भारत के पहले लोकपाल

- हाल ही में लोकपाल की नियुक्ति के लिये गठित समिति ने भारत के पहले लोकपाल के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चन्द्र घोष के नाम पर सहमति दर्ज़ की है।
- इस उच्च-स्तरीय समिति में भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी; भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस रंजन गगोई; लोकसभा स्पीकर, श्रीमती सुमित्रा महाजन और मुख्य अधिवक्ता मुकुल रोहतगी शामिल हैं।
- जस्टिस घोष मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे और मई 2017 में सेवानिवृत्त हुए तथा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं।
- जस्टिस घोष, जस्टिस अमिताव रॉय के साथ उस पीठ का हिस्सा थे जिसने आय से अधिक संपत्ति के मामले में वी.के. शशिकला की सज़ा को बरकरार रखा था।
- गौरतलब है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिये।
- इस अधिनियम में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिये एक सांविधिक निकाय के गठन का प्रावधान है।

नोट :

'खांदेरी' नौसेना में शामिल होने के लिये तैयार

- स्कॉर्पीन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी 'खांदेरी' नौसेना में शामिल होने के लिये तैयार है। इसे अप्रैल के अंत तक या मई की शुरुआत में नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा।
- 'खांदेरी' का जलावतरण जनवरी 2017 में किया गया था और तब से यह परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुज़र रही है।
- छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों को 'प्रोजेक्ट -75I' के तहत मझगांव डॉक्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा फ्राँस से प्राप्त प्रौद्योगिकी की सहायता से बनाया जा रहा है।
- 'खांदेरी' भारतीय नौसेना की स्कॉर्पीन श्रेणी की स्टील्थ पनडुब्बियों में से दूसरी है, पहली पनडुब्बी कलवारी दिसंबर 2017 में नौसेना में शामिल हो चुकी है।
- स्कॉर्पीन क्लास की तीसरी पनडुब्बी 'करंज' भी लॉन्च की जा चुकी है। चौथी पनडुब्बी 'वेला' जलावतरण के लिये तैयार है।
- अंतिम दो पनडुब्बियाँ वागीर और वाग्शीर विनिर्माण के उन्नत चरणों में हैं। यह परियोजना 2020 तक पूरी होने की उम्मीद है।

CAPEX

भारतीय रिज़र्व बैंक के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, 2018-19 की पहली छमाही में मंज़ूर की गई परियोजनाएँ पूंजीगत व्यय (Capital Expenditures-CapEx) चक्र में सुधार प्रदर्शित कर रही हैं।

पूंजीगत व्यय (CapEx)

- पूंजीगत व्यय (जिसे आमतौर पर CapEx के रूप में जाना जाता है) किसी कंपनी द्वारा संपत्ति, भवन, औद्योगिक संयंत्र, प्रौद्योगिकी या उपकरण जैसी भौतिक परिसंपत्तियों को हासिल करने, उनका उन्नयन करने तथा उन्हें बनाए रखने हेतु उपयोग में लाया जाता है।
- पूंजीगत व्यय में शामिल हो सकते हैं:
  - संयंत्र और उपकरणों की खरीद
  - भवनों का विस्तार और उनमें सुधार
  - हार्डवेयर की खरीदारी, जैसे-कंप्यूटर
  - माल की ढुलाई हेतु वाहन

क्षुद्र ग्रह 'रायुगु'

जापान की अंतरिक्ष एजेंसी- JAXA 5 अप्रैल, 2019 को अंतरिक्ष यान हायाबुसा-2 से क्षुद्र ग्रह रायुगु (Asteroid Ryugu) पर बेसबॉल के आकार का 2 किलोग्राम विस्फोटक गिराएगी।

- इससे क्षुद्र ग्रह पर एक गड्ढा (Crater) बन जाएगा और इस गहरे भूमिगत क्षेत्र, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, से नमूना एकत्र किया जाएगा।
- इस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यान को विस्फोटक गिराने के तुरंत बाद ही क्षुद्र ग्रह की दूसरी तरफ जाना होगा ताकि विस्फोट से यान को कोई नुकसान न हो।
- ग्रह के दूसरी तरफ जाने के दौरान हायाबुसा-2 विस्फोट की प्रक्रिया और परिणाम को रिकॉर्ड करने के लिये एक कैमरा वहीं छोड़ देगा।
- इस रिकॉर्ड की सहायता से वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति के बारे में विश्लेषण करेंगे।

UNNATEE

हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency-BEE) ने अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल (UNlocking NATional Energy Efficiency potential- UNNATEE) नामक रणनीतिक दस्तावेज़ जारी किया।

नोट :

- भारत में ऊर्जा दक्षता में तेज़ी लाने के लिये यह राष्ट्रीय रणनीतिक दस्तावेज़ विकसित किया गया है।
- यह दस्तावेज़ ऊर्जा आपूर्ति-मांग परिदृश्यों और ऊर्जा दक्षता अवसरों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने के तरीकों का वर्णन करता है।
- भारत के पर्यावरण पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिये UNNATEE ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है।
- गौरतलब है कि BEE भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है।
- BEE ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने, मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढाँचे की पहचान और उपयोग के लिये उपभोक्ताओं, एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

BEE स्टार रेटिंग प्रोग्राम

हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा की है कि दो और बिजली उपकरणों- माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन को अब उनकी ऊर्जा दक्षता मैट्रिक्स के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी।

- स्टार रेटिंग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को यह सूचित करना है कि उत्पाद कितना उर्जा दक्ष है।
- इसके तहत 5 स्टार तक रेटिंग दी जाती है। जिन उपकरणों को 4 या 5 स्टार मिला होता है वे 2 या 3 स्टार प्राप्त उपकरण की तुलना में ज़्यादा उर्जा दक्ष होते हैं।
- उपकरणों के निर्माताओं को यह स्टार रेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम, 2006 के अनुसार प्रदान करना होता है।

आपदा जोखिम पर कार्यशाला

हाल ही में आपदा जोखिम को कम करने के लिये तीसरी भारत-जापान कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई।

- भारत और जापान ने आपदा प्रबंधन पर सितंबर 2017 में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये थे।
- गौरतलब है कि इसी को ध्यान में रखते हुए पहली कार्यशाला 18-19 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में तथा दूसरी कार्यशाला 3-15 अक्तूबर, 2018 तक जापान के टोक्यो शहर में आयोजित की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की अनुसंधान संस्थाओं, शहरों और निजी क्षेत्र के बीच आपदा जोखिम को कम करने हेतु सहयोग बढ़ाना है।

एबेल पुरस्कार- 2019

- करेन उलेनबेक को 2019 का एबेल पुरस्कार (Abel Prize) प्रदान किया गया।
- उन्हें यह पुरस्कार ज्यामितीय विश्लेषण और गेज सिद्धांत (Geometric Analysis and Gauge Theory) में उनके द्वारा किये गए मौलिक काम के लिये प्रदान किया गया है।
- गौरतलब है कि करेन उलेनबेक यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं।
- एबेल पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा एक या एक से अधिक गणितज्ञों को दिया जाने वाला पुरस्कार है।
- यह पुरस्कार नॉर्वे के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ 'नील्स हेनरिक एबेल' को समर्पित है और इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी।

अभ्यास 'मित्र शक्ति- 2019'

'मित्र शक्ति' भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है।

- 2018-19 के लिये यह संयुक्त अभ्यास 26 मार्च से 8 अप्रैल, 2019 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा।
- यह अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत एवं श्रीलंका में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- यह 2012 में प्रारंभ हुआ था तथा इस वर्ष इसका छठा संस्करण आयोजित किया जाएगा।

नोट :

- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करना और रणनीतिक समझ बढ़ाना है।
- इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र आदेश के तहत अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह की रोकथाम और आतंकवादी माहौल का मुकाबला करने के लिये युक्तिपूर्ण परिचालनों को शामिल किया जाएगा।

भारत-इंडोनेशिया समन्वित निगरानी

33वें भारत–इंडोनेशिया समन्वित निगरानी (IND-INDO CORPAT) अभियान प्रारंभ हो चुका है। गौरतलब है कि यह निगरानी अभियान 19 मार्च से 4 अप्रैल, 2019 तक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया जाना है।

- दोनों देशों के जहाज़ और विमान 236 नॉटिकल माइल लंबी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर गश्त करेंगे।
- यह गश्त 22-31 मार्च, 2019 तक तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। इसके बाद इंडोनेशिया के बेलावन में एक समापन समारोह होगा, जो 01-04 अप्रैल, 2019 तक चलेगा।
- पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह में निगरानी अभियान के दौरान दोनों नौसेनाओं के बीच खेल-कूद और आपसी वार्ता जैसी विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई है।
- दोनों देशों की नौसेनाएँ रणनीतिक साझेदारी की व्यापक परिधि के अंतर्गत 2002 से वर्ष में दो बार 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा' (IMBL) पर समन्वित निगरानी का कार्य कर रही हैं।
- इसका उद्देश्य मित्रवत् देशों के साथ समुद्री क्षेत्र में भारत की शांतिपूर्ण उपस्थिति एवं एकता के लिये बेहतर माहौल सुनिश्चित करना तथा भारत-इंडोनेशिया के बीच मौजूदा संबंधों को सुदृढ़ करना है।
- इसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौपरिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये सुरक्षित बनाने पर विशेष बल दिया गया है।
- हाल के समय में क्षेत्र के समुद्री खतरों से निपटने के लिये भारतीय नौसेना की तैनाती बढ़ी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के 'सागर' (Security and Growth for All in the Region) विज़न के एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में कई राष्ट्रों की सहायता कर रही है।

क्षुद्रग्रह बेन्नू पर जल के प्रमाण

- हाल ही में नासा द्वारा बेन्नू (Bennu) नामक क्षुद्रग्रह पर जलवाहक खनिज तत्त्वों की खोज की गई है।
- नासा के अंतरिक्ष यान Osiris-Rex (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) द्वारा यह खोज की गई है।
- OSIRIS-REx को 8 सितंबर, 2016 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था।
- दो साल की यात्रा के पश्चात् इस अंतरिक्षयान ने बेन्नू क्षुद्रग्रह की परिक्रमा पिछले वर्ष 31 दिसंबर को शुरू की थी और यह 2023 में पृथ्वी पर नमूने भेजेगा।
- बेन्नू क्षुद्रग्रह की खोज लिंकन नियर-अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च (Lincoln Near-Earth Asteroid Research- LINEAR) द्वारा 11 सितंबर, 1999 को की गई थी। इसे मूल रूप से 1999 RQ36 नाम दिया गया था।
- यह सूर्य के चारों ओर अण्डाकार कक्षा में परिक्रमा करने वाला 500 मीटर चौड़ा एक क्षुद्रग्रह है। यह एक कार्बनयुक्त संरचना है जिसमें बड़ी मात्रा में कार्बन शामिल है।

विश्व जल दिवस- 2019

- प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को लोगों के बीच जल का महत्त्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये विश्व जल दिवस मनाया जाता है।
- वर्ष 2019 के लिये इसकी थीम 'Leaving no one behind' (लीविंग नो वन बिहाइंड) है।
- यह थीम सतत् विकास लक्ष्य- 6 (Clean Water and Sanitation) को निरूपित करती है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मार्च, 1993 को पहला विश्व जल दिवस आयोजित किया थाl

नोट :

नवरोज़

- 21 मार्च को पारसियों का प्रमुख त्योहार नवरोज़ मनाया गया।
- नवरोज़ 3,000 साल पुरानी एक पारसी परंपरा है जो पारसी नए साल की शुरुआत का संकेत देता है।
- यह वसंत विषुव के दिन मनाया जाता है और उत्तरी गोलार्द्ध में वसंत की शुरुआत को चिह्नित करता है।
- यह ईरानी कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है।
- इस दिन परिवार के लोग इकठ्ठा होते हैं और उत्सव मनाते हैं।

साइक्लोन ट्रेवर और वेरोनिका (Cyclone Trevor & Veronica)

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आए ट्रेवर और वेरोनिका नाम के दो चक्रवाती तूफानों से ऑस्ट्रेलिया के तटों में भूस्खलन होने की आशंका जताई जा रही है।

- ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमोत्तर तट पर वेरोनिका चक्रवात तथा पूर्वोत्तर तट पर ट्रेवर चक्रवात आया
- ट्रेवर और वेरोनिका हरिकेन और साइक्लोन की तरह ही हैं केवल इनके चक्रण की दिशा वामावर्त के बजाय दक्षिणावर्त है।
- सामान्यत: उत्तरी गोलार्द्ध में चक्रवात की दिशा वामावर्त है, और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त होती है।
- भीषण ऊष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रेवर के कारण बंदरगाह परिचालन बाधित रहा साथ ही विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई।
- इस चक्रवात की गति लगभग 165 किलोमीटर प्रति घंटे आँकी गई है।

गोलन हाइट्स (Golan Heights)

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान के पश्चात् 'गोलन हाइट्स' फिर से चर्चा में आ गया।

- गोलन हाइट्स दक्षिणी-पश्चिमी सीरिया में एक पथरीला पठार है जिसका राजनीतिक और रणनीतिक महत्त्व है।
- इज़राइल ने 1967 के छह दिवसीय युद्ध में इस पर कब्ज़ा कर लिया था।
- इसके पश्चात् एक युद्धविराम रेखा की स्थापना हुई और यह क्षेत्र इज़राइल के सैन्य नियंत्रण में आ गया।
- सीरिया ने 1973 के युद्ध के दौरान गोलन हाइट्स को वापस लेने की कोशिश की किंतु वह सफल नहीं हो पाया।
- दोनों देशों ने 1974 में युद्धविराम पर हस्ताक्षर किये और संयुक्त राष्ट्र का एक पर्यवेक्षक बल 1974 से युद्धविराम रेखा पर ध्यान रखे हुए है।
- 1981 में इज़राइल ने गोलन हाइट्स पर अपने अधिकार की घोषणा की किंतु उसके इस कदम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है।

अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एयरो एक्सपो-2019 International Maritime Aero Expo (LIMA) 2019

लांगकावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाईम एयरो एक्सपो (LIMA-2019) 26 मार्च, 2019 से 30 मार्च, 2019 तक मलेशिया के लांगकावी में आयोजित किया जाना है।

- भारतीय वायुसेना पहली बार मैरीटाइम एयरो एक्सपो में भाग ले रही है। इस दौरान अपने देश में विकसित एलसीए युद्धक विमान को प्रदर्शित किया जाएगा।
- भारतीय वायुसेना की टीम वायुसेना स्टेशन कलईकुंडा से 22 मार्च, 2019 को रवाना हुई। यह टीम म्यामाँर (यांगून) होते हुए लांगकावी जाएगी।
- LIMA-2019 में भारतीय वायुसेना की भागीदारी से वायुसैनिकों को रॉयल मलेशियाई वायुसेना (RMAF) के वायुसैनिकों से बातचीत करने का अवसर मिलेगा और दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच निकट संपर्क कायम हो सकेगा।
- यह भविष्य में मलेशियाई वायुसेना के साथ किसी प्रकार के संपर्क के लिये एक आधार के रूप में काम करेगा। इससे RMAF को भी एलसीए की क्षमताओं को परखने का एक अवसर मिलेगा।
- भारतीय वायुसेना की खेप में 2 एलसीए, 1 सी-130जे और 1 आईएल-76 के साथ 27 अधिकारी, 42 वायुसैनिक और 11 एचएएल कार्मिक शामिल हैं।

नोट :

लाइटसेल 2

- लाइटसेल 2 नियंत्रित सौर सेलिंग को प्रदर्शित करने हेतु एक परियोजना है।
- लाइटसेल 2 (LightSail 2) को फ्लोरिडा, अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अप्रैल 2019 में लॉन्च किया जाएगा।

सौर सेलिंग (Solar Sailing) क्या है ?

- सौर सेलिंग अंतरिक्षयानों की एक ऐसी प्रस्तावित प्रणोदन प्रणाली है जो सूर्य जैसे विभिन्न तारों द्वारा उत्पन्न विकिरण के प्रयोग से अंतरिक्षयानों को गति प्रदान करेगी।
- सौर सेलिंग प्रणाली से युक्त अंतरिक्षयानों के पास असीमित मात्रा में ईंधन होगा जो उन्हें खगोलीय दूरी पार कराने में सक्षम बना देगा।
- लाइटसेल 2 उन तीन उपग्रहों में से एक है जिन्हें सौर विकिरण का उपयोग करते हुए अंतरिक्षयान को गति देने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिये बनाया गया है।
- इस मिशन को यह देखने के लिये डिज़ाइन किया गया है कि क्या लाइटसेल सूर्य से केवल फोटॉन का उपयोग करके पृथ्वी की उच्च कक्षाओं में जा सकता है।

वर्चुअल सिम कार्ड

पुलवामा हमले की जाँच के दौरान जाँच एजेंसियों ने पाया है कि जैश-ए-मुहम्मद के आतंकवादियों द्वारा हमले में वर्चुअल सिम कार्ड (Subscriber Identification Module Cards) का इस्तेमाल किया गया था।

वर्चुअल सिम क्या है ?

- इस तकनीक में कंप्यूटर द्वारा एक टेलीफोन नंबर उत्पन्न किया जाता है और उपयोगकर्त्ता अपने स्मार्टफोन पर सेवा प्रदाता का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करता है।
- यह एक क्लाउड-आधारित (उपयोगकर्त्ता की सक्रियता के बगैर इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली सेवाएँ, खास तौर से डेटा स्टोरेज़) नंबर है जिसका उपयोग किसी भी उपकरण से एप के माध्यम से किया जा सकता है।
- इस वर्चुअल फोन नंबर के माध्यम से होने वाली सभी वॉयस कॉल और एसएमएस मोबाइल में उपलब्ध मोबाइल डेटा/वाई-फाई कनेक्शन की सहायता से वर्चुअल सिम (Virtual Sim) सेवा प्रदाता के नेटवर्क पर स्थानांतरित किये जाते हैं।

CBSE शिक्षा वाणी

हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education-CBSE) ने सभी हितधारकों को समान रूप से सूचना प्रसारित करने के लिये 'CBSE शिक्षा वाणी' नाम से एक नया एंड्रॉइड एप लॉन्च किया है।

- इस एप पर बोर्ड ने 2019 की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जाँच के लिये दिशा-निर्देश भी अपलोड किये हैं। गौरतलब है कि CBSE समय-समय पर महत्त्वपूर्ण सूचनाओं की घोषणा करता रहता है, जिन्हें हितधारकों तक पहुँचाने की ज़रूरत होती है।
- इस एप के माध्यम से CBSE को बेहतर तरीके से ऐसा करने में मदद मिलेगी।
- इस एप में सूचना का आकलन संबंधित व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है तथा इसमें बोर्ड परीक्षा के परिणाम की तैयारी के बारे में भी जानकारी दी गई है।

विश्व क्षय रोग दिवस

24 मार्च को दुनियाभर में विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया गया। क्षय रोग को तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है।

- इस वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस की थीम 'It's Time (यही समय है) रखी गई है।
- इस भावना के अनुरूप भारत ने वैश्विक लक्ष्य से पाँच वर्ष पूर्व ही अर्थात् 2025 तक क्षय रोग के उन्मूलन के लिये प्रतिबद्धता जताई है।

नोट :

- Revised National TB Control Program (RNTCP) के तहत क्षय रोग के नियंत्रण और उन्मूलन के लिये 'क्षय रोग 2017-2025 राष्ट्रीय रणनीतिक योजना' चलाई जा रही है। यह दिवस क्षय रोग से संबंधित समस्याओं और समाधान के बारे में लोगों को जागरूक करने और विश्वभर में इसके नियंत्रण के प्रयासों का समर्थन करने के लिये मनाया जाता है।
- गौरतलब है कि 1882 में क्षय रोग (TB) के जीवाणु की खोज करने वाले डॉ. रॉबर्ट कोच की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास (AUSINDEX)

हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनज़र भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 से 16 अप्रैल तक एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास (Bilateral Naval Exercise) में भाग लेंगे।

- यह 1947 के बाद ऑस्ट्रेलिया की अपनी रक्षा परिसंपत्तियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा।
- AUSINDEX अभ्यास का मुख्य फोकस 'पनडुब्बी-रोधी वारफेयर' (Anti-Submarine Warfare) होगा और यह अभ्यास विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित होगा।
- दोनों पक्ष P-8 I तथा P-8 A विमान तैनात करेंगे जो कि 'लंबी दूरी की पनडुब्बी-रोधी वारफेयर, एंटी-सरफेस वारफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही विमान' हैं और व्यापक क्षेत्र (Broad Area), तटीय तथा समुद्री परिचालन में सक्षम हैं।
- P-8I, P-8A Poseidon का एक प्रकार है जिसे अमेरिकी नौसेना के लिये विकसित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के पास P-8I विमान है जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास P-8A विमान है।

GRAPES-3, म्यूओन टेलीस्कोप फैसिलिटी (Muon detection facility)

हाल ही में, दुनिया में पहली बार ऊटी में GRAPES-3 म्यूओन टेलीस्कोप फैसिलिटी (Moun Telescope Facility) के शोधकर्त्ताओं ने 1 दिसंबर, 2014 में हुई घटना जिसमें सिर के ऊपर से गुज़रने वाले बादलों की गरज़ के साथ बिजली की चमक की ऊँचाई, आकार तथा विद्युतीय क्षमता को मापा है।

- GRAPES-3 (Gamma Ray Astronomy PeV EnergieS Phase -3) को एयर शॉवर डिटेक्टरों तथा एक बड़े क्षेत्र म्यूऑन डिटेक्टर के साथ कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- Muon में इलेक्ट्रॉन के समान एक प्राथमिक कण होता है, जिसमें अधिक द्रव्यमान के साथ -1 e का विद्युत आवेश तथा 1/2 का एक स्पिन होता है।
- भारत में ऊटी में स्थित GRAPES-3 प्रयोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई तथा ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी, ओसाका, जापान के सहयोग से शुरू हुआ।
- इस क्लाउड में 1.3 गीगावाट (GV) की क्षमता थी जो पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 10 गुना अधिक क्षमता थी।

भारतीय सेना का पर्वतारोहण अभियान

हाल ही में माउंट मकालू (8485 मीटर) के लिये प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण (First Indian Army Mountaineering) अभियान की शुरुआत की गई है।

- भारतीय सेना ने 8000 मीटर से ऊँची सभी चुनौतीपूर्ण चोटियों को फतह करने का लक्ष्य बनाया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने माउंट मकालू हेतु अपने पहले अभियान की शुरुआत की है।
- माउंट मकालू दुनिया की पाँचवी सबसे ऊँची चोटी है जिसकी ऊँचाई 8485 मीटर है।
- इस चोटी को दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत चोटियों में से एक माना जाता है और मौसम की दुरूह परिस्थितियों तथा हाड़ कंपा देने वाली ठंड के कारण उस पर चढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण समझा जाता है।

नोट :

- यह पर्वत चोटी पर्वतारोहियों की तकनीकी सूझबूझ, मानसिक और शारीरिक साहस तथा माउंट मकालू के शिखर तक पहुँचने के उनके संकल्प की परीक्षा लेती है।
- इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये भारतीय सेना अपने दल को पिछले छह महीनों से कड़ा प्रशिक्षण दे रही थी।
- इस अभियान की तैयारियों के तहत इस दल ने माउंट कामेट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की।
- यह दल इस चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए नई दिल्ली से रवाना होगा और माउंट मकालू की चोटी के शिखर तक पहुँचने के रास्ते में 6 शिविर स्थापित किये जाएंगे।

मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया-प्रशांत समूह

वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (Financial Action Task Force-FATF) द्वारा पाकिस्तान को ग्रे-लिस्ट में शामिल किये जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया-प्रशांत समूह भी पाकिस्तान को ग्रे-लिस्ट में शामिल करने पर विचार कर रहा है।

एशिया-प्रशांत समूह (Asia-Pacific Group- APG)

- APG एशिया-प्रशांत क्षेत्र हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (FATF) की शैली पर आधारित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- एशिया-प्रशांत समूह में भारत सहित 41 सदस्य हैं। एशिया-प्रशांत समूह यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि इसके सदस्य बड़े पैमाने के विनाशकारी हथियारों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं।
- APG को 13 मूल संस्थापक सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से एक स्वायत्त क्षेत्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निकाय के रूप में बैंकाक, थाईलैंड में 1997 में स्थापित किया गया था।

और पढ़ें...

विशेष : FATF : शिकंजे में पाकिस्तान
वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल ने जारी की 11 देशों की सूची
एफएटीएफ ने पाकिस्तान के लिये 10 बिंदुओं की योजना बनाई

एम्प्लॉयी स्टॉक परचेज़ स्कीम

हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एम्प्लॉयी स्टॉक परचेज़ स्कीम (Employee Stock Purchase Scheme-ESPS) के माध्यम से कर्मचारियों से लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है।

- एम्प्लॉयी स्टॉक परचेज़ स्कीम किसी कंपनी द्वारा संचालित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले कर्मचारी कंपनी के शेयरों को रियायती मूल्य पर खरीद सकते हैं।
- कंपनियाँ एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान (Employee Stock Option Plans-ESOPs) या एम्प्लॉयी स्टॉक परचेज़ स्कीम (ESPS) के रूप में अक्सर अपने कर्मचारियों को स्टॉक से पुरस्कृत करती हैं।
- एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान ऐसे स्टॉक होते हैं जिन्हें कर्मचारियों को एक तय अवधि में दिया जाता है। इस ऑप्शन प्लान के तहत कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी का शेयर खरीदने का अधिकार दिया जाता है।
- एम्प्लॉयी स्टॉक परचेज़ स्कीम (ESPS) कर्मचारियों को कंपनी के स्टॉक खरीदने (आमतौर पर रियायती मूल्य पर) हेतु अपने वेतन का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।
- एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान (ESOPs) के विपरीत, एम्प्लॉयी स्टॉक परचेज़ स्कीम (ESPS) धारकों के पास कोई विकल्प नहीं होता है, उन्हें अपने वेतन से मासिक कटौती के माध्यम से कीमत का भुगतान करना अनिवार्य होता है।

3 वैज्ञानिकों को ट्यूरिंग पुरस्कार

हाल ही में योशुआ बेन्जियो, जेफरी हिंटन और यान ली चुन को ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में डीप लर्निंग (Deep Learning) में विशेष योगदान के लिये इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2018 का ट्यूरिंग पुरस्कार दिया जा रहा है।

नोट :

- ध्यातव्य है कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का उपयोग बढ़ता जा रहा है।
- इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) तकनीकी को विकसित किया है।

ट्यूरिंग पुरस्कार

- एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी (Association of Computing Machinery) द्वारा स्थापित एसीएम ए.एम. ट्यूरिंग पुरस्कार (ACM A.M. Turing Award) को तकनीकी का नोबेल भी कहा जाता है।
- ट्यूरिंग अवार्ड 'कंप्यूटर क्षेत्र में स्थायी और प्रमुख तकनीकी महत्त्व' (Lasting and Major Technical Importance to the Computer Field) के योगदान के लिये दिया जाता है।
- ट्यूरिंग अवार्ड का नाम ब्रिटिश गणितज्ञ, एलन एम. ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने कंप्यूटिंग की गणितीय नींव और सीमाओं को स्पष्ट किया था।

रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव

हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने गैर-प्रवासियों (NRIs) को रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (Rupee Interest Rate Derivatives) में भागीदारी की अनुमति दे दी है जिसका उद्देश्य रुपया ब्याज दर स्वैप (Interest Rate Swap-IRS) बाज़ार को और अधिक प्रभावी बनाना है।

- गैर-प्रवासी भारतीय मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ओवर द काउंटर मार्केट्स में रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में लेनदेन कर सकते हैं।
- इस कदम से घरेलू बाज़ार में गैर-निवासियों की भागीदारी बढ़ने के साथ-साथ डॉलर के मुकाबले रुपए को स्थिरता भी मिलेगी।
- 'रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव' एक ऐसा वित्तीय साधन है, जो ब्याज दरों में परिवर्तन के साथ बढ़ता और घटता है।
- 'रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव' का उपयोग अक्सर संस्थागत निवेशकों, बैंकों, कंपनियों और लोगों द्वारा हेज के रूप में किया जाता है ताकि बाज़ार ब्याज दरों में बदलाव की स्थिति से बचा जा सके।

नमक की सबसे लंबी गुफा

हाल ही में इज़राइली शोधकर्त्ताओं ने दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोजने का दावा किया है।

- माल्हम नामक यह गुफा माउंट सोडोम से मृत सागर के दक्षिण-पश्चिम कोने तक फैली हुई है। गौरतलब है कि इस गुफा की लंबाई 10 किलोमीटर से ज़्यादा है।
- इससे पहले ज्ञात दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा ईरान में थी।
- हिब्रू विश्वविद्यालय के गुफा अनुसंधान केंद्र (CRC), इज़राइली गुफा खोजकर्त्ता क्लब और बुल्गारिया के सोफिया स्पेलियो क्लब ने नौ देशों के 80 खोजकर्त्ताओं के साथ मिलकर इस गुफा का मानचित्रण किया है।
- इस गुफा की छत से नमक के बड़े-बड़े टुकड़े लटके हैं। अक्सर इन टुकड़ों से बूँदों के रूप में खारा पानी टपकता रहता है।

मांकडिंग

हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग-2019 (IPL-2019) के एक क्रिकेट मैच के दौरान एक बल्लेबाज़ को मांकडिंग से रन आउट (जिसे मांकडिंग भी कहा जाता है) कर दिया गया।

मांकडिंग क्या होता है

- पूर्व भारतीय गेंदबाज वीनू मांकड़ के नाम पर इस तरीके को 'मांकडिंग' नाम दिया गया था।
- मांकडिंग में नॉन-स्ट्राइकर बल्लेबाज़ को बॉलर द्वारा गेंद फेंकने से पहले ही रन आउट कर दिया जाता है।

नोट :

- यदि गेंदबाज़ को ऐसा प्रतीत हो कि नॉन-स्ट्राइकर बल्लेबाज़ गेंद फेंकने से पहले ही क्रीज़ से बाहर निकल रहा है तो वह नॉन-स्ट्राइकर छोर की गिल्लियाँ उड़ाकर उसे आउट कर सकता है।
- रन-आउट के इस तरीके को क्रिकेट की दुनिया में खेल-भावना के विपरीत माना जाता रहा है।

वीनू मांकड से संबंध

- वीनू मांकड ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज़ बिल ब्राउन को दिसंबर 1947 में दो बार रन आउट किया था।
- यह घटना मांकडिंग के सबसे मज़बूत उदहारण के रूप में जानी जाती है।

आईएनएस 'मगर'

स्थल और जल दोनों ही क्षेत्रों के लिये अनुकूल एक महत्त्वाकांक्षी युद्धपोत आईएनएस 'मगर' (INS Magar) मोज़ाम्बिक के चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के लिये आवश्यक राहत सामग्री के साथ मुंबई से पोर्ट बीरा के लिये रवाना हो गया।

- भारतीय युद्धपोत आवश्यक दवाओं, एंटी-एपिडेमिक ड्रग्स, खाद्य पदार्थों, कपड़े, मरम्मत की सामग्री, पुनर्वास उपकरण तथा अस्थायी आश्रयों सहित 300 टन राहत सामग्री ले जा रहा है।
- जहाज़ एक नौसेना चेतक लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर भी ले जा रहा है, जिसका उपयोग राहत कार्यों में किया जाएगा।
- आईएनएस सुजाता, शारदुल और सारथी के बाद पोर्ट बीरा के लिये रवाना होने वाला यह भारतीय नौसेना के एक प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का चौथा जहाज़ है, जो मोज़ाम्बिक में भारतीय नौसेना के मौजूदा मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief-HADR) प्रयासों में जुटे हैं।

ओडिसी नृत्य

- ओडिसी नृत्य का उद्भव ओडिशा के मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों से हुआ था। यह एक शास्त्रीय नृत्य है।
- अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के समान ओडिसी नृत्य के भी दो प्रमुख पक्ष हैं- प्रथम 'नृत्य' या 'गैर-निरुपण नृत्य' एवं दूसरा 'अभिनय'।
- इस नृत्य की दो आधारभूत मुद्राएँ 'चौक' और 'त्रिभंग' हैं। 'चौक' एक वर्ग (चौकोर) की स्थिति है। यह शरीर के संतुलन के साथ नृत्य करने की एक पुरुषोचित मुद्रा है।
- 'त्रिभंग' एक स्त्रियोचित मुद्रा है। त्रिभंग का अर्थ है शरीर को तीन भागों- सिर, शरीर और पैर मंप बांटना। इसकी मुद्राएँ और अभिव्यक्तियाँ भरत नाट्यम के समान होती है।
- यह विशेषत: बारहवीं सदी में जयदेव द्वारा रचित गीत गोविन्द पर आधारित है।
- ओडिसी नृत्य को पुरातात्त्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक माना जाता है।
- ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है, साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है।

फकीम वन्यजीव अभयारण्य

नगालैंड में फकीम वन्यजीव अभयारण्य के एक फॉरेस्ट गार्ड, अलेम्बा यमचुंगर (Alemba Yimchunger) को अभयारण्य और उसके आसपास के जंगलों तथा जंगली जानवरों के संरक्षण हेतु 'अर्थ डे नेटवर्क स्टार' (Earth Day Network Star) से सम्मानित किया गया है।

- यह सम्मान अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन द्वारा दिया गया है जो दुनिया के 195 देशों के ग्रीन ग्रुप को एक साथ जोड़ता है।
- फकीम वन्यजीव अभयारण्य नगालैंड के कैफाइर ज़िले में स्थित है जो 642 हेक्टेयर में फैला हुआ है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी और यह म्याँमार से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैला हुआ है।
- इस अभयारण्य में कई वन्यजीव जैसे- तेंदुआ, बाघ, जंगली भैंस, हूलॉक गिबन्स और मिथुन पाए जाते हैं।
- नगालैंड का सबसे लोकप्रिय पक्षी हॉर्नबिल भी बहुतायत संख्या में इस अभयारण्य में पाया जाता है।

नोट :

नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर

डिबेंचर दीर्घकालिक वित्तीय साधन होते हैं जिन्हें पैसा उधार लेने के लिये कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है।

- हालाँकि कुछ डिबेंचर में ऐसी सुविधा होती है जिससे उन्हें शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है। किंतु ऐसे डिबेंचर जिन्हें शेयर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर कहलाते हैं।
- नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं-
  - सिक्योर्ड
  - अनसिक्योर्ड
- सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर कंपनी की परिसंपत्ति द्वारा समर्थित होते हैं। यदि कंपनी अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहती है, तो डिबेंचर धारक या निवेशक उस कंपनी की परिसंपत्तियों के परिसमापन के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके विपरीत अनसिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर में यह सुविधा उपस्थित नहीं होती है।

कॉफी की पाँच किस्मों को जीआई टैग

हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) ने भारतीय कॉफी की पाँच किस्मों को जीआई टैग प्रदान किया है।

जीआई टैग प्राप्त करने वाली पाँच किस्में इस प्रकार हैं-

- कूर्ग अराबिका कॉफी (Coorg Arabica coffee): यह मुख्यत: कर्नाटक के कोडागू ज़िले में उगाई जाती है।
- वायनाड रोबस्टा कॉफी (Wayanaad Robusta coffee): यह मुख्यत: वायनाड ज़िले में उगाई जाती है जो केरल के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है।
- चिकमगलूर अराबिका कॉफी (Chikmagalur Arabica coffee): यह विशेष रूप से चिकमगलूर ज़िले में उगाई जाती है। यह क्षेत्र दक्कन के पठार में अवस्थित है जो कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र से संबंधित है।
- अराकू वैली अराबिका कॉफी (Araku Valley Arabica coffee): इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ज़िले और ओडिशा क्षेत्र की पहाड़ियों से प्राप्त कॉफी के रूप में वर्णित किया जाता है।
  - जनजातियों द्वारा तैयार की जाने वाली अराकू कॉफी के लिये जैव विधि अपनाई जाती है जिसके तहत जैविक खाद एवं हरित खाद का व्यापक उपयोग किया जाता है और जैव कीटनाशक प्रबंधन से जुड़े तौर-तरीके अपनाए जाते हैं।
- बाबा बुदन गिरि अराबिका कॉफी (Bababudangiri Arabica coffee): यह भारत में कॉफी के उद्गम स्थल में उगाई जाती है और यह क्षेत्र चिकमंगलूर ज़िले के मध्य क्षेत्र में अवस्थित है।
  - हाथ से तोड़कर प्राकृतिक किण्वन द्वारा संसाधित किया जाता है।
  - इसमें चॉकलेट सहित विशिष्ट फ्लेवर होता है। कॉफी की यह किस्म सुहावने मौसम में तैयार होती है।
  - यही कारण है कि इसमें विशेष स्वाद और खुशबू होती है।

इससे पहले भारत की एक अनोखी विशिष्ट कॉफी 'मानसूनी मालाबार रोबस्टा कॉफी' (Monsooned Malabar Robusta Coffee) को जीआई प्रमाणन दिया जा चुका है।

नोट :

विविध

- केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिये एक नया रेल मंडल बनाने की घोषणा की है। नए मंडल का नाम दक्षिण तटीय रेलवे (SCOR) रखा गया है। इसमें मौजूदा गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीज़न शामिल होंगे। वाल्टेयर डिवीजन को दो भागों में बाँटा जाएगा। वाल्टेयर डिवीजन के एक हिस्से को नए मंडल यानी दक्षिण तटीय रेलवे में शामिल करके पड़ोसी विजयवाड़ा डिवीज़न में मिला दिया जाएगा। वाल्टेयर डिवीजन के बाकी हिस्से को एक नए डिवीज़न में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसका मुख्यालय पूर्वी तटीय रेलवे के अधीन रायगढ में होगा। दक्षिण-मध्य रेलवे में हैदराबाद, सिकंद्राबाद और नांदेड़ डिवीज़न शामिल होंगे। इस समय देश में 17 रेलवे मंडल (Zone) काम कर रहे हैं।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत बनाने के उद्देश्य से इंडिया-कोरिया स्टार्ट-अप हब और स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की। इंडिया-कोरिया स्टार्ट-अप हब डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। इसमें तीन लाख से अधिक स्टार्ट-अप्स और आकांक्षी उद्यमियों ने पंजीकरण कराया है। यह हब भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच नवाचार साझा करने और संसाधन संपन्न बाज़ारों तक पहुँच उपलब्ध कराएगा। स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज भारत और दक्षिण कोरिया के स्टार्ट-अप्स के बीच उद्यमिता कौशल का मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि वे विश्व के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिये मिलकर काम कर सकें। ये मुख्य रूप से वित्तीय साख, आर्थिक अनुमानों, धोखाधड़ी की पहचान, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। गौरतलब है कि सियोल में इन्वेस्ट इंडिया और कोरियाई उद्योग और वाणिज्य मंडल (KCCI) की ओर से 21 फरवरी को भारत-कोरिया व्यापार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था।

- केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीपद येसो नाईक ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान (NIUM) की आधारशिला रखी। यह संस्थान वर्तमान NIUM, बंगलुरू का विस्तार होगा और लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। 200 बिस्तरों वाला अस्पताल बन जाने के बाद NIUM, गाजियाबाद उत्तरी भारत के सबसे बड़े यूनानी औषधि संस्थानों में से एक होगा। स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के अलावा, NIUM में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और स्नातकोत्तर तथा पीएच.डी. स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने की सुविधा भी होगी।

- नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकीय नवाचारों के बारे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) में जागरूकता बढ़ाने और प्रतिस्पर्द्धा तथा अवसरों का सृजन करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिये MSME मंत्रालय ने नई दिल्ली में तकनीकी, प्रौद्योगिकी सहायता और आउटरीच (टेक-सोप 2019) पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि टेक-सोप 2019 MSME और प्रौद्योगिकी नवाचारों के मध्य अंतर को पाटने वाली एक पहल है ताकि वे इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर वैश्विक मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ सकें।

- असम सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिये अपने वयोवृद्ध माता-पिता और अविवाहित दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल करना अनिवार्य किया गया है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने असम कर्मचारी माता-पिता ज़िम्मेदारी और जवाबदेही एवं निगरानी नियम (PRANAM) आयोग का उद्घाटन किया। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी ज़रूरत के समय अपने वृद्ध माता-पिता और अविवाहित भाई-बहन को अनदेखा नहीं करे तथा उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करे, यदि उनके पास अपनी आय का कोई स्रोत नहीं है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष प्रणाम अधिनियम को मंज़ूरी दी थी, जो देश में अपनी तरह का पहला अधिनियम है।

- केंद्र सरकार ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मनेथी में 1299 करोड़ रुपए की लागत से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना को मंज़ूरी दी है। प्रस्तावित संस्थान में 750 बिस्तरों का एक अस्पताल होगा, जिसमें आपातकालीन चिकित्सा/ट्रॉमा बेड, आयुष बेड, निजी बेड तथा ICU स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी बेड शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, एक मेडिकल कॉलेज, आयुष ब्लॉक, ऑडिटोरियम, नाइट शेल्टर (रात में रुकने का स्थान), अतिथि गृह, छात्रावास तथा आवासीय सुविधाएँ होंगी। इसके रखरखाव तथा देखभाल के लिये 6 नए एम्स की तर्ज़ पर एक्सपर्ट मैन पावर का सृजन किया जाएगा। इस एम्स के निर्माण और संचालन का खर्च केंद्र सरकार द्वारा PMSSY के अंतर्गत वहन किया जाएगा।

नोट :

- केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 2 की उप-धारा (V) के तहत व्यक्ति की परिभाषा को संशोधित कर उसके स्थान पर ट्रस्ट को शामिल करने के लिये इस अधिनियम में संशोधन हेतु अध्यादेश लाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था होने से किसी भी ट्रस्ट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को 'व्यक्ति' के रूप में परिभाषित करने की सुविधा भी मिल जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी ट्रस्ट को SEZ में इकाई लगाने की अनुमति नहीं है। इस संशोधन से विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

- लापता और शोषित बच्चों के बारे में ऑनलाइन जानकारी तक पहुँच बनाने के लिये भारत और अमेरिका ने एक समझौता किया है। इस पर भारत की ओर से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और अमेरिका की ओर से नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लायटेड चिल्ड्रन (NCMEC) ने हस्ताक्षर किये। यह समझौता अमेरिका के NCMEC के पास उपलब्ध एक लाख से अधिक ऑनलाइन रिपोर्टों तक पहुँच और भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकार प्रदान करेगा। इससे अश्लील बाल-साहित्य और बच्चों के यौन उत्पीड़न संबंधी सामग्री के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के लिये एक नए तंत्र की स्थापना हो सकेगी और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। यह समझौता कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अश्लील बाल-साहित्य और बच्चों के यौन उत्पीड़न संबंधी सामग्री को साइबर स्पेस से हटाने का अधिकार प्रदान करेगा।

- केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र स्थापित करने की मंज़ूरी दे दी है। इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा और इसका नाम दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र, ग्वालियर होगा। इस केंद्र को लगभग 170.99 करोड़ रुपए की लागत से पाँच वर्षों में निर्मित किया जाएगा। इस केंद्र द्वारा खेल-कूद के लिये बेहतर बुनियादी ढाँचा तैयार किये जाने से विभिन्न खेलों में दिव्यांगजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित होगी और वे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा के लिये अधिक सक्षम होंगे। गौरतलब है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-30 के तहत सरकार द्वारा खेलों में दिव्यांजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ उनके खेल-कूद के लिये ढाँचागत सुविधाओं के प्रावधान भी शामिल हैं।

- अजय नारायण झा को 15वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने शक्ति कांत दास की जगह ली है, जिन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक का गर्वनर नियुक्त होने पर वित्त आयोग की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वित्त आयोग में शामिल होने से पहले 1982 बैच के मणिपुर कैडर के IAS अजय नारायण झा भारत सरकार के वित्त सचिव थे। वह RBI के पूर्व गर्वनर की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग के सचिव पद पर भी रह चुके हैं। विदित हो कि राष्ट्रपति के आदेश से 5 वर्षों की अवधि यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2025 के लिये केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे का फार्मूला तय करने के लिये 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था।

- अंतरिक्ष के मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक नया मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष की मौसम प्रणाली को समझने के लिये लगभग 4 करोड़ डॉलर की लागत वाले इस मिशन का नाम एटमोस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट (AWE) रखा गया है। 2022 में लॉन्च किया जा यहाँ से यह मिशन पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद प्रकाश के कलर्ड बैंड पर फोकस करेगा जिसे एयरग्लो कहा जाता है।

- अमेरिकी ऊर्जा विभाग की राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई प्रक्रिया का विकास किया है जिसकी मदद से पॉलिएस्टर मैटेरियल से बनाई जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों, फाइबर आदि को पुन:चक्रित (Recycled) किया जा सकेगा। अभी इनको एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इस प्रक्रिया की मदद से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खराब हो जाने पर उससे कई उपयोगी चीज़ें तैयार की जा सकेंगी। इससे प्लास्टिक के उत्पादन में कमी आएगी और महासागरों में बढ़ते जा रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या को कम करने में भी मदद मिल सकेगी। इस प्रक्रिया में PET के जीवनकाल में वृद्धि की जाती है और इसे पुन:चक्रित किया जाता है।

- भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 25 जनवरी, 2019 को IEA बायो-एनर्जी TCP का 25वाँ सदस्य बन गया है। आपको बता दें कि बायो-एनर्जी (IEA बायो-एनर्जी TCP) संबंधी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहयोग कार्यक्रम विभिन्न देशों के बीच सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका उद्देश्य बायो-एनर्जी अनुसंधान और विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाने वाले देशों के बीच सहयोग

नोट :

तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार करना है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड्स, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विटज़रलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोपीय संघ इसके अन्य सदस्य हैं। IEA बायो-एनर्जी TCP, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के दायरे में काम करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा IEA बायो-एनर्जी TCP में शामिल होने का प्रमुख उद्देश्य उन्नत बायो ईंधन के विपणन को बढ़ावा देना है, ताकि उत्सर्जन में कमी लाई जा सके और कच्चे तेल के आयात में कटौती की जा सके।

- केंद्र सरकार ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) की स्थापना के लिये अध्यादेश लाने को मंज़ूरी दी है जिसका उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता के लिये एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण करना है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:
  - अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता हेतु एक प्रमुख संस्थान के तौर पर खुद को विकसित करने के लिये लक्षित सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना।
  - समाधान हेतु मध्यस्थता और मध्यस्थता संबंधी कार्यवाहियों के लिये सुविधाएँ और प्रशासकीय सहयोग प्रदान करना।
  - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मान्यता प्राप्त पंचों, मध्यस्थों व सुलहकारों या सर्वेक्षकों और जाँचकर्त्ताओं जैसे विशेषज्ञों के पैनल बनाना।
  - प्रोफेशनल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थताओं और सुलहों का सुगम संचालन सुनिश्चित करना।
  - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता और सुलह के संचालन के लिये कम खर्चीली और समयोचित सेवाएँ प्रदान करना।
  - वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों के क्षेत्र में अध्ययन को प्रोत्साहित करना और झगड़ों के निपटारे की व्यवस्था में सुधारों को प्रोत्साहित करना।
  - वैकल्पिक विवाद समाधान को प्रोत्साहित करने के लिये अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाजों, संस्थानों और संगठनों के साथ सहयोग करना।

- केंद्र सरकार ने आधार को लेकर एक अध्यादेश जारी किया है। अब बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन के लिये पहचान-पत्र के रूप में आधार का इस्तेमाल स्वैच्छिक हो गया है। संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिये कड़े दंड का प्रावधान है। यह अध्यादेश लाना इसलिये जरूरी था कि 4 जनवरी को लोकसभा में इससे संबंधित संशोधनों को पारित करने के बावजूद इससे जुड़ा विधेयक राज्यसभा में अटक गया था। ऐसे में लोकसभा भंग होने के बाद यह निष्प्रभावी हो जाता। इस अध्यादेश से आधार एक्ट, 2016, Prevention of Money Laundering Act, 2005 तथा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 में संशोधन किये गए हैं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है। इसके अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

- आतंकवादियों पर लगाम कसने के क्रम में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर पाँच वर्ष के लिये प्रतिबंध लगा दिया है। जमात-ए-इस्लामी कश्मीर (Jamaat-e-Islami Kashmir) दरअसल जमात-ए-इस्लामी नाम के संगठन का एक धड़ा है, जो भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद अस्तित्व में आया और कश्मीर घाटी में सक्रिय हुआ। जमात-ए-इस्लामी के तीन धड़े हैं- जमात-ए-इस्लामी हिंद, जमात-ए-इस्लामी-पाकिस्तान और जमात-ए-इस्लामी कश्मीर। जमात-ए-इस्लामी हिंद को छोड़कर अन्य दोनों धड़े आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2012 के तहत इस संगठन पर पाबंदी लगाने की अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी-SIMI) पर प्रतिबंध पांच वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है।

- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में मन की बात–रेडियो पर एक सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। यह पुस्तक आकाशवाणी द्वारा प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन संवाद कार्यक्रम 'मन की बात' की 50 कड़ियों पर आधारित है। आपको बता दें कि 'मन की बात' का पहला प्रसारण 3 अक्तूबर, 2014 को हुआ था। इस पुस्तक की क्रमवार सामग्री अलाभकारी संगठन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा एकत्रित की गई है और इसका प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा किया गया है।

- वेनेज़ुएला कम संकट से निपटने के लिये अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव को रूस और चीन ने वीटो कर दिया और यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। अमेरिका के प्रस्ताव में वेनेज़ुएला में नए सिरे से राष्ट्रपति चुनाव कराने और निर्बाध मानवीय मदद मुहैया कराने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव के समर्थन में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में नौ देशों ने मतदान किया। रूस और चीन

नोट :

ने इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया। परिषद में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिये नौ मतों की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रस्ताव पारित करने के लिये यह भी ज़रूरी है कि परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों- ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका में से कोई वीटो का इस्तेमाल न करे। इसी तरह के रूस के प्रस्ताव को भी पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया और अमेरिका के विरोध के चलते यह प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाया। रूस के मसौदा प्रस्ताव में शांतिपूर्ण माध्यम से वेनेज़ुएला मामले को सुलझाने की अपील की गई थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और गिनी ने मतदान किया, जबकि अमेरिका सहित यूरोपीय देशों और पेरू ने रूसी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

- 3 मार्च को दुनियाभर में विश्व वन्यजीव दिवस का आयोजन किया गया। संकटग्रस्त जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनको विलुप्त होने से बचाने के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2013 को वन्यजीवों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये इस दिवस को मनाने की पहल की थी। विश्व वन्यजीव दिवस 2019 की थीम Life Below Water: for People & Planet रखी गई है। गौरतलब है कि भारत में वन और वन्यजीवों को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। एक केंद्रीय मंत्रालय वन्यजीव संरक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश बनाने और जारी करने का काम करता है तथा राज्यों के वन विभाग राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करते हैं।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इंडो-रूस राइफल परियोजना की शुरुआत की। अमेठी की कोरवा आयुध फैक्टरी में भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विश्व प्रसिद्ध कलाश्निकोव राइफलों के नवीनतम मॉडल बनाए जाएंगे। इस फैक्ट्री में लाखों की संख्या में AK-203 का निर्माण किया जाएगा, जो AK-103 का अपग्रेडेड वर्जन है। फिलहाल भारत की तीनों सेनाओं के पास इंसास असॉल्ट राइफल हैं, जो कि पुरानी पड़ चुकी हैं। आपको बता दें कि कलाश्निकोव राइफल (Kalashnikov Rifle) मिखाइल कलाश्निकोव द्वारा बनाई और विकसित की गई मूल संरचना पर आधारित स्वालित राइफलों की श्रृंखला में से कोई भी एक हो सकती है। मिखाइल कलाश्निकोव के नाम पर ही इन राइफलों को यह नाम मिला है।

- भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग, मेल-जोल और सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सम्प्रीति' की शुरुआत 3 मार्च को हुई। यह अभ्यास बांग्लादेश के तंगेल में आयोजित किया जा रहा है जो 15 मार्च तक चलेगा। गौरतलब है कि दोनों देशों के मध्य यह आठवाँ युद्धाभ्यास है। संयुक्त अभ्यास में बांग्लादेश की ओर से 36 ईस्ट बंगाल बटालियन जबकि भारत की ओर से राजपूताना राइफल्स की 9वीं बटालियन हिस्सा ले रही है। इस संयुक्त अभ्यास की शुरुआत 2009 में हुई थी। इस अभ्यास में उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला करने और आपदा प्रबंधन के लिये नागरिक अधिकारियों को सहायता देने में उनके सामरिक और तकनीकी कौशल की परख की जाएगी। इसी प्रकार के एक अन्य घटनाक्रम में हाल ही में बांग्लादेश के कोमिला में श्रीमन्तापुर के निकट भारत के बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स तथा बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच तीन दिवसीय मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 संपन्न हुआ। इस अभ्यास का नाम बांग्लादेश के कोमिला के निकट स्थित मैनामती पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया।

- इंडियन रलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये अपना पेमेंट एग्रिगेटर सिस्टम IRCTC iPay लॉन्च किया है। इससे ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करने में आसान होगी। IRCTC iPay से यात्रियों को किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस प्लेटफार्म पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इंटरनेशनल कार्ड जैसे पेमेंट विकल्पों से भुगतान किया जा सकेगा। इससे बैंक और IRCTC के बीच का अंतर कम होगा जिससे पेमेंट असफल होने की संभावना कम होगी। इसके अलावा अगर कभी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन असफल होती है, या अन्य कोई कठिनाई सामने आती है तो IRCTC सीधे बैंक के संपर्क में आ सकता है, जिससे कि इस प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। आपको बता दें कि पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम में एक मूल अंतर है कि पेमेंट गेटवे के तहत सभी तरह की क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट होती है, जबकि पेमेंट एग्रीगेटर में बहुत सारे पेमेंट गेटवे शामिल होते हैं।

- हाल ही में असम में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत हुई है। यह एक कृषि वेब पोर्टल है जो चावल उत्पादन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों, उत्पादन के सर्वोत्तम तरीकों और राज्य कृषि के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिये समर्पित है। इसे विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना-कृषि-व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन (APART) के तहत लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI)

नोट :

की तकनीकी सहायता के साथ असम रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज़ सोसाइटी (ARIAS) तथा असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (AAU) के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। इसका प्रमुख उद्देश्य असम में छोटे किसानों के लिये अनुसंधान और ऑन-फील्ड चावल उत्पादन तरीकों के बीच अंतर को कम करना है।

- केंद्र सरकार ने पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तीन साल की अवधि के लिये उनकी नियुक्ति को मंज़ूरी दी है। गुजरात कैडर के 1981 बैच के IAS की अंतिम नियुक्ति वित्त सचिव के पद पर थी। गौरतलब है कि विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा और इस विलय को सरकार की मंज़ूरी मिल चुकी है। इसी तरह के एक अन्य मामले में रवनीत गिल ने तीन साल की अवधि के लिये निजी क्षेत्र के येस बैंक के MD और CEO का पदभार संभाल लिया। उन्होंने राणा कपूर का स्थान लिया, जो इस बैंक के संस्थापक सदस्यों में हैं। रवनीत गिल 1991 से डोएश बैंक (Deutsche Bank) में भारत में प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे।

- रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) के चेयरमैन जी. सतीश रेड्डी को संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित मिसाइल सिस्टम पुरस्कार से नवाज़ा गया है। वह रेथेऑन (Raytheon) मिसाइल सिस्टम के एक पूर्व प्रमुख इंजीनियरिंग फेलो रॉन्डेल जे. विल्सन के साथ यह पुरस्कार साझा करेंगे। मिसाइल सिस्टम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिये यह पुरस्कार अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया जाता है। आपको बता दंण कि यह पुरस्कार विषम संख्याओं वाले वर्षों में हर दो वर्ष में एक बार मिसाइल सिस्टम प्रौद्योगिकी को विकसित करने और क्रियान्वित करने में उत्कृष्टता के लिये दिया जाता है। जी. सतीश रेड्डी पिछले चार दशकों में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिका से बाहर के पहले व्यक्ति हैं।

- भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को एक बार फिर से तीन साल के लिये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। यह फैसला दुबई में हुई ICC की त्रैमासिक बैठक में लिया गया। 2012 में कुंबले को ICC क्रिकेट समिति का सदस्य बनाया गया था और 2013 में उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। गौरतलब है कि ICC क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन करने वाली संस्था है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने 1909 में इसे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में स्थापित किया था। 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। 1989 में इसे वर्तमान नाम ICC दिया गया और इसका मुख्यालय दुबई में है।

- चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ (Xinhua) ने बिलकुल मनुष्य जैसा दिखने वाला महिला रोबोट एंकर बनाया है। इस रोबोट का इस्तेमाल 3 मार्च को पहली बार बतौर न्यूज़ एंकर के रूप में बीजिंग में होने वाली वार्षिक संसद की बैठक को प्रस्तुत करने के लिये किया गया। न्यूज़ पेश करते हुए यह आसानी से अंदाजा नहीं लगता कि यह इंसान नहीं रोबोट है। शिन श्याओमेंग (Xin Xiaomeng) नाम के इस रोबोट ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को और आगे बढ़ाया है। यह रोबोट छोटे बालों वाली ईयर रिंग पहने महिला की तरह दिखता है। इस तकनीक को विकसित करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसे न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ और सोगो इनकॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाया है। गौरतलब है कि यह न्यूज़ एजेंसी पिछले साल नवंबर में वुजैन में आयोजित हुए विश्व इंटरनेट सम्मेलन में पुरुषों के कपड़े पहने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दो न्यूज़ एंकरों को पेश कर चुकी है।

- अमेरिका ने भारत और तुर्की से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेंज़ (GSP) कार्यक्रम के लाभार्थी का दर्जा वापस लेने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वहाँ की संसद को यह जानकारी दी। अमेरिकी कानून के मुताबिक यह बदलाव नोटिफिकेशन जारी होने के 2 महीने बाद लागू हो पाएंगे। गौरतलब है कि अमेरिका के GSP कार्यक्रम में शामिल देशों को विशेष तरजीह दी जाती है और अमेरिका इन देशों से एक तय राशि के आयात पर शुल्क नहीं लेता। GSP कार्यक्रम के तहत भारत को 5.6 अरब डॉलर (लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपए) के एक्सपोर्ट पर छूट मिलती है। भारत GSP का सबसे बड़ा लाभार्थी देश है और अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, उन्हें भारत से यह भरोसा नहीं मिल पाया है कि वह अपने बाज़ार में अमेरिकी उत्पादों को बराबर की छूट देगा। भारत GSP के मापदंड पूरे करने में नाकाम रहा है। अमेरिका दुनिया के 120 विकासशील देशों को अपने यहाँ बिना किसी आयात शुल्क के सामान निर्यात करने की छूट देता है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह सूची समय-समय पर बदलती रहती है।

नोट :

- चीन ने इस वर्ष के लिये अपने रक्षा बजट में पिछले वर्ष की तुलना में साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि की है। 177.61 अरब डॉलर की यह भारी-भरकम राशि भारत के रक्षा बजट के मुकाबले तीन गुना अधिक है। विश्व में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट चीन का ही होता है। हाल के वर्षों में चीन ने अपनी सेना में कई बड़े सुधार किये हैं। इसके तहत उसने दूसरे देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिये नौसेना और वायुसेना को प्राथमिकता देते हुए उनका विस्तार किया है। इसके अलावा चीन ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की संख्या में भी तीन लाख तक की कमी की है। इसके बावजूद 20 लाख के संख्या बल के साथ यह अब भी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। गौरतलब है कि भारत ने इस वर्ष अपना रक्षा बजट 6.87 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3.18 लाख करोड़ रुपए रखा है।

- हाल ही में जारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में केवल 6 देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। इन देशों में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्राँस, लातविया, लक्ज़मबर्ग और स्वीडन शामिल हैं। विश्व बैंक ने दुनिया के 187 देशों में हुए सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। Business and the Law 2019: A Decade of Reform रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों में भी महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। भारत को इस रिपोर्ट में 125वें स्थान पर रखा गया है और 71.25 अंकों के साथ वह अपने पड़ोसी देशों से बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान को 46.25, बांग्लादेश को 49.38, नेपाल को 53.13, श्रीलंका को 65.63, भूटान को 69.38 और म्यांमार को 56.25 अंक मिले हैं। यह रिपोर्ट महिलाओं के बाहर निकलने की आज़ादी, नौकरी की स्वतंत्रता, पुरुषों के समान वेतन, विवाह के बाद महिलाओं की कानूनी और आर्थिक स्थिति, नौकरी के दौरान गर्भावस्था में और बच्चे को जन्म देने के दौरान मिले अधिकार, महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने की आज़ादी तथा समान पेंशन के संकेतकों के आधार पर तैयार की गई है।

- प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना की औपचारिक लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च को गुजरात में की। इस योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हज़ार रुपए की पेंशन मिलेगी। यह योजना प्रमुख रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लक्षित करके बनाई गई है। योजना के तहत पंजीकरण का काम 15 फरवरी से शुरू हो चुका है। इस योजना के लिये अंतरिम बजट में 500 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:
  - 40 साल तक के कामगार इस योजना के लिये पंजीकरण करवा सकते हैं।
  - 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पंजीकृत व्यक्ति को 3 हजार रुपए की पेंशन हर महीने मिलेगी।
  - योजना में हर महीने 15 हजार रुपए तक कमाने वाले अंसगठित क्षेत्र के कामगार शामिल होंगे।
  - न्यूनतम 18 साल की उम्र में इस योजना में शामिल होने पर हर महीने सिर्फ 55 रुपए और 40 साल में शामिल होने पर 200 रुपए जमा करने होंगे। यह धनराशि 60 साल की उम्र तक देनी होगी।
  - जितनी रकम पंजीकृत व्यक्ति देगा उतनी की रकम सरकार भी देगी, लेकिन इसके लिये आधार कार्ड और बैंक में अकाउंट होना जरूरी है।
  - इस योजना में रेहड़ी वाले, रिक्शा चलाने वाले, कंस्ट्रक्शन मज़दूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इस तरह के काम-धंधों से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं।
  - राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना में आने वाले लोग तथा आयकर भरने वाले भी इसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
  - इस स्कीम के लिये सरकार एक पेंशन फंड बनाएगी और इस फंड के ज़रिये ही सभी को पेंशन दी जाएगी।
  - यदि योजना के दौरान किसी सदस्य का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी स्कीम में योगदान देकर इसको जारी रख सकती है।
  - किसी सदस्य के निधन पर उसकी पत्नी या पति योजना से बाहर होना चाहता है तो जमा कराई गई कुल रकम ब्याज के साथ वापस ली जा सकती है।
  - पेंशन शुरू होने के बाद किसी सदस्य का निधन होने पर पति या पत्नी को पेंशन की 50% रकम मिलेगी।

- हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पंजाब प्रांत में 53 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव झेल रही पाकिस्तान सरकार ने पंजाब प्रांत में आतंकी संगठनों का समर्थन करने के आरोप में यह कार्रवाई की है। पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी प्राधिकरण (NCTA) की वेबसाइट के मुताबिक जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 के तहत जनवरी 2017 में निगरानी सूची में रखे गए थे। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले

नोट :

के बाद इन दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने, उनके वित्तपोषण पर अंकुश लगाने और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को लागू करने के लिये पाकिस्तान ने एक कानून का एलान किया। पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (धन-संपत्ति पर रोक और ज़ब्ती) आदेश 2019 जारी किया। इसका उद्देश्य आतंकवादी घोषित व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों को लागू करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाना है।

- ब्रिटेन सरकार ने 2030 तक 'पीरियड पावर्टी' खत्म करने के लिये दुनियाभर के संगठनों को सहायता हेतु दो मिलियन पाउंड देने की घोषणा की है। ब्रिटेन में इस समस्या से निपटने के लिये नए आइडियाज़ को सामने लाने हेतु सरकारी विभागों, व्यवसायों, चैरिटी और निर्माताओं से जुड़े कार्यबल बनाने के लिये भी 250,000 पाउंड देने की घोषणा की गई। देखने में आया है कि कई देशों में लड़कियाँ पीरियड्स के दौरान स्कूल छोड़ने के लिये विवश हो जाती हैं और पुराने कपडे और कागज़ का इस्तेमाल करती हैं। दक्षिण सूडान में 83% स्कूली लड़कियाँ ऐसा करने को विवश हैं। हाल ही में नेपाल में पीरियड्स के दौरान कुछ लड़कियों और महिलाओं को अलग झोंपड़ी में रहने को विवश करने की घटनाएँ सामने आईं। इस अभियान का उद्देश्य पीरियड्स से जुडी भ्रांतियों को कम करना है। यह एक वैश्विक मुद्दा है।

- अमेरिका के बाद रूस ने भी परमाणु हथियार संधि (Intermediate Nuclear Force) से बाहर आने का फैसला किया है। रूस ने यह कदम 1987 की परमाणु संधि से अमेरिका के बाहर आने के बाद उठाया है। रूस ने अमेरिका पर पूर्वी यूरोप में मिसाइल रक्षा सुविधाओं को तैनात करने के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए परमाणु हथियार संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित करने का फैसला किया। मध्यवर्ती दूरी की परमाणु मिसाइलों पर रोक लगाने वाली 32 वर्ष पुरानी इस संधि पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने 8 दिसंबर,1987 को अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर किये थे। इसीलिये इसे 'वॉशिंगटन निरस्त्रीकरण संधि' के नाम से भी जाना जाता है। 1 जुलाई 1988 को मॉस्को में अंतिम दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर के साथ यह संधि प्रभावी हुई थी। गौरतलब है कि यह संधि सतह से छोड़ी जा सकने वाली ऐसी सभी परमाणविक मिसाइलों के साथ गैर-परमाणविक मिसाइलों पर भी रोक लगाती है, जिनकी मारक दूरी 500 से 5500 किलोमीटर के बीच है। लेकिन समुद्र से छोड़ी जा सकने वाली ऐसी ही प्रणालियाँ इस संधि के दायरे में नहीं आतीं।

- अमेरिका के इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसके सहयोगी संस्थानों के शोधकर्त्ताओं के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण के बढ़ने की वजह से श्वास संबंधी बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। इससे देश को वार्षिक 30 अरब डॉलर (लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए) की क्षति होती है। इस अध्ययन के ज़रिये पहली बार उत्तर भारत में पराली जलाने से स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नुकसान की चर्चा की गई है। गौरतलब है कि वायु की खराब गुणवत्ता विश्वभर में स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है।

- केंद्र सरकार ने 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के ज़रिये विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों को रोकने के लिये एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश में 200 पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था की गई है,, ताकि रिज़र्व कैटेगरी के SC, ST और OBC को विश्वविद्यालय फैकल्टी में नौकरी के लिये समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 पॉइंट रोस्टर के फैसले को बदलने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी के बदले विभागवार नियुक्ति को मानने का फैसला किया था। 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के अनुसार विश्वविद्यालयों के एसोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिये विभागवार आरक्षण लिस्ट तैयार होनी थी। इसके तहत नियुक्तियाँ विभागवार होनी थीं और इस वज़ह से आरक्षित वर्ग के लिये सीटों की संख्या पर असर पड़ता। यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिये बहुत कम सीटें निकलती हैं और ऐसे में विभागवार रोस्टर होने पर आरक्षित वर्ग के लिये सीटें कम हो जातीं।

- रक्षा मंत्रालय द्वारा महिला सैन्य अधिकारियों को सेना की 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन दिया जाएगा। इनमें अब तक महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) में शामिल किया जाता था। अभी भी सेनाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाता है लेकिन वह कुछ गैर-युद्धक ब्रांचों तक ही सीमित है। 14 साल की सेवा के बाद शिक्षा, कानून, सिग्नल, इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिया जाता है। ग़ौरतलब है कि सेना में SSC के ज़रिये जो अधिकारी भरती होते हैं, वे 14 साल तक सेवाएँ दे पाते हैं। पहले यह अवधि 10 साल थी, जिसे छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद 14 साल कर दिया गया। फिलहाल सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति का केवल SSC ही एकमात्र माध्यम है।

नोट :

- पुलवामा आतंकी हमले के बाद से स्थगित हुआ श्रीनगर-मुजफ्फराबाद सड़क मार्ग से सीमा के आर-पार होने वाला व्यापार 5 मार्च को फिर बहाल हो गया है। यह वस्तु विनिमय व्यापार (Barter Trade) सप्ताह में चार दिन मंगलवार से शुक्रवार तक होता है। खास बात यह है कि नियंत्रण रेखा (LoC) के पास उड़ी में होने वाले इस व्यापार में पैसों का लेन-देन नहीं होता तथा सामान के बदले सामान ही लिया-दिया जाता है। इस व्यापार में भारत की ओर से जीरा, काली मिर्च, कपड़े, दालचीनी, केले, अनार, अंगूर, बादाम आदि भेजे जाते हैं। पाकिस्तान की ओर से दरियाँ, पूजा में बैठने के लिये इस्तेमाल में आने वाले आसन, कपड़े, संतरे, आम और जड़ी-बूटियाँ आती हैं। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था और वहाँ से आने वाले सामान पर आयात शुल्क को भी बढ़ा दिया था।

- IIT कानपुर के एयरोस्पेस विभाग ने स्वदेशी अंतरिक्ष यान 'गगनयान' के लिये ग्रीन जेल नामक इको-फ्रेंडली विशेष ईंधन तैयार किया है। इस ग्रीन जेल से अंतरिक्ष यान की रफ्तार में इज़ाफा होगा और ईंधन की खपत भी कम होगी तथा प्रदूषण में भी 40% तक की कमी आएगी। गौरतलब है कि IIT कानपुर के एयरोस्पेस विभाग ने इसरो के इस प्रोजेक्ट को दो साल की अवधि में पूरा कर लिया है। इससे इंजन का तापमान कम रखने में भी मदद मिलेगी। अभी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिये तरल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पैरा ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है।

- संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और मानवाधिकार विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दुनियाभर में प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है, जिनमें 6 लाख बच्चे भी शामिल हैं। लगभग 6 अरब लोग नियमित रूप से इतनी प्रदूषित हवा में साँस ले रहे हैं कि इससे उनके जीवन और स्वास्थ्य पर जोखिम बना रहता है। हर घंटे 800 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से बहुत से लोग कई साल बाद कैंसर, साँस संबंधी बीमारी या दिल की बीमारी की वजह से मर जाते हैं, जो प्रत्यक्ष तौर पर प्रदूषित हवा में साँस लेने के कारण होती हैं।

- IQAir द्वारा जारी AirVisual 2018 वर्ल्ड एअर क्वालिटी के अनुसार, दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 15 भारत के हैं। गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और भिवाड़ी शीर्ष छह प्रदूषित शहरों में शामिल है। इनके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी रहा और दिल्ली अलग से 11वें स्थान पर रही। कभी दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल रही चीन की राजधानी बीजिंग सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में 122वें नंबर पर है, लेकिन यह अब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक सुरक्षित सीमा से कम से कम पाँच गुना अधिक प्रदूषित शहर है। रिपोर्ट में परिवेशी वायु प्रदूषण के कुछ बड़े स्रोतों और कारणों की पहचान की गई है। उद्योगों, घरों, कारों और ट्रकों से वायु प्रदूषकों के जटिल मिश्रण निकलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। इन सभी प्रदूषकों में से सूक्ष्म प्रदूषक कण (Particulate Matter) मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं। यह रिपोर्ट ग्रीनपीस साउथ-ईस्ट एशिया के सहयोग से तैयार की गई है।

- हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चलता है कि शौचालयों के इस्तेमाल में गाँव अब पीछे नहीं है और 90% अधिक गाँव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। गाँवों में 96% लोग शौचालयों का नियमित उपयोग करते हैं। नवंबर 2018 से फरवरी 2019 के बीच कराए गए इस सर्वेक्षण में देश के 6136 गाँवों के 92 हज़ार से अधिक परिवारों को शामिल किया गया था। गाँवों में स्वच्छता के प्रति बढ़ते रुझान का पता इस बात से भी चलता है कि लगभग साढ़े 95 फीसदी गाँवों में न्यूनतम कचरा और न्यूनतम जल ठहराव पाया गया तथा कचरा प्रबंधन की स्थिति भी बेहतर हुई है।

- पर्यावरण प्रबंधन और नीति अनुसंधान संस्थान तथा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा बनाई गई कर्नाटक की जलवायु परिवर्तन राज्य कार्ययोजना ने कर्नाटक में फूलों की लुप्तप्राय प्रजातियों में 'फ्लेम लिली' को शामिल किया है। फ्लेम लिली तमिलनाडु का राजकीय पुष्प है। विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में उतार-चढ़ाव से इस पौधे के पुष्पित होने का चक्र प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि फ्लेम लिली ज़िम्बाब्वे का राष्ट्रीय पुष्प है, जो एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।

- प्रसिद्ध वैज्ञानिक अजित कुमार मोहंती को तीन साल के लिये देश के प्रतिष्ठित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र-बार्क (BARC) का निदेशक नियुक्त किया गया है। अब तक वह बार्क में भौतिकी समूह के निदेशक और साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान के निदेशक के रूप में जिम्मेदारियाँ संभाल रहे थे। मुंबई में स्थित बार्क भारत का अग्रणी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करता है। आपको

नोट :

बता दें कि परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्रॉम्बे को औपचारिक रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 20 जनवरी, 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 12 जनवरी, 1967 को इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा, जो जनवरी 1966 में डॉ. होमी जहांगीर भाभा की हवाई दुर्घटना में हुई मृत्यु के पश्चात रखा गया था।

- अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे मध्यस्थता के लिये भेज दिया। रिटायर्ड जस्टिस एफ.एम. खलीफुल्ला की अध्यक्षता में गठित पैनल को चार सप्ताह के भीतर मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने के लिये कहा गया है, जबकि आठ हफ्ते की भीतर इसे सुलझाने का आदेश दिया गया है। मध्यस्थता की यह प्रक्रिया कैमरे के सामने होगी, लेकिन इसे बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। मीडिया में मध्यस्थता की प्रक्रिया की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध रहेगा। मध्यस्थता फैजाबाद में की जाएगी और पैनल के अध्यक्ष के साथ इसमें श्रीश्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पांचू शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के नियम-8 के तहत उसे मामले को मध्यस्थता के लिये भेजने का अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार फैज़ाबाद में मध्यस्थों को सभी सुविधाएं प्रदान करेगी।

- दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की गई है, जिसमें एक, दो, पाँच, दस और बीस रुपए मूल्य के सिक्के हैं और इन्हें नई श्रृंखलाओं के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। इन सिक्कों की डिज़ाइनिंग राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ने की है तथा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इनकी ढलाई की गई है। इन सिक्कों में कई नई विशेषताएँ शामिल की गई हैं, ताकि दृष्टिबाधित लोगों के उपयोग के लिये आसानी हो। सिक्कों के आकार और भार कम से अधिक मूल्य के सिक्कों के अनुसार हैं। बीस रुपए मूल्य का नया सिक्का 12 दिशाओं का है और इसमें किसी तरह का नुकीला कटाव नहीं है, जबकि शेष मूल्य के सिक्के गोलाकार हैं।

- फ्राँसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी (ISRO) के विशेषज्ञों को 'गगनयान' परियोजना के लिये इसी महीने से फ्रांस के 'तोलुज स्पेस सेंटर' में प्रशिक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। इन विशेषज्ञों को फ्राँस के कैडमॉस (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोग्रैविटी एप्लीकेशंस एंड स्पेस ऑपरेशंस) एवं MEDES स्पेस क्लिनिक में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के लिये भारत एवं फ्राँस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने समुद्री निगरानी के उद्देश्य से उपग्रहों का समूह निर्मित करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इसका लक्ष्य हिंद महासागर में जहाज़ों को पहचानना एवं उनकी स्थिति का पता लगाना है। फ्राँस का तोलुज स्पेस सेंटर अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े अनुसंधान एवं विकास का केंद्र है।

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली वेब वंडर वुमेन को व्यापक अनुसंधान प्रक्रिया के बाद 30 महिलाओं को चुना था। हाल ही में ट्विटर इंडिया तथा ब्रेकथ्रू इंडिया के सहयोग से एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने इन महिलाओं को सम्मानित किया। #वेब वंडर वुमेन ऐसी आवाज़ों को मान्यता देने, सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिये है, जिन्होंने अपनी क्षमता में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सार्थक प्रभाव डाले हैं। इन महिलाओं का चयन 240 से अधिक नामांकनों में से मीडिया, जागरूकता, कानूनी, स्वास्थ्य, सरकारी, खाद्य, पर्यावरण, विकास, व्यवसाय तथा कला श्रेणियों के तहत किया गया।

- नित बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनज़र इको-फ्रेंडली पदार्थों के विकास पर ज़ोर देने के क्रम में IIT मंडी ने जूट और पटसन जैसे प्राकृतिक रेशों को मिलाकर पर्यावरण अनुकूल कम्पोजिट प्लास्टिक बनाया है। पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीएथिलीन आधारित इस कम्पोजिट प्लास्टिक में इन रेशों को पॉलीमर साँचे में वितरित करके उच्च तापमान पर प्रसंस्कृत किया गया है। इस कम्पोजिट प्लास्टिक का इस्तेमाल एयरोस्पेस प्रणालियों से लेकर उद्योगों, ऑटोमोबाइल्स और विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों में होता है। इस कम्पोजिट प्लास्टिक से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।

- स्टार्टअप को एंजेल टैक्स से छूट संबंधी नए नियम आयकर विभाग ने अधिसूचित कर दिये हैं। नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम 19 फ़रवरी से प्रभावी माना जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले DPIIT ने स्टार्टअप कंपनियों को 25 करोड़ रुपए तक के निवेश पर एंजेल टैक्स में छूट का एलान किया था। इसके अलावा इसका लाभ लेने की अवधि को बढ़ाकर 10 साल किया गया था। इससे पहले इन स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 7 साल के लिये यह छूट मिलती थी।

नोट :

- देश की युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगाने के लिये हाल ही में लाल किला परिसर में आज़ादी के भूले-बिसरे दीवानों की स्मृति में आज़ादी के दीवाने नाम के संग्रहालय की शुरुआत की गई है। इस डिजिटल संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बनाया है। इस संग्रहालय को विशिष्ट प्रकार से बनाया गया है और इसमें मल्टी सेंसर तकनीक का प्रयोग हुआ है जो दर्शकों को व्यस्त रखेगी। इस संग्रहालय को इस तरह से बनाया गया है जिसमें गैलरी के एक भाग से दूसरे तक जाते समय हर कोई आज़ादी के लिये हुए युद्ध को जीवंत रूप में देख पाएगा और महसूस भी कर पाएगा। गौरतलब है कि लाल किला परिसर में बनाया गया यह पाँचवां संग्रहालय है। क्रांति के मंदिर श्रृंखला में अब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA, जलियाँवाला बाग, स्वाधीनता संग्राम का प्रथम युद्ध (1857) और दृश्यकला संग्रहालय स्थापित किये गए हैं।

- हाल ही में मुजफ्फरपुर, बिहार के भाजपा नेता भगवान लाल साहनी ने नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला। उनके साथ वाराणसी के पूर्व मेयर कौशलेंद्र सिंह पटेल, हरियाणा से पूर्व लोकसभा सदस्य एवं भाजपा की राष्ट्रीय सचिव सुधा यादव और तेलंगाना भाजपा के महासचिव आचार्य तलोजू सदस्य नियुक्त किये गए हैं। आपको बता दें कि 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले तक यह केवल सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने या पहले से शामिल जातियों को सूची से बाहर करने का काम करता था। 2018 में 123वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हुईं। पुराने कानून में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा और उसके अलावा तीन अन्य सदस्य होंगे। नए कानून के अनुसार आयोग का अध्यक्ष सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाला सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता होगा तथा उपाध्यक्ष व तीन सदस्य होंगे।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में सुधारों के तहत सौम्या स्वामीनाथन को डिप्टी डायरेक्टर जनरल से मुख्य वैज्ञानिक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। मुख्य वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के ऊपर WHO के मानदंडों की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी होती है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अक्तूबर में भारतीय डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथ को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का डिप्टी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। वह WHO में इस पद को संभालने वाली पहली भारतीय थीं। इससे पहले वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) में डायरेक्टर जनरल रह चुकी हैं तथा उनकी गिनती देश के प्रख्यात बाल-रोग विशेषज्ञों में होती है। सौम्या स्वामीनाथन विश्व विख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की पुत्री हैं, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है।

- राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संकलन सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के प्रत्येक खंड को पाँच उपखंडों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सुशासन; देश को सक्षम और कुशल बनाने; हमारे बहादुर जवानों, अन्नदाता किसानों और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की सराहना; विकास और आशा के समावेशी मार्ग पर लोगों को एकजुट करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पुनरुत्थानशील भारत के संदेश को साझा करने के बारे में प्रधानमंत्री के विचारों को कवर किया गया है।

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में भारत में महिलाओं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार, 2018 प्रदान किये। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और संस्थानों को महिला सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण के लिये उनकी अथक सेवा के लिये ये पुरस्कार प्रदान करता है। महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिये इस वर्ष मंत्रालय ने इन पुरस्कारों के लिये 44 नामों का चयन किया। चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कमज़ोर और हाशिये पर रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने में उनका कितना योगदान है। इसके अलावा, उन महिलाओं को भी शामिल करने का प्रयास किया गया, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे क्षेत्रों और मुद्दों पर कार्य किया है, जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण और ध्यान केंद्रित करने वाले रहे हैं। इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में वैज्ञानिक, उद्यमी, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्त्ता, किसान, कलाकार, राज-मिस्त्री, नौसेना की महिला पायलट, महिला कमांडो ट्रेनर, पत्रकार और फिल्म निर्माता आदि शामिल हैं।

नोट :

- शोध एवं बाजार अध्ययन करने वाली कंपनी डेलायट ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिये महिलाओं और लड़कियों का सशक्तीकरण नामक एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार कम होते हुए 25 फीसदी रह गई है,जबकि देश में कुल 19.5 करोड़ महिलाएँ हैं जो असंगठित क्षेत्र में या बिना के वेतन काम करती हैं। रिपोर्ट में कार्यस्थल के लिये तैयारी, सॉफ्ट स्किल, तकनीकी विशेषज्ञता तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास पर ज़ोर देने की आवश्यकता बताई गई है।

- भारतीय रेलवे जल्द ही 4791 रेलवे स्टेशनों में मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने की योजना पर काम कर रहा है। रेलवे ने इसके लिये टाटा के साथ करार किया है। टाटा ट्रस्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत इसके लिये एक बड़ी राशि खर्च कर रहा है। यह सुविधा हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर अन्य सभी स्टेशनों में उपलब्ध होगी। कुल 6441 स्टेशनों में वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और फिलहाल 832 रेलवे स्टेशनों में वाई-फाई सेवा मिल रही है। मार्च 2019 तक 775 और रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा मिलने लगेगी यानी 1600 से अधिक स्टेशनों तक वाई-फाई की सुविधा पहुँच जाएगी।

- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत और जर्मनी के बीच समझौते के नवीनीकरण को सरकार ने मंज़ूरी दे दी है। इससे दोनों देशों के बीच विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई प्रशिक्षण तकनीक अपनाने और जोखिमों से निपटने में काफी मदद मिली है। इस समझौते के तहत निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के माध्यम से जर्मनी की सामाजिक दुर्घटना बीमा के ज़रिये काफी मदद मिल रही है। इस समझौते से श्रम मंत्रालय के तकनीकी विभाग- कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय के कौशल विकास तथा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा।

- सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिये भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हुए समझौते को सरकार ने मंज़ूरी दे दी है। इसके ज़रिये दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन, सड़क/राजमार्ग आधारभूत संरचना विकास, प्रबंधन और प्रशासन तथा सड़क सुरक्षा और आधुनिक परिवहन प्रणाली के लिये द्विपक्षीय सहयोग की एक प्रभावी रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सड़क परिवहन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने से सड़क सुरक्षा तथा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की संभावनाओं को बल मिलेगा। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे।

- कैंसर शोध पहल पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों देश क्लीनिकल शोध, जनसांख्यिकी शोध, नई तकनीक और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञों को साथ लाकर किफायती, रोकथाम तथा कैंसर देखभाल जैसी शोध चुनौतियों की पहचान करेंगे। यह कार्यक्रम भारत के विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा कैंसर रिसर्च UK का 5 वर्षीय सहयोगी द्विपक्षीय शोध कार्यक्रम है, जो कैंसर के किफायती दृष्टिकोण पर फोकस करेगा। इसके लिये कुल शोध राशि 10 मिलियन पाउंड (लगभग 90 करोड़ रुपए) होगी, जिसे दोनों देश बराबर-बराबर वहन करेंगे।

- केंद्र सरकार ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद के लिये भारत और बेलारूस के बीच समझौते को मंज़ूरी दे दी है। इसके अमल में आने के साथ ही समझौता करने वाले दोनों पक्षों के बीच दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते का उद्देश्य दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी सलाह का अनुरोध करने वाले पक्षों के नागरिकों को लिंग, समुदाय और आय के मामलों में बिना भेदभाव किये लाभ पहुँचाना है।

- मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में स्थित नौरादेही अभयारण्य में देश से विलुप्त होते चीते को बसाने की तैयारियाँ फिर शुरू हो रही हैं। वन्यजीवों की विश्व स्तरीय संस्था International Union for Conservation of Nature (IUCN), नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ और सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को भारत में लाने की अनुमति दे दी है। ये चीते दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मंगाए जाएंगे। लगभग 260 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत अभयारण्य के 500 वर्ग किमी. क्षेत्र में चीतों को बसाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिये दोनों देशों और विभिन्न संस्थाओं की अनुमति मिल चुकी है। गौरतलब है कि देश से चीते विलुप्त हो चुके हैं और 1948 में मध्य प्रदेश के सरगुजा के जंगलों में आखिरी बार चीता देखा गया था।

नोट :

- लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान द्वारा किये गए एक हालिया शोध के दौरान असम में एशिया के सबसे प्राचीन बाँस की नाल के जीवाश्मों का पता चला है। अभी तक वैज्ञानिकों की यह धारणा थी कि एशियाई बाँस की उत्पत्ति यूरोप में हुई थी। इस शोध के दौरान असम के तिनसुकिया ज़िले के माकुम कोल फील्ड में मिले बाँस के जीवश्म ढाई करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं। यह इस बात का भी प्रमाण है कि बाँस की उत्पत्ति और विकास दक्षिणी गोलार्द्ध में हुआ।

- एलन मस्क की अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनी स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (International Space Station-ISS) से पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौट आया है। यान पूर्वी मानक समयानुसार आज सुबह 8.45 बजे अटलांटिक महासागर में उतरा। डेमो-1 नामक यह मानवरहित प्रदर्शन मिशन मानव के लिये डिज़ाइन की गई किसी अंतरिक्ष प्रणाली की पहली परीक्षण उड़ान है। यह एक अमेरिकी व्यावसायिक कंपनी की सार्वजनिक-निजी भागीदारी के ज़रिये निर्मित और संचालित है। गौरतलब है कि 2 मार्च को अपनी पहली मानवरहित उड़ान भरने के बाद ड्रैगन क्रू 3 मार्च को ISS पर पहुँचा था। अब नासा और स्पेसएक्स आगे डेमो-2 की तैयारी के लिये डेमो-1 से मिले आँकड़ों का इस्तेमाल करेंगे। डेमो-2 मानवयुक्त मिशन होगा, जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर लेकर जाएगा। यह मिशन फिलहाल जुलाई में प्रस्तावित है।

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Program-UNDP) ने भारतीय-अमेरिकी टीवी स्टार, लेखिका और फूड स्पेशलिस्ट पद्मालक्ष्मी को अपना नया सद्भावना राजदूत (Goodwill Ambassador) नियुक्त किया है। UNDP के संचालक अचिम स्टेनर के अनुसार, वह विश्वभर में असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करेंगी। इसके अलावा, अपनी नई भूमिका में वह वंचितों के सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति समर्थन जुटाने का काम भी करेंगी। पद्मालक्ष्मी एंडोमेट्रियोसिस फाउंडेशन की सह-संस्थापक भी हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुई थे और इसने 1 जनवरी, 1966 से कार्य करना शुरू किया था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है, जो गरीबी कम करने, बुनियादी ढाँचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।

- भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की वज़ह से इस महीने सिंधु नदी घाटी में परियोजनाओं के निरीक्षण के लिये भारतीय दल का प्रस्तावित पाकिस्तान दौरा टल गया है। गौरतलब है कि लाहौर में 29-30 अगस्त, 2018 को स्थायी सिंधु आयोग की 115वीं बैठक में दोनों देशों के आयुक्त सिंधु नदी घाटी के दौरों के लिये सहमत हुए थे। इसी वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह में पाकिस्तानी विशेषज्ञ भारत आए थे और उन्होंने जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर पाकल दल, रेटिल और लोअर कलनाई परियोजनाओं को देखा था। उल्लेखनीय है कि सिंधु नदी के जल बंटवारे के सवाल पर भारत-पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच 1960 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसी के तहत दोनों देशों में सिंधु आयोग की स्थापना हुई थी।

- 10 मार्च को देशभर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के साथ ही राष्ट्रीय पोलियो दिवस भी आयोजित किया गया। इससे पहले इस दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम-2019 की शुरुआत की। देश से पोलियो उन्मूलन के लिये टीकाकरण अभियान के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के 17 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो की दवा दी जाएगी। बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिये सरकार ने इंजेक्शन के ज़रिये पोलियो की दवा देने के अपने नियमित टीकाकरण अभियान में इनएक्टिवेटेड पोलियो टीका भी शामिल किया है। इसके अलावा, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के साथ ही देश में मिशन इंद्रधनुष की भी शुरुआत की गई है ताकि 90 प्रतिशत से ज़्यादा बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

- विश्व बैंक ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) के तहत छह राज्यों में 220 से अधिक बड़े बांधों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिये 137 मिलियन डॉलर (लगभग 960 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान किया है। ये बांध कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में स्थित हैं। गौरतलब है कि 2010 में भी विश्व बैंक ने DRIP के तहत वित्तपोषण के लिये 350 मिलियन डॉलर (लगभग 2450 करोड़ रुपए) की मंज़ूरी दी थी। DRIP ने शहरी और ग्रामीण समुदायों के 25 मिलियन प्राथमिक लाभार्थियों को अब तक फायदा पहुँचाया है। आपको बता दें कि भारत में 5200 से अधिक बड़े बांध हैं और 300 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक की भंडारण क्षमता वाले 400 बांध निर्माणाधीन हैं।

नोट :

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी एंड वीडियो वॉल की शुरुआत की है। इसके माध्यम से सरकार निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार के साथ नागरिकों, शिक्षाविदों और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। इसके अलावा, अत्याधुनिक तकनीकों तथा रियल टाइम और डाक्यूमेंट्स दोनों से असंख्य स्रोतों के माध्यम से डेटा प्राप्त करेगी। इस ऑब्जर्वेटरी से परिवहन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल, वित्त जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिये सार्थक संकेतकों की विश्वसनीय जानकारी को अपडेट करने में मदद मिलेगी। इससे सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और भविष्य की रणनीतियों को आवश्यकतानुरूप और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से विकसित करने में भी सहायता मिलेगी। इस ऑब्जर्वेटरी की संकल्पना 'चतुर्भुज-हेलिक्स' मॉडल के चार हितधारकों- सरकार, नागरिक, शिक्षा और उद्योगों को मद्देनज़र रखते हुए की गई है।

- ड्रेज़िंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को सरकार ने चार बंदरगाहों के कंसोर्टियम को 1050 करोड़ में बेच दिया। 510 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी बेची गई। इसके बाद सरकार का कुल विनिवेश फंड 57 हजार 523 करोड़ रुपए हो गया है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ड्रेज़िंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपनी 100% हिस्सेदारी देश के चार बड़े बंदरगाहों के जरिए मिलकर बनाए गए बंदरगाहों के कंसोर्टियम को बेचने का फैसला किया था। बंदगाहों पर जहाजों की आवाजाही के रास्ते से गाद निकालने का काम करने वाली इस कंपनी में केंद्र सरकार की 73.44% हिस्सेदारी थी।

- भारत के पर्यटन मंत्रालय ने बर्लिन में 6 से 10 मार्च तक आयोजित हुए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज़्म अवाड्र्स 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। गौरतलब है कि अतुल्य भारत अभियान 2.0 के तहत निर्मित निम्नलिखित 5 प्रचार फिल्मों/ टेलीविजन विज्ञापनों को पुरस्कार प्राप्त हुए:
  1. रेसट्रैक के योगी (Yogi of the Racetrack)
  2. मिस्टर एंड मिसेज जोंस का पुनर्जन्म (The Reincarnation of Mr. & Mrs. Jones)
  3. पेरिस में अभयारण्य (Sanctuary in Paris)
  4. मैनहट्टन की महारानी (Maharani of Manhattan)
  5. मसाला मास्टर शेफ (The Masala Master Chef)

  आपको बता दें कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टीमीडिया अवाड्र्स प्रतिवर्ष पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में दिये जाते हैं। यह देशों, शहरों, क्षेत्रों और होटलों के लिये एक रचनात्मक मल्टी-मीडिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है।

- प्रसार भारती ने 11 और राज्यों के दूरदर्शन चैनल शुरू किये हैं जिनमें पाँच चैनल पूर्वोत्तर राज्यों के लिये हैं। भारत के सेटेलाइट दायरे का विस्तार करते हुए इन चैनलों का निशुल्क प्रसारण डीडी फ्री डिश के माध्यम से किया जाएगा। क्षेत्रीय संस्कृति को मज़बूत करने तथा जन आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद देने वाले ये चैनल छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिये हैं।

- मिज़ोरम सरकार ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो राज्य में रहने वाले 'वास्तविक भारतीय नागरिकों' के लिये यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। मिज़ोरम मेंटेनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्ट्रेशन बिल, 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि सरकारी योजनाओं के लिये पात्र परिवारों का रिकॉर्ड राज्य को रखना होगा। कानूनी रूप ले लेने के बाद यह विधेयक अवैध प्रवासियों की पहचान करके भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा। यह विधेयक कल से शुरू होने वाले अंतरिम बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा।

- शोधकर्त्ताओं ने एक ऐसे तेंदुए की प्रजाति को 30 साल से अधिक समय बाद पहली बार दक्षिण-पूर्व ताइवान में देखने का दावा किया है, जिसके लिये माना जाता था कि वह पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। तेंदुए की इस प्रजाति का नाम फॉरमोसन क्लाउडेड लेपर्ड (Formosan Clouded Leopard) है। इसे आधिकारिक तौर पर 2013 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, क्योंकि यह तेंदुआ 1983 के बाद से नहीं देखा गया था और प्राणी विज्ञानियों द्वारा किये गए 13 साल के लंबे अध्ययन में इस प्रजाति का एक भी तेंदुआ देखने को नहीं मिला। हाल ही में दक्षिण-पूर्व ताइवान के डैरन, ताइतुंग शहर में स्थानीय लोगों ने इस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए को देखने का दावा किया है। केवल ताइवान में पाई जाने वाली तेंदुए की इस प्रजाति को IUCN की विलुप्त (Extinct) कैटेगरी में रखा गया है।

नोट :

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये संयुक्त रूप से बांग्लादेश में कई विकास परियोजनाओं का उदघाटन किया। इन परियोजनाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण है पानी साफ करने वाले प्लांट्स जो बांग्लादेश के हज़ारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुँचाएंगे। इसके अलावा, कई सामुदायिक अस्पतालों का उदघाटन किया गया, जिनसे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इनके अलावा भारत से बांग्लादेश को बसों और ट्रकों की आपूर्ति की जाएगी, जिससे वहाँ सस्ता परिवहन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

- भारत सरकार ने तेल एवं गैस खोज के क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये इससे जुड़ी नीति में अहम बदलाव किये हैं। अब कम खोज वाले ब्लॉक में निवेशक द्वारा तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में उससे होने वाले लाभ में सरकार को हिस्सा नहीं देना होगा। सभी अवसादी बेसिनों के लिये एक समान अनुबंध व्यवस्था की ढाई दशक पुरानी नीति में बदलाव करते हुए नई नीति में अलग-अलग क्षेत्रों के लिये अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। इसके तहत बेसिन की स्थिति पर विचार किये बिना उत्पादकों को भविष्य में बोली दौर में तेल एवं गैस के लिये विपणन और कीमत के मामले में आज़ादी होगी। इसके अलावा, भविष्य में सभी तेल एवं गैस क्षेत्र या ब्लॉक का आवंटन प्राथमिक रूप से खोज कार्यों को लेकर जताई गई प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाएगा। नए नियमों के तहत कंपनियों को श्रेणी-1 के अंतर्गत आने वाले अवसादी बेसिन से होने वाली आय का एक हिस्सा सरकार को देना होगा। इसमें कृष्णा गोदावरी, मुंबई अपतटीय, राजस्थान तथा असम शामिल हैं, जहाँ वाणिज्यिक उत्पादन पहले से हो रहा है। वहीं कम खोज वाले श्रेणी-2 और 3 के बेसिन में तेल एवं प्राकृतिक गैस पर केवल मौजूदा दर पर रायल्टी ली जाएगी।

- भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने 5 से 7 मार्च तक पराग्वे का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने पराग्वे के राष्ट्रपति मारियो अब्दो बेनितेज़, उपराष्ट्रपति ह्यूगो वेलाज़क्वेज़ और सीनेट के अध्यक्ष सिल्वियो ओवेलर के साथ मुलाकात की तथा भारत-पराग्वे बिज़नेस फोरम को भी संबोधित किया। पराग्वे ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके अलावा, पराग्वे की राजनयिक और दूतावास अकादमी तथा भारत के विदेश सेवा संस्थान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने 7 से 9 मार्च तक कोस्टा रिका का दौरा किया और वहाँ के राष्ट्रपति एच.ई. कार्लोस अल्वाराडो क्यूसादा से मुलाकात की। दोनों देशों ने दो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर भी किये। इनमें से एक समझौता भारत और कोस्टा रिका के बीच डिप्लोमैटिक और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिये वीज़ा की आवश्यकता को समाप्त करने के लिये किया गया तथा दूसरा समझौता जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिये किया गया। आपको बता दें कि यह भारत की ओर से इन दोनों देशों की पहली उच्च-स्तरीय यात्रा थी।

- राजस्थान सरकार ने जवाबदेही कानून को अध्यादेश के ज़रिये मंज़ूरी दे दी है। अब सरकारी अधिकारियों को बताना होगा कि फाइल क्यों रुकी ? पेंशन जारी क्यों नहीं हुई ? सेवा में विलंब क्यों हुआ ? गली-मोहल्ले में बिजली गुल क्यों हुई ?आदि...इत्यादि। इस तरह के जवाबदेही कानून को धरातल पर उतारने वाला राजस्थान संभवतया देश का पहला राज्य है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद किसान कर्ज़ माफी, बेरोज़गारी भत्ता, नि:शुल्क दवा योजना और वृद्धावस्था एवं विकलांगों की पेंशन में बढ़ोतरी के बाद अब जवाबदेही कानून लाया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जवाबदेही कानून के प्रावधानों की समीक्षा के लिये उच्च अधिकारियों की एक समिति का गठन किया था । इसके बाद राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने जनता से सुझाव मांगे थे।

- महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अटल आहार योजना शुरु की है। इस योजना के प्रथम चरण में लगभग 20 हज़ार श्रमिकों को 5 रुपए की दर से भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को बेहद कम खर्च में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ लेने के लिये श्रमिक होने के साथ राज्य का स्थायी निवासी होना भी ज़रूरी है। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिये आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना ज़रूरी है।

- उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार आँगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में दो बार मुफ्त दूध (100 मिली.) प्रदान करेगी। इस पहल के माध्यम से लगभग 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा जिससे कुपोषण के खतरे को रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में लगभग 20 हज़ार आँगनवाड़ी केंद्र हैं और इन केंद्रों पर 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त दूध मिलेगा। इस अभियान से आँगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे कुपोषित बच्चों को आगामी वर्षों में उचित पोषण प्रदान किया जाएगा। आँगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 2.5 लाख से अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं और इनमें से अधिकांश समाज के वंचित वर्गों से आते हैं।

नोट :

- जापानी वास्तुकार अराता इसोजाकी को 2019 का प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़ (Pritzker Architecture Prize) देने का एलान किया गया है। लगभग छह दशकों से इस क्षेत्र में कार्यरत अराता इसोजाकी ने एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य-पूर्व, ऑस्ट्रेलिया में कई बेहतरीन भवनों का आर्किटेक्चर तैयार किया है। वह आठवें जापानी आर्किटेक्ट हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। फ्राँस के शैटॉ डि वर्सेल्स में दिये जाने वाले इस पुरस्कार के तहत एक लाख डॉलर की धनराशि और ब्रोंज मैडल प्रदान किया जाता है। 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया प्रित्ज़कर एनुअल प्राइज़ वास्तुकला के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

- जीव विज्ञानियों ने इंडोनेशिया के एक द्वीप में बीटल्स (Beetles) की 103 नई प्रजातियों की खोज की है। इनके नाम जीव विज्ञानियों और ग्रीक पौराणिक पात्रों के नाम पर तो रखे ही गए हैं, साथ ही इनमें से एक का नाम स्टारवार्स के कैरेक्टर 'योडा' के नाम पर रखा गया है। कुछ बीटल्स के नाम फ्रेंच कॉमिक्स 'एडवेंचर ऑफ एस्टेरिक्स' के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। इन बीटल्स की खोज इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर हुई, जो अपने रहस्यपूर्ण जीवों के लिये दुनियाभर में जाना जाता है। अब तक इस प्रजाति (जीनस ट्रिगोनोप्टेरस) के केवल एक कीट के बारे में जानकारी थी।

- केंद्र सरकार ने राज्यों को कुछ शत्रु संपत्तियों के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दे दी है। यह पहल ऐसे समय हुई है, जब केंद्र सरकार लगभग एक लाख करोड़ रुपए की 9400 से ज़्यादा शत्रु संपत्तियों और तीन हजार करोड़ रुपए के शत्रु शेयर बेचने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार राज्य सरकारों को शत्रु संपत्तियों के सार्वजनिक इस्तेमाल की अनुमति देने के लिये शत्रु संपत्ति आदेश, 2018 के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि शत्रु संपत्ति वह संपत्ति है जिसे बँटवारे के समय लोग छोड़कर पाकिस्तान और 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद छोड़कर चीन चले गए थे। शत्रु संपत्तियों में पाकिस्तान की नागरिकता लेने वाले लोगों की 9280 संपत्तियाँ और चीन जाने वाले लोगों की 126 संपत्तियाँ शामिल हैं। पाकिस्तान जाने वाले लोगों की संपत्तियों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 4991 संपत्तियाँ हैं। इसके बाद 2735 शत्रु संपत्तियाँ पश्चिम बंगाल में और 487 शत्रु संपत्तियाँ दिल्ली में हैं। वहीं चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई शत्रु संपत्तियाँ सबसे ज़्यादा मेघालय में 57, पश्चिम बंगाल में 29 और असम में 7 हैं।

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के वैज्ञानिकों ने मेडिकल लेबोरेटरी में कुछ ऐसी दवाइयाँ विकसित की हैं, जिससे आतंकी या नक्सली हमलों में घायल हुए जवानों को अस्पताल पहुँचाए जाने से पहले तक के 'गोल्डन पीरियड' को बढ़ाया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने अपनी इस खोज को कॉम्बैट कैज़ुअल्टी ड्रग्स नाम दिया है। इन दवाइयों में रक्तस्राव को तुरंत रोकने वाली दवा, विशेष प्रकार की ड्रेसिंग और ग्लिसरेटेड सेलाइन शामिल हैं। DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज़ में ये दवाइयाँ तैयार की गई हैं। गौरतलब है कि यदि घायलों को प्रभावी प्राथमिक उपचार मिल जाए तो उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है।

- भारत सरकार की ज्योग्राफिकल इंडीकेशंस रजिस्ट्री ने तमिलनाडु की पारंपरिक थिरुभुवनम रेशमी साड़ियों को GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है। थिरुभुवनम रेशमी साड़ियाँ शुद्ध ज़री के धागों का इस्तेमाल करते हुए विस्तृत डिज़ाइन के साथ बनाई और पहनी जाने वाली पारंपरिक साड़ियाँ हैं। थिरुभुवनम में बुनकरों द्वारा तैयार की जाने वाली ये साड़ियाँ गुणवत्तापूर्ण बारीक रेशम के काम के लिये प्रसिद्ध हैं। अब इस साड़ी के बुनकर इस प्रसिद्धि पर अपने एकमात्र अधिकार का दावा कर सकते हैं। आपको बता दें कि GI टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है या किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है या वह उसका मूल स्थान होता है। GI टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं को उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिये दिया जाता है।

- भारत सरकार ने Central Public Sector Enterprises (CPSE) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की अतिरिक्त पेशकश जारी करने का फैसला किया है, जिससे उसे कम-से-कम 3500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इस अनुवर्ती निर्गम के ज़रिये ETF की बिक्री में 5000 करोड़ रुपए तक का ग्रीन-शू विकल्प रखने की सुविधा होगी। ETF की अतिरिक्त पेशकश 19 मार्च को आ सकती है। निर्गम का मूल आकार 3500 करोड़ रुपए होगा और इसमें अतिरिक्त अभिदान रखने की अनुमति होगी। ETF एक साझा कोष यानी इंडेक्स फंड होता है, जिसका पैसा चुनिंदा सरकारी उपक्रमों में लगाया जाता है और इसकी यूनिटें शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जा सकती हैं। विश्वभर में ETF रिटेल निवेशकों और संस्थागत निवेशकों में निवेश का लोकप्रिय साधन है।

नोट :

- 8 वर्ष बाद भारत को पीछे छोड़ते हुए सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2014-18 तक प्रमुख हथियारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था। विश्व में हथियारों की बिक्री का कुल साढ़े 9 प्रतिशत हिस्सा भारत को जाता है। यह मूल्यांकन पाँच साल की अवधि (2014-2018) के लिये किया गया। इससे पहले की अवधि (2009-13) में भारत पहले स्थान पर था और तब हथियारों की खरीद में इसका हिस्सा 13 प्रतिशत था। 2009-13 और 2014-18 के बीच भारत के हथियार आयात में 24 प्रतिशत की कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाँच साल की ब्लॉक अवधि (2011-2015) में पाँच सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका, रूस, फ्राँस, जर्मनी और चीन थे। अमेरिका और रूस सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से हैं, जिनका हथियारों के कुल वैश्विक व्यापार में हिस्सा क्रमश: 36 और 21 प्रतिशत है।

- भारत और मालदीव के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिये वीज़ा सुविधा समझौता 11 मार्च से प्रभावी हो गया। यह समझौता सभी आव्रजन कार्यालयों, सीमा बिंदुओं और सीमा शुल्क अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराने के साथ सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्रभावी हुआ है। यह समझौता मालदीव के नागरिकों को पर्यटन, व्यवसाय, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिये भारत आने के लिये एक उदार वीजा व्यवस्था प्रदान करेगा। साथ ही यह समझौता भारतीयों के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये भी सहायक होगा। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह की पिछले साल दिसंबर में भारत यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे। इससे पहले दोनों देशों के संबंधों में अब्दुल्ला यामीन के राष्ट्रपति रहने के दौरान तनाव आ गया था।

- नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार (AAHAR) के 34वें संस्करण की 12 मार्च को शुरुआत हुई। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइज़ेशन (ITPO) द्वारा आयोजित इस पाँच दिवसीय मेले में भारत और विदेशों के 560 से अधिक प्रतिभागियों के खाद्य उत्पादों, मशीनरी, खाद्य और पेय पदार्थ उपकरण, आतिथ्य और सजावट के सामान, कन्फेक्शनरी आइटम आदि शामिल हैं। इस मेले में चीन, जर्मनी, हांगकांग, इटली, इंडोनेशिया, जापान, रूस, स्पेन, अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य देशों के विदेशी प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं।

- मदर टेरेसा के जीवन पर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बायोपिक का नाम 'मदर टेरेसा: द संत' रखा गया है। सीमा उपाध्याय ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है और वही इसका निर्देशन भी करने वाली हैं। इस फिल्म के निर्माता प्रदीप शर्मा, नितिन मनमोहन, गिरीश जौहर और प्राची मनमोहन हैं। इसके लिये मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी की वर्तमान सुपीरियर जनरल सिस्टर प्रेमा मैरी पियरिक और कोलकाता में सिस्टर लिन से अनुमति ली गई। गौरतलब है कि मदर टेरेसा 1929 में अल्बानिया से भारत आई थीं और उन्होंने 1948 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इससे पहले उन पर 'मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता' फिल्म बनी थी और 1997 में 'मदर टेरेसा: इन द नेम ऑफ गॉड्स पुअर' जैसा पॉपुलर टीवी शो आया था।

- एक्सिस बैंक ने राकेश मखीजा को को अपना गैर-कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है और वे इस वर्ष जुलाई में कार्यभार संभालेंगे। वह तीन साल के लिये इस पद पर रहेंगे। वह संजीव मिश्रा की जगह लेंगे, जो 17 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब इस नियुक्ति की पुष्टि के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक और एक्सिस बैंक के शेयरधारकों की मंज़ूरी लेनी होगी। राकेश मखीजा SKF इंडिया और टाटा टेक्नोलॉजीज़ से जुड़े रहे हैं।

- लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय के वरिष्ठ निदेशक प्रोफेसर प्रजापति त्रिवेदी को लोक प्रशासन में उनके अहम योगदान के लिये 2019 के हैरी हट्री (Harry Hatry) डिस्टिंग्विश्ड परफॉरमेंस मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हर साल अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबद्ध सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉरमेंस द्वारा ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, जिसके परफॉरमेंस मैनेजमेंट में शिक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण और सलाह के उल्लेखनीय कार्यों ने लोक प्रबंधन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रजापति त्रिवेदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और गैर-अमेरिकी हैं। प्रजापति त्रिवेदी UK में राष्ट्रमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय और विश्व बैंक के साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में काम कर चुके हैं और शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में भी उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त है।

- शोधकर्त्ताओं ने इक्वाडोर के गैलापोगस द्वीप में शार्क की विलुप्त हो चुकी एक प्रजाति को खोजने का दावा किया है। शार्क की यह विलुप्त हो चुकी प्रजाति हैमरहैड (Hammerhead) वंश से संबंध रखती है। जहाँ इस प्रजाति की शार्क को देखा गया है वह जगह सांताक्रूज़ द्वीप के पास स्थित है। यहाँ हैमरहैड की इस प्रजाति की लगभग 20 विलुप्तप्राय शार्क मछलियाँ देखी गई हैं। IUCN ने हैमरहैड शार्क की दो प्रजातियों को लुप्त होने वाली श्रेणी में रखा है और इसका एक बड़ा कारण इसका ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना है।

नोट :

- हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्त्ताओं ने हिंद, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में सात हज़ार नई अतिसूक्ष्म प्रजातियों का पता लगाने का दावा किया है। समुद्र में पहली बार क्रिस्पर जीन एडिटिंग सिस्टम युक्त एसिडोबैक्टीरिका सहित अन्य प्रजातियों की खोज की गई है। इसके लिये शोधकर्त्ताओं को आठ साल का समय लगा और उनकी यह खोज इस बात को गलत साबित करती है कि दुनियाभर में केवल 35 हज़ार सूक्ष्म प्रजातियाँ हैं। इन प्रजातियों की खोज से एंटीबायोटिक्स और एंटी-ट्यूमर दवाएँ बनाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि एसिडोबैक्टीरिका में बायोसिंथेटिक जीन समूहों की अधिकता पाई गई है।

- 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस दुनियाभर में आयोजित किया गया। हर वर्ष मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य किडनी रोग और उससे संबंधित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम करना तथा मानव स्वास्थ्य में किडनी के महत्त्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। विश्व किडनी दिवस को 2006 से मनाना शुरू किया गया था और यह एक प्रकार से वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान है। 2019 के लिये इस दिवस की थीम Kidney Health for Everyone Everywhere रखी गई है। विश्व किडनी दिवस एक अभियान है, जो किडनी रोगों के बढ़ते प्रकोप को दर्शाने और silent killer कहे जाने वाले इस रोग के प्रति लोगों को सचेत करने का काम करता है।

- 13 मार्च की देर रात चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर जैश सरगना मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकी (Global Terrorist) घोषित करने वाले प्रस्ताव के विरोध में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे बचा लिया। जबकि परिषद के चार अन्य स्थायी सदस्यों- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस और रूस ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। गौरतलब है कि सुरक्षा परिषद में चौथी बार चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल किया है। सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के समक्ष अज़हर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिये फ्राँस, ब्रिटेन और अमेरिका ने 27 फरवरी को प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद समिति ने सदस्य देशों को आपत्ति दर्ज करने के लिये 10 दिनों का समय दिया था।

- भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास 'अल-नागाह-III' की शुरुआत 13 मार्च को जबल रेजिमेंट, निजवा, ओमान में हुई। ओमान के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व वहाँ की रॉयल सेना की जबल रेजिमेंट की टुकड़ी कर रही है, जबकि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की 10वीं बटालियन की टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है। 25 मार्च तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देश के सैनिक संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अंतर्गत पर्वतीय इलाकों में संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में अपनी निपुणता और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच अल-नागाह-II सैन्याभ्यास 2017 में हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पहाड़ियों के बीच स्थित बकलोह में हुआ था। पहला अल नागाह अभ्यास 2015 में ओमान में आयोजित किया गया था।

- मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने हेतु अध्यादेश जारी किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अध्यादेश को मंज़ूरी देने के साथ ही मध्य प्रदेश OBC के लिये 27% आरक्षण का प्रावधान करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। साथ ही प्रदेश में कुल आरक्षण 70% से अधिक हो गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) के लिये 16% और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये 20% आरक्षण सीमा है।

- इधर कुछ समय से लगातार चर्चा में बने हुए भगवान अयप्पा के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में वार्षिकोत्सव की शुरुआत हो गई है। मंदिर के कपाट 10 दिनों तक चलने वाले वार्षिक उत्सव और मासिक पूजा के लिये खुल गए हैं। इसके लिये पारंपरिक 'कोदियेट्टू' से शुद्धिकरण अनुष्ठान की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान अयप्पा को शिव और मोहिनी (विष्णु जी का एक रूप) का पुत्र माना जाता है। भगवान अयप्पा को अयप्पन, शास्ता, मणिकांता नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में इनके कई मंदिर हैं और उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है सबरीमाला। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है।

- ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में 50 पेंस का एक नया सिक्का जारी किया है जो ब्लैक होल पर की गई उनकी रिसर्च को समर्पित है। पूरी तरह लकवाग्रस्त होने की वज़ह से स्टीफन हॉकिंग व्हीलचेयर पर ही रहते थे और वह बोलने में भी असमर्थ थे। वॉइस सिंथेसाइजर की मदद से वह अपने विचार प्रकट करते थे। 21 वर्ष की आयु में वह मोटर न्यूरोन बीमारी से पीड़ित हो गए

नोट :

थे। स्टीफन हॉकिंग ने क्वांटम फिजिक्स के अलावा ब्लैक होल, बिग बैंग और सापेक्षता के सिद्धांत के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण शोध किये। इस सिक्के का अनावरण स्टीफन हॉकिंग की बेटी लूसी एवं बेटे टिम ने किया। गौरतलब है कि ब्रिटेन की रॉयल मिंट इससे पहले आइज़ैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन के सम्मान में भी सिक्का जारी कर चुकी है।

- लंदन पुस्तक मेला 12 से 14 मार्च तक लंदन ओलंपिया में आयोजित किया गया। भारत ने भी इस मेले में हिस्सा लिया और भारतीय मंडप में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें भारत की संस्कृति, इतिहास, लोक साहित्य के अन्य विविध शीर्षकों के अलावा 'कलेक्टिड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' के डिजिटल संस्करण का प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी के जीवन और काल के बारे में एक संवादात्मक डिजिटल मीडिया अनुभव, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और भारत की अन्य मुख्य उपलब्धियाँ भी इस मंडप में दर्शाई गईं।

- नासा ने एक सुपर कार्गो प्लेन सुपर गप्पी (Super Guppy) बनाया है, जो बड़े और भारी सामानों की सुपरफास्ट डिलीवरी करने का काम आसान बना देगा। हाल ही में इस प्लेन ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है, जिसमें इस प्लेन ने 30 फुट चौड़े डबल डेकर जितने बड़े डिब्बे को कैलिफोर्निया से वर्जीनिया तक सफलतापूर्वक पहुँचाया। Aero Spacelines द्वारा निर्मित यह प्लेन किसी विशाल व्हेल मछली की तरह दिखता है, जिसका कॉकपिट वाला हिस्सा ढक्कन की तरह खुल जाता है। दरअसल यह एक बोइंग 377 विमान है, लेकिन भारी-भरकम चीज़ों को ढोने के लिये इसमें फेरबदल किया गया है। इसके लिये प्लेन के ढाँचे को स्टील से मज़बूत धातुओं और कार्बन कंपोजिट से बनाया गया है। यह प्लेन 460 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। Aero Spacelines ने सुपर गप्पी से पहले ऐसा ही एक प्लेन 'प्रेगनेंट गप्पी' के नाम से बनाया था।

- दिल्ली के फीरोजशाह कोटला में खेले गए पाँचवें और अंतिम एकदिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 35 रन से पराजित कर 3-2 से सीरीज़ पर कब्ज़ा कर लिया। यह 28 महीने बाद हुआ, जब भारत को अपने घरेलू मैदानों पर हार का सामना करना पड़ा है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार एकदिवसीय सीरीज़ हारी है। आपको बता दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में पाँच मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 3-1 से और एकदिवसीय सीरीज़ में 2-1 से हराया था। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा को मैन ऑफ द सीरीज़ चुना गया।

- रिज़र्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाते हुए IDBI बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रख दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा IDBI बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद यह कदम उठाया गया है। IDBI बैंक में चुकता शेयर पूंजी का LIC द्वारा 51 प्रतिशत हिस्सा अधिग्रहण करने के बाद इस बैंक को निजी श्रेणी में डाला गया है। आपको बता दें कि LIC द्वारा IDBI में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने से NPA के बोझ से दबे बैंक को करीब 10 हज़ार करोड़ से 13 हज़ार करोड़ रुपए तक का पूंजी समर्थन मिला। सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने से LIC को लगभग 2000 बैंक शाखाएँ उपलब्ध होंगी। IDBI बैंक को रिज़र्व बैंक की तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा के अंतर्गत रखा गया है।

- अमेरिका और भारत सुरक्षा व असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने और भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने पर सहमत हुए हैं। वाशिंगटन में दो दिनों तक चली बातचीत के बाद दोनों देश इस मसौदे पर सहमत हुए। भारत की तरफ से विदेश सचिव विजय गोखले और अमेरिका के स्टेट फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी विभाग की अंडर सेक्रेटरी एंड्रिया थॉम्पसन ने बातचीत में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि दोनों देश लगभग एक दशक से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत को अमेरिकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की आपूर्ति की दिशा में ठोस कुछ नहीं हो पाया है। 18 जुलाई 2006 को जब भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ था, तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस पर हस्ताक्षर किये थे। अब अमेरिकी सहयोग से छह परमाणु संयंत्र स्थापित होने के बाद भारत को अतिरिक्त ऊर्जा मिलने लगेगी। इससे भारत की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी कम होगी।

- सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 3 जुलाई को दिये अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों का सेवाकाल कम-से-कम 6 महीने से अधिक बचा है, उनके नामों पर पुलिस महानिदेशक (DGP) पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जाना चाहिये। लेकिन इसमें मेरिट का ध्यान रखना अनिवार्य है और यह नियुक्ति सभी तरह के दबावों और हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिये। गौरतलब है कि इस फैसले में

नोट :

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्यवाहक DGP की नियुक्ति नहीं होनी चाहिये और वर्तमान DGP के सेवानिवृत्त होने के 3 महीने पहले अगले DGP की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिये। आपको बता दें कि नियुक्ति के बाद DGP का न्यूनतम दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिये, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी क्यों न हो।

- हाल ही में यह खबर आई कि केरल के मालापुरम में सात वर्ष का एक बच्चा वेस्ट नाइल वायरस (West Nile Virus-WNV) से पीड़ित है। इसके मद्देनज़र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और केंद्र तथा राज्य स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। देश के अन्य भागों में इस वायरस के फैलने के बारे में की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आपको कि बता दें कि वेस्ट नाइल वायरस मच्छर जनित बीमारी है और यह बीमारी अधिकतर द्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। वेस्ट नाइल वायरस पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल ज़िले की एक महिला में पाया गया था। पक्षियों (कौवे और कोलंबीफॉर्म) में इसकी पहचान 1953 में नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। 1997 से पहले इस वायरस को पक्षियों के लिये रोगजनक नहीं माना जाता था। यह वायरस कुछ विशेष पक्षियों में प्राकृतिक रूप से अपना घर बना लेते हैं। वेस्ट नाइल वायरस मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। यह वायरस घोड़ों में गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकता है तथा घोड़ों में इसकी रोकथाम के लिये टीके उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों के लिये अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं हैं।

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को गंगा के पानी की गुणवत्ता की मासिक रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। दोनों राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सभी प्रमुख स्थलों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता की मासिक रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली NGT की पीठ ने चेतावनी दी है कि इसमें असफल रहने पर दोनों राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही NGT ने राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन के तहत कानपुर से बक्सर और बक्सर से गंगा सागर तक के हिस्से की बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा स्पष्ट जानकारी न देने की आलोचना की। इन राज्यों को स्पष्ट कार्ययोजना बनाने के लिये 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने जैसलमेर की पोकरण फायरिंग रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह इस मिसाइल का यूज़र ट्रायल था जो पूरी तरह सफल रहा। परीक्षण में मिसाइल ने अपनी अधिकतम मारक क्षमता ढाई किलोमीटर की दूरी तक जाकर अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। इन्फेंट्री के लिये विकसित की गई इस मिसाइल से सेना को मदद मिलेगी। यह एक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे पोर्टेबल होने की वज़ह से आसानी से ले जाया जा सकता है। इसे टैंक और हेलीकॉप्टर या युद्धक विमान के अलावा कंधे पर रखकर भी दागा जा सकता है। अभी इस मिसाइल का नामकरण नहीं किया गया है।

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा स्थापना समारोह में वीरता पुरस्कार तथा विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किये। अद्भुत वीरता, अदम्य साहस और कर्त्तव्य परायणता का प्रदर्शन करने के वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को 3 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र प्रदान किये गए। इनमें 2 कीर्ति चक्र और एक शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किये गए हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवाओं के लिये सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को 15 परम विशिष्ट सेवा पदक, एक उत्तम युद्ध सेवा पदक और 25 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किये। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सहित 19 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि परम विशिष्ट सेवा पदक शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। जनरल रावत के अलावा जिन्हें यह सम्मान दिया गया है, उनमें 15 लेफ्टिनेंट जनरल व तीन मेजर जनरल हैं।

- केंद्र सरकार ने एम.आर. कुमार को जीवन बीमा निगम (LIC) का चेयरमैन नियुक्त किया है। वह प्रबंध निदेशक हेमंत भार्गव का स्थान लेंगे। उन्हें पाँच साल के लिये LIC का चेयरमैन बनाया गया है। वह इससे पहले उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी) थे। इनके अलावा टी.सी. सुशील कुमार और विपिन आनंद को पाँच साल के लिये LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार दक्षिण मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी) और विपिन आनंद पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी) के पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि LIC के कार्यकारी बोर्ड में 1 चेयरमैन और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं।

- अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी कानूनविद नियोमी राव की डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में जज के रूप में नियुक्ति की पुष्टि कर दी है। अमेरिका की येल और शिकागो विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट नियोमी राव ब्रेट कोवनोह का स्थान

नोट :

लेंगी। फिलहाल वह प्रबंधन एवं बजट कार्यालय में 'एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ऑफिस ऑफ इनफॉर्मेशनइन्फॉर्मेशन एंड रेग्युलेटरी अफेयर्स' के पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के बाद यह दूसरी बड़ी अदालत है और इसके पास महत्त्वपूर्ण नियामक, राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्तियों के पृथक्करण जैसे विषयों पर सुनवाई करने का अधिकार है।

- 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन हुआ। इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम Trusted Smart Products रखी गई है। हमारे देश की एक बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ है, लेकिन उपभोक्ता अधिकारों के मामले में शिक्षित लोग भी अपने अधिकारों के प्रति उदासीन नज़र आते हैं। इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये इस दिवस का आयोजन किया जाता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाया गया है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये देशभर में 500 से भी अधिक ज़िला उपभोक्ता फोरम हैं तथा प्रत्येक राज्य में एक राज्य उपभोक्ता आयोग है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में स्थित है। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

- IIT गुवाहाटी, IIT मंडी और IISC बेंगलुरु के शोधकर्त्ताओं ने हिमालय के नज़दीक बसे 12 प्रदेशों के मौसम परिवर्तन का तुलनात्मक मानचित्र तैयार किया है। इस मानचित्र से इन राज्यों के लिये सुविधाओं का विकास करने में मदद मिलेगी। जिन राज्यों के बारे में रिपोर्ट तैयार की गई है, उनमें असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। इन राज्यों का ज़िलावार नक्शा बनाकर वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी साझा की गई है। गौरतलब है कि हिमालय का इलाका पर्यावरण के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। इस मानचित्र में कई बिंदुओं पर फोकस किया गया है, जिनमें मौसम, तापमान, वर्षा, उपज, वन और रहन-सहन के बारे में जानकारियाँ शामिल हैं।

- मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के परंपरागत पर्व भगोरिया महोत्सव की शुरुआत 14 मार्च से हुई। होली के सात दिन पहले साप्ताहिक हाटों में इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। पारंपरिक भगोरिया महोत्सव में इस क्षेत्र की संस्कृति, परिवेश, रहन-सहन, वेषभूषा, वाद्ययंत्र प्रमुख आकर्षण होते हैं। आदिवासी समुदाय मान्यतानुसार दलिया, खजूर, काकनी, माजक आदि की खरीदारी करते हैं और इसे पर्व की मिठाई कहा जाता है। भगोरिया त्योहार में आदिवासी लोग भागोरादेव की पूजा करते हैं। झाबुआ, धार, अलीराजपुर और खरगोन जैसे क्षेत्रों में यह सबसे पुराने त्योहारों में से एक है।

- हिंदी के जाने-माने साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी को उनके 2013 में प्रकाशित काव्य संग्रह 'जितने लोग उतने प्रेम' के लिये 2018 का व्यास सम्मान देने का एलान किया गया है। आपको बता दें कि के.के. बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान के तहत चार लाख रुपए और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार 1991 में शुरू किया गया था और डॉ. रामविलास शर्मा, डॉ. धर्मवीर भारती, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह, मन्नू भंडारी, विश्वनाथ त्रिपाठी सहित कई प्रमुख साहित्यकार इससे सम्मानित हो चुके हैं। 2017 का व्यास सम्मान ममता कालिया को उनके उपन्यास 'दुक्खम सुक्खम' के लिये दिया गया था। लीलाधर जगूड़ी को 2004 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। उनकी प्रमुख कृतियों में 'शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चाँद और खबर का मुँह विज्ञापन से ढंका है' शामिल हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने BCCI की अनुशासनात्मक समिति द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को लेकर तेज़ गेंदबाज़ एस. श्रीसंत के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने BCCI को उन पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध पर तीन महीने के भीतर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। श्रीसंत 2007 विश्व टी-20 और 2011 एकदिवसीय विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। आपको बता दें कि श्रीसंत के साथ मुंबई के स्पिनर अंकित चव्हाण और हरियाणा के अजीत चंदीला को 2013 में BCCI की अनुशासनात्मक समिति ने आजीवन प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके बाद श्रीसंत ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी।

- विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने भारत में पहली बार 2020 में अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन करने की मंज़ूरी दे दी है। भारत ने फ्राँस को पीछे छोड़ते हुए मेज़बानी का अधिकार हासिल किया। यह अंडर-17 महिला विश्व कप का सातवाँ संस्करण होगा। गौरतलब है कि यह भारत में फीफा का दूसरा आयोजन होगा। इससे पहले 2017 में भारत ने पहली बार अंडर-17 पुरुष विश्व कप की

नोट :

मेज़बानी की थी। उसमें इंग्लैंड ने स्पेन को फाइनल में हराकर खिताब जीता था। अंडर-17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करने वाला भारत दूसरा एशियाई देश होगा। इससे पहले जॉर्डन ने 2016 में इसकी मेज़बानी की थी और तब खिताब उत्तर कोरिया ने जीता था, जो इस टूर्नामेंट में दो बार खिताब जीतने वाला एकमात्र देश है।

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 14 मार्च से 21 मार्च तक विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक देशों के 7500 विशेष एथलीट प्रतिस्पर्द्धा करेंगे। ये खेल पहली बार पश्चिम एशिया में आयोजित किये जा रहे हैं, जिनमें 24 ओलंपिक खेलों में एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। आबु धाबी और दुबई में नौ विश्वस्तरीय खेल आयोजन स्थलों पर ये खेल आयोजित किये जा रहे हैं। मेज़बान UAE के बाद भारत ने इन खेलों में सबसे बड़ी टीम भेजी है। आपको बता दें कि विशेष ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय खेल आयोजन और वैश्विक आंदोलन है, जो खेल की शक्ति के माध्यम से बौद्धिक रूप से अशक्त लोगों के सशक्तीकरण पर केंद्रित है।

- इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए राष्ट्रीय टी-20 टूर्नामेंट के फाइनल में महाराष्ट्र को नौ गेंद शेष रहते हुए आठ विकेट से हराकर कर्नाटक ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी जीती। कर्नाटक ने यह राष्ट्रीय टी-20 टूर्नामेंट का खिताब पहली बार जीता है, जबकि महाराष्ट्र दूसरी बार यह ट्रॉफी जीतने में असफल रहा। उसने 2009-10 में यह ट्रॉफी जीती थी। आपको बता दें कि कर्नाटक छठी टीम है जिसने तीनों प्रारूपों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप- रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। इस ट्रॉफी की शुरुआत 2008-09 में हुई थी।

- हाल ही में ऑस्कर अवॉर्ड विनर ए.आर. रहमान (KM Music Conservatory) के शिष्य पियानोवादक लिडियन नादस्वरम ने अमेरिकी रियलिटी शो 'द वर्ल्ड्स बेस्ट' का खिताब जीता है। लिडियन ने दक्षिण कोरिया के कुक्कीवोन उर्फ द फ्लाइंग ताइक्वांडो मास्टर्स को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। इसके तहत लिडियन ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार जीता है।

- अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल महासंघ (फीफा) ने इस बार अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 की मेज़बानी करने का मौका भारत को दिया है। अमेरिका के मियामी में फीफा परिषद की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इससे पहले भारत ने अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2017 की मेज़बानी की थी।

- ब्रिटेन सरकार ने ब्रेक्जिट के बाद लागू की जाने वाली नीतियों को तैयार करते हुए एक नई 'अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति' की घोषणा की है। इस रणनीति के तहत शिक्षा उपरांत दिये जाने वाले वीज़ा व्यवस्था में सुधार होगा जिससे भारतीय छात्रों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इस नई रणनीति के तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के पश्चात् ब्रिटेन में काम की तलाश हेतु छह माह तक रहने का मौका दिया जाएगा। यह रणनीति आगामी सत्रों से प्रभावी होगी।

- भारत का पहला रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) अब निवेश के लिये उपलब्ध है। एम्बेसी ऑफिस पार्क, बंगलूरू के एक रियल एस्टेट डेवलपर ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) हेतु इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लॉन्च किया है। एम्बेसी ऑफिस पार्क ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से 4,570 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है।

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन (National Institute of Nutrition-NIN) और सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics-Icrisat) ने किशोरियों में देखी जाने वाली कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु 'FeFA गर्ल्स' की शुरुआत की है। 'FeFA गर्ल्स' का उद्देश्य लड़कियों में हीमोग्लोबिन और आयरन के स्तर में सुधार लाना है। दोनों संस्थान तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर इस परियोजना को पूरा करने हेतु काम करेंगे। 'FeFA गर्ल्स' का तात्पर्य है-
  - Fe- आयरन का रासायनिक प्रतीक
  - FA- किशोरियों के लिये (For Adolescent)

- भारत-थाईलैंड राजनयिक संबंधों के 72 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रॉयल थाई एम्बेसी ने हाल ही में तीन दिवसीय 'नमस्ते थाईलैंड महोत्सव' का आयोजन किया था। इस महोत्सव की शुरुआत 15 मार्च को हुई थी, जबकि समापन 17 मार्च को हुआ। द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में, भारत का थाईलैंड के साथ एक अच्छा और शांतिपूर्ण संबंध रहा है।

नोट :

- हाल ही में रघु कर्नाड को प्रतिष्ठित विंडहम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि यह पुरस्कार नॉन-फिक्शन श्रेणी में उनकी किताब 'फारदेस्ट फील्ड: एन इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर' के लिये दिया गया है। 2013 में शुरू हुआ यह पुरस्कार अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। इस साल यह पुरस्कार दुनिया भर से चुने गए 8 लेखकों को प्रदान किया गया है। रघु कर्नाड को अपनी इस किताब के लिये साल 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार (अंग्रेज़ी) भी मिल चुका है। यह किताब दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े कुछ भारतीयों के अनुभवों के बारे में है।

- मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स ज़िले के मासिनराम क्षेत्र में दुनिया की सबसे गहरी सैंडस्टोन केव (गुफा) क्रेम पुरी (Krem Puri) की खोज के एक साल बाद अब देश में सबसे गहरी शाफ्ट केव का पता चला है। पिछले माह Caving in the Abode of the Clouds Expedition के 28वें संस्करण की खोज प्रक्रिया के दौरान क्रेम उम लाडॉ (Krem Um Ladaw) नामक देश की इस सबसे गहरी शाफ्ट केव का पता चला। गौरतलब है कि 24,583 मीटर लंबी Krem Puri गुफा को विश्व में सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा के रूप में जाना जाता है। मेघालय में इंडिया की सबसे लंबी गुफाएँ हैं। अनुमान है कि मेघालय में 1580 से भी अधिक भूमिगत गुफाओं का नेटवर्क है, जिसमें से 980 का ही पता चल पाया है। ये गुफाएँ जयंतिया, खासी और गारो हिल्स में 427 किमी. इलाके में फैली हैं। भारत की 10 सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से 9 मेघालय में हैं।

- 20 मार्च को दुनियाभर में विश्व गौरैया दिवस (World Sparrow Day) मनाया गया। गौरैया के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाना भी इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है। गौरैया की लगातार कम होती जा रही तादाद के मद्देनज़र 2010 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। 2012 में दिल्ली की राज्य सरकार ने गौरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित किया था। ब्रिटेन की 'रॉयल सोसायटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स' ने भारत से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को 'रेड लिस्ट' में डाला है। गौरैया की संख्या में यह कमी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखी गई है। गौरैया 'पासेराडेई' (Passeridae) परिवार की सदस्य है।

- आपदा सहनशील आधारभूत ढाँचा 2019 पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (International Workshop on Disaster Resilient Infrastructure-IWDRI) का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ। इसमें 33 देशों के विकास और आपदा जोखिम विशेषज्ञ, बहुपक्षीय विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और अन्य भागीदारों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में आपदा सहनशील आधारभूत ढाँचे के लिये प्रस्तावित गठबंधन Coalition for Disaster Resilient Infrastructure-CDRI) को विश्व स्तर पर ले जाने पर भी चर्चा हुई। इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम कम करने संबंधी कार्यालय और ग्लोबल कमीशन ऑन एडॉप्शन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक के साथ मिलकर किया। गौरतलब है कि CDRI की परिकल्पना सूचना के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण भागीदारी के रूप में की गई है। भारत ने नई दिल्ली में 2016 में आयोजित एशियन आपदा जोखिम कम करने पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के तुरंत बाद CDRI के सृजन की घोषणा की थी।

- अमेरिका द्वारा अपना पहला **एक्सास्केल सुपरकंप्यूटर 2021** तक बना लेने की संभावना है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार, देश का पहला 'एक्सास्केल सुपरकंप्यूटर' 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा जो प्रति सेकंड एक अरब से अधिक गणनाएँ करने में सक्षम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्षमताओं वाला यह सुपरकंप्यूटर अब तक के बने सबसे पावरफुल सिस्टम से सात गुना तेज़ी से काम करेगा। सुपरकंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप प्रति सेकंड में मापा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर कई टेराफ्लॉप्स प्रति सेकंड की स्पीड के साथ करोड़ों की संख्या में गणना करने में सक्षम हैं।

- भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबु धाबी में संपन्न हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में 85 स्वर्ण, 154 रजत और 129 कांस्य पदकों सहित कुल 368 पदक जीते। इन खेलों में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नौवीं बार स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लेते हुए भारत ने 284 एथलीट उतारे थे। भारत ने पॉवरलिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा 20 स्वर्ण, 33 रजत और 43 कांस्य सहित कुल 96 पदक जीते। रोलर स्केटिंग में भारत ने 13 स्वर्ण, 20 रजत और 16 कांस्य सहित 49 पदक जीते। साइक्लिंग में भारत ने 11 स्वर्ण, 14 रजत और 20 कांस्य सहित 45 पदक जीते। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्द्धाओं में भारत को 5 स्वर्ण, 24 रजत और 10 कांस्य पदक मिले। अगले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का आयोजन 2021 में स्वीडन में किया जाना प्रस्तावित है।

नोट :

- शंघाई सहयोग संगठन के देशों का आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यास सैरी-अर्का एंटी टेरर इस वर्ष कज़ाखस्तान में होने जा रहा है। भारत और पकिस्तान भी इस संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास की घोषणा क्षेत्रीय आतंकवाद-निरोधी ढाँचे (Regional Anti-Terrorist Structure-RATS) की उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुई 34वीं बैठक में की गई। इस बैठक में भारत, कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताज़िकिस्तान, उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों के अलावा RATS की कार्यकारी समिति के सदस्य शामिल हुए। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान भी SCO के पूर्ण सदस्य हैं। पिछले वर्ष रूस में हुए SCO के वॉर गेम में भी दोनों देशों ने हिस्सा लिया था। SCO का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है।

- रक्षा मंत्रालय ने नए नौसेना प्रमुख के पद पर वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नियुक्त करने का फैसला किया है। फिलहाल वह विशाखापत्तनम की पूर्वी कमांड की अगुवाई कर रहे हैं। करमबीर सिंह देश के 24वें नौसेना प्रमुख होंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला से प्रशिक्षण प्राप्त अतिविशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करमबीर सिंह 1980 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा 31 मई को रिटायर हो रहे हैं।

- 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNAIDS ने जानकारी दी है कि भारत ने एड्स जनित टीबी से होने वाली मौतों को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। भारत ने यह कमी 2020 की तय समय-सीमा से तीन महीने पहले हासिल की है तथा टीबी से होने वाली मौतों के मामले में 20 से अधिक देशों में सर्वाधिक गिरावट भारत में देखी गई है। वैसे 2010 के बाद दुनियाभर में इन मौतों में 42% के कमी हुई है और ऐसी टीबी से मरने वालों की संख्या 52 लाख से घटकर 30 लाख रह गई है। गौरतलब है कि HIV संक्रमण के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने के कारण टीबी की वज़ह से सबसे अधिक रोगियों की मौत होती है।

- आंध्र प्रदेश की यनादि (Yanadi) जनजाति के लगभग 2000 लोग आगामी लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। 10 स्वयंसेवकों के एक समूह ने इन लोगों को मताधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। राज्य के कृष्णा ज़िले में पाई जाने वाली यह घुमंतू जनजाति लगातार एक मौसम से अगले मौसम तक रोज़गार की तलाश में भटकती रहती है। इनमें से अधिकांश लोग जंगली केकड़ों और मछलियों का शिकार करने के लिये मैंग्रोव जंगलों और दलदली भूमि के निकट रहते हैं और एक स्थान पर टिककर न रह पाने की वज़ह से सरकारी अधिकारियों को इन तक पहुँचने में कठिनाई आती थी। इसके अलावा, इस जनजाति को राजनीतिक अधिकारों और वोट के महत्त्व से दूर रखने में अशिक्षा भी एक बड़ी वज़ह रही है।

- नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने लोनावला स्थित INS शिवाजी में भारतीय नौसेना की परमाणु, जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा (Nuclear, Biological and Chemical Training Facility-NBCTF) का उद्घाटन किया। NBCTF को अभेद्य नाम दिया गया है और यह परमाणु, जैविक एवं रासायनिक पहचान तथा सुरक्षा प्रणालियों से लैस नौसैनिक जहाज़ों के प्रशिक्षित कर्मियों की मदद करेगा। यह सुविधा नौसेना कर्मियों को परमाणु, जैविक और रासायनिक एजेंटों का पता लगाने के साथ ही उनके संरक्षण और परिशोधन के लिये वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। आपको बता दें कि INS शिवाजी 2019-20 में अपना प्लैटिनम जयंती वर्ष मना रहा है।

- स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे की राजधानी ओस्लो इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिये वायरलेस चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। नॉर्वे सरकार ने एक प्रोजेक्ट के तहत ओस्लो शहर की सड़कों पर इंडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ चार्जिंग प्लेट इंस्टॉल किया है, जहां इलेक्ट्रिक कार को चार्ज किया जा सकता है। कुल 52 लाख जनसंख्या वाले नॉर्वे में वहाँ की सरकार ने देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। वहाँ इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन का पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर लोगों में इलेक्ट्रिक कार खरीदने को बढ़ावा देने के लिये टैक्स और अन्य छूट दी जाती है। इसी का नतीजा है कि 2018 में नॉर्वे में 46,143 नई इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई। आज नॉर्वे दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कारें रखने वाला देश है और वहाँ 2023 तक शून्य उत्सर्जन प्रणाली कायम करने का लक्ष्य रखा गया है।

- केन्या के विज्ञान शिक्षक पीटर तबीची को ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले अफ्रीकी हैं। दुबई में हुए समारोह में पीटर तबीची को लगभग सात करोड़ रुपए बतौर पुरस्कार दिये गए। उन्हें इस पुरस्कार के लिये 10 हज़ार अन्य आवेदक शिक्षकों में से चुना गया। वह अपनी आय का 80 % हिस्सा केन्या के गाँव पिवानी के अनाथ और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिये देते हैं। पिवानी केन्या का ऐसा इलाका है, जहाँ का हर तीसरा बच्चा अनाथ है या उसके माता-पिता में से कोई एक जीवित नहीं है। यह इलाका प्राय: सूखाग्रस्त

नोट :

रहता है। पीटर तबीची जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, उसमें संसाधन के नाम पर एक कंप्यूटर और बीच-बीच में कट जाने वाला इंटरनेट कनेक्शन और कुछ मेज़-कुर्सियाँ ही हैं। इसके बावजूद वे 11 से 16 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल टीचर प्राइज़ शिक्षकों को दिये जाने वाले दुनिया के बड़े अवॉर्ड में से एक है। यह पुरस्कार हर साल शैक्षणिक संस्थान वर्के फाउंडेशन (Verkey Foundation) द्वारा दिया जाता है।

- प्रख्यात साहित्यकार और सामजिक कार्यकर्त्ता रमणिका गुप्ता का दिल्ली में 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वह साहित्य, समाजसेवा और राजनीति सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने स्त्री विमर्श पर बेहतरीन काम किया और वह सामाजिक सरोकारों की पत्रिका 'युद्धरत आम आदमी' की संपादक भी थीं। उन्होंने झारखंड के हज़ारीबाग के कोयलांचल से मजदूर आंदोलनों को साहित्य के ज़रिये राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का काम किया। बिहार विधानसभा और विधान परिषद् में विधायक रही रमणिका गुप्ता की आत्मकथा 'हादसे और आपहुदरी' बेहद लोकप्रिय पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा, उनकी प्रमुख रचनाओं में 'भीड़ सतर में चलने लगी है', 'तुम कौन', 'तिल-तिल नूतन', 'मैं आजाद हुई हूं', 'अब मूरख नहीं बनेंगे हम', 'भला मैं कैसे मरती', 'आदम से आदमी तक', 'विज्ञापन बनते कवि', 'कैसे करोगे बँटवारा इतिहास का', 'दलित हस्तक्षेप', 'निज घरे परदेसी', 'सांप्रदायिकता के बदलते चेहरे', 'कलम और कुदाल के बहाने', 'दलित हस्तक्षेप', 'दलित चेतना- साहित्यिक और सामाजिक सरोकार', 'दक्षिण- वाम के कठघरे' और 'दलित साहित्य', 'असम नरसंहार-एक रपट', 'राष्ट्रीय एकता', 'विघटन के बीज' शामिल हैं।

- ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के शोधकर्त्ताओं ने पूर्वी अंटार्कटिका के सबसे बड़े ग्लेशियर टॉटेन में 160 दिनों तक चले एक अभियान के दौरान यह पाया कि वहाँ बर्फ के नीचे झीलों का एक बड़ा नेटवर्क छिपा हुआ है। इस खोज से यह पता लगाने में आसानी हो सकती है कि भविष्य में ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से दुनिया के महासागर किस प्रकार प्रभावित होंगे। अनुमान है कि 30 किमी. लंबा और लगभग 2 किमी. मोटी बर्फ वाला टॉटेन ग्लेशियर यदि पिघल जाए तो समुद्र का जलस्तर 7 मीटर तक बढ़ सकता है।

- तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बोलीविया पहुँचने पर संवैधानिक राजधानी सूक्रे के सांताक्रूज़ वीरू वीरू इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोराल्स ने उनकी अगवानी की। आपको बता दें कि बोलीविया में सरकार ला पाज़ से काम करती है और उसे प्रशासनिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद भारत और बोलीविया के राष्ट्रपतियों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। रामनाथ कोविंद ने भारत-बोलिविया व्यापार फोरम की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों ने आठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये, जिनमें राजनयिकों के लिये वीज़ा रहित आवागमन, राजनयिक अकादमियों के बीच आदान-प्रदान, खनन, अंतरिक्ष, पारंपरिक चिकित्सा, IT के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और द्वि-महासागरीय रेलवे परियोजना शामिल हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद भारत की ओर से इस लैटिन अमेरिकी देश की यह पहली उच्चस्तरीय यात्रा है।

- दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षक मनु गुलाटी को लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये डेढ़ लाख की पुरस्कार राशि के साथ मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडिविज़ुअल श्रेणी में उत्कृष्टता के लिये 2019 के मार्था फैरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि डॉ. मार्था फैरेल ने लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। आपको बता दें कि मार्था फैरेल अवार्ड उनकी याद में 2017 में शुरू हुआ था। यह पुरस्कार रिजवान आदातिया फाउंडेशन और Participatory Research in Asia द्वारा सह-प्रायोजित और मार्था फैरेल फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। यह पूरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाता है- मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडिविज़ुअल और बेस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर जेंडर इक्वैलिटी। बेस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर जेंडर इक्वैलिटी श्रेणी में यह पुरस्कार महिला जन अधिकार समिति को मिला है। आपको बता दें कि मार्था फैरेल 13 मई, 2015 को काबुल में एक गेस्ट हाउस में आतंकवादी हमले में मारे गए 14 लोगों में शामिल थीं।

CISF

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंदिरापुरम स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के 50वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया।

- CISF (Central Industrial Security Force) एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसे 'केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968' के तहत गठित किया गया था।

नोट :

- यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
- CISF पूरे भारत में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खानों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाहों आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को CISF द्वारा संरक्षित किया जाता है।
- भारत में अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force-CRPF), सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force-BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police-ITBP), सशस्त्र सीमा बल (Sashastra Seema Bal-SSB) शामिल हैं।

NCRB का 34वाँ स्थापना दिवस

- 11 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau- NCRB) ने अपना 34वाँ स्थापना दिवस मनाया।
- NCRB के अनेक अधिकारियों को उनके कार्य के प्रति लगन एवं समर्पण के लिये प्रशस्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के साथ-साथ क्रीडा एवं अन्य स्पर्द्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।
- गौरतलब है कि NCRB का गठन 1986 में हुआ था यह देश में अपराध आँकड़ों का संग्रह, रखरखाव एवं विश्लेषण के लिये उत्तरदायी है।
- NCRB नीतिगत मामलों एवं अनुसंधान के लिए अपराध, दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं तथा कारागृहों पर आँकड़ों के प्रामाणिक स्रोत के लिये एक नोडल एजेंसी है।
- यह भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना, अपराध एवं अपराधियों की ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (The Crime and Criminal Tracking Networks and Systems- CCTNS) के कार्यान्वयन हेतु एक निगरानी एजेंसी है।
- CCTNS परियोजना का उद्देश्य देश में पुलिस कार्य की दक्षता में वृद्धि के लिये एक व्यापक एवं समेकित प्रणाली का सृजन करना है।
- NCRB भारतीय पुलिस अधिकारियों एवं विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिये सूचना प्रौद्योगिकी एवं फिंगर प्रिंट विज्ञान में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य भारतीय पुलिस/जाँच अधिकारियों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना है।

इडुक्की का मरयूर गुड़

- हाल ही में केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित मरयूर के गुड़ को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ।
- इस गुड़ का निर्माण पारंपरिक तरीके से किया जाता है।
- वर्तमान में मरयूर के गुड के नाम पर नकली गुड भी बाज़ार में बेचा जाता है जिससे असली गुड़ का दाम कम हो जाता है।
- GI टैग मिलने के बाद उपभोक्ताओं को असली गुड़ ही मिलेगी और किसानों को भी अच्छा दाम मिलेगा।
- ज्ञातव्य है कि GI टैग अथवा पहचान उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, या किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है अथवा वह उसका मूल स्थान हो।
- GI टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिये दिया जाता है।

ओरांग राष्ट्रीय उद्यान

- ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है।
- यह असम के दर्रांग और सोनितपुर ज़िलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर 78.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है।

नोट :

- इसे 1985 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1999 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। इसे 2016 में देश का 49वाँ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
- इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (IUCN साइट) का छोटा रूप भी माना जाता है क्योंकि दोनों पार्कों में एक समान परिदृश्य है जो दलदल, जलधाराओं और घास के मैदानों से बना है।
- यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर गैंडों का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग टाइगर रिजर्व को 50वाँ नवीनतम टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया है।

पिनाका रॉकेट सिस्टम

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने राजस्थान स्थित पोखरण रेंज में पिनाका (PINAKA) मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है।

- यह हथियार प्रणाली अत्याधुनिक गाइडेंस किट और आधुनिक नेवीगेशन तथा नियंत्रण प्रणाली से लैश है।
- गौरतलब है कि परीक्षण के दौरान यह प्रणाली सटीक निशाना लगाने में पूरी तरह सफल रही।
- उड़ान के दौरान टेलिमैट्री प्रणाली की सहायता से वाहन की मॉनीटरिंग की गई।
- पिनाका स्वदेश विकसित रॉकेट प्रणाली है और सटीक निशाना लगाने में सेना की मदद करेगी।

सिरसी सुपारी को जीआई टैग

हाल ही में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले की 'सिरसी सुपारी' को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सिरसी सुपारी को जीआई नंबर 464 प्रदान किया गया है।

- ध्यातव्य है कि इसकी खेती येल्पुरा, सिदपुरा और सिरसी तालुका में की जाती है।
- सिरसी सुपारी की कुछ अनूठी विशेषताएँ-
  - आकार में गोल और सिक्के जैसी चपटी
  - विशेष बनावट, अनुप्रस्थ काट (cross-sectional) दृश्य
  - अनूठा स्वाद
- उक्त विशेषताएँ किसी अन्य क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुपारी में नहीं पाई जाती हैं। सिरसी सुपारी का औसत वज़न 7.5 ग्राम (सूखा) होता है।

जीआई टैग

- भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication- GI) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है।
- इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- वर्ष 2004 में 'दार्जिलिंग टी' जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।
- भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिये मान्य होता है।
- जीआई टैग प्राप्त कुछ उत्पाद इस प्रकार हैं- कांचीपुरम सिल्क साड़ी, अल्फांसो मैंगो, नागपुर का ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, इत्यादि।

नोट :

नवाचार केंद्र (Innovation Centre)

- संयुक्त राष्ट्र की दूरसंचार संस्था अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunications Union- ITU) ने भारत में दक्षिण एशिया के लिये अपने पहले क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ पहला नवाचार केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।
- ITU दूरसंचार क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकी मानकों को स्थापित करने के लिये विश्व स्तर पर देशों और कंपनियों के साथ समन्वय करता है।
- पिछले चार वर्षों में भारत ने तकनीकी योगदान के मामले में अपनी भागीदारी पाँच गुना बढ़ा दी है।
- ITU ने इसे मान्यता दी है और इसीलिये उक्त निर्णय लिया गया है।
- ITU पूर्णकालिक सदस्यता के लिये प्रत्येक संगठन से 32,000 स्विस फ्रैंक, लगभग 32,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर शुल्क लेता है।
- ITU का नवाचार केंद्र उत्पादकता बढ़ाने के लिये छोटे और मध्यम व्यवसायों द्वारा प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर काम करेगा।
- केंद्र 5 जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आगामी नई प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिये फर्मों के साथ सहयोग करेगा।

गिरनार वन्यजीव अभयारण्य

- गिरनार वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में स्थित है।
- यहाँ पेड़ों की कई प्रजातियाँ, लगभग 179 पक्षियों की प्रजातियाँ, 33 सरीसृप प्रजातियाँ और 30 स्तनधारी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं।
- गुजरात में गिर का जंगल दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ शेरों को जंगल में घूमते हुए देखा जा सकता है।
- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार, वर्तमान में गिर जंगल एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान है।

वुड स्नेक (Wood Snake)

- वुड स्नेक की एक प्रजाति, जिसे पिछले 140 वर्षों से नहीं देखा गया था, को मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य में वैज्ञानिकों द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण में पुनः पाया गया।
- यह मेघमलाई जंगलों और पेरियार टाइगर रिज़र्व की स्थानीय प्रजाति मानी जाती है।
- हाल ही में आर चैतन्य (सरीसृप पर अध्ययन करने वाले) और वरद गिरी (फाउंडेशन फॉर बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन के निदेशक) द्वारा इसे फिर से खोजा गया है।
- वुड स्नेक की इस स्थानीय प्रजाति को आखिरी बार 1878 में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी और प्रकृतिवादी कर्नल रिचर्ड हेनरी बेड्डोम द्वारा देखा गया था।
- उन्होंने इसे एक नई प्रजाति 'ज़ाइलोफ़िस इंडिकस' के रूप में वर्णित किया।
- गौरतलब है कि मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के थेनी ज़िले में स्थित है।
- यहाँ बड़े स्तनधारियों के अलावा साँपों, तितलियों और चींटियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

डेलाइट सेविंग टाइम

डेलाइट सेविंग टाइम मार्च में प्रारंभ होकर नवंबर के पहले रविवार को समाप्त होता है। पिछले साल DST 11 मार्च को शुरू हुआ और 4 नवंबर को समाप्त हुआ था। इस साल DST 10 मार्च को शुरू हो गया है जो 3 नवंबर, 2019 को समाप्त होगा।

क्या है डेलाइट सेविंग टाइम

- ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा होता है, दिन के प्रकाश का अधिकतम उपयोग करने के लिये कई देश गर्मियों में अपनी घड़ियों को एक घंटा आगे सेट कर लेते हैं ताकि जल्दी काम शुरू करके खत्म कर सके। कुछ दिन बाद वे देश फिर से अपने मूल समय पर वापस आ जाते हैं इसे टाइमलाइट सेविंग टाइम कहा जाता है।
- हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में स्थानीय समयानुसार 2 बजे, अमेरिकियों ने अपनी घड़ियों को एक घंटे आगे सेट किया। इसके बाद timeanddate.com के अनुसार 70 से अधिक देशों ने इसका अनुसरण किया।

नोट :

- भारत डेलाइट सेविंग टाइम का पालन नहीं करता है क्योंकि भूमध्य रेखा के पास के देशों में मौसमों के बीच दिन के समय में उच्च विविधता का अनुभव नहीं होता है।

World Wide Web

- 12 मार्च, 2019 को वर्ल्ड वाइड वेब (World Wide Web- WWW) के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गूगल ने WWW को डूडल समर्पित किया।
- वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था।
- उन्होनें डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने के लिये हाइपरटेक्स्ट के उपयोग की कल्पना की थी। इसमें HTML, URL, HTTP जैसे फंडामेंटल शामिल थे।
- WWW आमतौर पर वेब के रूप में जाना जाता है। यह ऑनलाइन सामग्री का एक नेटवर्क है, जहाँ डॉक्यूमेंट्स और अन्य वेब रिसोर्सेज़ की पहचान यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) द्वारा की जाती है।
- पहली वेबसाइट वर्ष 1990 में बनाई गई थी जो World Wide Web प्रोजेक्ट को ही समर्पित थी।

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923

हाल ही में अटॉर्नी-जनरल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में राफेल सौदे वाले दस्तावेज़ के चोरी के लिये ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ 'आपराधिक कार्रवाई' हेतु आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम को संज्ञान में लाया गया।

- औपनिवेशिक शासन में गुप्त एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिये सामान्यत: राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी के मुद्दों पर अधिकारियों द्वारा सूचना को गोपनीय रखने के लिये इस कानून को लाया गया था।
- पहली बार 1923 में इस अधिनियम को लागू किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भी इसे बरकरार रखा गया।
- सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिये लागू यह कानून, राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने तथा जासूसी, राजद्रोह और अन्य संभावित खतरों से निपटने हेतु रूपरेखा प्रदान करता है।
- यह कानून जासूसी, साझा 'गुप्त' जानकारी, वर्दी का अनधिकृत उपयोग, जानकारी रोकना, निषिद्ध/प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के कार्यों में हस्तक्षेप, अन्य लोगों के लिये दंडनीय अपराध बनाता है।
- यह जानकारी सरकार, दस्तावेजों, तस्वीरों, रेखाचित्रों, मानचित्रों, योजनाओं, मॉडल, आधिकारिक कोड या पासवर्ड से संबंधित किसी स्थान के संदर्भ में हो सकती है।
- अपराधी व्यक्ति को 14 साल तक का कारावास, जुर्माना या दोनों सज़ा दी जा सकती है।

नोट :